Fourth Series Vol. XXXVIII - No. 29

Thursday, April 2, 1970
Chaitra 12, 1892 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Tenth Session)

(Vol. XXXVIII contains Nos. 21 - 30)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Price : Rs. 1.00

CONTENTS

No. 29—Thursday, April 2, 1970/Chaitra 12, 1892 (Saka)

	COLUMNS
Oral Answers to Questions—	
*Starred Questions Nos. 751 to 754 and 758 . . .	2–29
Written Answers to Questions —,	
rred Questions Nos. 755 to 757 and 759 to 780 . .	29–47
Unstarred Questions Nos. 4801 to 4821, 4823 to 4829, 4831 to 4852, 4854 to 4903, 4905 to 4911, 4913 to 4938 and 4940 to 4964	47–176
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
Stay Order by Certain High Courts on Government decision for fixing low price of sugar	176–191
Papers Laid on the Table	191–93
Estimates Committee—	
ndred and twelfth, Hundred and seventeenth and Hundred and Eighteenth Reports	193
apers Laid on the Table	194
Matter Under Rule 377—	
A R coverage of CPI (M) Members speeches in Lok Sabha .	194–200
Shri P. Ramamurti	194–95
Shri Satya Narayan Sinha .	196–98
Demands for Grants, 1970–71—	
Ministry of Home Affairs . . .	200–95
Shri Krishna Kumar Chatterji .	201–05
Shri Indrajit Gupta .	205–12
Shri Vidya Charan Shukla .	212–23
Shri Badrudduja	223–32
Shri Prem Chand Verma	232–38
Shri P. Gopalan	240–45
Shri Nageshwar Dwivedi	246–50

n + marked above the name of a Member indicates that the question was ac ed on the floor of the House by that Member.

COLUMNS

Shri Ghayoor Ali Khan . . 250-56

Shri Kushok Bakula . . . 256–62

Shri Prakash Vir Shastri 262–70

Shri Randhir Singh . . . 271–75

Shri J. Mohamed Imam . 275–82

Shrimati Laxmi Bai . . . 283–87

Shri Ram Gopal Shalwale . . . 288–94

Shri Sheo Narain 294–95

Discussion Re. Non-implementation of Gajendra gadkar Commission's Recommendations in regard to Jammu and Ladakh . 295-330

Shri Atal Bihari Vajpayee 295-306

Shri Inder J. Malhotra . 306–10

Shri H. N. Mukerjee . . . 310–12

Shri Ahmed Aga 312–16

Shri Prakash Vir Shastri 316–19

Shri Sheo Narain 319–21

Shri Kushaok Bakul . . . 321–23

Shri Molahu Prasad . 323–26

Shri Y. B. Chavan 326–30

LOK SABHA

Thursday, April 2, 1970 / Chaitra 12, 1892 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

RE: QUESTIONS 751 AND 753

MR. SPEAKER: Shri Onkar Lal Berwa.

श्री ओंकार लाल बेरवा : प्रश्न संख्या 751 ।

SHRI S. M. BANERJEE: Question 753 may also be taken along with it.

It is the same type of Question; only the State is different.

MR. SPEAKER: It is all right.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) Information is being collected....

श्री ओंकार लाल बेरवा: जब सवाल हिन्दी में दिया गया है तो जवाब भी उस का हिन्दी में ही मिलना चाहिए ।

श्री शेर सिंह : ठीक है, मैं हिन्दी में जवाब पढ़े देता हूं...

SHRI S. KANDAPPAN: I object to this attitude. This is unfair. This is not fair to non-Hindi people. After all, when they get simultaneous translation, why should they go on insisting on Hindi like this? I would request the Hindi Members to be indulgent enough to non-Hindi people. When they go on insisting on Hindi like this, it is very unfair. (*Interruption*) My point is this. There are Members from my State who do not know any language except Tamil. This is very agonising. I am not going to tolerate this kind of thing. When there is a simultaneous translation, why should they insist like this? If they think this is a prestige question, then we also want that there should be simultaneous translation for our language. Is the Lok Sabha Secretariat prepared to provide for simultaneous translation in Tamil language? I strongly object to this. I resent it. (*Interruptions*)

Sir, the position is this. There is the simultaneous translation. When the answer is given in English, it is simultaneously translated into Hindi, and when the answer is given in Hindi, it is simultaneously translated into English. The Members have got to realise that, after all, we the Tamils also speak a language which is recognised in the Constitution and which does not find any place here during the Question Hour. What is the fun of insistence on Hindi by these Members? This is very bad. I object to this.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Leave it to the Minister.

MR. SPEAKER: After all, we have the arrangement of simultaneous translation in both the languages. What is the fun in raising these matters.... (*Interruptions*)

वर्ष 1968 में बन्द हड़ताल में भाग लेने के कारण मध्य प्रदेश के डाक तथा तार विभाग के निलम्बित कर्मचारियों की बहाली

+

***751. श्री ओंकार लाल बेरवा:**
श्री टी० पी० शाह :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में, जिला-वार सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण डाक तथा तार विभाग

के कितने कर्मचारियों को निलम्बित और उत्पीड़ित किया गया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त कर्मचारियों के मामलों पर फिर से विचार करने तथा सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार उनके दण्ड को माफ करने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और तैयार होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) जी हां । यह निर्णय ले लिया गया है और आदेश जारी कर दिये गए हैं कि ऐसे सभी स्थायी या अस्थायी कर्मचारी जिनके विरुद्ध पिछली हड़ताल के संबंध में हिंसा, डराने-धमकाने या भड़काने के काम में सक्रिय भाग लेने की शिकायतें होने के कारण जिन्हें अब तक बहाल नहीं किया गया है, उन्हें अब सेवा पर वापस ले लिया जाए । भले ही उनके विरुद्ध न्यायालय में या विभागीय कार्रवाई चल रही हो अथवा नियमों के अंतर्गत समुचित अनुशासनिक कार्रवाई करनी हो ।

सितम्बर 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण उत्तर प्रदेश में निलम्बित किए गए डाक-तार कर्मचारियों की बहाली

*753. श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसे डाक कर्मचारियों की जिला-वार संख्या क्या है जो सितम्बर, 1968 की हड़ताल के बाद निलम्बित तथा परेशान किये गये थे ; और

(ख) क्या सरकार उस राज्य के निलम्बित डाक कर्मचारियों के मामलों पर पुनर्विचार करेगी और इस बारे में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए उनके दण्ड को माफ कर देगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) उत्तर प्रदेश में हड़ताल के कारण मुअत्तल किये गए कर्मचारियों की कुल संख्या 113 है और जिन अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई थी उनकी संख्या 33 है । प्रत्येक डिवीजन की अलग-अलग संख्या संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है ।

(ख) जी हां । यह निर्णय ले लिया गया है और आदेश जारी कर दिये गए हैं कि ऐसे सभी स्थायी या अस्थायी कर्मचारी जिनके विरुद्ध पिछली हड़ताल के संबंध में हिंसा, डराने-धमकाने या भड़काने के काम में सक्रिय भाग लेने की शिकायतें होने के कारण जिन्हें अब तक बहाल नहीं किया गया है, उन्हें अब सेवा पर वापस ले लिया जाए भले ही उनके विरुद्ध अदालत में या विभागीय कार्रवाई चल रही हो अथवा नियमों के अंतर्गत समुचित अनुशासनिक कार्रवाई करनी हो ।

विवरण

उत्तर प्रदेश सर्किल

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल संबंधी सूचना

क्रमांक	डिवीजन का नाम	मुअत्तल किये गए स्थायी या अर्ध-स्थायी कर्मचारियों की संख्या	दंडित किये गए स्थायी या अर्ध-स्थायी कर्मचारियों की संख्या और दंड का ब्यौरा	सेवा से बर्खास्त किए गए अस्थायी कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5
	डाक			
1	लखनऊ	1	—	—
2	कानपुर	21	—	1

1	2	3	4	5
3	इलाहाबाद	—	—	1
4	गोरखपुर	1	—	—
5	बरेली	1	—	—
6	नैनीताल	37	—	9
	रेल डाक सेवा			
7	'ए' मण्डल इलाहाबाद	1	—	1
8	'ओ' मण्डल, लखनऊ	4	—	1
9	'एक्स' मण्डल, झांसी	7	—	—
	इंजीनियरी तार			
10	मेरठ	5	—	—
11	बरेली	11	—	13
12	गोरखपुर	4	—	—
13	कानपुर	1	—	—
	इंजीनियरी टेलीफोन			
14	कानपुर	6	—	—
15	लखनऊ	—	—	2
	तार परियात			
16	वाराणसी	3	—	1
17	बरेली	10	—	4
	जोड़	113	—	33

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : अध्यक्ष महोदय, आप को एक निर्णय देना होगा, इस बात का बुनियादी निर्णय देना होगा कि सवाल जिस भाषा में पूछा जाता है उसी भाषा में जवाब देने का दायित्व है या नहीं? इस बात पर आप को निर्णय देना है ताकि हर वक्त इस बात के बारे में इस तरह से झगड़ा न हो। इस तरह का झगड़ा हर वक्त यहां पर उठ खड़ा होना ठीक बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : It is becoming difficult for me.

यहां हमारे हाउस में इंग्लिश और हिन्दी दोनों में साइमलटेनियस ट्रान्सलेशन का प्राविजन है। अब अगर मंत्री महोदय इंग्लिश में जवाब देते हैं तो उसका साइमलटेनियस हिन्दी ट्रान्सलेशन हो जाता है और अगर हिन्दी में देते हैं तो उसी तरह अंग्रेजी में उस का साइमलटेनियस ट्रान्सलेशन हो जाता है। इसलिए इस विषय को सदन में इस तरह से व्यर्थ में उठा कर भड़काया न जाय।

श्री कंवरलाल गुप्त : ठीक है, ठीक है।

SHRI S. M. BANERJEE : On a point of order, Sir.

MR. SPEAKER : There is no point of order during Question Hour.

SHRI S. M. BANERJEE : On a point of submission, Sir.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : It can be only after that question. If you permit one, there will be no end to it.

SHRI S. M. BANERJEE : I am trying to support.... (*Interruptions*)

SHRI KANWAR LAL GUPTA : You are setting up a bad precedent. I strongly object to this.

SHRI S. M. BANERJEE : It is said that information is being collected. A 21-days notice has been given. . .

MR. SPEAKER : That is no point of order.

श्री ओंकार लाल बेरवा : प्रश्नोत्तरकाल में कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं होता। मुझे सवाल करने दिया जाय।

श्री कंवर लाल गुप्त : उन्हें प्वाइंट आफ आर्डर क्वेश्चन आवर के बाद उठाना चाहिए। श्री ओंकार लाल बेरवा को सवाल करने दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय 753 का जवाब भी साथ ही में दे दें ।

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : The answer is given to the whole House and not to a particular Member. The answer should be full. The answer is given to all the members, not only to the Member who put the question. He has been given 21 days notice. He should have collected the information.

श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस में सूचना जिलेवार मांगी गई है, एक, एक जिले की अलग अलग मांगी गई है इसलिए इस के इकट्ठा करने में इतने दिन लग रहे हैं । अगर सारे प्रदेश की चाहें तो वह मैं दे सकता हूं । सारे प्रदेश के बारे में मेरे पास फ़ीगर्स हैं लेकिन जैसा मैं ने अभी कहा जिलेवार इकट्ठा करने में समय लगेगा ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं जैसे कि मंत्री जी ने यह कहा कि इन्फार्मेशन इकट्ठी की जा रही है तो हम उनको 21 दिन पहले सवाल देते हैं और उसके बाद में 21 दिन तक वह कोई जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं और उस के बाद में 21 दिन तक वह कोई जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं तो यही समझा जा सकता है कि यह टालमटोल करने की मंत्री लोगों की आदत होती है वरना कोई वजह नहीं है कि इतनी मुद्दत में वह इसे इकट्ठा न कर सकें ।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि अभी तक कितने कर्मचारियों को आप ने नौकरी से अलग कर रखा है । दूसरे यह कि आप ने कब आर्डर दिया कि इन को वापिस नौकरी पर ले लिया जाय और अब तक न लेने का क्या कारण है ? क्या आप इस की जांच करेंगे ? मुझे पता है कि अभी तक उन्हें नौकरी पर नहीं लिया गया है ?

श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि जिलेवार हम अगर सूचना इकट्ठी करें तो उसमें समय लगता है इसलिए वह इकट्ठी करके हम माननीय सदस्यों को दे देंगे । लेकिन सारे प्रदेश की मेरे पास सूचना है । मध्य प्रदेश में सिर्फ 23 ऐसे कर्मचारी थे जिनको सर्विस में वापिस नहीं लिया गया था । अब हमारा आर्डर चला गया है । अभी माननीय सदस्य ने पूछा कि कौन सी तारीख को गया था तो वह 6 मार्च को गया था होम मिनिस्ट्री का जो पत्र था उस की प्रतिलिपि सब को भेज दी गई थी और उस के बाद 9 मार्च को एक और एम्लीफिकेटरी इंस्ट्रक्शन भी भेजा जिससे कि यह सारी चीज उनके सामने स्पष्ट हो जाय । और उस पर कार्रवाई कर सकें । मैं समझता हूं कि सारी जगहों पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अगर कोई एक आध बाकी हो तो उसको भी जल्दी करने की कोशिश करेंगे ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : जिन कर्मचारियों को 19 सितम्बर की हड़ताल में नोकरी से पृथक किया गया था उनको नौकरी देने तक की तनख्वाह प्रोमोशन तथा दूसरी जितनी भी सुविधायें मिलनी चाहियें क्या वे प्राप्त होंगी ? अगर नहीं होंगी तो उसका कारण क्या है ? कब तक आप उनको ये सारी सुविधायें दे देंगे ?

श्री शेर सिंह : 19 सितम्बर की हड़ताल के कारण जिन की सर्विसेस टर्मिनेट की गई थीं उनकी सर्विस में जो ब्रेक आ गया है उसको तो हमने कनडोन कर दिया है, ब्रेक नहीं रहेगा । लेकिन जो बीच का अर्सा बीत गया है उसके कारण सीनियारिटी में जो असर पड़ गया है वह असर तो रहेगा । यही होम मिनिस्ट्री की हिदायतें थीं और इन्हीं के मुताबिक अमल किया गया है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : क्यों रहेगा ? उनकी यह गलती नहीं थी । यह आपकी गलती से हुआ ।

श्री राम गोपाल शालवाले : सरकार ने अपनी गलती को स्वीकार कर बहुत अच्छा किया है । उनको वापिस ले कर उसने बहुत अच्छा काम किया है । इसके लिए वह बधाई की पात्र हैं । जो छः महीने का अर्सा बीता है बीच में और उसके कारण जो उनको मुश्किलात हुई हैं, उनके सम्बन्ध में भी क्या सरकार कोई विचार करेगी ?

सरकारी कर्मचारी रोज हड़ताल करते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी उन से हड़ताल करवाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाएगी— (इंटरप्शंज) ये पाकिस्तान के एजंट हैं, चीन के एजंट हैं। इनको शर्म आनी चाहिये। इनका आका पाकिस्तान और चीन है। कभी सरकारी कर्मचारी हड़ताल करते हैं कभी बैंक कर्मचारी करते हैं, कभी डाकखानों में हड़ताल होती है। इससे न केवल सरकार को नुक्सान पहुंचता है बल्कि स्वयं कर्मचारियो को भी नुकसान पहुंचता है, कर्मचारियों को भी दुख सहन करना पड़ता है। क्या सरकार इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध लगाएगी ताकि सरकारी कर्मचारी भविष्य में हड़ताल न कर सकें ? जो विदेशी एजंट हैं वे उनको भड़का न सकें ?

श्री शेर सिंह : सरकार ने कोई गलती नहीं की। इसलिए गलती को स्वीकार करने का कोई सवाल नहीं है। गलती कर्मचारियों ने की लेकिन फिर भी उनके साथ नरमी का बरताव किया गया है। उनके मामले में हमने इतना ही किया है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है।

दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही है, वह सजेशन फार एक्शन है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : 19 सितम्बर की हड़ताल न तो कम्युनिस्ट पार्टी ने करवाई और न किसी विदेशी एजंट ने करवाई। यह हड़ताल जो कर्मचारियों की कठिनाइयां थी, उनके कारण हुई। जो उनकी मांगें थीं उनको ले कर यह हड़ताल हुई।

जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है, मुझे याद है कि मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि 36 लोग निकाले गये हैं और उन में से रतलाम प्रापर के 26 लोग थे। उस रोज जंगल में जा कर भोजन बना कर उन्होंने खाया था। वे लोग हड़ताल में शामिल नहीं थे। केवल उस रोज उन्होंने जंगल में जा कर भोजन बना कर खाया। उनका जो अफसर था उसने जो व्यवस्था दी थी, चूंकि उसका पालन नही हुआ इस वास्ते उन से उसने बदला लिया। जिस अफसर ने इस प्रकार से बदला निकाला क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी ?

साथ साथ जो बिना कसूर निकाले गए हैं, बहुत से अधिकारियों ने व्यक्तिगत रंजिश की वजह से उनको निकाला था, उन मामलों की छानबीन करके दोषी अफसरों को दंड दिया जाएगा और उन कर्मचारियों की सर्विस को बराबर जारी रखा जाएगा ?

श्री शेर सिंह : ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है कि किसी अफसर ने तंग करने की गर्ज से या बदला लेने की गर्ज से निकाला। जितने भी मध्य प्रदेश में निकाले गए मैंने सूचना मांगी है और मुझे पता चला है कि उन में से केवल एक केस अभी रहता है। उसके लिए भी हिदायतें दे दी हैं। उसको भी वापिस ले लिया जाएगा। इस तरह से कोई ऐसा नहीं है जो बाहर रह जाएगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मध्य प्रदेश में 36 में से 26 केवल एक जिले के थे रतलाम के थे। बाकी जो दस हैं वे बाकी सभी जिलों के हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय जांच करवायेंगे, कार्रवाई करवायेंगे ?

श्री कंवर लाल गुप्त : उस अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे ?

श्री शेर सिंह : जो आरोप माननीय सदस्य लगाते हैं, उसको तह मुझे दे देंगे तो जो भी अफसर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसके बारे में पता लगाया जाएगा।

श्री शारदानन्द : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो प्रश्न करने का अवसर मिलना चाहिये। जो उत्तर मंत्री महोदय ने दिया है उस में कहा है कि 113 और 33 व्यक्तियों को दंडित किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस में वायोलेंस करने वाले कितने केसिस थे और एक्टिव इंस्टीगेशन का चार्ज कितने कर्मचारियों के ऊपर लगाया गया था ?

श्री शेर सिंह : इसके लिए नोटिस चाहिये। मैंने सूचना दे दी है डिविजनवाइज जो लोग निकाले गए ।

श्री शारदानन्द : जो सूचना दी है उस में यह नहीं है जो मैंने पूछा है।

श्री शेर सिंह : जो प्रश्न था वह यह था कि कितने लोग अस्थायी थे जिन को हटाया और कितने स्थायी को सस्पेंड किया। दोनों सूचनायें मैंने दे दी हैं। जो आप चाहते हैं कि किस किस ढंग के कितने केसिस हुए, उसके लिए नोटिस मुझे चाहिये।

श्री शारदानन्द : आपने उनको रीइंस्टेट किया, यह अच्छी बात है। लेकिन अभी तक उनके ऊपर जो मुकदमे चल रहे थे उनको उठाया नहीं गया है। क्या आप जल्दी से जल्दी उन मुकदमों को उठाने की व्यवस्था करेंगे ?

जो अफसर बैठे हुए हैं वे उन कर्मचारियों के खिलाफ जो उनके मन के मुताबिक नहीं बैठते हैं, उनके मन के मुताबिक काम नहीं करते हैं, जब ऐसे मौके आते हैं तो एक्टिव इंस्टीगेशन का चार्ज लगा कर उनको तरह तरह से परेशान करते हैं। क्या आप आदेश जारी करेंगे कि इस प्रकार से कर्मचारियों को परेशान न किया जाए ? भविष्य के लिए आप कोई इस प्रकार के आदेश जारी करेंगे ?

श्री शेर सिंह : जितनी बाते सामने आती हैं उसको हम समय समय पर रिव्यू करते रहे हैं। इसीलिए बहुत से लोगों को वापिस लिया गया है। उनको हम रीइंस्टेट भी करते रहे हैं। अब तो एक जनरल आर्डर भी हो गया है। उन सब बातों की समय समय पर हम जांच करते रहे हैं।

जहां तक गलत ढंग से इनवाल्व करने की बात है, वे केसिस जिन में जान नहीं थी उनको वापिस ले लिया गया है। जिस केस में इंस्टीगेशन की, हिंसा की या और कोई ऐसी चीज थी और जो केसिस अभी चल रहे हैं उनका कोर्ट में फैसला हो जाएगा। लेकिन उनको भी हमने सब को सर्विस में वापिस ले लिया है।

श्री भारत सिंह चौहान : जब यह निर्णय हो गया कि इन कर्मचारियों को बहाल किया जाये, तो उस को कार्यान्वित करने में इतना विलम्ब क्यों हुआ ? केन्द्रीय सरकार के आदेश जल्दी से जल्दी अमल में लाये जायें, क्या इस बारे में कोई विचार किया गया है, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि शासन की ओर से जो आदेश दिये जाते हैं, उन का पालन करने में महीनों लग जाते हैं और इसी लिए ये सब कठिनाइयां होती हैं ? क्या सरकार इस पर विचार करने के लिए तैयार है कि उस के आदेश पर तुरन्त अमल किया जाये ?

श्री शेर सिंह: जैसा कि मैं ने पहले निवेदन किया है, 9 मार्च को यहां से हिदायतें दी गई और उस के बाद उन पर तुरन्त अमल किया गया। जब भी कोई एक-आध केस हमारे नोटस में लाया गया है, हम ने उस के बारे में आदेश दिया है। सारे देश में ऐसे चार पांस केस बचे हुए हैं। हम उन के बारे में कार्यवाही कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री श्रीगोपाल सब्बू : अब तक ऐसे कितने मामले उत्तर प्रदेश में बाकी रह गये हैं, जिन के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है और उन के बारे में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री शेर सिंह : किस दृष्टि से निर्णय ? सब को सर्विस में वापिस ले लिया गया है। ऐसा कोई केस बाकी नहीं रहा है, जिस में कर्मचारी को वापिस सर्विस में नहीं लिया गया है।

SHRI S. M. BANERJEE: On 2nd March, 1970 an annoncement was made in this House by the Home Minister that in the case of those Central Government employees, whether in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh or elsewhere, who participated in the strike of 19th September, 1968 and suffered a break in service, their break in service would be condoned, and it was also assured in this House by the hon. Minister, Shri Satya Narayan Sinha, that the break in service would not result in the banning

of any promotion, but it has been brought to our notice that after this announcement on 2nd March, 1970, on the 3rd March 1970 some promotions were made at various places where the claims of the senior employees were ignored because they participated in the strike in 1968. I wish to know from the hon. Minister whether the decisions taken by the departmental promotional committtees for promoting employees to various posts ignoring the claims of those who participated in the strike will now be reconsidered, whether all such promotions which were made after the issue of these orders will be annulled and fresh panels drawn up. I want an assurance from the hon. Minister who knows the case very well.

THE MINISTER OF INFORMATION & BROADCASTING, AND COMMUNICATIONS (SHRI SATYA NARAYAN SINHA): More than once this position has been explained to the hon. friend there, and I told him that so far as I am concerned I had passed orders, but some clarification was needed from the Home Ministry and it has been referred to them.

SHRI S. M. BANERJEE: Certain provisional promotions are said to have been made subject to confirmation by the Minister. Will those promotions be held in abeyance, as otherwise there will be no post left?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA: I would request the hon. Member to wait for a few days and let the clarification come, when it will be decided.

श्री शशि भूषण : सरकार ने स्ट्राइक में भाग लेने वाले कर्मचारियों को वापिस लेने का जो फ़ैसला किया है, मंत्री महोदय उस के लिए मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने स्ट्राइक में हिस्सा नहीं भी लिया, जो लीडर ज़रूर थे, उन को—यहां तक कि पोस्टमैन को भी—दूर दूर शहरों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अगर बड़े अधिकारी दिल्ली में आ जायें, तो वे पंद्रह साल तक वापिस नहीं जाते हैं। लेकिन उन छोटे छोटे कर्मचारियों को बदले की भावना से दूर दूर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मैं चाहूंगा कि उन लोगों के ट्रांसफ़र वापिस लिये जायें और उन को पहली जगहों पर रखा जाये।

श्री शेर सिंह : अगर माननीय सदस्य कोई ऐसे केस देंगे, तो हम उन पर ज़रूर विचार करेंगे।

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, अभी किसी माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश के बारे में पूछा है और किसी ने उत्तर प्रदेश के बारे में। 17 सितम्बर को जो स्ट्राइक हुई थी, वह देश भर में हुई थी। इस लिए मैं पूरे देश के बारे में सवाल पूछना चाहता हूं। "हित अनहित पशुपक्षी जाना"। लेकिन यह सरकार देश में किसी को भी अपना शुभचिन्तक नहीं बना रही है। वह सब को एक ही लाठी से हांक रही है। सामने बैठे हुए लोग भी सत्याग्रही रहे हैं और उन्होंने भी आन्दोलन किया है। उसी तरह इन कर्मचारियों ने भी आन्दोलन किया था। यह सरकार सोशलिज्म में विश्वास करने का दावा करती है और सोशलिज्म का स्लोगन लगाती है। मैं यह पूछना चाहता हूं क्या यह माइनारिटी गवर्नमेंट उन लोगों को वारनिंग दे कर वापिस काम पर लगायेगी और फिर उन का काम वाच करेगी (व्यवधान)

श्री शेर सिंह : श्री शिव नारायण का सवाल लाजवाब है। (व्यवधान)

श्री एस० एम० जोशी : मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार यह कहने से कि मजदूरों की गलती थी, मजदूरों और अफ़सरों के बीच अच्छे ताल्लुकात कायम होने में ख़लल पड़ता है। इस लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि बार-बार यह बात न कही जाये, क्योंकि यह एक डिसपूटिड पायंट है। हमारे ख़याल में तो गवर्नमेंट ही सौ फ़ीसदी फलत है। इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि यू० पी० में नैनीताल में 37 पर्मानेंट या क्वैसी-पर्मानेंट कर्मचारियों को ससपेंड किया गया और 9 टेम्पोरेरी कर्मचारियों को डिसचार्ज किया गया। ये सब केस हल्दवानी के हैं। इस स्टेटमेंट से यह पता नहीं चलता है कि उन

लोगों ने कोई गड़बड़ी की थी, जिस के कारण उन सब को निकाल दिया गया, या वहां के अफ़सरों ने किसी अन्य भावना से काम ले कर यह कार्यवाही की । क्या हुकूमत अपने अफ़सरों को यह हिदायत देगी कि हम एक नया ज़माना शुरू करने वाले हैं, जिस में कर्मचारियों और अफ़सरों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित हों और इस लिए ऐसी कोई कार्यवाही न की जाये, जिस से उन सम्बन्धों में किसी प्रकार की कटुता आये ? अभी माननीय सदस्य ने कर्मचारियों के ट्रांसफ़र्ड का जिक्र किया है । मेरे पास इन्दौर से तार आया है कि बहुत से लोगों को बिना किसी औचित्य के ट्रांसफ़र कर दिया गया । क्या सरकार पहले के से अच्छे सम्बन्ध कायम करने के लिए उन लोगों के बारे में कोई संतोषजनक प्रबन्ध करेगी ?

श्री शेर सिंह : यह जो निर्णय लिया गया है, उस की भावना और उद्देश्य यह है कि फिर से अच्छे सम्बन्ध स्थापित हों और सद्भावना बढ़े और काम ठीक तरह से चले । शायद माननीय सदस्य को डीटेल्ज़ की जानकारी नहीं है । उन्होंने 37 की संख्या देख कर समझ लिया कि वहां किसी अफ़सर ने ज्यादती की है, लेकिन यह भी हो सकता है कि वहां कर्मचारियों ने अधिक संख्या में कानून का उल्लंघन किया हो ।

श्री मधु लिमये : मैंने बहुत पहले हल्दवानी के बारे में श्री सत्य नारायण सिंह को पत्र लिखा था ।

SHRI NAMBIAR : May I know whether the Government are aware that a large number of P & T employees in Kerala Circle are being transferred to various places immediately after their reinstatement from discharge or suspension, because they participated in the strike of 19th September, 1968, and whether the Government are taking any action to see that such vindictive actions are stopped?

SHRI SHER SINGH : He has referred to vindictive action. Transfers may have been done in a routine way. After an employee has served at a particular place for a specific period, he can be transferred. But I will find out if there are any such cases where there is vindictiveness.

SHRI S. KANDAPPAN : I do not think that the authorities concerned will give a statement to the Minister about their vindictiveness. He has to find out and tell us.

SHRI NAMBIAR : My submission is, after a long duration of dismissal or suspension, they are taken back, as pressure comes and as agreement is reached, but on joining duty, immediately they are transferred indiscriminately, especially those who are responsible office-bearers of the union. So, what are we to derive from this? Will the Minister go into those cases wherein officials of the union are involved and see that such things are not done?

SHRI SHER SINGH : I shall go into it and find out.

दूर संचार सेवा का जापान के सहयोग से विस्तार

*752. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में दूर संचार सेवाओं से सम्बन्धित विकास कार्यों का अध्ययन करने के लिए जापान के शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया था तथा क्या उक्त शिष्टमंडल ने देश के दूर संचार उपकरण बनाने वाले कारखानों का भी दौरा किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त शिष्टमंडल ने जापान के सहयोग से देश में दूर संचार सेवाओं का विस्तार करने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय के साथ बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिनिधिमण्डल ने 5 मार्च, 1970 को शिष्टाचार के नाते भेंट की थी।

(ग) जापानी दूर संचार दल के प्रमुख ने बतलाया कि उनका देश दूरसंचार सेवाओं से सम्बन्ध भारतीय प्रायोजनाओं में सहयोग देने में रुचि दिखलायेगा। किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस शिष्ट मंडल ने क्या भारत के अतिरिक्त एशिया के कुछ और देशों का भी दौरा किया है और क्या वे वहां भी इसी प्रयोजन के लिये गये थे ? जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि भारत सरकार के साथ उन की कोई निश्चित बात नहीं हुई, परन्तु फिर भी क्या उन्होंने जापान का सहयोग देने के लिये कोई ठोस प्रस्ताव भारत सरकार के सामने रखा है या नहीं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : कोई ठोस प्रस्ताव उन लोगों ने हमारे सामने नहीं रखा । यहां आने के पहले वह पाकिस्तान गये थे। यह उन का कर्टसी विजिट था। हमारे साथ उन की बातें हुई, उन्होंने कहा– हम जापानवाले टेली कम्यूनिकेशन के मामले में आप की मदद कर सकते हैं, अगर कोई प्रपोजल होगी तो आपके साथ डिस्कस करेंगे और कोई बात शिष्ट मंडल से नहीं हुई। यह गुडविल मिशन था, घूमने के लिये आया था।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या पाकिस्तान के अलावा भी और कई जगहों पर गये थे?

श्री सत्यनारायण सिंह : शायद थाई लैंड या और कहीं भी गये होंगे। लेकिन पाकिस्तान का जिक्र शिष्टमंडल ने किया था।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या इस शिष्ट-मंडल ने हमारे जो टेलीकम्यूनीकेशन की इण्ड-स्ट्रीज या कारखाने हैं, उन का दौरा किया था तथा दौरा करने के बाद भारत सरकार ने कोई विचार-विनिमय उन के साथ किया ?

श्री सत्यनारायण सिंह : उन्होंने ख्वाहिश जाहीर की थी कि वे हमारे कारखानों को देखना चाहते हैं। हम ने उन्हें सुविधा दे दी। उन्होंने उन को देखा, लेकिन किसी खास मामले पर हम लोगों के साथ उन्होंने विचार-विनिमय नहीं किया।

SHRI S. KANDAPPAN: The Minister has said that it was a courtesy call. I would like to know whether the Department of Telecommunications before, after or during the visit tried to assess the ways and means in which we could be benefited by Japanese collaboration. If they had made an assessment, I would like to have an indication of the lines in which the collaboration would benefit us.

SHRI SATYA NARAYAN SINHA: As I have said, no specific things were discussed. There was a general discussion. Therefore I cannot say what assessments they have made. All that they said was that in future if we wanted something to be done, they could help us and were prepared to do so. We also said that if such occasions arose, we would certainly welcome their support.

SHRI S. KANDAPPAN: Have we assessed in what field we need their help and may benefit by it?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA: Neither they gave any specific proposal nor did we ask for anything. It was a general discussion. How can I say that they offered certain things and an assessment was made?

श्री अमर सिंह सहगल : आप के साथ जो चर्चा डेलीगेशन की हुई थी, क्या उस की कोई रिपोर्ट आप ने अपने पास रखी ? यदि रखी, तो किन किन बातों पर आपने रिपोर्ट रखी या उन लोगों ने कोई रिपोर्ट आप को दी ?

श्री सत्यनारायण सिंह : न उन्होंने कोई रिपोर्ट दी, न हमने कोई रिपोर्ट रखी। कर्टसी काल की कोई रिपोर्ट नहीं रखी जाती है।

श्री अमर सिंह सहगल : मुझे माफ कीजिये, चर्चा के मिनिट्स जरूर रखे जाते हैं।

SHRI K. LAKKAPPA : I would like to know from the hon. Minister whether orders for certain sophisticated telecommunication equipment regarding direct dialling system were placed with Belgium in collusion with certain officers of this department ignoring the lowest quotation given by the Japanese firm. As a result of that, such equipments are not working properly in this country and we are facing every trouble in the telecommunication system. I want to know whether this system has been rectified. Japanese were pressurising this Government to place an order because they were supplying sophisticated equipment at a much cheaper rate than Belgium. I want to know whether the Government had any such discussions with them and whether the Japanese also had a talk with the hon. Minister on their visit here. May I know whether the Government has reviewed the position that there is a defective tele-communication in the country, because of the equipment being ordered from Belgium, and that material is useless and as a result of that, the tele-communication system has gone worse.

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : The first part of the question has nothing to do with the Question..

SHRI K. LAKKAPPA: There is a like between Japanese and Belgium.

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : The gentleman who came to see me never had a discussion about this thing so far as I am concerned.

SHRI K. LAKKAPPA: My point is this that the Japanese quoted certain rates. The very purpose of this visit was to have a discussion between the Japanese and this Ministry. There was a discussion. He is suppressing the information.

MR. SPEAKER : You mean to say during a courtesy call, some serious matters were also discussed?

SHRI LAKKAPPA: Certain officers who are working in his Department have in collusion done it.... (*Interruption*)

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : I do not know. I would ask the Secretary if they have had any discussion like that. So far as I am concerned, they never discussed it with me.

SHRI BISWANARAYAN SHASTRI : The hon. Minister has just stated that the Japanese delegation made only a preliminary survey of the background of the tele-communication system in our country and that they will come forward if and when any help is required. In this connection, may I know from the hon. Minister whether he has some information or he has collected the information as to which countries in the world are more advanced in tele-communication service, where these sophisticated equipments are manufactured? Will he contact those countries before negotiation is completed with the Japanese firm.

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : I have not been able to follow the hon. Member. If there are further negotiations, in such matters, we invite global tenders and we decide on the basis of the tenders received.

SHRI BISWANARAYAN SHASTRI : Has he got some information as to which countries are more advanced in tele-communication service?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : Everybody knows it.

SHRI N. K. P. SALVE : Assuming that the delegation visited India for the sake of nimbu-pani—I don't concede ; I do'nt understand what is this courtesy call—assuming it is correct that it was for the sake of lavish entertainment, I would like to know....

MR. SPEAKER: What is your question?

SHRI N. K. P. SALVE : Please allow me to preface it. The tele-communication system in Japan, and those who have visited Japan will bear me out, is a marvel of modern technology. May I, therefore, know from the hon. Minister, notwithstanding how they visited, for what purpose they visited, whether we tried to benefit out of their visit and whether we tried to find out and ascertain from them how we can improve our entire system which is most inefficient?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : We did not discuss anything about it.

SHRI A. SREEDHARAN : On a point of order, Sir. The Minister did not reply to that question. The hon.

Member asked a very relevant question as to how did the Government benefit by their visit and discussion. If the Government has not benefited, why did the Minister waste his time on having the discussion? (*Interruptions*)

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : The House must be told whether they discussed family matters...(*Interruptions*). He says that it was a courtesy call. We are entitled to know as to what was the discussion. (*Interruptions*).

श्री हुकम चन्द कछवाय : सदन की भावना है कि मंत्री जी इस का जवाब दें।

MR. SPEAKER : That is not the way.

SHRI A. SREEDHARAN : This is not the way the Minister should give reply. If you allow this precedent to go, all the Ministers will adopt it.

SHRI NAMBIAR : Sir, he is answering. Let us hear him.

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : Did you call me to answer, Sir? (*Interruptions*) I am really sorry and I have not been able to follow why the hon. Members get excited because I have said that there was no specific discussion.

So far as the general benefit is concerned, when such people and delegations meet from different countries, some unspecified benefits generally accrue. (*Interruptions*).

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : Let him say as to what the benefits are. Is it a monetary benefit or is it a personal benefit?

SHRI N. K. P. SALVE : This is very unfair. He first said that he did not discuss. That I can understand. But when he says that general benefits do come, are we talking of some abstract and subjective benefits? We want to know with reference to the system as to how we are benefited.

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : No specific proposal, I said, was discussed.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : For 20 minutes we are trying to elicit one point and he is suppressing that point.

MR. SPEAKER : Some hon. Members have come fresh after visiting their constituency. That is the trouble. (*Interruptions*).

Order please. If one person shouts, the other two get up. When two are there, three get up from this side. It is such a contagious disease. I am so sorry.

Rehabilitation of persons displaced in 1965 Indo-Pak Conflict from Taran Taren Border and Ferozepore District

*754. SHRI SHRI CHAND GOYAL : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the persons who were displaced in the Pakistani war of 1965 from the Taran Taren and Ferozepur district borders have all been rehabilitated ;

(b) whether Government have received complaints from some persons about it ; and

(c) if so, the steps taken or proposed to be taken to remove their grievances?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI S. C. JAMIR) : (a) Yes, Sir, It may, however be mentioned that Taran Taren was not affected during the 1965 conflict with Pakistan.

(b) Yes, Sir.

(c) The demands made in the various representations have been examined in detail and disposed off on merits. On one point, the views of the State Government have been solicited. A decision will be taken on receipt of the State Government's views.

SHRI SHRI CHAND GOYAL : I must say that the noteworthy hon. Minister is trying to develop a dexterity for hiding information and whatever information he has given is just vague and ambiguous and signifies nothing. What he said is that the demands made in the various representations have been examined in detail and disposed of on merits. We do not know what were the demands, when they were disposed of and what were the merits on which they were disposed of. He further says that on one point the views of the State

Government have been solicited. I would like to know that in view of the fact that goods on the Khem Karan and Ferozepur borders were also destroyed, burnt and looted and no compensation has been given to the owners of those goods whereas compensation was given for crops and other things, why these persons have been denied the benefit of compensation and whether the Government would consider the desirability of giving them compensation also?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): In this conflict there were about 52,000 people who were uprooted in Punjab. We gave them help through different means. We gave them grants and loans for construction of houses and shops, for business and agricultural purposes. We gave to the State Government loans for the repair of public places and places of worship and all that. Regarding the second point, he says about crops and cattle that were lost and asks why compensation was not given. Government do not accept in principle compensation for the war damages and therefore the crops that were lost could not be given compensation, but as I said we gave them this help and also ex-gratia grants for them.

श्री रणवीर सिंह : क्यों नहीं दिया जाय। मकान गिरने पर तो मदद दी जाय, और क्रौप्स चलने पर कम्पेनसेशन न दिया जाय यह कौन सा फैसला है। यह किसान के लिये अत्याचार है।

श्री यशवन्त शर्मा : मान्यवर, यह आप की कांस्टीट्यूएंसी है, आप ज्यादा जानते हैं।

SHRI SHRI CHAND GOYAL: I never thought the Minister would be so ignorant, he should know that compensation for crop has actually been given whereas he says that they have not accepted the principle of giving them compensation. Sir, my second question is this. Is the Government going to wind up the Rehabilitation Department so far as Punjab and Haryana are concerned? In respect of people who came from West Punjab, especially from the western zone, those people were not given any compensation for their houses because the value was less than Rs. 10,000 and whatever may be the plots of land they were given, they have not been given any compensation on the ground that they did not occupy those plots of land. May I know whether the Government is contemplating winding up the Department and whether they would compensate them to some extent for their houses and for their plots of land?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: As I said, this is the position. The hon. Member knows better than myself and therefore he has said that. He has got that knowledge; we have no knowledge. What I said was, we gave grants and loans for the construction of houses. We gave grants and loans for business purposes. We gave grants to the State Government for the construction of public places for worship and all that. So far as the cattle lost or damaged and so far as the crop damaged are concerned we could not agree to give compensation for them because, number one, it was not possible to establish that at this distance of time; and number two, because its financial implication would be very huge. Therefore, we could not agree to this.

SHRI RANGA: He has not replied to the second question.

SHRI SHRI CHAND GOYAL: He has not answered the second question. West Punjab was not given any compensation.

MR. SPEAKER: The Minister said some compensation was granted to them, and about the goods looted in Khem Karan he replied to that and referred to the loans for rehabilitation which were given. That has been partly replied to.

SHRI SHRI CHAND GOYAL: My second question was not answered. My question was whether government was contemplating given any compensation for the people in Haryana and Punjab who came from West Pakistan or they were not given any compensation for houses on the ground that they were worth less than Rs. 10,000. The plots which have been given to them have been taken back on the ground that they were not occupied by them, without giving them any compensation.

I want to know whether the government will give them compensation before winding up the department.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: There are two distinct questions involved. One refers to the war damages and

the other refers to winding up of Rehabilitation Department and principles governing the payment of compensation. For this I want notice.

SHRI RANGA: What is the answer that the Minister has given? He has not followed the question. He repeated so many times but the Minister has not grasped the question. How many times are we to go on repeating the question?

MR. SPEAKER: Shri Ranga, I have asked him to reply to that question.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: No amount of shouting will do. I have followed the question.

SHRI RANGA: He has asked about those people whose houses worth Rs. 10,000 were damaged in the war—would they be given something? Would anything be given to the people who were allotted lands but they could not occupy them before winding up the Rehabilitation Department? Would some consideration be given to these people? Let the Cabinet Minister answer.

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): I am sorry the question has not been properly answered. With regard to the houses, in rural areas, if the refugee or the migrant wanted to construct kutcha house, Rs. 1,000 as grant and Rs. 2,000 as loan was given. For a pucca house, Rs. 2,000 as grant and Rs. 3,000 as loan was given. This is for the rural areas.

In the urban areas, Rs. 1,000 for kutcha house as grant and Rs. 2,000 as loan, for a pucca house Rs. 4,000 as grant and Rs. 6,000 as a loan and so on were given. For the agriculturist, for a pair of bullocks Rs. 1200, for agricultural implements, seeds and fertilisers Rs. 175 were given to them. Even for business people the same is being done. But where there is any difficulty, before the whole department is wound up, it would be our responsibility to see that arrangement is made with the State Government. So far as the rehabilitation cost is concerned, the Central Government will bear it.

श्री रणधीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट किसान को इन्सान समझती है या हैवान समझती है। मैं ने जो रेप्लाई सुना है उससे साफ जाहिर है कि मकान का तो वे देते हैं कम्पेन्सेशन, या फिर मवेशी वगैरह का सौ, डेढ़ सौ, रुपया देते हैं जबकि मवेशी आता है दो हजार का तो फिर सौ रुपए देने के क्या मतलब हुए? फिर किसी किसान की फसल 20 हजार की थी, किसी की 50 हजार की थी, उसका कोई जिक्र नहीं है। किसान का बेटा फ्रंट पर लड़ते लड़ते मर जाये और सारे देश का पेट भरे और उसकी जमीन को सरमायेदार जबर्दस्ती एक्वायर कर लें। उस बेचारे का मीन्स आफ प्रोडक्शन खेती है, उसको वार डेमेजेज, कम्पेन्सेशन न मिले इसकी क्या वजह है? आप उसको कम्पेन्सेशन क्यों नहीं देंगे, उससे वोट क्यों लेते हैं?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: As I said, I have not been able to make clear my answer to the question. There are two questions—one is about the war damages. What I said was that they had been given grants and loans for construction of houses. I also said that they had been given ex-gratia cash grant. I also said that for crop compensation we could not agree in principle. But we have given for crops ex-gratia cash grant for that. But no compensation for war damages has been given.

श्री रणधीर सिंह : वार डैमेजेज नहीं चाहिए, हमें कम्पेन्सेशन दो। मकान के लिए देते हैं तो उसके लिए क्यों नहीं देते हैं? हमें आपका रहम नहीं चाहिए।

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: As I said, it is not possible to grant anything for the loss of cattle; for the crops, we have given compensation ex-gratia. It is not possible to give compensation for war damages.

श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि 1965 की भारत पाक लड़ाई में जम्मू कश्मीर तथा पंजाब में कितने लोग विस्थापित हुए, इस युद्ध के कारण, उन विस्थापितों की सम्पत्ति को कितनी हानि हुई और सरकार ने उस सम्पत्ति की हानि के लिए—यानी जो मकान आदि उनके टूट गए या उजड़ गए उनके

निर्माण के लिए उनकी कितनी सहायता दी तथा अभी तक कितना काम बाकी है? . . . (व्यवधान) . . .

मेरे प्रश्न का दूसरा हिस्सा यह है कि सार्वजनिक संस्थान—स्कूल, कालेज, हास्पिटल, मंदिर आदि कितने नष्ट हुए? इस सरकार ने इस विभाग को अगर बन्द करना है तो उसके बाद उन संस्थानों का निर्माण कार्य नहीं हो पायेगा तो फिर उस कार्य को आप राज्य सरकारों के साथ मिल कर अथवा केन्द्रीय सरकार की जो जिम्मदारी है उसके अनुसार, किस प्रकार से करने वाले हैं—यह बतलाने का कष्ट करें।

श्री भागवत झा आजाद : जैसा मैं ने कहा इस कांफ्लिक्ट में करीब 52 हजार आदमी विस्थापित हुए—अमृतसर, जालंधर, फीरोजपुर लुधियाना, गुरदासपुर और कपूरथला इत्यादि में। अब तक प्रायः सभी के सभी अपने स्थानों पर वापिस जा चुके हैं। जैसा कि मैं ने बतलाया उनके मकान गिरने पर कर्ज और ग्रान्ट वगैरह दे दी है। यह बात सही है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट को जल्द से जल्द बन्द कर दिया जाये। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो कार्य वहां पर बाकी रह जायेंगे उनको समाप्त नहीं किया जायेगा। अगर हम यहां पर डिपार्टमेन्ट रखें तो उसके लिए निगोशिएटेड सेटिलमेन्ट पैकेज डील के अन्दर पंजाब, हरयाणा और तमाम सरकारों से इस बात पर निश्चित राय ले रहे हैं और इस लिए ऐसी कोई कठिनाई नहीं होगी। जहां तक यह प्रश्न है कि कितना दिया गया है, उसकी मेरे पास लम्बी फैहरिस्त है जो कि मैं टेबिल पर रख दूंगा कि किस आइटम पर हमने कितना खर्चा किया।

Setting up of Deep Sea Fishing Project at Raychak, West Bengal

\+

*758. SHRI CHENGALRAYA NAIDU:
SHRI DHANDAPANI:
SHRI SAMINATHAN:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have agreed to the proposal of West Bengal Government for setting up deep sea fishing project at Raychak;

(b) if so, the total cost of expenditure involved thereon;

(c) the amount Centre has agreed to give; and

(d) when the project is likely to be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) to (b). A statement is placed on the Table of the Sabha.

Statement

(a) In connection with a scheme of provision of fishing harbours at major ports, for which block provision has been made in the Fouth Five Year Plan in the Central Sector, the question of providing a fishing harbour at Raychak has been taken up for consideration. A detailed project report is being finalised by the Calcutta Port Commissioners.

(b) The total cost involved in the proposal will be known after the project report is ready.

(c) The question of sanctioning the project will be taken up on receipt of the report. The entire cost of harbour construction under the scheme is borne by the Central Government.

(d) An assessment of the likely period of construction can be made only when the Project Report is available.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: The Minister has said in the statement that a detailed project report is being finalised by the Calcutta Port Commissioners, but he has not said when it will be ready. The Government is not showing interest in this fishing project. They are only interested in political fishing, they are not interested in regular fishing.

AN HON. MEMBER: They are fishing in troubled waters.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: Bengal is already in trouble waters.

I would request the Minister to tell us whether this project report will be

ready within one or two months. After the estimate is ready, how long will the Government take to sanction it, and how long will it take to complete the project?

SHRI ANNASAHIB SHINDE: The Port Trust authorities of Calcutta are supposed to prepare this estimate, and naturally as soon as they submit their estimate, it will be sanctioned and I do not think there will be delay in sanctioning the project, because we are ourselves anxious to see that fishing harbours are dveloped on the eastern coast including West Bengal.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: May I know from the Minister whether they are going to undertake any such project near Nellore District at Sriharikota?

SHRI ANNASAHIB SHINDE: May I seek your protection? I have all sympathy for him, and I can only say that if minor harbour projects are submitted by the Andhra Government, we will consider them sympathetically because 100 per cent assistance goes from the Centre for the development of minor harbours.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Scarcity of Vanaspati Ghee in Delhi

*755. SHRI MANIBHAI J. PATEL:
SHRI DEVINDER SINGH GARCHA:
SHRI VALMIKI CHOUDHARY:
SHRI N. R. DEOGHARE:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the scarcity of Vanaspati in Delhi;

(b) if so, whether Government have ascertained the reasons therefor; and

(c) whether Government have taken up the matter with the mills of the vanaspati to improve the supply position of vanaspati in the Capital?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes, Sir.

(b) The scarcity is understood to be due to the curtailment of production by some of the factories for varying periods during March due to rising oil prices.

(c) The matter has been discussed with the representatives of the industry and it is expected that the supply position will be normalised in the near future.

Mortgage of Children for Paddy in Assam

*756. SHRI R. K. BIRLA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of foodgrains in certain parts of Assam;

(b) whether it is a fact that distressed persons either have sold or mortgaged their children for some paddy in the month of February this year;

(c) if so, the number of such cases during the last three months; and

(d) what steps have been taken by Government to meet the shortage of food in that State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) So far as Government are aware, the food position in Assam is quite satisfactory.

(b) The State Government have reported that they have no knowledge of any such happening.

(c) and (d). Do not arise.

होशंगाबाद तथा पूर्वी निमाड़ (मध्य प्रदेश) में सिंचाई सुविधाओं की कमी तथा सूखे के कारण फसल को हानि

*757. श्री गं० च० दीक्षित : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तथा पूर्वी निमाड़ जिले में सिंचाई सुविधाओं की कमी और सूखे के कारण फसलों को हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो हानि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त जिलों या उनके कुछ भागों को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). राज्य सरकार से मांगी गयी जानकारी की अभी प्रतीक्षा है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं होता ।

Propaganda Materials Circulated by USSR and USA to Indian Dailies and Weeklies

*759. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that U.S.S.R. and U.S.A. circulate regular propaganda materials to different dailies and weeklies;

(b) if so, the names of the dailies and weeklies which received and printed such propaganda materials ; and

(c) the amount paid for printing such propaganda materials?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) Yes, Sir.

(b) Foreign missions are not required to submit to the Government of India the names of newspapers to which they send their publicity material.

(c) This Ministry are not aware of payments made to Indian newspapers by foreign missions for publishing press releases. But the foreign missions do buy advertisement space in Indian newspapers for publicity campaigns.

Suggestions by British Economist on efforts to make small Farming Successful

*760. SHRI N. R. LASKAR : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sir John Hicks, a renowed British economist has stressed the need for big organisational efforts to make small farming successful in the country ;

(b) if so, the other points made by him in address during the three day Seminar ;

(c) whether he has stated that the land reforms, even if they are completed, would not alone solve the problem; and

(d) whether Government have examined his suggestions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) to (d). The recommendations of the Seminar held by Indian Social Institute, a non-official organisation, on 'Challenge of Poverty in India' have not been received by the Government so far. Hence it is not possible to indicate the specific suggestions made at the Seminar and the reactions of the Government thereon.

Winding up of Central Fisheries Corporation, Howrah

*761. SHRI INDRAJIT GUPTA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it has been decided to wind up the Central Fisheries Corporation, Ltd. Howrah on the plea of losses ;

(b) if so, whether it is also a fact that the Corporation actually never took up various activities, viz., deep-sea fishing, installation of plants for cold storage, curing and canning of fish, which were proclaimed as its objectives in the Memorandum of Association ;

(c) whether, any efforts were made to maintain and expand the Corporation's activities in co-operation with the West Bengal State Government ; and

(d) in the event of the Corporation's closure, what alternative arrangements

will be made to absorb the surplus staff?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) No decision has been taken to wind up the Central Fisheries Corporation. The question of the future of the Corporation is however under consideration.

(b) The Memorandum of Association of the Corporation lists several objectives including deep sea fishing, installation of plants for cold storage and curing and canning of fish. The first objective of the Company as listed in the Memorandum is to "to undertake procurement of fish and acquatic products from various sources in India and in neighbouring and other countries, to make arrangements for their preservation, transportation and storage and to carry on sale of the same either directly or through agents, in wholesale or retail, in any place in India, primarily in Calcutta with a view to ensuring fair price to the producers in India and making it available to the consumers at reasonable rates." The Corporation took up the first objective of procurement of fish from various sources for supply primarily in Calcutta. It also took up development of several reservoirs. It has not extended its activities to other areas of fisheries development.

(c) The West Bengal Government is a share-holder of the Corporation and is represented on the Board of Directors. The Corporation's work has been carried on with co-operation of West Bengal and also of other share-holding States. It has not been found feasible to expand the Corporation's activities further.

(d) Specific arrangements to absorb surplus staff can be worked out only if and when a decision is taken to wind up the Corporation. In the event of the Corporation's closure, however, deputationists will be returned to their parent organizations and direct recruits will be accorded the highest priority for alternative appointments which can be secured for them under the regulations.

Construction of Fisheries Berth at Vishakhapatnam

*762. SHRI P. C. ADICHAN: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether a proposal for construction of fisheries berth in the proposed outer harbour of Vishakhapatnam has been under Government's consideration;

(b) if so, the estimated cost and details thereof; and

(c) Government's decision in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) In connection with a scheme of provision of fishing harbours at major ports, for which block provision has been made in the Fourth Five Year Plan in the Central Sector, investigations are being conducted at several ports including Vishakhapatnam.

(b) The port authorities are working on a project report for a fishing harbour in the proposed outer harbour at Visakhapatnam in consultation with the Ministry of Transport and the State Government. An amount of Rs. 1.50 lakhs has been sanctioned by the Central Government for the investigations and preparation of the project report. The estimated cost and details of the fishing harbour will be available on completion of the report.

(c) After the project report is available, the feasibility of sanctioning a fishing harbour at Visakhapatnam under the scheme will be examined by the Government.

Contract between Samachar Bharati and Government regarding Disposal of Property

*763. SHRI SHIVA CHANDRA JHA:

SHRI RAMAVATAR SHASTRI:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there was any contract between Samachar Bharati News Agency and Government that no property of the News Agency should be mortagaged, sold or hypothecated without specific permission of Government;

(b) if so, whether this provision has been violated in large number of cases;

(c) if so, give the details thereof; and

(d) the steps taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir, (according to the contents of a letter dated March 28, 1970, written to the Ministry by the Secretary of the news agency in the matter).

(c) and (d). Do not arise.

Plan for strong Trade Unions to Improve Management-Labour Relations

*764. SHRI GADILINGANA GOWD: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Mr. Naval H. Tata, Industrialist and President of the Employers' Federation of India, on the 17th January, 1970 stressed the need for strong trade unions and organisations, bodies of employees to improve the management-labour relations;

(b) whether he also suggested that the trade unions should also form an apex body but it should be an organization purely of the labour and without politicians; and

(c) if so, the reaction of Government, particularly in the public undertakings in the country thereto?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): (a) to (c). Apart from what has appeared in certain newspapers, Government have no other information on the subject.

Assistance from U.S.A. for improving Production of Edible Oilseeds

*765. SHRI R. K. AMIN:
SHRI K. P. SINGH DEO:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the U.S.A. Government has offered assistance for improving India's production of edible oilseeds on the lines parallel to green revolution;

(b) if so, whether the attention of Government of India has been invited in this regard to a report in the *Times of India* of the 5th February 1970; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) No, Sir.

(b) Yes.

(c) As and when any such offer is made by the U.S.A. Government it will be duly considered.

AITUC Views on Recommendations of Central Wage Board for Road Transport Industry

*766. SHRI V. NARASIMHA RAO: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the All India Trade Union Congress has called for a fresh review of the wages recommended by the Central Wage Board for road transport industry; and

(b) if so, the reaction of Government in regard thereto?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): (a) Reports to this effect appeared in the press sometime ago.

(b) Does not arise. The recommendations of the Wage Board were unanimous and were accepted by the Government on 2nd February, 1970.

TV for Punjab

*767. SHRI YASHPAL SINGH: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are proposing to establish a TV Centre in Punjab;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) when a final decision would be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा टेलीफोन सामग्री की कम सप्लाई और मेरठ डिवीजन के विकास पर इसका प्रभाव

*768. श्री महाराज सिंह भारती : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलोर देश की बढ़ती हुई टेलीफोनों की मांग को पूरा करने में असमर्थ है और इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में अग्रेतर विकास रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त गतिरोध को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो मेरठ डिवीजन के विकास के लिये सामग्री सप्लाई न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) ।

(क) और (ख). जी हां । किन्तु, फिर भी यह कहना सही नहीं होगा कि इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की क्षमता के अग्रेतर विकास में गतिरोध आ गया है । इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, टेलीफोन उपकरणों और अन्य दूरसंचार उपस्कर के निर्माण की अपनी क्षमता को प्रगामी रुप से बढ़ा रही है । लम्बी-दूरी के परिषण उपस्कर के निर्माण के लिये एक नया कारखाना इलाहाबाद के निकट नैनी में स्थापित करने का भी निश्चय किया जा चुका है । टेलीफोन उपकरणों तथा एक्सचेंज उपस्कर के निर्माण के लिये और कारखाने स्थापित करने या न करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) भारत में अन्य स्थानों की तरह मेरठ प्रभाग की एक्सचेंज क्षमताओं के अग्रेतर विस्तार का प्रश्न सम्पूर्ण देश में इस प्रकार के विस्तार के लिये उपलब्ध वित्तीय तथा सामग्री स्रोतों की समग्र स्थिति पर निर्भर होगा ।

Growing Indiscipline among Industrial Workers in West Bengal

*769. SHRI G. Y. KRISHNAN:
SHRI N. SHIVAPPA:

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that differences have cropped up in the industry and business circles in West Bengal over what they should do in the face of the uncertainty created by growing indiscipline among workers and deterioration in law and order;

(b) whether it is also a fact that such feelings have been conveyed to the State as well as the Central Government; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): (a) to (c). Government of West Bengal have informed that they have no information about such 'differences'. There have, however, been reports about workers' unrest and the law and order situation in the State, which is a matter for the State authorities to deal with.

Setting up of Fertiliser Credit Guarantee Corporation to remove Bottleneck in Fertiliser Consumption

*770. SHRI RABI RAY: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an expert Committee went into the question of bottleneck in the fertiliser consumption the country;

(b) if so, whether it is also a fact that the said committee recommended for the establishment of Fertiliser Credit Guarantee Corporation as a solution to this problem; and

(c) what steps Government have taken to implement the decision of the expert Committee?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) A fertiliser Credit Committee appointed by the Fertiliser Association of India, an organisation of the producers of fertilisers in the country, went into the different aspects of credit needs, arrangements and sources etc. for fertiliser marketing.

(b) The said Committee recommended that a Fertiliser Credit Guarantee Corporation may be set up so that credit to fertiliser dealers may become available smoothly and easily.

(c) The matter is under consideration.

Indian Subscription towards International Telecommunication Union

*771. SHRI S. K. TAPURIAH: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) how much India has so far subscribed towards the International Telecommunication Union; and

(b) the benefit which have been extended to India by this organisation during the last three years?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND COMMUNICATIONS (SHRI SATYA NARAYAN SINHA): (a) In the last eight years India has subscribed £4,37,827-4-4 to the International Telecommunication Union.

(b) A statement giving the required information is laid on the Table of the Sabha.

Statement

The benefits which have been extended to India by this organisation during the last three years?

The benefits derived by India from its association with the I.T.U. during the last three years are briefly the following:—

(1) 3710 frequency usages of India have been registered with the I.T.U. Membership of the I.T.U. gives international protection to our wireless usages against harmful interference from operations of other member countries.

(2) Establishment of an experimental satellite communication earth station at Ahmedabad through the assistance of the ITU/UNDP (United Nations Development Programme). The aid is to the extent of $6,17,000. In addition, I.T.U. provided experts for the establishment of this station and training of our engineers. This station is now engaged in training engineers and technicians of India and other countries, such as Afghanistan, Kenya, Sudan, Syria, Turkey, Burma, Kuwait, Republic of Korea, Nigeria, Malayasia, Singapore, Czechoslavakia etc. This station will also be used during 1972, when experiments for broadcasts from satellites will be conducted by the Department of Atomic Energy in collaboration with the National Aeronautics and Space Administration of U.S.A.

(3) In addition to arranging seminars on various current topics in telecommunications, the I.T.U. provides facilities in the form of fellowships for training of our engineers in various modern telecommunication techniques in more advanced countries, such as U.S.A., U.K., Federal Republic of Germany, etc.

(4) Participation at the Conferences organised by the I.T.U. has given India the benefit of its views being incorporated in the Radio Regulations and the Telephone and Telegraph Regulations. This is of great help for the development of our telecommunication industries according to international standards. This has also resulted in making a beginning in the export of wireless communication equipment to other nations.

(5) Receipt of information regarding latest telecommunication developments through the I.T.U. journal and other publications.

(6) Assistance in carrying out pre-investment surveys and feasibility studies for new telecommunication links in the ECAFE region, which includes India.

Employment of East Pakistan Refugees in M.P.

*772. SHRI S. M. BANERJEE: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the East Bengal refugees in various camps in Madhya Pradesh have been given full employment; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): (a) and (b). It is usually not the policy of the Government to provide full employment to the refugees while they are staying in camps, except that they are provided with casual employment on such items of work as levelling of sites, construction of roads, building of houses etc. The refugees remain in the camps only as a temporary measure till they are given necessary rehabilitation assistance, according to their professional categorisation, e.g., while the agriculturists are settled on land, the non-agriculturists are settled as Small Traders, Weavers etc.

Construction of Office Building and Residential Quarters for Employees Provident Fund Organisation at Delhi

*773. SHRI SHASHI BHUSHAN: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the present position with regard to the construction of an office building for Headquarters Office and residential quarters for the staff of the Employees Provident Fund Organisation at Delhi;

(b) whether it is a fact that an amount exceeding Rs. nineteen lakhs is tied up in acquiring plots and that the money is losing interests heavily; and

(c) if so, the actual loss by way of interest and the action taken against persons responsible for this serious irregularity?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): (a) to (c). The administration of the Employees' Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees. The Provident Fund authorities have reported that the Department of Works, Housing and Urban Development and the Delhi Development Authority have allotted plots of land for construction of an Office building and staff quarters of the Employees' Provident Fund Organisation respectively in Delhi. An advance payment in respect of both the plots has been made to the authorities concenred in accordance with their Rules. The Organisation has not taken over possession of the plots as certain formalities are yet to be completed. While the delay that has taken place is unfortunate, Government are satisfied that it could not be helped; necessary steps are being taken to put the Organisation in possession of the plots as early as possible.

Role of AIR in World Affairs

*774. SHRI M. L. SONDHI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether any study has been undertaken or is proposed to be made of the role of the All India Radio in relation to 'International relations and World Affairs';

(b) the number of talks arranged on these subjects, country-wise in the last year and the year preceding;

(c) the reasons for ignoring certain countries in the programme of talks; and

(d) whether Government propose to take steps to improve the role of All India Radio in this field, and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) No, Sir.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Talks on International Relations and World Affairs are broadcast to project India's point of view on significant events and to foster our relations with other countries. In view of this the question of ignoring any country would not arise.

(d) Improvement and change in the External Service and Home Service Broadcasts to meet changing commentaries in world affairs are constantly under review.

Mica Exports and Wages of Workers in Mica Industry

*775. SHRI MADHU LIMAYE: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Mica exports are experiencing difficulty in pushing exports of Mica;

(b) whether the stagnation in export earnings is given as one of the reasons by the mine owners for not increasing the wages of mine workers;

(c) if so, whether his Ministry has recommended any new incentives to Mica exporters such as reduction of excise duty or cash incentives in order to raise the wages; and

(d) if not, the reasons for not taking up this cause in the interests of Labour?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): (a) There have been reports of a declining trend in Mica exports during last few years for several reasons.

(b) These considerations are not relevant to payment of minimum wages fixed under the Minimum Wages Act, 1948.

(c) and (d). Do not arise.

Official Team to Asansol Collieries to assess situation created there by C.P.M.

*776. SHRI D. N. PATODIA: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to send an officer to assess the situation in the Asansol Collieries created by the Communist Party (Marxists) to capture the trade union there;

(b) whether pursuant to the decision any official team has been sent to Asansol;

(c) if so, the terms of reference given to the official team; and

(d) whether the team has since submitted any report to Government and if so, the details thereof, and if not, the reasons for the delay in sending the team?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): (a) to (c). The Acting Chief Labour Commissioner was deputed on March 3, 1970 to study the prevailing situation in the Asansol coalmining area, with particular reference to the recent clash between rival groups of workers at the Benali Colliery, and to secure resumption of work at this Colliery which had been closed down from February 26, 1970.

(d) This officer has furnished his report to Government. He had a series of discussions with the State and local authorities and was assured that all necessary steps would be taken to see that law and order situation remained under control. He also held discussions with the management of Benali Colliery and the workers' representatives; the lockout was lifted by the management and the Colliery re-opened as from March 9, 1970.

Nationalisation of Sugar Industry

*777. SHRI BABURAO PATEL: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether his Ministry has been recently advised by the legal experts of the Government that the Central Government alone can nationalise the sugar industry by an Act of Parliament;

(b) if so, the salient features of this expert note;

(c) whether Government now propose to nationalise the sugar industry; if so, when, if not, the reasons therefor;

(d) apart from the legal right to nationalise the sugar industry, whether Government have studied the economics of the industry from the national point of view to justify the necessity of nationalisation; and

(e) if so, the compelling reasons that justify the urgency of nationalisation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) to (e). Government have decided to appoint a Committee to study the working of the sugar industry in the context of the demand for its nationalisation. The Committee will enquire, *inter-alia*, into the economics of the industry. The Constitution of the Committee and the finalisation of the terms of reference are being processed.

Agreement with France for Development of Dry Farming

*778. SHRI NAVAL KISHORE SHARMA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether any agreement has been signed with the French Government to develop dry farming;

(b) if so, whether Rajasthan, as one of the formost States in need to develop dry farming, has been selected for this purpose; and

(c) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) The French Government offered assistance for an Indo-French Collaboration Project of Dry farming specifically in the Anantapur District of Andhra Pradesh. Since this offer was with reference to a specific area, Government of India examined it accordingly in consultation with the State Government. An agreement was signed on 11th March, 1970, for a joint project.

(b) and (c). The question do not arise, because the offer of the French Government was with reference to a specific area where their experts had done some research and investigation work earlier, and also because cooperation in the Anantpur District had been mentioned in the Indo-French Cultural Exchange Programme signed between two Governments earlier for the years 1969-70 and 1970-71.

Review of Production and Price of Vanaspati Ghee

*779. SHRI RAM AVTAR SHARMA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the practice of a fortnightly review of Vanaspati prices has been stopped since January, 1970;

(b) whether Government are also aware that prices of oils have gone up considerably leaving thereby a small margin of profit for the manufacturer;

(c) whether due to high prices of oils, manufacturers have curtailed production of Vanaspati; and

(d) if so, the steps Government are taking to increase the production of Vanaspati and reduce the prices of oils?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes, Sir. Price revisions are now proposed at intervals of two months; unless there is substantial rise in the prices of raw material in any fortnight.

(b) Some increase in the price of groundnut oil had occurred in the early part of March but prices have since shown a downward trend. Margin of profit of manufacturers is not directly connected with the rise or fall in the prices of oils.

(c) Yes, Sir. Some of the factories are reported to have curtailed production for varying periods.

(d) The matter has been discussed with the representatives of the industry and it is expected that the production will be restored to normalcy in the very near future. Steps to curb speculative trends in oil prices have also been taken through tighter credit control.

Aid to U.P. for Agricultural Production, Minor Irrigation and Land Development

*780. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the details of the assistance given to the Government of U.P. for agricultural production including minor irrigation and land development for the year 1969-70;

(b) the amount of assistance actually asked for by that Government for the purpose during the same period and for 1970-71; and

(c) the amount sanctioned by Central Government as aid for these schemes against the said demand for 1969-70?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) to (c). The procedure for release of Central assistance to State Governments for their plan schemes. has been revised from 1969-70. Assistance is now released to State Governments in block loans and grants for the annual plan as a whole and is not related to any individual scheme or programme. The Central assistance for the annual plan 1969-70 of the Govt. of Uttar Pradesh has been fixed at Rs. 94.00 crores. Against this an assistance of Rs. 90.88 crores has been released to the State on the basis of their expenditure figure. Quantum of assistance for the year 1970-71 is yet to be finalised.

Rural Indebtedness and Steps for its Removal

4801. SHRI R. K. BIRLA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that despite the financial assistance given to the farmers and agricultural labourers, there is a great indebtedness among these persons;

(b) if so, whether Government in consultation with the State Governments or on their own accord have undertaken a study to find out the indebtedness among small farmers and agricultural labourers; if so, the details thereof;

(c) the name of the State where there is heavy rate of indebtedness, and steps proposed to be taken to remove this indebtedness during the Fourth Plan; and

(d) the *per capita* income of an agricultural labourer on an average in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes, Sir. This is correct.

(b) The Rural Credit Review Committee had undertaken a study of the entire rural credit situation recently. However, specific figures regarding the indebtedness of the small farmers and agricultural labourers are not separately available.

(c) In 1961-62 the average indebtedness per rural house-hold was highest in Rajasthan (Rs. 800.4) followed by Punjab (Rs. 797.8) Mysore (Rs. 686.8); Madras (Rs. 628.8); Gujarat (Rs. 542.6); and Andhra Pradesh (525.8). In other States the average Debt per rural household was lower than the National average of Rs. 406.3 per family in that year.

Several steps have been taken and are currently in hand to increase the flow of credit into agriculture through reliable channels such as cooperative and commercial Banks. Two special Central Sector schemes for assisting the small and submarginal farmers and agricultural labourers have been included in the Fourth Five Year Plan to improve the income of such people, through mixed farming and other occupations.

(d) The 18th Round of National Sample Survey revealed that the average annual income per agricultural labour, household, evaluated at wholesale prices, was of the order of Rs. 660.19 in 1963-64 as against Rs. 385.38 in 1956-57.

Rise in Price of Wheat in Different States

4802. SHRI R. K. BIRLA:
SHRI MAYAVAN:
SHRI S. M. BANERJEE:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that prices of wheat have recently gone up in certain States in the country;

(b) if so, the names of the States where the prices have gone up, and to what extent the prices have gone up during the months of January, February and March this year as compared to those during the last six months of 1969;

(c) whether Government have released large quantities of wheat to these States to lower down the prices; and

(d) if so, to what extent prices have gone down in these States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes, Sir. Wheat prices showed an increase during January to mid-March, 1970 in the wheat growing States of Bihar, Gujarat, Harayana, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—3061/70.].

(c) Yes, Sir.

(d) During the second fortnight of March, 1970, prices have generally declined or become steady in these States as may be seen from the statement given in part (b).

Retrenchment of Labour in Palana Colliery

4803. SHRI P. L. BARUPAL: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Palana Colliery have effected large scale retrenchment of labour;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the date on which retrenchment notices were issued from the office of the Palana Colliery; and

(d) whether the representatives of workers were consulted before taking such steps by the Management?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): (a) Yes.

(b) It became an uneconomic unit because of recurrent fire due to spontaneous heating and was closed.

(c) 20-11-1969.

(d) No.

Demand for Wheel Tractors, Power Tillers and Crawler Tractors till 1973-74

4804. SHRI RAMACHANDRA VEERAPPA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the estimated demand, year-wise, for Wheel Tractors, Power Tillers and Crawler Tractors till 1973-74; and

(b) the arrangements made for fulfilling this demand?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) The estimated demand year-wise for wheel tractors, power tillers and crawler tractors till 1973-74 is given below:—

(i) *Wheel Tractors and Power Tillers.*

Year	Total Demand	
	Wheel Tractors	Power Tillers
1969–70	70,000	20,000
1970–71	70,000	30,000
1971–72	75,000	40,000
1972–73	80,000	60,000
1973–74	90,000	80,000
Total :	3,85,000	2,30,000

(ii) The average demand per annum for Crawler Tractors would be 1,000 machines during the Fourth Five-Year Plan and in 1973-74, 1,400 tractors would be required.

(b) (i) *Wheel Tractors.*

Industrial licences have already been issued for a capacity of 30,000 nos. p.a. Eight new schemes for a total capacity of 68,000 nos. p.a. have been approved in principle and five more schemes for a total capacity of 43,000 nos. p.a. are at present under various stages of consideration.

(ii) *Power Tillers*

One scheme for a capacity of 3,000 nos. p.a. has already been licensed. This unit is under production since 1965. Three new schemes for a total capacity of 23,000 nos. have also been approved and one of these units has since withdrawn its scheme for a capacity of 12,000 nos. p.a. and the Letter of Intent issued to the unit is being cancelled. Besides, two more schemes for a capacity of 25,000 nos. p.a. have been approved in principle and another two schemes for a capacity of 15,000 p.a. are under consideration at various stages.

(iii) *Crawler Tractors*

Four firms have been licensed with an optimum capacity of 1,000 nos. machines per annum.

The shortfall in the supply over the demand will continue to be met by imports as heretofore to the extent foreign exchange is available.

Use of Lathyrus Sativa (Tivda Daal) as Protein Food

4805. SHRI BABURAO PATEL: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Lathyrus Sativa known as "Tivda Daal", which has caused paralysis amongst thousands of farmers of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, is likely to be used as a source of protein food after boiling and straining it properly and then converting it into flour;

(b) the names of the scientists who have advised Government to utilize the "daal" in this manner, the nature of specific experiments conducted in this connection to arrive at the conclusion that the "daal" was good;

(c) whether this kind of "protein" food is worth consuming, knowing fully well its dangerous after-effects; and

(d) the exact reasons why Government are delaying the total ban on growing this poisonous "Tivda Daal" instead of finding out vague unconvincing and pseudo-scientific excuses to continue its wholesale cultivation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) The Nutrition Research Laboratory of the Indian Council of Medical Research has discovered that neurotoxic chemical principle in the *thivda daal* (*Lathyrus sativus*) is water soluble ad therefore if the thivda bean is boiled and soaked overnight and the liquid is thrown away, the daal can be freed from the harmful chemical.

(b) This research work has been done by the Nutrition Research Laboratory of the Indian Council of Medical Research at Hyderabad by Dr. C. Gopalan, Director of the Institute, and his colleagues.

(c) Does not arise.

(d) Although it has been known that continuous consumption of *thivda daal* in large quantities can lead to lathyrisum disease in human beings, the problem of banning the cultivation of this crop has met with considerable difficulty. One problem relates to the determination of suitable alternative crops in the place of *thivda daal*. The lathyrus plant is very hardy and comes up beautifully when planted in rice fields towards the end of the rice crop season. Besides the pulse, it yields a considerable amount of fodder. Few other plants have been found to be as suitable as lathyrus for growing under such conditions. It may also be mentioned that some research has been conducted at the I.A.R.I. for developing varieties of lathyrus in which the harmful neurotoxic chemical principle is either totally absent or is present in very low amounts. The promising lines, which have been developed, are still under test. It is hoped that in the near future there will be such varieties which can be safely taken up for cultivation.

Setting up of Seed Processing Plants by Food Corporation of India

4806. SHRI BABURAO PATEL: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the cost of the seed processing plant set up by the Food Corporation of India recently in Daurala;

(b) the annual capacity of the processing plant per annum;

(c) whether the Food Corporation of India is contemplating the setting up of similar processing plants in other States as well, if so, where; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) The Food Corporation of India has not set up any seed processing plant at Daurala.

(b) to (d). Do not arise.

Excessive use of Fertiliser and its Ill Effects

4807. SHRI BABURAO PATEL: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a warning in the Periodical "British Birds" by Robert Hudson saying, "The use of toxic chemicals in agriculture should be considered in the wider context of pollution of essential water supplies";

(b) the names of chemical fertilisers and their ratio with compost used for various crops cropwise;

(c) whether farmers have been warned and trained about the excessive use of fertilisers; if so, in what manner; if not, the reasons therefor; and

(d) the number and nature of complaints from farmers regarding the ill effects of fertilisers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) The specific article referred to has not been readily available and is being obtained. However, differing views regarding the use of chemical fertilisers have been expressed from time to time.

(b) A large number of chemical fertilisers are used in India, such as urea, ammonium sulphate, ammonium sulphate nitrate, calcium ammonium nitrate, ammonium chloride, diammonium phosphate, ammonium phosphate, complex (NPK) fertilisers, nitrophosphate, super-phosphate, muriate of potash, sulphate of potash etc. Farmers are advised to use the farm yard manure or compost alongwith the chemical fertilisers. Generally it is recommended that 40 tonnes of cattle dung manure should be used for each tonne of sulphate of ammonia which, on nitrogen basis, give a ratio of 1:1. For paddy it has been recommended that 6 tonnes of farm yard manure or compost per acre should be applied.

(c) Farmers are advised to judiciously apply fertilisers after getting the soils tested to ensure that all factors limiting fertility are removed and that fertilisers increase fertility status of the soil.

(d) No complaints have been received. It may be added that use of fertilisers in India as compared to agriculturally advanced countries of the world, is low. India is just using 10.96 kg. nutrients per hectare as against 626.25 Kg per hectare in Netherlands, 371.25 Kg per hectare in Japan and 75.74 kg. per hectare in the U.S.A. The amount of fertilisers used in India is not only low but also a fraction of the optimum level required for normal production of crops. Thus, the question of any ill effects of excessive use of fertilisers does not arise.

Films Exempted from Entertainment Tax

4808. SHRI N. R. DEOGHARE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the names of the films which were exempted from the Entertainment Tax in the country during the year 1969; and

(b) the reasons for exemption from the entertainment tax in the case of each film?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Requirement of Gujarat for Tractors

4809. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Government of Gujarat has sent its tractor requirements during the Fourth Five Year Plan;

(b) if so, the details thereof;

(c) the reaction of Government thereto; and

(d) whether Government have formulated any plan to guarantee their supply and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) and (b). Yes, Sir. The details of the tractor requirements during the Fourth Five Year Plan of the Gujarat State are given below:—

1st year.	2,000
2nd year.	2,150
3rd year.	2,300
4th year.	2,450
5th year.	2,600
Total..	11,500

(c) The requirements have been noted by Government and will be taken into consideration at the time of making allocations of imported tractors.

(d) With a view to meeting the increased demand for tractors, as far as practicable, it has been decided to import a substantially large number of tractors besides stepping up the indigenous production.

Workers Employed in Delhi Cinemas

4810. SHRI JUGAL MONDAL: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the number of workers employed in Ritz, Vivek, Regal and Amba Cinemas of Delhi;

(b) the numbers out of them, who are permanent and temporary servants and the numbers of those whose services are terminated every three months of their services; and

(c) the number of workers who are re-appointed after putting in three months of service?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILTATION (SHRI D. SANJIVAYYA): (a) and (b) The number of permanent and temporary workers employed in the four cinemas are as follows :

Name of the Cinemas	Permanent	Temporary	Total	No. of workers whose services are terminated every three months.
Ritz	54	4	58	None reported
Vivek	Nil	31	31	
Regal	57	2	59	
Amba	58	..	58	

(c) Does not arise.

Retenchment of Workers in Coal Mines in Asansol Raniganj Coal Belt

4811. SHRI JUGAL MONDAL: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the number of workers retrenched in the coal mines in Asansol Rani Ganj coal belt during the last 3 years up to March, 1970;

(b) the names and addresses of the coal mines together with the dates on which they were retrenched; and

(c) whether any industrial disputes are pending regarding these retrenchments, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

State Awards to Producers and Artistes

4812. SHRI JUGAL MONDAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of persons who got State Awards in respect of films during 1967-68 and 1968-69; and

(b) whether it is a fact that cash awards were given to some film producers and artistes during that period and if so, the details thereof and the reasons for giving cash awards?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) National awards for films are given for films certified by the Central Board of Film Censors in a particular calendar year. For films certified in the years 1967 and 1968, eighty-six awards were given.

(b) Yes, Sir. Cash prizes were awarded to the producers, directors and certain categories of technicians. A statement containing details is being laid on the table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-3062/70]. The object of these awards is to encourage production of films of high aesthetic and technical standard and of social and educational and cultural value and to promote healthy competition between creative film-makers.

Denial of Children Allowance to Employees in Forest Department, Manipur

4813. SHRI M. MEGHACHANDRA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Children Allowance is denied to the employees in the Forest Department under the Government of Manipur;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the number of incumbents who have been paid this allowance and the amount paid to them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The number of incumbents who have been paid the allowance is 107. The amount paid to them upto end of January, 1970, is Rs. 37,824.00.

Alleged Indulgence in Black-Marketing and Profiteering in Fertiliser Business by Fertilizer Companies in Private Sector

4814. SHRI N. SHIVAPPA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Fertilizer Companies in the private sector are indulging in black-marketing and profiteering business in the country;

(b) whether Government propose to take various methods to check black-marketing and profiteering in the fertilizer business;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the quantity and value of fertilizers imported by them during the last three years and the value realised by selling the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) to (c). No such general complaint has been received by this Ministry. There is no statutoy control on prices of Fertilizers except on sulphate of ammonia, ammonium sulphate nitrate, urea and calcium ammonium nitrate (20.5% N). As and when any such complaint on these four fertilisers is received, it is referred to the concerned State Government for inquiry and legal action, where necessary. The charging of prices higher than the notified prices for the abovementioned four fertilisers is a violation of the fertiliser (Control) Order, 1957, and is an offence punishable under the provisions of the Essential Commodities Act, 1955. Moreover, supply position in comparison to demand of fertilisers is very comfortable and the likelihood of black-marketing in fertiliser is very remote. The Fertiliser (Control) Order, 1957 has been recently amended to replace the 'licensing' system with the system of 'registration'. Now any person is free to start fertiliser business provided he makes an application for registration in the prescribed form within 14 days of starting such business. As a result of this, the number of retail sale points is likely to increase and with competition so generated, chances of black-marketing will be reduced.

(d) The import of fertilisers by private companies is not at present allowed. The import of fertilisers has been canalised through the State Trading Corporation or is made on Government account by the Department of Agriculture. During the last three years, import of only Sulphate of potash was allowed only for the licensing period 1967-68, to established importers on 100% quota basis, of the value of a few lakhs of rupees only out of the total import of about Rs. 200 crores worth of fertilisers during that year.

It is not possible to furnish details of the value of sulphate of potash imported by the private fertilisers companies who were granted licences for its import under the Established Importers Category during the year 1967-68, as the data relating to actual imports are maintained for the country as a whole and not for individual importers. No information is available regarding the details of the value of the imported sulphate of potash sold by private companies.

Formulation of Principles for Planning Indian Press during Fourth Plan

4815. SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any principles of planning the

Indian Press during the Fourth Plan period;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) to (c). In a democratic country, where the Freedom of the Press is assured by the Constitution (as in India) any attempt on the part of the Government to undertake planning of the Press will not be in keeping with the highest traditions of democracy. In view of this the Government has not formulated any principles of planning the Indian Press during the Fourth Plan period.

सत्तारूढ़ कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा राज्यों का दौरा

4816. **श्री शारदा नन्द :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सत्तारूढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष ने अभी हाल ही में विभिन्न राज्यों का दौरा कांग्रेस अध्यक्ष की अपनी हैसियत से किया था अथवा कि एक मन्त्री के रूप में; और

(ख) यदि उन्होंने यह दौरा एक मन्त्री के रूप में किया था तो उस दौरे पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के उपरान्त केन्द्रीय खाद्य और कृषि मन्त्री द्वारा किये गए विभिन्न राज्यों के सभी दौरे चाहे वे सरकारी कार्य के लिए रहे हों और चाहे अन्य कार्यों के लिए हों, सभी को "गैर सरकारी" समझा गया है। 24 दिसम्बर, 1969 के उपरान्त किये गये सभी दौरों के सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं लिया गया है ।

Call for 'Miss a Meal Every week' to meet Food Shortage in the Country

4817. SHRI BENI SHANKER SHARMA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state.

(a) whether it is a fact that the late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri, had given a call to the country to 'miss a meal every week'; and

(b) if so, whether Government propose to take some effective steps to continue this campaign so that the import of foodgrains from foreign countries could be stopped?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes, Sir.

(b) With the general improvement in the food situation in the country, import of foodgrains from foreign countries is being progressively reduced and is expected to be stopped altogether very soon. In the circumstances, it is not considered necessary to continue the campaign.

कच्ची सुपारी का उत्पादन

4818. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कच्ची सुपारी की कुल कितनी मांग है;

(ख) उस मांग को देश में उत्पादन से कहां तक पूरा किया जाता है;

(ग) पिछले तीन वर्ष में कुल कितने मूल्य की सुपारी का आयात किया गया;

(घ) क्या कच्ची सुपारी का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई योजना विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) लगभग 1.45 लाख मीटरी टन वार्षिक ।

(ख) आवश्यकता की लगभग 95 प्रतिशत मांग को देश के उत्पादन से पूरा किया जाता है ।

(ग) आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती है । फिर भी, गत तीन वर्षों में निम्नलिखित मात्रायें पकड़ी गई थीं:

वर्ष	लाखों रु० में मूल्य
1966-67	4.11
1967-68	1.05
1968-69	कुछ नहीं

(घ) जी हां ।

(ङ) पूछी गई जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

चौथी योजना के अंत तक सुपारियों की आवश्यकता 1,26,000 मीटरी टन के वर्तमान उत्पादन की अपेक्षा 1,50,000 मीटरी टन होने का अनुमान लगाया गया है । चौथी योजना के अंत तक 24,000 मीटरी टनों के अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । यह लक्ष्य केरल, मैसूर और असम के तीन मुख्य सुपारी उत्पादक राज्यों में पैकेज कार्यक्रम को आयोजित करके सघन खेती के उपायों द्वारा पूरा किया जाना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने हेतु उर्वरकों, कीड़े तथा कीट के आक्रमण के विरुद्ध छिड़काव के लिए अपेक्षित पौद रक्षा उपकरणों तथा रसायनों की खरीद के लिए किसानों को ऋण दिए जाएंगे । इस योजना के लिए अपेक्षित स्टाफ का खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा जो निम्न प्रकार होगा :

	लाख रु० में
(i) केरल	2.05
(ii) मैसूर	1.40
(iii) असम	0.67
जोड़	4.12

अन्य केन्द्रीय क्षेत्रक कार्यक्रमों में, असम तथा गोवा के राज्यों में, जहां उपज तुलनात्मक रूप से कम होती है, इस फसल की वैज्ञानिक खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदर्शन प्लाटों का आयोजन करने पर बल दिया जाएगा । चौथी योजना में असम में कुल 0.625 लाख रु० के परिव्यय से 25 ऐसे प्लाट बनाए जाएंगे और गोवा में 0.250 लाख रु० की लागत से 5 एकड़ वाला प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा ।

पेकिंग रेडियो द्वारा भारत के प्रतिक्रियावादी व्यक्तियों को उत्तेजित करना

4819. **श्री रामगोपाल शालवाले :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिक्रियावादी व्यक्तियों को अपनी विजय के लिये बन्दूकें चलाने के लिये उत्तेजित करने वाले पेकिंग प्रसारणों का उत्तर देने के लिये सरकार ने कोई उपयुक्त तरीका अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). चीनी प्रचार का आकाशवाणी

के विभिन्न केन्द्रों को घरेलू तथा वैदेशिक सेवाओं के अन्तर्गत समाचारों, समाचार समीक्षाओं तथा वार्ताओं में खण्डन किया जाता है उन तथ्यों तथा घटनाओं, जिनको चीन गलत रूप से प्रस्तुत करता है, का समाचार बुलेटिनों में सही रूप प्रस्तुत करके तथा अन्य नेताओं के भाषण और वक्तव्य प्रस्तुत करके चीनी प्रचार का खण्डन किया जाता है।

हरिजनों के लिये शिक्षा की समान सुविधाओं की मांग

4820. **श्री वंश नारायण सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 21 मई, 1969 के दैनिक हिन्दुस्तान के पृष्ठ चार पर "हरिजनों के लिये शिक्षा की समान सुविधाओं की मांग" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित उनके वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त वक्तव्य सही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

कोटा के लिये आकाशवाणी केन्द्र

4821. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा, राजस्थान की जनता ने श्रीमती इंदिरा गांधी से मांग की है कि वहां पर एक रेडियो स्टेशन स्थापित किया जाय;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) संभव है कि ऐसी प्रार्थना की गई हो, किन्तु इस बारे में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग). विभिन्न क्षेत्रों से कई स्थानों पर रेडियो स्टेशन स्थापित करने की प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं। रेडियो स्टेशन के स्थान का निर्णय सरकारी नीति, जैसे क्षेत्र, जन-संख्या, संबंधित प्रदेश की भाषा और संस्कृति, उसका प्रशासन कार्य स्थान, कलाकारों की उपलब्धि तथा तकनीकी शक्यता आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि आकाशवाणी के अजमेर और इन्दौर केन्द्रों से प्रसारित कार्यक्रम कोटा जिले में अच्छी तरह सुने जाते हैं।

बिना लाइसेंस वाले रेडियो सेट

4823. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में ऐसे कुल रेडियो सेट कितने हैं जिनके लाइसेंस बने हुए हैं;

(ख) ऐसे रेडियो सेट कितने होंगे जो बिना लाइसेंस के चलाये जाते हैं; और

(ग) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में रेडियो लाइसेंसों से सरकार को कुल कितनी आय हुई थी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1,05,00,578 (31 दिसम्बर, 1969 को)।

(ख) बिना लाइसेंस के चलाये जा रहे रेडियो सेटों की संख्या का अनुमान लगा सकना संभव नहीं है ।

(ग)	रुपये
1967 . .	9,76,92,635.00
1968 . .	12,06,59,164.50
1969 . .	12,53,52,476.00

लाइसेंसों से प्राप्त आय की गणना कलैंडर वर्षों के अनुसार की जाती है ।

Houses for Industrial Workers in Public Sector Projects

4824. SHRI BABURAO PATEL: SHRI V. NARASIMHA RAO:

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Shri K. K. Shah, Minister for Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development stated in the Consultative Committee that he proposes to enact legislation to compel industrial employers to build houses for their workers;

(b) how many public sector projects have built houses for their workers, with their names; and

(c) if none has been built, the reasons for not making of beginning by compelling the public sector projects to provide houses for their workers and thus set an example for the private sector projects?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): (a) No, Sir.

(b) and (c). According to information received from 104 Companies/Corporations and departmental undertakings comprising 205 units, nearly 70% have provided housing facilities to their workers.

Loss Incurred by Public and Private Undertakings on Account of Gheraos

4825. SHRI D. N. PATODIA: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government have assessed the loss suffered, both quantitative and in terms of finance, by the Industry —Public and Private Sector separately— due to loss of man-hours of gheraoes;

(b) the total number of man-hours lost during the last three years; and

(c) the industries which have been affected most?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): (a) to (c). The available information is given in the statements (I to III) laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-3063/70.]

भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन

4826. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समझती है कि देश में लोगों की भोजन सम्बन्धी आदतें तथा उनके द्वारा उपयोग किया जाने वाला भोजन पोषक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो देश की जनता की भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन लाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या सरकार ने छोटे बच्चों को मुफ्त भोजन देने की योजना के द्वारा भोजन सम्बन्धी आदतों में परिवर्तन लाने का कोई प्रयत्न किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने शाकाहारी परिवारों के कितने बच्चों को मांसाहारी बनाया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास, तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) भोजन सम्बन्धी उपयुक्त आदतों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि पोषाहार में सुधार करने के लिए अनाजों की खपत में कमी और भोजन में विविधता लाई जा सके ।

(ख) सरकार ने देश में लोगों की भोजन सम्बन्धी आदतों में परिवर्तन लाने के लिए बहुत से कार्यक्रम शुरु कर रखे हैं। सहायक

तथा सस्ते प्रोटीन आहारों को लोक प्रिय बनाने, खाद्य-परिरक्षण, पाक-विधि की वैज्ञानिक विधियों और खाद्य-पदार्थों के उपयोग सम्बन्धी जानकारी का प्रसार करने के लिए विभिन्न राज्यों में 17 चलते-फिरते खाद्य तथा पोषाहार विस्तार यूनिट कार्य कर रहे हैं। मेलों तथा प्रदर्शिनयों में भाग ले कर और प्रचार के सामान्य साधनों, स्वयंसेवी एजेंसियों के सहयोग अनाज रहित खाद्य व्यंजनों आदि की सूचियों वाली पुस्तिकाओं के प्रकाशन द्वारा सहायक खाद्य, संतुलित भोजन और खाद्य परिरक्षण सम्बन्धी जानकारी का भी प्रसार किया जा रहा है। चार खान-पान औद्योगिकी तथा व्यावहारिक पोषाहार संस्थान स्थापित किए गए हैं और पांच खाद्य पौलीटेकनिक खोले गए हैं। सरकारी क्षेत्र में स्थापित आठ स्वचालित बेकरियां भी बड़े शहरों में कार्य कर रही हैं जोकि पौष्टिक दृष्टि से समृद्ध डबल रोटियों का उत्पादन करती हैं।

(ग) कुछ राज्यों में "केयर" द्वारा आयोजित मुफ्त फीडिंग कार्यक्रम भी चला रहा है। सरकार इस कार्यक्रम के लिए देशी ढंग से तैयार सम्मिश्रित पौष्टिक खाद्य-पदार्थ जोकि आवश्यक विटामिन तथा खनिजों से समृद्ध होता है, बालाहार का उत्पादन कर रही है।

(घ) भोजन सम्बन्धी आदतों में परिवर्तन के कार्यक्रम का विशिष्ट रूप से शाकाहारी परिवारों को मांसाहारी बनाने से सम्बन्ध नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भरतपुर के डाक तथा तार डिवीजनल कार्यालय में अत्यधिक काम होने के कारण सवाई माधोपुर के लिए अलग डाक डिवीजन

4827. **श्री मोठालाल मीना :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में भरतपुर के डाक तथा तार डिवीजन कार्यालय में कार्य इतना अधिक है कि सम्बन्धित अधिकारी अपने कार्य को सुचारु रूप से करने में कठिनाई अनुभव करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सवाई माधोपुर के लिये अलग डिवीजन बनाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता। इस समय भरतपुर डाक डिवीजन को दो भागों में विभक्त करने और एक नये डाक डिवीजन के निर्माण का कोई औचित्य नहीं है।

Export of Sugar by Indian Sugar Industry Corporation, Delhi

4828. SHRI JYOTIRMOY BASU: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Indian Sugar Industry Corporation Limited, Delhi has been named by the Government as an export agency for handling export of sugar;

(b) if so, the details of its structure and composition;

(c) whether Government have any control over this Corporation;

(d) if so, the nature of that control; and

(e) why it was not considered desirable to take over the sugar export trade directly in the hands of any Government Undertaking set up to handle export and import trades?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) The Indian Sugar Industry Export Corporation Limited, Delhi, has been specified as an export agency for the purposes of the Sugar Export Promotion Act, 1958.

(b) The membership of the Corporation is confined to the owners of the licensed sugar factories or their authorised representatives. Its affairs are managed by a Committee of 20 persons comprising of the representatives of the co-operative sugar factories and other sugar factories. The Committee has a Chairman and a Vice-Chairman who also serve as the Chairman and Vice-Chairman of the Corporation. The offices of the Chairman and the Vice-Chairman are rotated alternately between the representatives of the cooperative sugar factories and representatives of other factories.

(c) and (d). The export agency specified under the provisions of the Sugar Export Promotion Act, 1958 is bound in the discharge of its functions under the said Act, by such general or special directions, as the Central Government may give to it in writing.

(e) The present agency has developed specialised knowledge and some degree of expertise and works on 'no profit no loss' basis. Morever, during 1968 and 69 all exports were made under the provisions of the Sugar Export Promotion Act, 1958 and the entire loss was met by the sugar industry whose representatives constitute the export agency. In 1970 also the preferential quota of about 95,000 tonnes is being exported under the Sugar Export Promotion Act and the loss will be borne by the sugar industry.

मालवियानगर, नई दिल्ली में गाय को मार मार कर उसकी हत्या कर देना

4829. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस घटना की ओर दिलाया गया है जिसमें मालवियानगर, नई दिल्ली में एक गाय को बर्बरता से पीटा तथा उसकी हत्या कर दी गई ; और

(ख) यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्ति के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) दिल्ली प्रशासन से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि शिकायत की जांच की गयी और यह पता चला कि गाय को न तो पीटा गया था और न ही जख्मी किया गया था । परन्तु वह अपनी स्वाभाविक मृत्यु से मरी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में डाकघर

4831. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री शारदा नन्द :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969–70 में उत्तर प्रदेश में जिलावार कितने डाक-घर खोले गये;

(ख) 1970–71 में जिलावार कितने डाक-घर खोले जायेंगे; और

(ग) उत्तर प्रदेश में इस समय कितने डाकघरों में तार की सुविधायें उपलब्ध है और कितने डाकघरों में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तार भेजने की सुविधायें उपलब्ध हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) 1969–70 के दौरान उत्तर प्रदेश में जिलावार खोले गए डाकघरों की संख्या इस प्रकार है —

1. सहारनपुर	7
2. मुजफ्फरनगर	1
3. आगरा	15
4. मेरठ	8
5. गोरखपुर	18
6. देवरिया	12
7. फरूखाबाद	5

8. इटावा	7
9. मैनपुरी	5
10. इलाहाबाद	कोई नहीं
11. मिर्जापुर	4
12. आजमगढ़	7
13. बलिया	10
14. फैजाबाद	14
15. जौनपुर	9
16. कानपुर	19
17. उन्नाव	2
18. फतेहपुर	5
19. लखनऊ	कोई नहीं
20. बाराबंकी	14
21. गोंडा	5
22. बहराइच	10
23. बस्ती	6
24. सीतापुर	18
25. हरदोई	4
26. खेडी	4
27. वाराणसी	3
28. गाजीपुर	4
29. अलीगढ़	12
30. बुलन्दशहर	11
31. अल्मोड़ा	16
32. पिथोरागढ़	9
33. बरेली	2
34. बदायूं	6
35. शाहजहांपुर	4
36. देहरादून	4
37. टिहरी	3
38. उत्तरकाशी	1
39. झांसी	8
40. हमीरपुर	1
41. जालौन	7
42. बांदा	1
43. मथुरा	4
44. एटा	8
45. मुरादाबाद	7
46. रामपुर	4
47. बिजनौर	11
48. नैनीताल	4
49. पीलीभीत	2
50. पौड़ी	12
51. चमोली	6
52. प्रतापगढ़	6
53. राय बरेली	10
54. सुल्तानपुर	6

(ख) 1970-71 के दौरान उत्तर प्रदेश में जिलावार खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या का अभी अन्तिम रूप से निश्चय नहीं किया गया है ।

(ग) उत्तर प्रदेश में ऐसे डाकघरों की संख्या जिनमें 1-2-70 को तार सुविधायें मौजूद हैं 1,146

उत्तर प्रदेश में ऐसे डाकघरों की संख्या जिनमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तार भेजने की सुविधाएं उपलब्ध हैं ... 595

रबी फसल के लिये गेहूं का मूल्य

4832. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी रबी फसल के लिये गेहूं का मूल्य निर्धारित कर दिया है और यदि नहीं, तो इस बारे में किस तारीख तक घोषणा कर दी जायेगी ;

(ख) क्या उक्त मूल्य निर्धारित करते समय किसानों के प्रतिनिधियों से भी परामर्श किया गया है ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु अन्य वस्तुओं के तुलनात्मक बाजार भावों को भी ध्यान में रखा जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) सरकार विपणन मौसम 1970-71 के लिए गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्यों पर विचार कर रही है और बहुत जल्द निर्धारित किए जाएंगे ।

(ख) और (ग). कृषि मूल्य आयोग मूल्यों के बारे में सिफारिश करते समय सभी संगत तथ्यों पर जिन में अन्य खाद्यान्नों के मूल्य भी शामिल है, विचार करता है । आयोग को परामर्श देने के लिए किसानों का एक पेनल भी है ।

संचार विभाग में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाना

4833. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार विभाग ने अपनी सेवाओं में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु कुछ विशेष कार्यवाही की है ;

(ख) विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी को शामिल करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) विभागीय परीक्षा के लिये जिन पुस्तकों की आवश्यकता होती है उनके हिन्दी संस्करणों के प्रकाशन में कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :(क) राजभाषा अधिनियम और गृह मंत्रालय के अनुदेशों में दिये गये प्रावधानों का विभाग में कार्यान्वयन किया जा रहा है । कर्मचारियों से भी यह निवेदन किया गया है कि वे जहां तक हो सके हिंदी में कामकाज करें ।

(ख) इस प्रश्न पर गृह मंत्रालय में जांच की जा रही है । गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदेशों को डाक-तार विभाग में कार्यान्वित किया जायेगा ।

(ग) विभागीय परीक्षा में जिन मेनुअलों की आवश्यकता पड़ती है उनके हिंदी संस्करणों को जल्द प्रकाशित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है । तीन खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं, चार खण्ड प्रेस में हैं और बाकी मेनुअलों के अनुवाद और जांच का कार्य भिन्न भिन्न स्तर पर है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक व तार सुविधाओं का विस्तार

4834. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक, तार व टेलीफोन सेवाओं के विस्तार हेतु कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गांवों में इन सुविधाओं के विस्तार के बारे में उदासीनता दिखाते हैं और बड़े गांवों के बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट देते हैं और इस प्रकार कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :(क) **डाक सेवा**—देहाती इलाकों में डाक सेवाओं का विस्तार हाल में, कुछ मानकों के आधार पर किया जाता है । इनका उल्लेख सभा पटल पर रखे गये विवरण में किया गया है । [ग्रन्थालय में रखा दिया गया । देखिये संख्या LT—3064/70] इन मानकों के आधार पर खोले गए डाकघरों में भविष्य में भी डाकघर खोलते समय आने वाली लागत का 25 प्रतिशत आय के रूप में अर्जित करना होगा । ऐसे गांवों में, जो ग्रामपंचायतों के मुख्यालय हों, डाकघर खोलने पर खास ध्यान दिया जाएगा ।

राज्य मंत्री महोदय ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि ग्राम पंचायतों को अपने इलाके में प्रायोगिक डाकघर खोलने में होने वाले खर्च की पूर्ति करने

के लिये अधिकृत किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने यह सुझाव मान लिया है। उन्होंने महाराष्ट्र जिला परिषद और समिति अधिनियम 1961 में उचित संशोधन कर दिया है ताकि देहात में डाकघर खोलने के लिए वे खर्च उठा सकें।

तार और टेलीफोन सेवा :

आम तौर पर तार और टेलीफोन सुविधाएं ऐसी जगहों पर दी जाती हैं जहां डाक सेवाएं उपलब्ध हों बशर्ते कि यह योजना लाभकारी हो। यदि ऐसी योजनाएं अलाभकारी हों तो किसी इच्छुक पार्टी द्वारा विभाग के घाटे की पूर्ति करने पर ये सुविधाएं दी जाती हैं। फिर भी, अविकसित क्षेत्रों में (जिनमें देहाती क्षेत्र भी शामिल हैं) तार और टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए एक नीति बनाई गई है। इस नीति के अनुसार कुछ खास वर्ग के स्थानों पर, उनके प्रशासनिक महत्व, आबादी, सामान्य दूरसंचार जाल से अति दूर होने के आधार पर घाटे पर भी ये सुविधाएं दी जा सकती हैं। कुछ सीमाओं तक पर्यटन केंद्रों, यात्रा केंद्रों, और कृषि और सिंचाई प्रायोजना के स्थानों और उप-नगरों में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर भी सीमित घाटे के आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। विभागीय मानकों के पूरा होने और निधि के उपलब्ध होने पर देश में डाक-तार और टेलीफोन संबंधी सुविधाएं दी जा रही हैं।

(ग) प्रश्न नहीं ही उठता।

Export of Fish

4835. SHRI SHARDA NAND:
SHRI KANWAR LAL GUPTA:
SHRI SURAJ BHAN:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) how much export of fish has been made in the last three years;

(b) whether Government propose to provide facilities to private companies who are working in this trade;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the steps Government propose to take to explore the possibility of making more exports of fish to foreign countries and supplying fish to all the States of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) The export of marine products including fish and fishery products from India during the last three years were as follows—

Year	Quantity (in tonnes)	Value (Rs. crores)
1967	21764	19·93
1968	24810	22·08
1969	30584	33·10

(b) and (c). Information on new fishery resources collected by survey and exploratory vessels of the Government are made available to the fishing industry. The survey fleet is being strengthened in order to improve and enlarge the scope of this assistance to the fishing industry. Banks and Credit institutions are now in a position to advance loans for suitable fishery projects. In order to encourage exports, facilities are given to exporters to import material and equipment required for fishing and processing of fish and fishery products. Such imports include tinplate, refrigerants, spare parts for marine diesel engines and refrigerating equipment etc.

(d) The measures which are being taken to devlop the fishing industry are designed to increase the availability of varieties suitable for export as well as supplies of fish for the internal market. Under Central and Centrally Sponsored Schemes, fishing harbours are being provided in several ports, survey of fish resources is being intensified and research and training facilities are being expanded. A scheme for import of thirty deep sea fishing vessels for commercial fishing is being implemented.

Steps have been taken to organise the manufacture of fishing vessels in the country. A scheme has been drawn up for subsidising deep sea fishing vessels constructed in the country. Under Centrally aided state plan schemes the most important programme is that of mechanisation of fishing vessels. Five thousand boats are expected to be introduced under this programme in the Fourth Plan period in addition to about eight thousand five hundred boats already introduced and in operation. A survey of India's export potential of marine products has been conducted recently by the Indian Institute of Foreign Trade. Their report is expected to be finalised shortly. The Inland fishery development programmes are directed towards increased production of fish seed, reclamation of derelict water areas for fish farming and development of reservoir fisheries. It has also been proposed to bring in large areas under intensive pisciculture and also to take up a pilot scheme for development of brackish-water fisheries.

Rehabilitation of Persons Displaced in 1965 Indo-Pak Conflict from Jammu and Kashmir Borders

4836. SHRI SHRI CHAND GOYAL: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the persons who were displaced in the Indo-Pak. war of 1965 from the Jammu and Kashmir State borders have been rehabiltated;

(b) whether there are some persons still remaining to be rehabiltated; and

(c) if so, by what time they will be rehabilitated?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): (a) Yes, Sir. assistance on approved scale has been extended to all the affected families.

(b) No, Sir.

(c) The question does not arise.

Prospects of Rabi Crops in Punjab and Haryana

4837. SHRI SHRI CHAND GOYAL: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the prospects of Rabi crops in Punjab and Haryana;

(b) whether the targets will be completed; and

(c) what are the procurement targets for the above States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) and (b). According to present indications, the prospects of rabi crops in Punjab and Haryana during 1969-70 are generally good. However, firm estimates of production of rabi crops for 1969-70 (All-India and Statewise) would become available after the close of the agricultural year i.e., sometime in July August, 1970.

(c) The procurement targets envisaged in respect of wheat for 1970-71 marketing season are as follows:—

Punjab	:	25 lakh tonnes
Haryana	:	3.5 lakh tonnes

Quality and Content of Milk Supplied by D.M.S.

4838. SHRI VAJNA DATT SHARMA:
SHRI JAI SINGH:
SHRI HARDAYAL DEVGUN:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the entire quantity of 'standard', 'toned' and 'double toned' milk sold by the Delhi Milk Scheme is prepared from the pure buffalo milk and if not, whether milk powder is used for this purpose;

(b) if milk powder is used for the purpose also, the quantity separately of 'standard', 'toned' and 'double toned' milk prepared separately from milk and milk powder; and

(c) the quantity and value of the milk powder used for preparing one litre of 'standard', 'toned' and 'double toned' milk separately?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Standardised, Toned or Double Toned

milk is normally prepared from fresh milk. Skim milk powder is utilised in the preparation of these types of milk only if there is shortage of fresh milk, particularly during the summer months.

(b) The estimated quantities of milk of various types prepared with the use of fresh milk only and also with the addition of skim milk powder during the year 1969-70 (upto 23.3.70) is indicated below:—

Type of Milk	Quantity produced from fresh milk only	Quantity produced by addition of SMP to fresh milk.
	(litres)	(litres)
Standardised	2,89,88,236	4,07,87,813
Toned	60,21,045	1,23,92,739
Double toned	5,46,298	46,23,980

(C)

Type of milk	Milk produced from fresh milk with addition of skim milk powder.		Milk produced wholly from skim milk powder	
	Qty. of SMP used for preparation of one litre.	Value of SMP used per litre.	Qty. of SMP used for preparation of one litre.	Value of SMP used per litre.
Standardised	20 gms.	Paisa 5·6	91 gms.	Paisa 25·48
Toned	46·5 ,,	,, 13·02	91 ,,	,, 25·48
Double Toned	70·0 ,,	,, 19·60	95 ,,	,, 26·60

Visit by Minister of Food and Agriculture to Orissa

4839. SHRI YAJNA DATT SHARMA:
SHRI JAI SINGH:
SHRI HARDAYAL DEVGUN:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that he visited Orissa in the first half of March this year;

(b) whether his visit to Orissa synchronised with the visit of the Soviet Ambassador to Orissa;

(c) if so, whether it was in any way related to the visit of the Soviet Ambassador; and

(d) the specific purpose of his visit?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes, Sir. He visited Bhubaneswar & Cuttack on 6-3-1970.

(b) The Soviet Ambassador was also at Cuttack on that date.

(c) The visit of Minister of Food and Agriculture was not related to that of the Soviet Ambassador.

(d) To inaugurate the 9th National Conference of the Indo-Soviet Cultural Society held at Cuttack, to commemorate the birth centenary of Lenin.

Exchange and application of New Ideas and Techniques in Agricultural Production

4840. SHRI MANIBHAI J. PATEL:

SHRI DEVINDER SINGH GARCHA:

SHRI VALMIKI CHOUDHARY:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Dr. D. R. B. Banks—a U.S. Expert in animal husbandry and animal nutrition, was on a visit to India recently;

(b) whether he gave any suggestions to Government on the importance of full exchange and prompt application of new ideas and techniques in the field of agricultural production; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes, Dr. Banks visited India. He is a British national.

(b) He discussed certain Animal Husbandry Development and Disease Control Programmes in the country which had stress to a large measure on the use of antibiotics marketed by M/s Cyanamid, the firm which he represents. The ideas or techniques which he dwelt on are known to our scientists.

(c) Does not arise.

Meeting of Indian Labour Conference or Standing Labour Committee to Consider Recommendations of National Labour Commission

4841. SHRI MANIBHAI J. PATEL:

SHRI DEVINDER SINGH GARCHA:

SHRI VALMIKI CHOUDHARY:

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether there is a proposal under the consideration of Government to call a meeting of either the Indian Labour Conference or the Standing Labour Committee in order to consider the recommendations of the National Labour Commission in the near future; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): (a) Yes; it is proposed to convene the Session of the Standing Labour Committee sometime towards the end of July, 1970, to consider, *inter alia*, the recommendations of the National Commission on Labour at that Meeting.

(b) The agenda of the Meeting has not yet been finalised.

Present Food Situation

4842. SHRI R. K. BIRLA:

SHRI JAGESHWAR YADAV:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the present food situation in the country as compared to the last year; and

(b) whether the recent rains in certain parts of the country have bettered the prospects of rabi crop, if so, to what extent?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) The food situation in the country at present is quite satisfactory and is better than what it was last year. The availability of foodgrains in the markets is generally easy.

(b) Rains received after mid-January, 1970 have been generally beneficial to the standing crops. In some parts of Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Haryana and Delhi some adverse effect by rains and hailstorm on crops are reported. On the basis of qualitative reports about weather and crop conditions, it is expected that total production of rabi foodgrains during 1969-70 would be higher than that of last year.

आकाशवाणी के भोपाल तथा इन्दौर केन्द्रों से फिल्मी संगीत के प्रसारण की अवधि

4843. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के भोपाल तथा इन्दौर केन्द्रों से प्रत्येक मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा में फिल्मी संगीत प्रसारित करने के लिये कुल कितने घण्टे नियत किये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त भाषाओं में फिल्मी संगीत प्रसारित करने के लिये नियत समय में भारी असमानता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) आकाशवाणी के भोपाल तथा इन्दौर केन्द्रों से हिन्दी फिल्म संगीत क्रमश: 19 घण्टे तथा 19 घण्टे 46 मिनट प्रतिमाह प्रसारित होता है ।

(ख) और (ग). श्रोताओं की मुख्य मांग हिन्दी फिल्म संगीत के बारे में होती है । अन्य भाषाओं के फिल्म संगीत की मांग प्राप्त होने पर, उसपर विचार किया जायेगा

मध्य प्रदेश में होशंगाबाद तथा ईस्ट नीमाड़ में सब-आफिस डाकघर

4844. **श्री गं० च० दीक्षित :** सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तथा ईस्ट नीमाड़ जिलों के किन किन स्थानों पर इस समय सब डाक-घर काम कर रहे हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : मध्य प्रदेश में होशंगाबाद और पूर्वी नीमाड़ (खंडवा) में जिन स्थानों पर उप डाकघर काम कर रहे हैं, उनके नाम ये हैं —

होशंगाबाद जिला

विभागीय उप-डाकघर

1. बवाई
2. बानपुरा
3. बानखेरी
4. हारदा
5. हारदा आर० एस०
6. होशंगाबाद सिटी
7. होशंगाबाद आर० एस०
8. इटारसी
9. खेड़ीपुरा
10. खिड़कियां आर० एस०
11. मंगलवाड़ा-पीपरिया
12. पंचमढ़ी
13. पंचमढ़ी बाजार
14. पचमढ़ी छावनी
15. पीपरिया
16. पोवरखेदा
17. पुरानी बस्ती, इटारसी
18. सिक्युरिटी पेपर मिल्स, होशंगाबाद
19. स्योनी मालवा
20. सोहागपुर
21. तवानगर
22. सोहागपुर आर० एस०
23. तिमरनी
24. तिमरनी आर० एस०
25. पोलिटेकनिक हारडा
26. न्यू यार्ड कालोनी, इटारसी

अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर

1. गांधीनगर
2. मकराई
3. सेवारी हरचन्द

पूर्वी नीमाड़ (खंडवा) जिला :

विभागीय उप-डाकघर

1. आनन्दनगर खंडवा
2. बीर
3. बुर्हानपुर
4. बुर्हानपुर सिटी
5. बुर्हान राजपुरा
6. बुर्हानपुर आर० एस०
7. छेगांव माखन
8. घासपुरा खांडवा
9. हरसूद पी०सी०ओ०
10. इच्छापुर
11. खंडवा-रतागढ़
12. मुंडी सी० ओ०
13. नेपानगर पी०सी०ओ०
14. नेपानगर मजदूर कैम्प
15. नीमाड़ खेड़ी
16. पंधाना
17. शाहबाजार बुर्हानपुर
18. शाहपुर (नीमाड़)
19. टैगोर कालोनी, खंडवा
20. इतवारा बुर्हानपुर
21. महाजनपेठ बुर्हानपुर
22. गणेश तलाई खंडवा
23. जासवाड़ी ।

अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर :

1. पाडवा खंडवा

मध्यप्रदेश के होशंगाबाद तथा ईस्ट नीमाड़ जिलों म डाक का बांटा जाना

4845. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि होशंगाबाद तथा ईस्ट नीमाड़ जिलों के उन कस्बों के नाम क्या हैं ? जिन में दिन में एक से अधिक बार डाक के बांटे जाने की व्यवस्था है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): होशंगाबाद तथा पूर्वी नीमाड़ जिलों में जिन कस्बों में दिन में एक से अधिक बार डाक बांटी जाती है, उनके नाम इस प्रकार हैं —

होशंगाबाद (13 कस्बे)

होशंगाबाद, बवाई, बानपुरा, बानखेरी, हरदा, इटारसी, खिड़कियां आर० एस०, मकरी, पंचमढ़ी, पीपरिया, स्योनी मात्वा, सोहागपुर, टिमरनी, ।

पूर्वी नीमाड़ (7 कस्बे)

बीर, बुर्हानपुर, हरसूद, इच्छापुर, खंडवा, नेपानगर, शाहपुर (नीमाड़) ।

Report of Committee on the Working of Co-operatives

4846. SHRI DHANDAPANI:
SHRI N. R. LASKAR:
SHRI SAMINATHAN:
SHRI GHENGALRAYA NAIDU:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a six-member Committee under the chairmanship of Shri S. K. Dey was appointed by Government to see the working of co-operatives in India;

(b) if so whether Government have examined the report;

(c) how many recommendations have been accepted; and

(d) the steps taken to implement them?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI D. ERING): (a) No such committee was appointed by the Government of India.

(b) to (d). Do not arise.

Tractors Alloted to J & K State and sold in Punjab in Black Market

4847. SHRI DHANDAPANI:
SHRI N. R. LASKAR:
SHRI SAMINATHAN:
SHRI CHENGALRAYA NAIDU:
DR. SUSHILA NAYAR:
SHRI S. M. KRISHNA:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that tractors allotted by the Union Government to

Jammu and Kashmir State, have been sold in the black market in Punjab;

(b) if so, whether Government have enquired into the allegations; and

(c) what action has been taken against the persons held responsible?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) No such complaint has come to the notice of Government.

(b) and (c). Do not arise.

Code of Conduct for Broadcast by State Authorities

4848. SHRI DHANDAPANI:

SHRI N. R. LASKAR:

SHRI CHENGALRAYA NAIDU:

SHRI RABI RAY:

SHRI N. SHIVAPPA:

SHRI DEVEN SEN:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have agreed and approved of a code of conduct, governing relations between the Centre and the State authorities;

(b) if so, whether Governments too have approved of this scheme; and

(c) the main features of this code of conduct?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) No, Sir. However, a Code of Conduct governing broadcasts over All India Radio has been drawn up in consultation with the States.

(b) and (c). The Code seeks to regulate the standard of broadcasts by individuals over All India Radio as also the procedure to be followed in resolving disputes as to its interpretation.

Agreement under World Food Programme to Augment supply of Processed Milk in Four Cities

4849. SHRI DHANDAPANI:

SHRI N. R. LASKAR:

SHRI SAMINATHAN:

SHRI CHENGALRAYA NAIDU:

SHRI RAGHUBIR SINGH SHASTRI:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Union Government have signed an agreement with the World Food Programme Executive Director for a $56 million dairy project for augmenting the supply of processed milk in four cities in India;

(b) if so, the main features of this agreement; and

(c) how far the project will increase the milk supply in the four cities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes.

(b) In response to a project request made by India, the World Food Programme authorities have agreed to supply, free of cost, during the next five years, in a phased programme, 1,26,000 tonnes of skimmed milk powder and 42,000 tonnes of butter oil at the international valuation of about Rs. 42 crores. These commodities, when recombined into liquid milk, will generate funds worth about Rs. 95.40 crores. These generated funds will be utilised for expanding the milk processing facilities of the four Public Sector dairies in Bombay, Calcutta, Delhi and Madras and for increasing the milk production and procurement in the rural milk shed areas of the four metropolitan cities located in ten States of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal and Union Territory of Delhi, which will be done through improved breeding, feeding and management of milch animals. As a result the indigenous production of milk in the milk-shed areas of these cities will be stepped up so that by the time the supply of imported skimmed milk

powder is tapered off, the level of supply from the dairies is sustained through increased local milk. The Project will also help in salvaging about 1 lakh high-yielding milch animals (and their calves) which are brought to the cities and pre-maturely destroyed after they go dry. Furthermore the Project will help the small farmers, the sub marginal farmers to undertake animal husbandry activities and thereby to increase their earnings through increased milk production.

(c) The milk supply in the four cities is expected to be increased from one million litres a day at present to 2.75 million litres a day at the end of the project period.

ओला-वृष्टि से प्रभावित देश के भागों में खड़ी फसल की हुई हानि

4850. **जंगेश्वर यादव :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री यशवंत सिंह कुशवाह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के जिन भागों से हाल में ओला वृष्टि के सम्बन्ध में समाचार प्राप्त हुए हैं उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उक्त ओला-वृष्टि से देश में खड़ी फसलों को अनुमानतः कितनी हानि हुई है ;

(ग) इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश से मिले समाचार का ब्यौरा क्या है तथा वहां खड़ी फसलों को अनुमानतः कितनी हानि हुई है ;

(घ) क्या यह सच है कि उक्त ओला-वृष्टि से उत्तर प्रदेश के उन्हीं भागों में तबाही हुई हैं जो कई वर्षों से सूखाग्रस्त रहे हैं ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि ओला-वृष्टि से उत्तर प्रदेश के झांसी डिवीजन में भारी तबाही हुई है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न जिलों से मिली सूचनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार क्या राहत कार्य करना चाहती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा दिल्ली के भागों में फरवरी-मार्च, 1970 के दौरान ओला-वृष्टि से रबी की खड़ी फसलों को कुछ हानि हुई है ।

(ख) हानि की ठीक मात्रा प्रदर्शित करने वाली रिपोर्टें समस्त राज्यों से प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ग) से (ङ). उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है । उस राज्य में खड़ी फसलों को हुए अनुमानित हानि का ब्यौरा और झांसी प्रभाग के विभिन्न जिलों से प्राप्त रिपोर्टें और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए जाने वाले राहत कार्यों के बारे में जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखा है कि राज्य में 18, 19 तथा 24 फरवरी, 1970 और फिर 9, 10 तथा 11 मार्च, 1970 को वर्षा हुई जिसके साथ ओला-वृष्टि भी हुई और इससे मार्च में 32 जिलों को और फरवरी में 25 जिलों को हानि हुई ।

फरवरी, 1970 में प्रभावित जिले ये थे : आगरा, बदाऊं, फरुखाबाद, एटावा, कानपुर फतहपुर, इलाहाबाद, बन्दा, हमीरपुर, झांसी जालौन, वाराणसी, जोनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, नैनीताल, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, फैजाबाद, गोन्डा और सुलतानपुर ।

मार्च, 1970 में प्रभावित जिले ये थे : बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बरेली, बदाऊं, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, फरुखाबाद, एटावा, कानपुर, फतहपुर, इलाहाबाद, बन्दा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया, अल्मोड़ा

लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खेड़ी, फैजाबाद, बहराइच और बाराबांकी ।

ओला-वृष्टि ने केवल सूखाग्रस्त जिलों को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि अन्य को भी प्रभावित किया है ।

झांसी प्रभाग को भारी हानि हुई । इस प्रभाग के जिलों में हुई हानि के और राहत कार्यों के ब्यौरे राज्य सरकार से अभी आने बाकी हैं ।

मुफ्त सहायता तथा संकट तकाबी वितरित की जा रही हैं । उन क्षत्रों में, जहां फसलों को भारी हानि हुई है, सरकारी देय की वसूली को स्थगित कर दिया गया है ।

जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में खाद्य उत्पादन में वृद्धि

4851. **श्री अगेश्वर यादव** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कोई कार्यक्रम बना रही है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने कृषि योग्य नई भूमि पर खेती करने के लिये कोई कार्यवाही की है यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितनी नई भूमि पर खेती की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि-दर प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है और यदि दर इस अवधि के दौरान जनसंख्या की अनुमानित वृद्धि-दर के दुगने से भी अधिक होगी । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृषि विकास की नई नीति के अन्तर्गत अर्थात् खाद्यान्नों की अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती, बहुफसल सघन खेती के लिए लघु सिंचाई का विकास करना, अच्छी जल प्रबन्ध पद्धतियां, उर्वरक, उन्नत बीच और कीटनाशि औषधियों जैसे आदानों की व्यवस्था करना, सांस्थनिक वित्त, सहित यथासमय और उदारता से ऋण सुविधायें प्रदान करना, प्रोत्साहान मूल्यों की सुनिश्चितता, कृषकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण और अनुसन्धान तथा विस्तार की सधनता के लिए विभिन्न विकास प्रयत्नों को बढ़ाने का विचार है । छोटे किसानों, बारानी खेती के क्षेत्रों तथा उपसीमान्त फार्मों और भूमिहीन श्रमिकों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिए जाने का भी प्रस्ताव है । इन से सम्बन्धित योजनाओं पर चौथी योजना में कुल 135 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । कुछ मुख्य कार्यक्रमों के लक्ष्यों में निम्न शामिल हैं : 250 लाख हैक्टार क्षेत्र में खाद्यान्नों की खेती का विस्तार करना, 72.0 लाख हैक्टार अतिरिक्त क्षेत्र में लघु सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, उर्वरकों की खपत को पोषकों के 55 लाख मीटरी टन के स्तर तक बढ़ाना और पौध संरक्षण उपायों को 800 लाख हैक्टार के स्तर तक बढ़ाना ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए और अधिक भूमि में खेती करने के उद्देश्य से, बेकार भूमि के सुधार और भूमिहीन कृषि श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत एक योजना के पश्चात् यह योजना वर्षानुवर्ष आधार पर ही आगे चलती रही । यह स्थिति 31 मार्च, 1969 तक की है । राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, अब यह योजना पहली एप्रैल, 1969 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई है ।

भारत के संविधान के अन्तर्गत "भूमि" राज्य का विषय है, अत: सुधारे गए क्षेत्र के बारे में आज तक की जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है । परन्तु उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1966–67 से 1968–69 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता से सुधारा गया क्षेत्र निम्न प्रकार है :

	लाख हैक्टार
1966–67 . .	1.4
1967–68 . .	0.9
1968–69 . .	0.8

मध्य प्रदेश में डाकघर

4852. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री टी० पी० शाह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969–70 में मध्य प्रदेश में जिलावार कितने नये डाकघर खोले गये हैं ;

(ख) 1970–71 में मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले में कितने-कितने नये डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ग) उनमें से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग कितने डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1969–70 के दौरान मध्य प्रदेश में जिलावार खोले गए नए डाकघरों की संख्या—

1. दमोह	कोई नहीं
2. रायसेन	1
3. सोगर	4
4. सेहोर	1
5. बिदिशा	4
6. जबलपुर	9
7. मण्डला	2
8. बालाघट	—
9. रायपुर	17
10. दुर्ग	9
11. बस्तर	5
12. इंदौर	15
13. धार	1
14. देवास	2
15. खरगोन	7
16. बिलासपुर	9
17. रायगढ़	7
18. सरगुजा	8
19. छिंदवाड़ा	2
20. सिओनी	—
21. बेतूल	4
22. छत्तरपुर	6
23. रिखा	5
24. पन्ना	6
25. सतना	4
26. सिधा	1
27. टीकमगढ़	7
28. शहडोल	2
29. होशंगाबाद	6
30. खण्डवा	4
31. नरसिंहपुर	9
32. भिण्ड	12
33. मुरेना	1
34. ग्वालियर	2
35. दतिया	4
36. गुना	—
37. शिवपुरी	3
38. उज्जन	6
39. शाजामुर	3
40. राजगढ़	5
41. झाबुआ	6
42. मंदसौर	9
43. रतलाम	9

(ख) 1970–71 के दौरान मध्य प्रदेश में जिलेवार खोले जाने वाले नए नए डाकघरों की संख्या के बारे में अभी अंतिम रूप से निर्णय करना बाकी है ।

(ग) ऊपर भाग (ख) को उत्तर को मुद्दे-नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

Khosla Committee Report on Film Censorship

4854. SHRI MUHAMMAD SHERIFF :
SHRI RAMAVATAR SHASTRI :

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have received the State Government views on the

Khosla Committee's report on film censorship and if so, the details therof;

(b) if not, the time by which it is likely to be received; and

(c) whether consultations in the matter of film kiss have been made and if so, the decisions arrived at?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) Replies from six State Governments of Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, West Bengal, Mysore, Haryana and Jammu and Kashmir have been received so far. A brief summary of their views is given in the statement laid on that Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT-3065/75*].

(b) State Governments were requested to send their views on the Khosla Committee's Report by January 7, 1970. Later the date was extended to 31st January, 1970. The defaulting State Governments were last reminded on March 13, 1970.

(c) The views of State Governments were called for on the entire Report of the Enquiry Committee on Film Censership. The Report of the Committee is still under consideration of the Central Government.

Request of Rajasthan Govenment to other States for Production of Coarse Grains

4855. SHRI N. R. LASKAR:
SHRI CHENGALRAYA NAIDU:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether State Government of Rajasthan has protested to the Centre that despite its directive to some States to produce coarse grains for supply to Rajasthan they have not cared to do so; and

(b) if so, the reaction of the Centre?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) No, Sir. No such directives are issued by the Centre.

(b) Does not arise.

आकाशवाणी, दिल्ली से प्रेस संवाददाताओं द्वारा वार्ता

4856. **श्री बृज भूषण लाल :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में अंग्रजी में समाचार प्रसारित होने के पश्चात् आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से किन विषयों पर वार्ताएं प्रसारित की गई थीं ;

(ख) उक्त वार्ता प्रस्तुत करने वाले सम्वाददाताओं तथा समाचार-पत्रों के नाम क्या हैं ;

(ग) यह निर्णय करने वाला अधिकारी कौन है कि किस संवाददाता की वार्ता प्रसारित होनी चाहिये ;

(घ) क्या यह सच है कि उक्त निर्णय करने में राजनैतिक दखल होता है ;

(ङ) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में निर्णय करने के लिये एक निष्पक्ष समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है ; और

(च) यदि नहीं, तो, इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) संभवतया माननीय सदस्य रात्रि के 9 बजे प्रसारित होने वाले अंग्रेजी समाचार बुलेटिन के बाद 'स्पाट लाइट' नाम से प्रसारित होने वाली दैनिक समाचार वार्ता के बारे में पूछ रहे हैं। इस बारे में एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT–3066/70]

(ग) कार्यक्रम देखरेख करने वाले एक उप समाचार निदेशक, समाचार सेवा निदेशक की सलाह से वार्ता का विषय तथा वार्ता का चयन करते है ।

(घ) और (ङ). जी नही ।

(च) 'स्पाट लाईट' एक ऐसा कार्यक्रम है जो आकाशवाणी के दैनिक कार्य की सीमा में आता है ।

Implementation of Recommendations of Commission of enquiry on Job Security in Oil Companies

4857. SHRI INDRAJIT GUPTA:

DR. RANEN SEN:

SHRI YOGENDRA SHARMA:

SHRI DHIRESWAR KALITA:

SHRI SAMAR GUHA:

SHRI HIMATSINGKA:

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact the Commission of Inquiry appointed by Government to go into the question of Job Security in the Oil Companies including the Refineries submitted its report in April, 1969;

(b) if so, its main recommendations; and

(c) the action taken by Government to implement the recommendations?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): (a) Yes, Sir.

(b) The Commission recommended in the main that the Government should consider—(i) whether the model agreement on rationalisation evolved by the Indian Labour Conference in 1957, should, modified as necessary to suit subsequent technological changes, be incorporated in a statute on an all-India basis; (ii) steps to protect the management/supervisory staff of the oil companies, drawing salary upto Rs. 1500 per month, by bringing it within the purivew of the Industrial Disputes Act or by separate legislation; (iii) appointment of an expert body to go into the question of automation and evolve safeguards against the adverse impact of computers; (iv) setting up of a 'Redundancy Rehabilitation Fund', confined to the oil industry, in consultation with unions and companies; (v) appointment, either under the Companies Act or special legislation, of a Director of Job Security in each of the oil companies, having overriding powers to consider every application for Early Voluntary Retirement and give his decision which would be final and binding both on the companies and the unions.

(c) Arising out of the report of the Gokhale Commission, there was a tripartite meeting on October 15, 1969. Following the exchange of views, the employers' and 'workers' representatives agreed to hold bipartite discussions on the recommendations of the Commission with a view to coming to an amicable settlement on all issues within a month, failing which to report on their differences to the Labour Ministry for a further meeting. During the period of negotiations, and till the next meeting was called, the employers also agreed to maintain 'status-quo'. The parties have since concluded their bipartite talks and reported failure. The question of further action to be taken is under Government's consideration.

Irrigation Agreement in Arid Districts of Rajasthan

4858. SHRI J. K. CHOUDHARY:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether any arrangements have been made for irrigation of the four Western and arid Districts of Rajasthan; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes, Sir.

(b) In the four western, most arid District of Rajasthan, namely, Jaisalmer, Barmer, Bikaner and Jalore, about 50 Government tubewells for irrigation have been constructed. As a result of exploratory-cum-production drilling carried out, ground water potential zones have been demarcated and further construction of tubewells for irrigation would be taken up where feasible.

Irrigation is already available to about 3100 acres from tanks in Jalore district and to about 2520 acres from the Khuddies in Barmer district. 9 schemes with irrigation potential of 6823 acres have been investigated in Jalore district. 5 schemes out of these have been taken up under famine works. 13 more schemes are under investigations in the district.

The Rajasthan Canal under construction will irrigate, on completion, 11.71 lakh acres in Bikaner district and 6.92 lakh acres in Jaisalmer district.

Average Consumption of Chemical Fertiliser per acre and per year in India as compared to Foreign Countries

4859. SHRI P. C. ADICHAN: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the average quantities of chemical fertilisers used per year, per acre of land under cultivation of high-yielding varieties of foodgrains and of other usual varieties in India as a whole and in each State separately; and

(b) how the average annual per acre consumption of chemical fertilisers in India compares with that in Pakistan, Japan, Burma, China, U.K., U.S.A. and Australia?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) and (b). Two statement showing average consumption of fertilisers (NPK) per hectare of land on all-India basis and State-wise and fertiliser consumption per hectare of arable land in various countries during 1967-68 are laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT*-3067/70].

Policy Evolved for opening Ceremonies for New Branch-Post Offices

4860. SHRI R. K. AMIN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a branch of the Ahmedabad Post Office was opened in Behrampura-Maninagar area on the 27th February, 1970 whose opening ceremony was performed by the President of Ahmedabad City Congress;

(b) whether opening of every branch office needs some ceremony at the hands of some political persons; and

(c) the details of the policy evolved by the Government for opening ceremonies of branches of the post offices?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) Bhairavnath Road Single handed TSO of Ahmedabd was inaugurated by Postmaster General, Ahmedabad. Shri Ramanlal Mathurabhai Justice of Peace presided over the function. Shri Jamuna Shankar Pandey, President City Congress who is a resident of the same locality was one of the speakers. The function was arranged by the landlord and no expenditure was incurred by the Department.

(b) No.

(c) Expenditure on such formal functions is discouraged.

Establishment of an Agricultural University in Gujarat

4861. SHRI R. K. AMIN: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an agricultural University is to be established in Gujarat State in one of its districts in the North;

(b) if so, whether the location of the University has been finally decided; and

(c) whether the Central Government are giving aid from PL-480 funds to this university?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) The Government of Gujarat have intimated that an Act (No. 13 of 1969) has been passed for establishing an Agricultural University in Gujarat with principal campus located in the district of Mehsana, Sabarkantha or Banaskantha.

(b) The location is yet to be decided finally.

(c) No, Sir.

Assessment of Needs of Seeds

4862. SHRI V. NARASIMHA RAO: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the recent All India Symposium on Improved Seed Equipment has suggested that the National Seeds Corporation should assess the needs of the seed trade in addition to

the efforts made by the industry to study the market; and

(b) if so, the broad out-lines of the steps taken in the direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes, Sir.

(b) An Industry service Cell has been set up in the National Seeds Corporation to work out the requirements of seed processing equipment in the country and intimate them to the manufacturers in the country. The Cell will also maintain contacts with the manufacturers of various seed processing equipment in the country.

वर्ष 1969 में मध्य प्रदेश में गेहूं तथा चावल का उत्पादन

4863. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में मध्य प्रदेश में गेहूं तथा चावल का कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) वर्ष 1970 में इस राज्य में इनका कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) अखिल भारतीय अंतिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 1968–69 के दौरान मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन 2007.5 हजार मीटरी टन तथा चावल का उत्पादन 3004.6 हजार मीटरी टन था ।

(ख) वर्ष 1969-70 के लिये खाद्यान्नों के उत्पादन के अखिल भारतीय तथा राज्यवार अंतिम अनुमान वर्तमान कृषि वर्ष के समाप्त होने पर, अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1970 में किसी समय, उपलब्ध होंगे ।

मध्यप्रदेश में गेहूं और चावल के अन्तर्गत कुल क्षेत्र

4864. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कुल कितनी भूमि पर गेहूं और चावल की खेती होती है ; और

(ख) मध्य प्रदेश में कितने एकड़ भूमि पर खेती नहीं की जाती है और सरकार द्वारा एकत्रित किये गये आंकड़ों के अनुसार ऐसी कितनी एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाया जा सकता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) अखिल भारतीय अन्तिम अनुमानों के आधार पर, 1968–69 की अवधि में मध्य प्रदेश में गेहूं का क्षेत्र 3055.6 हजार हैक्टार तथा चावलों का क्षेत्र 4391.2 हजार हैक्टार था ।

(ख) 1959 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त अकृष्य भूमि सर्वेक्षण और भूमि सुधार समिति ने मध्य प्रदेश राज्य में सुधार के लिए 101 हैक्टार (250 एकड़) अथवा उससे अधिक के खंडों में 1.03 लाख हैक्टार भूमि का पता लगाया था । किन्तु समिति ने अनुभव किया कि इस क्षेत्र में से केवल 0.82 लाख हैक्टार भूमि ही लाभकारी लागत पर कृषि के अन्तर्गत लायी जा सकती है । अकृष्य भमि के सर्वेक्षण और वर्गीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 1968–69 के अन्त तक 101 हैक्टार से कम के खंडों में 9.38 लाख हैक्टार अकृष्य भूमि को कृषि के योग्य पाया गया था ।

Introduction of Dry Farming Scheme

4865. SHRI SRADHAKAR SUPAKAR: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the details of the dry farming scheme to be introduced in the current year; and

(b) the areas in different States selected for the purpose of the operation of this scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) The Scheme is still in the formulation stage. However, a sum of Rs. 2.00 crores has been budgeted for the current year and steps are being taken to finalize the Scheme quickly.

(b) The selection of areas will take place after the Scheme is finalised.

Branch Post Offices in Ganguli and Damodarpur in Darbhanga, Bihar

4866. SHRI BHOGENDRA JHA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there is not a single branch post office in Balia-Ganguli and Damodarpur gram-panchayats of Beimpatti whole of Darbhanga district in Bihar;

(b) whether population of each of the panchayats is about 5000 and postal transactions justify a separate branch post office;

(c) if so whether it is proposed to open a separate branch Post Office in villages Ganguli and Damodarpur of the Panchayats without further delay; and

(d) if so, the details thereof and, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) There is a branch post office named Tisi Narsam located in village Balia of Balia-Ganguli Gram Panchayat. There is no post office in Damodarpur Gram Panchayat.

(b) to (d). Population of Balia-Ganguli Gram Panchayat is 4324 and of Damodarpur Gram Panchayat is 3611. But for opening post offices, which are not remunerative, the relevant population criterian is that of the group of villages falling within a radius of two miles. A proposal for opening of a post office in Balia-Ganguli was examined earlier and it was found that the post office would work beyond the permissible limits of loss. It could only be opened if some interested party could make good the extra loss of the proposed post office amounting to Rs. 720 for the first year as a Non-Returnable Contribution (NRC). Since this was not paid, the post office was not opened.

Proposal for opening of a post office at Damodarpur is being examined.

मेरठ में टेलीफोन एक्सचेंज भवन का प्रयोग

4867. **श्री महाराजसिंह भारती** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेरठ में वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंज भवन के कुछ कमरों को निकट भविष्य में खाली कराया जा रहा है जहां हजारों नये टेलीफोन कनेक्शन देने सम्बन्धी कार्य किया जा सकता है और अन्य टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने में कई वर्ष लगेंगे क्योंकि इस प्रयोजन के लिये अभी तक भूमि अर्जित नहीं गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कमरों का प्रयोग कर प्रसार की वर्तमान समस्या को हल करने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). मेरठ के मौजुदा टेलीफोन एक्सचेंज भवन में आगामी दो वर्षों के दौरान दो कमरे खाली करने के लिए इंतजाम किया जा रहा है। आशा है कि इन दो कमरों में 1000 लाइनों के एक्सचेंज उपस्कर लगाना संभव हो सकेगा। दूसरे स्थानों की मांगों और साज-सामान और वित्तीय साधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, इन दो कमरों में एक्सचेंज उपस्कर स्थापित करने के लिए उचित योजना तैयार की जाएगी। मेरठ में नया टेलीफोन लेने के लिए औसतन दो वर्ष के समय तक इंतजार करना पड़ता है जबकि समूचे देश में नया कनेक्शन लेने के लिए औसतन 4 वर्ष की अवधि तक इंतजार करना पड़ता है।

इन दो कमरों में अतिरिक्त क्षमता वाले उपस्कर लगाये जाएंगे वे मेरठ की दीर्घकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं

होंगे । अतः ऐसा प्रस्ताव है कि एक दूसरा मुख्य स्वचल टेलीफोन केन्द्र भवन बनाने के लिए जमीन का एक और प्लाट प्राप्त कर लिया जाए जिसमें आगे चलकर लगभग 20,000 लाइनों की क्षमता वाला एक्सचेंज लगाया जा सके ।

मेरठ–रोहटा–बिनौली के बीच सीधी टेलीफोन लाइन का निर्माण

4868. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ-रोहटा-बिनौली के बीच सीधी टेलीफोन लाइन का निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा, जिसकी मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): मेरठ-रोहटा-बिनौली सीधी टेलीफोन लाइन के निर्माण की योजना की मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है । इस कार्य के लिए प्राक्कलन की मंजूरी 1970–71 में दी जाएगी और सामग्री प्राप्त होने पर कार्य हाथ में लिया जाएगा ।

चम्बल घाटी क्षेत्र के समतलन तथा भूमि सुधार पर व्यय

4869. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** :
श्री वंश नारायण सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चम्बल घाटी क्षेत्र के समतलन तथा भूमि सुधार पर 320 रुपये प्रति एकड़ की दर से लगभग 5.25 करोड़ रुपयों का अनुमानित व्यय होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा इस क्षेत्र में पुलिस रखने पर किये जाने वाले लगभग दो वर्ष के व्यय से समस्त घाटी को समतल किया जा सकता है जिसके पश्चात् डाकुओं के गिरोह वहां छुप नहीं सकेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इन घाटियों को शीघ्र ही समतल करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) चम्बल घाटी की खो-खंड वाली भूमि को सकल रूप से समतल करना न तो आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त है और न ही भूमि उपयोग क्षमता के विचार से ही इसे ठीक समझा गया है । उथली तथा मध्यम श्रेणी की खो-खंड वाली भूमि का कृषि के लिए सुधार किया जा सकता है । जबकि गहरी खो-खंड वाली भूमि को वनारोपण और घास विकास के लिए रखना पड़ता है । चम्बल घाटी में खो-खड वाली भूमि के सुधार के लिए लागत का ठीक-ठीक पता लगाना स्थानीय खो-खंड वाली भूमि की गहराई, चौड़ाई, उतराई आदि के बिन्दु परिणाम पर निर्भर करेगा ।

(ख) और (ग). चूंकि लागत और भूमि उपयोग क्षमता की दृष्टि से खो-खंड वाली भूमि को सकल रूप से समतल नहीं किया जा सकता, अतः डाकुओं के गिरोह के गुप्त-स्थान को समाप्त करने के प्रश्न को दूसरे तरीकों से हल करना होगा । गृह मन्त्रालय इस कानून और व्यवस्था की समस्या से अवगत है ।

चम्बल घाटी विकास निगम की स्थापना

4870. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** :
श्री वंश नारायण सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार चम्बल घाटी विकास निगम स्थापित करने और समस्त घाटी को उपयोगी बनाने के लिये एक जोरदार कार्यक्रम तैयार करने का है जिससे घाटी में डाकुओं का खतरा समाप्त किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निगम की कब स्थापना की जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी नहीं।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

डाक तथा तार विभाग के सेवा निवृत्त अधिकारियों की गैर-सरकारी फर्मों में नियुक्ति

4871. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री प० मु० सईद :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री डाक तथा तार विभाग के सेवा-निवृत्त अधिकारियों की गैर-सरकारी फर्मों में नियुक्ति के बारे में 20 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 690 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): जी हां। 20 नवम्बर, 1969 को उत्तरित लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 690 के विषय में सूचना इस बीच एकत्र कर ली गई है और नीचे दी जा रही है :

(क) टाटा तथा बिड़ला उद्योगों में कोई नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हिंदी में तारों को स्वीकार न करने के कारण सरोजिनी नगर, नई दिल्ली के तारघर के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

4872. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार इस तथ्य की आकस्मिक जांच कराने का है कि हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में और विशेषकर सरोजिनी नगर, नई दिल्ली जैसी सरकारी बस्तियों में तारघरों के अधिकारी न तो हिन्दी में तार स्वीकार करते हैं और ना ही तारों को स्वीकार करने से लिखित रूप से इन्कार करते हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री श्री शेर सिंह): जब तक किसी तारघर में हिन्दी के तार बुक करने से इंकार करने के किन्हीं खास अवसरों का उल्लेख न किया जाए, हिन्दी भाषी इलाकों में और खास तौर पर नई दिल्ली की सरकारी कालोनियों में हिन्दी में तारें स्वीकार न करने के मामले के बारे में कोई भी उपयोगी जांच-कार्य संभव नहीं हो सकेगा। फिर भी, हिन्दी भाषी इलाकों के सभी डाक तार घरों को एक बार फिर ऐसी हिदायतें कर दी जाएंगी कि जिन तारघरों को हिन्दी के तार बुक करने के लिए निर्धारित किया गया है, उनमें हिन्दी में तार बुक करने के लिए पेश किये गए तारों को लेने से किसी भी हालत में इंकार न किया जाए ।

हिंदी भाषा-भाषी क्षेत्रों और पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के डाक और तार-घरों और बचत बैंकों में हिंदी का प्रयोग

4873. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों और पंजाब, गुजरात महाराष्ट्र राज्यों में स्थित डाक और तार घरों और बचत बैंकों का सब काम हिन्दी में करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब से किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) इन क्षेत्रों में डाक व तारघरों का सरकारी काम-काज दोनों भाषाओं अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में किया जा सकता है। केवल हिन्दी का ही प्रयोग करना संभव नहीं है, क्योंकि राजभाषा अधिनियम में केवल हिन्दी के प्रयोग की व्यवस्था नहीं है ।

(ख) राजभाषा अधिनियम दोनों ही भाषाओं के प्रयोग की अनुमति देता है ।

भिंड जिले (मध्य प्रदेश) में कृषक-उत्पादक सहकारी क्षेत्र में चीनी फैक्टरी की स्थापना

4874. **श्री यशवंत सिंह कुशवाह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भिण्ड जिले में सो ी मेहगांव में कृषक-उत्पादक सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत एक चीनी फैक्टरी स्थापित करने के बारे में एक ोजना भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बंध में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश के मोरेना जिले में चीनी मिल की स्थापना

4875. **श्री यशवंत सिंह कुशवाह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने ी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की स्वीकृति के बाद मध्य प्रदेश के मोरेना जिले में एक सहकारी चीनी मिल की स्थापना करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) उक्त कार्य में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० एरिंग) : (क) जी हां ।

(ख) समिति ने चीनी के कार ाने ी स्थापना करने के लिए लाइसेन्स प्राप्त कर लिया है । औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय बीमा निगम द्वारा समिति को क्रमशः 80 लाख रु० तथा 40 लाख रु० के ब्लाक पूंजी ऋण मंजूर किए गए हैं । 70 लाख रुपये की कीमत की मशीनरी कारखाने लगाने के स्थान पर पहुंच चुकी है । उम्मीद की जाती है कि सिविल कार्य का निर्माण शीघ्र ही शुरू हो जायगा और यह कारखाना अप्रैल, 1971 तक उत्पादन करने लग जायेगा ।

(ग) विलम्ब के मुख्य कारण ये हैं—ग ा उत्पादकों द्वारा अपर्याप्त अंशपूंजी अंशदान देना, राज्य में इस प्रकार की पहली प्रायोजना होना, संयंत्र तथा मशीनरी के लिए आदेश देने में विलम्ब होना तथा समिति के प्रबन्ध मंडल में बार-बार परिवर्तन किया जाना ।

भिंड, मध्य प्रदेश, में डाकघर की इमारत और टेलीफोन एक्सचेंज के निर्माण में विलम्ब

4876. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में भिण्ड जिले में डाक-घर की इमारत और टेलीफोन एक्सचेंज बनाने की एक योजना को स्वीकृति दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में विलम्ब करने और उक्त परियोजना के निर्माण को आरम्भ करने में उपेक्षा करने के क्या कारण है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां । डाकघर की इमारत के निर्माण की परियोजना की स्वीकृति 6-3-69 को और टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत के निर्माण की परियोजना की स्वीकृति 18-2-69 को दी गई थी ।

(ख) टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत का निर्माण-कार्य पूरा होने वाला है ।

डाकघर की इमारत के लिए चार बार टेंडर मंगाए गए थे परन्तु किसी ठेकेदार ने टेंडर नहीं दिया । 30-12-69 को पांचवी बार टेंडर की मांग करने पर केवल एक टेंडर प्राप्त हुआ, लेकिन इसमें दी गई रकम मंजूरशुदा रकम से बहुत ज्यादा थी । अतिरिक्त खर्च उठाने की मंजूरी 5-3-1970 को दी गई थी । इसी बीच उस ठेकेदार की भी मृत्यु हो गई

जिसने टेंडर भरा था। नए टेंडर मंगाए गए हैं और नए टेंडर आने पर काम का ठेका नए टेंडर देने वाले ठेकेदार को सौंप दिया जाएगा।

Delay in Installation of Direct Telephone Line between Bhind and Etawah

4877. SHRI YASHWANT SINGH KUSHWAH: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a scheme for the installation of a direct trunk telephone line from Bhind to Etawah has already been sanctioned; and

(b) if so, the reasons for delay in and indifference towards starting installation work on the said project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) All the items of stores have been indented. These are still awaited. The work will be taken up on receipt of stores.

खण्ड विकास अधिकारियों के पदों की समाप्ति

4878. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कुछ राज्यों में खण्ड विकास अधिकारी के पदों को समाप्त कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके कारण और विवरण क्या हैं;

(ख) क्या इन पदों को कुछ राज्यों में बहाल कर दिया गया है अथवा किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके कारण और विवरण क्या हैं; और

(ग) इन पदों के समाप्त करने का विकास कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार में उप-मंत्री श्री (डा० एरिंग) : (क) से (ग). 1 जनवरी, 1966 से केवल मध्य प्रदेश राज्य में खण्ड विकास अधिकारी का पद समाप्त किया गया था। पता चला है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय मुख्यत: इस आधार पर लिया था कि चूंकि खण्डों का अधिकांश कार्य कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित था, अत: कृषि विभाग उसे सीधे अपने तंत्र के माध्यम से कर सकता था मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने तब से राज्य में सामुदायिक विकास प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए 2-10-1969 से प्रत्येक खण्ड के लिए 'न्यूक्लियस' कर्मचारियों सहित विकास सहायकों के राजपत्रित पदों का सृजन किया है।

और अधिक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Creation of 'Sports Cell' in A. I. R.

4879. SHRI SITARAM KESRI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether a plea has been made by the Sports Federations, Sports Journalists and Broadcasters for creating a 'sports cell' within the various units of A.I.R.; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) At a meeting held on 9th March 1970 at Delhi the local representatives of National Sports Associations and sports editors had made a suggestion for creating a Sports Cell in the Directorate General, All India Radio.

(b) The suggestion is under consideration.

Discussions with Editors of Small and Medium Language Newspapers

4880. SHRI SITARAM KESRI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government had arranged a series of discussions with the Editors of Small and Medium language

Newspapers from all parts of the country during March, 1970;

(b) if so, the objective of such discussion; and

(c) the decisions taken thereat ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Press Information Bureau arranges briefings from time to time on national plans, policies and programmes for editors etc. to keep the Press and people informed. Such meetings serve a very useful purpose as informal discussions help in proper appreciation of Government policies and programmes by the Press.

चन्द्र शेखर आजाद और आचार्य नरेन्द्र देव की स्मृति में डाक-टिकट

4881. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चन्द्र शेखर आजाद, आचार्य नरेन्द्र देव तथा अन्य स्वतन्त्रता सेनानियों की स्मृति में डाक-टिकट जारी करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). 1970 में हमने 30 मार्च 1970 को स्वामी श्रद्धानन्द की स्मृति में एक डाक-टिकट जारी किया है और निम्न स्वाधीनता सेनानियों की स्मृति में दो और डाक-टिकट जारी किये जाने हैं :

1. वी० डी० सावरकर 28-5-70
2. जतीन्द्रनाथ मुखर्जी 9-9-70

आचार्य नरेन्द्र देव की स्मृति में डाक-टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। फिर भी अब इसे डाक-टिकट सलाहकार समिति के समक्ष रखा जाएगा। चन्द्र शेखर आजाद की स्मृति में डाक-टिकट जारी करने के प्रस्ताव पर डाक-टिकट सलाहकार समिति ने विचार किया था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सका।

ट्रैक्टरों तथा उनके विक्रय के लिये बिहार कृषि-उद्योग निगम को प्राप्त हुए आवेदन-पत्र

4882. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार में बहुत से किसानों ने ट्रैक्टरों को खरीदने के लिये परमिटों के लिये बहुत समय से आवेदन-पत्र भेजे हुए हैं परन्तु उन्हें ट्रैक्टर नहीं मिल सके हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) कृषि-उद्योग निगम, बिहार को गत दो वर्षों में ट्रैक्टरों के लिये प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों का ब्यौरा क्या है और उनमें से कितने आवेदनकर्ताओं को ट्रैक्टर सप्लाई किये गये हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि जो व्यक्ति पहले आवेदन-पत्र भेजते हैं उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है और जो व्यक्ति देर से आवेदन-पत्र भेजते हैं उन्हें ट्रैक्टरों की सप्लाई के लिये अधिमान दिया जाता है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस बारे में बत दो वर्षों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) और (ख). जी हां। ट्रैक्टरों के उपलब्ध न होने के कारण अभ्यावेदन अनिर्णित हैं। पहले किसान ट्रैक्टरों को नहीं चाहते थे। लेकिन अब फार्मकार्यों के तीव्र यन्त्रीकरण पर अधिक बल दिये जाने के कारण, किसानों द्वारा ट्रैक्टरों की मांग काफी बढ़ गई है। जहां तक संभव

हो ट्रैक्टरों की बढ़ती हुई मांग को पूरी करने की दृष्टि से, देशी उत्पादन बढ़ाने के अतिरिक्त काफी बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों को आयात करने का निर्णय किया गया है ।

(ग) फरवरी, 1970 तक कुल 2,076 अभ्यावेदन अनिर्णित थे । कुबोटा शक्ति चालित हलों के लिये 80 अभ्यावेदन अनिर्णित हैं । अब तक 1,436 ट्रैक्टर सप्लाई किये गये ।

(घ) और (ङ). बिहार राज्य कृषि-उद्योग निगम ने सूचना भेजी है कि अग्रता आधार में परिवर्तन नहीं किया गया है । अलाटी कृषकों को ट्रैक्टरों को लेने के लिये काफी समय दिया जाता है और यदि वे धन की कमी या अन्य कारणों से ट्रैक्टरों को निश्चित समय के अन्तर्गत नहीं ले जा पाते हैं तो सूची में उनसे नीचे वाले कृषकों को ट्रैक्टर दे दिये जाते हैं ।

पंचायत स्तरों पर कृषकों को सुविधाएं

4883. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसानों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई अनेक घोषणाओं के सिलसिले में ऐसी कोई व्यापक योजना है जिसके अनुसार उपज बढ़ाने, उसका मूल्य निश्चित करने और उसके लिये बाजार की व्यवस्था करने, ऋण, सिंचाई सुविधाएं और उर्वरक प्रदान करने के बारे में किसानों को वहीं पर साथ साथ पंचायत स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध की जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो इस व्यापक योजना का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) बिहार में ऐसी योजनाएं कहां-कहां क्रियान्वित की गई हैं अथवा किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी हां । छोटे क्षमतापूर्ण कृषकों को ऋण, उन्नत आदानों, तकनीकों और विपणन आदि की सहायता प्रदान करने के लिए, चतुर्थ योजना की अवधि में 40/45 परियोजनाओं की एक मार्गदर्शी योजना कार्यान्वित की जानी है ।

(ख) छोटे किसानों की समस्याओं पर ही पूरा ध्यान देने के लिये 40/45 जिलों में, छोटी कृषक विकास एजन्सियां स्थापित करने का प्रस्ताव है । यह एजेंन्सी छोटे कृषकों को आर्थिक सहायता और अन्य सहायता प्रदान करेगी, जिससे की कृषक अपने उत्पादन व आय में वृद्धि के लिए ऋणों, उन्नत आदानों और तकनीकों के रूप में समुचित सुविधायें प्राप्त करने के योग्य बन सकें । एजेन्सी ऐसे किसानों के लाभ के लिये विपणन और परिसंस्करण संगठनों को सुदृढ़ बनाने में भी सहायता करेगी । केन्द्रीय सरकार एजेन्सियों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिसमें कि अधिकतर हिताधिकारियों, उस क्षेत्र की सहकारी ऋण संस्थाओं और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे । चतुर्थ योजना में 45 ऐसी एजेन्सियों के लिए 67.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । अभी तक दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) पूर्णिया (बिहार) और छिंदवारा (मध्य प्रदेश) की योजनायें स्वीकार की जा चुकी हैं । अन्य राज्यों के सम्बन्ध में योजनायें राज्य सरकारों द्वारा बनाई जा रही हैं । एजेन्सियां जिला स्तर पर राज्य प्रशासन के निकट सहयोग में कार्य करेंगी ।

(ग) बिहार राज्य सरकार ने पूर्णियां और पटना जिलों में योजना की कार्यान्विति का सुझाव दिया है । पूर्णियां की योजना स्वीकृत की जा चुकी है और पटना की योजना राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही है । अन्य जिलों के सम्बन्ध में अभी योजनायें तैयार की जानी हैं ।

विभिन्न जोनों में चीनी के भिन्न-भिन्न मूल्य

4884. **श्री वंश नारायण सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के लोगों को चीनी का अधिकतम मूल्य देना पड़ेगा क्योंकि मध्य प्रदेश के लिये चीनी का मूल्य 196 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जबकि महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के लिये चीनी का मूल्य 135 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त भेदभाव के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी नहीं । यद्यपि मध्य प्रदेश के चीनी कारखानों की लेवी चीनी का निकासी मल्य सब से अधिक है, मध्य प्रदेश की चीनी कारखाने राज्य की लेवी चीनी सम्बन्धी जरूरतों का केवल थोड़ा भाग ही पूरा करती है, शेष जरूरतें अधिशेष अपेक्षाकृत कम मूल्य के क्षेत्रों में कारखानों से पूरी की जाती है । राज्य सरकार ने एकीकृत मूल्य पर चीनी वितरण करने की व्यवस्था की है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Drinking Water Supply to Villages

4885. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the number of villages, state-wise, where clean drinking water supply is easily available; and

(b) the number of villages likely to be covered in the Fourth Five-Year Plan under the scheme, State-wise?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI D. ERING). (a) and (b). The information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House.

Steps to Check Replacing of Seals of Milk Bottles Supplied at DMS Booths

4886. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of cases have come to notice where the Delhi Milk Scheme booth suppliers are found changing the seals of bottles;

(b) whether it is also a fact that these seals can be easily replaced by other seals; and

(c) if so, the measure Government propose to check such malpractice?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes.

(b) Yes, but such replacements can be easily detected.

(c) Surprise checks of milk depots are made by the Inspection staff and the suspected bottles are removed for testing by the Quality Control Laboratory of the Scheme. The agencies of the depot Agents are terminated if tampering of seals of milk bottles or adulteration is established.

Cut in water supply to all establishments of Posts and Telegraphs Department in Goa

4887. SHRI RABI RAY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Public Works Department of Goa cut off water supply to all posts and Telegraphs establishments for non-payment of water bills;

(b) if so, whether it is also a fact that this has been done in retaliation to the cutting off telephone connections of Government establishments; and

(c) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) Water supply to Wireless quarters at

Bambolim was abruptly cut off on 5-3-70. Similarly water supply to Panaji H.P.O. and Postal Divisional Office was cut off on 6-3-1970. The supply was restored on 7 & 10-3-70 respectively. No payment of water bills was outstanding.

(b) The measure may have been retaliatory on account of disconnection of telephones due to non-payment of bills by the Goa P.W.D.

(c) The matter figured in the Goa Assembly wherein the C.W.D. Minister stated that water supply was cut off due to non-payment of some water bills. Further details are awaited from the State Government.

Advice to Unemployed Youth to take up Trade Union Work

4888. SHRI RABI RAY: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that he advised the unemployed youth to take to trade union work in course of a speech delivered at a meeting of journalists at Hyderabad on the 7th March, 1970;

(b) if so, whether he discussed with the Planning Commission about the assistance to be given to such people; and

(c) what steps Government have taken to implement his scheme into action and the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): (a) While dealing with various aspects of labour policy and programmes I stated that it would be a good thing if some of the highly educated unemployed youth, like engineers and agricultural graduates, could take up trade union work among agricultural labour.

(b) and (c). The matter has not yet been discussed with the Planning Commission and there is no specific scheme on this subject at present.

1969–70 में राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गला-सड़ा खाद्यान्न

4889. **श्री मीठालाल मीना** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान और भारतीय खाद्य निगम के अधीन विभिन्न खाद्यान्नों के भंडार में से 1969–70 में कितना खाद्यान्न खराब हो गया था और मानव उपभोग के लिये योग्य नहीं था ;

(ख) उसके खराब हो जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार खाद्यान्नों को खराब होने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) लगभग 12 मीटरी टन चना और 190 किलो चने की दाल क्षतिग्रस्त हुई थी।

(ख) निभारों की पर्याप्त व्यवस्था होने के बावजूद भी किराये के गोदामों में सीलन और भूमिगत पानी के बढ़ने के कारण।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने किराय के गोदामों में खाद्यान्नों की ऐसी क्षति रोकने हेतु और अधिक सतकर्ता बरतने के लिए उपाय किए हैं।

Malpractices of Ration Shops in Delhi

4890. SHRI S. K. TAPURIAH: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it has come to the notice of Government that many ration shopkeepers in Delhi are indulging in malpractices and are not giving to the cardholders their due quota of superior quality wheat and rice and they have to buy to that from the open market at a higher price; and

(b) whether it is also a fact that about 2,00,000 of these card-holders have not renewed their cards so far ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Some complaints about a few fair price shopkeepers indulging in malpractices were received by the Delhi Administration. Intensive checking of fair price shops was undertaken and action was taken to ensure that such malpractices are not repeated.

(b) No, Sir. Only 68,000 cards were not presented for renewal.

Problem of Residential Accommodation of P & T Staff at Jamshedpur

4891. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the total number of employees working in P & T Department at Jamshedpur;

(b) the total number of P & T employees who have been provided with the quarters and other residential facilities at Jamshedpur;

(c) the total number of quarters proposed to be constructed during 1970-72;

(d) whether it is a fact that even rented accommodation is not available for P & T employees, because entire houses at Jamshedpur belong to Tatas and they do not give their houses on rent to P & T employees; and

(e) the arrangements proposed to be made by the Government keeping in view peculiar circumstances there to provide residential acccommodation for the P & T employees by pressing Tatas to provide them accommodation for messing purposes so that they may not be compelled to live in the street?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) 594.

(b) 110.

(c) Estimates have at present been sanctioned for:—Type II (a) quarters 12 Nos.

Type I quarters 12 Nos. for further provision, the case is to be examined.

(d) No. It is not correct that the entire houses belong to Tatas. There are houses of private persons in the town.

(e) The Department has so far provided 75 residential quarters of its own. The rest of the 33 quarters allotted have been taken on rent from different industrial concerns in the area. Tata authorities have been requested from time to time to arrange accommodation for the P & T staff and they have given some quarters. Two quarters are being utilised by employees as Mess. Tatas have expressed inability for providing more quarters immediately.

आकाशवाणी के चौकीदारों के लिये काम के समान घण्टे

4892. **श्री रामावगार शास्त्री** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विभिन्न स्टेशनों में कुल कितने चौकीदार हैं ;

(ख) उन्हें प्रति दिन कितने घंटे काम करने को कहा जाता है तथा नियमों के अन्तर्गत उनके निर्धारित काम के घंटे कितने हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि पटना तथा कुछ अन्य केन्द्रों पर चौकीदारों को 12 घन्टे काम करना पड़ता है, जब कि कुछ अन्य केन्द्रों पर वे केवल 8 घण्टे काम करते हैं ;

(घ) यदि हां, तो इस भेद भाव के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार सब केन्द्रों के चौकीदारों के लिये काम करने के समान घंटे नियत करने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) 319.

(ख) चौकीदारों के रोज के काम करने के घण्टे प्रत्येक स्थानीय कार्यालय में उनको आवश्यकताओं के अनुसार 8 घण्टे से लेकर 12 घण्टे तक अलग अलग हैं ।

(ग) और (घ). जी हां । प्रत्येक केन्द्र की आवश्यकताओं अलग अलग हैं तथा सम्बन्धित चौकीदारों को आवश्यकतानुसार काम पर लगाया जाता है ।

(ङ) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

Telephone Bills outstanding against firms/persons in Bihar

4893. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the names of persons/firms against whom telephone dues are outstanding amounting to Rs. 1,000 and above and the actions proposed to be taken or taken against all such persons/firms to realise the telephone dues by the Government; and

(b) the telephone numbers working in the names of persons/firms against whom telephone dues are pending exceeding one thousand rupees as on the 1st January, 1970 and the reasons for allowing such telephones to be in service?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) and (b). The information in respect of names of persons/firms against whom telephone dues are outstanding amounting to Rs. 1000 and above is not readily available. This will be collected and will be placed on the Table of the Lok Sabha. However, instructions have been issued for prompt disconnection of telephones of defaulting subscribers. The outstanding bills are pursued with the parties concerned and legal action is taken, where necessary.

Voice of America Broadcast in Tamil Language

4894. DR. SUSHILA NAYAR:
SHRI S. M. KRISHNA:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Voice of America have decided to end Broadcasts in Tamil language from the month of May, 1970;

(b) if so, the reasons thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) Yes, Sir.

(b) It is understood that the decision has been taken on budgetary grounds.

(c) Government have nothing to say in the matter.

Financial Assistance to U. P. of Taking Over Sugar Mills

4895. SHRI S. M. BANERJEE: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Uttar Pradesh Government has taken over certain Sugar Mills in Uttar Pradesh;

(b) if so, what financial assistance has been given to Uttar Pradesh Government; and

(c) what was the demand of Uttar Pradesh Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) The Government of Uttar Pradesh have attached certain sugar mills against which there were substantial arrears of cane price, cess/purchase tax, commission and interest in respect of previous years and to appoint Official Receivers for their management.

(b) and (c). No financial assistance was demanded by the Uttar Pradesh Government nor has any been given.

Non-acceptance of Money Orders at Sangjamai and Imphal Bazar Post Office

4896. SHRI M. MEGHACHANDRA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether two Post Offices at Sangjamai and Imphal Bazar have recently stopped accepting Money Orders;

(b) if so, the reasons for their not accepting the money orders;

(c) in view of the Imphal Bazar Post Office being situated just near the Police Station why at all, the Post Office at Imphal Bazar did not accept the Money Orders; and

(d) how long this state of things continued in the two aforesaid post offices?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) Yes. Acceptance of money orders was stopped from 20th February 1969 in the two post offices but the work has been resumed on 27th February 1969 at the Imphal Bazar H.O.

(b) An armed robbery took place at Imphal in November 1968 involving post office cash while being carried to the local treasury and another dacoity took place at Imphal Bazar Post Office on 18th February 1969. The situation became tense all over Imphal town. The work of booking of money orders was, therefore, suspend at Imphal Bazar and Sangjamai Town Sub-Post Offices as a security measures in consultation with the Manipur Administration.

(c) The situation was not considered safe in view of the occurrence of a dacoity at Imphal Bazar P. O. on 18th February 1969.

(d) While the booking of money orders at Imphal bazar post office was resumed soon afterwards on armed police guards being posted, the booking of money orders at Sangjamai Bazar post office has not been restored so far as the Manipur Administration have still not been able to provide armed police guards at this office. However, the Postmaster General, Assam Circle has been directed to review the position once against in consultation with the Manipur Administration.

Contractor-Labour Dispute in Manipur

4897. SHRI M. MEGHACHANDRA : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether a group of local workers engaged in earth work of the construction of the Transmitter Station at Mayang Imphal for All India Radio, Imphal applied to the Labour Commissioner Manipur that their wages for the earth work done have not been paid by the contractor;

(b) whether the Labour Commissioner has given a compromise decision for payment of an agreed amount to the worker and also asked the P.W.D. authorities, Manipur for deducting the said amount of Rs. 5,000 from the bill of the contractor for necessary payment to the workers;

(c) if so, the present position thereto; and

(d) whether the work of construction is being completed?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA) : (a) and (b), Yes.

(c) The concerned workers have since received payment of the amount from the contractors and therefore the Government have not withheld payment of the bill to contractors.

(d) The construction work is in progress.

Post Office opened in Manipur during 1969-70

4898. SHRI M. MEGHACHANDRA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of new post offices opened in the Union Territory of Manipur during 1969-70;

(b) the total number of Post Offices functioning in Manipur till date;

(c) whether the location of Post Offices for Lilong and Sajing village is a matter of dispute; and

(d) if so, whether two Post Offices are being opened in both the two bazars?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATIONS AND BROADCASTING, AND THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH) : (a) 10.

(b) 235 as on 26-3-70.

(c) and (d) Lilong Post Office after upgradation to a departmental Sub-Post Office was shifted to a new building which is at a distance of one furlong from the previous location of the extra departmental branch Post Office. Certain parties have represented that the new location of the Post Office is in Chajing and not in Lilong proper. The Deputy Commissioner, Manipur, however, considers the location of the departmental sub-Post Office to be in Lilong proper. In view of the opinion of the District Authorities and the distance between the new location and the old location being one furlong, it is not proposed to open another Post Office at the previous location of the Post Office.

Distribution of Fertilizer to Farmers in Manipur

4899. SHRI M. MEGHACHANDRA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the amount of fertilizer distributed to the farmers of Manipur during 1969;

(b) the latest figure of undistributed fertilizer stock as in the month of January, 1970 and the agencies holding the stock;

(c) the amount of fertilizer proposed to be distributed during the year 1970; and

(d) the comparative rate for fertilizer distributed in the year 1969 and the current year 1970 per kg. and the agencies entrusted with distributing or selling the fertilizer for the current year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) The following quantities of fertilisers in terms of N.P. and K have been distributed:

Nitrogen	459 tonnes
P_2O_5	57 ,,
K_2O	5 ,,

(b) The Co-operative Marketing Society Ltd. and its sub-agents were holding the following stock of fertilisers in terms of N.P. & K:—

Nitrogen	1089 tonnes
P_2O_5	230 ,,
K_2O	14 ,,

(c) The following quantities of fertilisers in terms of N. P. & K are to be distributed during the year 1970 :—

Nitrogen	708 tonnes
P_2O_5	110 ,,
K_2O	24 ,,

(d) The comparative rates for fertiliser distributed in the years 1969 and 1970 are as under :—

	1969 Rs.	1970 Rs.
Urea	0·86 per kg.	0·83 per kg.
Superphosphate	0·32 ,, ,,	0·40 ,, ,,
Di-Ammonium Phosphate	1·09 ,, ,,	0·93 ,, ,,
Muriate of Potash	0·48 ,, ,,	0·53 ,, ,,

The fertiliser is being distributed through thirty-three sub-agents in the current year.

Resentment of Students against Illequipped Department of Agricultural Engineering of Orissa University of Agriculture and Technology

4900. SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the comments on the status of agricultural universities in the country made in the "Times of India" of 22nd January, 1970, under the caption, "Waste of Time";

(b) whether it is a fact that the Orissa University of Agriculture and Technology, especially the Department of Agricultural Engineering, is hopelessly under-equipped in terms of laboratories, staff facilities, etc.;

(c) whether it is also a fact that some students have written to the Vice-Chancellor of the said University demanding compensation for the years that they wasted in the University; and

(d) whether Government of India has a concurrent responsibility on such matters and if so, the steps taken by Government to discharge the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) The Ministry is aware of the comments pertaining to Orissa University of Agricultural Sciences and Technology, Bhubaneswar.

(b) A team of experts recently set up by the Indian Council of Agricultural Research has been asked to report on the condition of the Agricultural Engineering College. A definite reply could be given on the basis of this report.

(c) Yes.

(d) The Agricultural University is an autonomous body and functions in accordance with the provisions of the Orissa University of Agriculture and Technology Act, 1965. Government of India do not have concurrent responsibility in the management of the University. A representative of the ICAR is on the Board of Management and Government of India provide financial assistance for devlopment of certain facilities on the recommendations of the team of experts constituted for this purpose.

Implementation of Recommendations of Sub-Committees of E.P.F. Organisation on various Problems

4901. SHRI SHASHI BHUSHAN: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the number of sub-committee formed to examine the various problems i.e. coverage, recruitment and building pertaining to the Employees Provident Fund Organisation;

(b) if so, whether the recommendations of the Sub-Committees have been implemented;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the total amount of expenditure incurred on these sub-committees?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): The administration of the Employees' Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees. The Provident Fund authorities have reported as under:—

(a) to (c). Three Sub-Committees, viz., Recruitment Sub-Committee, Coverage Sub-Committee and Building Sub-Committee were formed to advise the Central Board of Trustees. The Recruitment Sub-Committee and the Coverage Sub-Committee have already submitted their reports and have since ceased to exist. The recommendations of these Sub-Committees as approved by the Central Board of Trustees/Central Government are being implemented. The Building Sub-Committee is in the nature of a Standing Committee which scrutinises proposals for construction work in the Organisation. The recommendations of the Building Sub-Committee are implemented as and when approved by the Board/Central Government.

(d) Rs. 5,835.00.

Misuse of Position by Members of Central Board of Trustees of E.P.F., to Evade Recovery of P. F. Dues

4902. SHRI SHASHI BHUSHAN: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some of the Employers' representatives on the Central Board of Trustees of employees Provident Fund are Chairmen

or Directors of major defaulting establishments which have been successfully dodging the recovery of Provident Fund dues by the Employees' Provident Fund authorites;

(b) if so, whether it does not reflect that they have misutilised their position as a member of the Board of Trustees in evading the coercive process of law for recovery of dues;

(c) if so, the particulars of such establishments, the amount of Provident Fund in default and the period for which they have been successfully evading payment; and

(d) the reasons for allowing them to continue as members of the Board and the action Government propose to take in this matter?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA) : (a) to (c). The administration of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 is the concern of the Central Board of Trustees constituted under the Employees' Provident Funds Act, 1952 and is not the concern of the Government of India. A Statement containing the information furnished by the provident fund authorities is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-3068/70.]

(d) Non-official members of the Board of Trustees represent the Central Organisations of employers and workers and are not appointed on the Board of Trustees in their personal or individual capacity. Hence, except when they cease to represent the Organisations concerned or are disqualified under Para 8 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, the question of replacing them does not arise.

Subsidised Accommodation to E. P. F. Organisation Employees and Alleged Discrimination in Allotment

4903. SHRI SHASHI BHUSHAN: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether pending construction of Staff Quarters for Employees Provident Fund Organisation at Delhi the eligible ministerial staff members were not given the facility of subsidised accommodation as decided by the Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund, the executive authority of the Organisation, as far back as in 1963;

(b) whether Board's decision of 1963 applied equally to gazetted and non-gazetted staff of the E. P. F. Organisation; and

(c) if so, the reasons for discriminatory treatment in granting the facility of the subsidised Housing accommodation only to gazetted staff and not to Ministerial Staff?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): The administration of the Employees' Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees. The Provident Fund authorities have reported as under:—

(a) In pursuance of the Board's decision, residential accommodation was actually hired only in cases presenting exceptional circumstances and for some key personnel (including non-gazetted staff) who are on deputation or are liable to transfer in the normal course. The matter is being re-examined in the context of the 5% additional House Rent Allowance subsequently allowed to the employees of the Organisation stationed at Delhi, Calcutta, Bombay and Madras.

(b) Yes.

(c) Does not arise.

Supply of Uniforms and Sandals to Class IV Employees of Bombay General Post Office

4905. SHRI M. L. SONDHI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the Bombay General Post Office about 100 class IV employees were getting uniforms and sandals from Government but this supply was terminated in 1965 on some pretext;

(b) whether several representations have been received from these low paid Bombay General Post Office employees known as "Mazdoors" and have been the subject of protracted correspondance between Bombay General Post Office and the D. G. P. T. New Delhi; and

(c) whether Government propose to take steps to remove the genuine grievance of the "Mazdoors" and sanction the supply of Uniforms and Sandals without further delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) Yes. Under the Departmental rules Mazdoors on Postal side are not eligible for supply of uniforms, but in Bombay G. P. O. the supply was made by local authorities irregularly. This has been stopped.

(b) and (c). It is true that several representations have been received in this connection. The proposal for supply of uniforms to Mazdoors is linked up with the general question of supply of uniforms to excluded categories *i.e.* the categories of staff, who are not eligible for supply of uniforms at present, and which is under consideration of a Committee of the National Council of the Joint Consultative Machinery.

Restrictions on Cultural Horizon of AIR Listeners

4906. SHRI M. L. SONDHI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that literary achievements of person of Indian origin abroad are in several cases of very high order;

(b) whether there is any ban on literature, written by person of Indian origin, residing abroad, who may not be Indian nationals, being broadcast on All India Radio network;

(c) whether Government proposed to restrict the cultural horizon of AIR listeners by rejecting literary material of high merit sent by writers of Indian origin domiciled abroad; and

(d) if not, whether Government will direct the External Services Division of All India Radio to keep an open mind when considering literary materials received from writers of merit among persons of Indian origin abroad, especially from Africa in accordance with UNESCO philosophy of inter-cultural and inter-racial understanding?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Plan for New Building of Bombay General Post Office

4907. SHRI M. L. SONDHI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Bombay G. P. O. Building is not safe in view of the dilapidated condition and taking into account the collapse of a portion of it during the month of February, 1970;

(b) why Government continues to endanger the lives of 3000 officials working in the Bombay G. P. O. in spite of the clear technical advice that the General Post Office building is unfit for use in the present condition;

(c) the steps Government propose to take to ensure the safety of the men and women working in the Bombay G. P. O. and the general public; and

(d) when Government intends to start work on a new building for the G. P. O.; and the date when the plans for the new building were approved and the reasons for the delay in starting work?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) to (c). About 200 sq. of the roof of the varandah on the second floor of the West Wing of the GPO Building collapsed on 22-1-70. When gunniting work of this roof was being carried out. Load tests in respect of the portions of the roof which have been gunnited recently are being arranged to be carried out to ascertain the safety of such roofs. It has, however, been found that the roof and floor slabs require immediate replacement. Resorting to this instead of whole sale dismantlement and construction of a new

building has been found advisable because of the following reasons:—

1. Since the walls of the building are sound replacement of floor and roof slabs will prolong the life of he building.

2. Difficulties of obtaining a suitable building on rent can be obviated and only small portions of the building will be replaced by moving sections of office to alternate accommodation for short periods.

3. Wholesale reconstruction of the building will not yield any additional accommodation because of the floor area coverage restrictions.

The Postmaster General has taken action to reduce the load on such floors to bring it within the safety limits.

Action is already in progress to make necessary arrangements in case any of the sections of the GPO have to be shifted somewhere else, during the replacement work.

(d) Plans for the new building in the compound of Bombay GPO have been approved by Bombay Municipal Corporation only in December, 1969. Subsequent work of preparation of further detailed drawings is in progress and the work is likely to start during the current financial year.

Milk supplied by Delhi Milk Scheme and Establishment of more Booths in New Delhi

4908. SHRI N. SHIVAPPA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the number of persons drawing milk in Delhi and New Delhi through the Delhi Milk Scheme Depots; and

(b) the number of booths Government are going to establish in New Delhi?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) 3,52,650 milk tokens have been issued by the Delhi Milk Scheme as on 15-3-70.

(b) In addition to 514 milk booths already established, of which 161 are in New Delhi area, the Delhi Milk Scheme has selected additional sites for 62 milk booths of which 40 are located in New Delhi area.

Legal Power to Village Panchayats for Recognising Trade Unions

4909. SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the village panchayats are going to be given the legal power for recognizing the agriculture trade unions as recommended by the National Commission on Labour;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI D. ERING): (a) No, Sir. The National Commission on Labour have not made any such recommendation.

(b) and (c). Do not arise.

New Policy for Cooperatives

4910. SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in view of the failure of the Cooperatives Government are planning to formulate any new policy for the Cooperatives;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI D. ERING): (a) to (c). A statement is placed on the Table of the House.

Statement

It is not correct to say that the cooperative movement has failed. The recent report of the All-India Rural Credit Review Committee set up by the Reserve Bank of India under the Chairmanship of Shri B. Venkatappiah which went into the whole question of rural

credit refers to the impressive and striking progress in expansion of cooperative credit. Short and medium-term credit advanced by co-operatives has increased from Rs. 202 crores in 1960-61 to Rs. 486 crores in 1968-69. Long-term credit provided by the land development bank has increased from Rs. 11.62 crores in 1960-61 to Rs. 129 crores in 1968-69. However, there are dificiencies like uneven development of the movement, existence of weak units and inadequacies in flow of credit. Some of these are related to organisational and structural weaknesses in the cooperative movement and some to external factors like the economic backwardness of the region.

Committees had been set up and studies undertaken from time to time in the past regarding the problems faced by the cooperative movement. Suggestions had been made and guidelines had been indicated to the State Governments for correcting the structural imbalances and organisational deficiencies. They relate to re-organisation of primary credit societies to form viable units at the base, rehabilitation of weak central banks, re-orientation of loaning policies and procedures and building up of competent and trained personnel to man the institutions. The States and the cooperatives have initiated action on these measures, though the progress is slow. The Rural Credit Review Committee has also observed that "there is greater need for full implementation of the policies which have already been agreed upon in principle rather than for formulation and adoption of new policies".

A Central Act has been passed to facilitate the setting up of agricultural credit corporations in States where the cooperative movement is weak. These corporations are meant to supplement cooperative credit. A scheme of direct financing of primary credit societies by commercial banks in areas where central banks are weak is also being tried as an experimental measure in five States. New institutional agencies like the Small Farmers Development Agency and an analogous one for the sub-marginal and landless labourers are also being set up. These agencies would utilise the existing co-operative structure in their areas of operation.

Appreciable progress had also been recorded by cooperatives in other spheres of activity like marketing, processing, agricultural supplies and consumer trade. The value of agricultural produce handled by the co-operative marketing and processing societies increased from Rs. 179 crores in 1960-61 to Rs. 583 crores in 1968-69. The co-operative sugar factories account for more than 1/3rd of the total sugar production in the country, as against 14.8% in 1960-61. The cotton processing units and rice mills also handled substantial portion of the cotton and paddy produced in the country. The value of agricultural inputs distributed by the cooperatives rose from about Rs. 34 crores in 1960-61 to over Rs. 250 crores in 1968-69. The cooperatives now account for nearly 60% of the total value of fertilizers distributed in the country. Storage capacity owned by co-operatives has increased from 0.8 million tonnes in 1960-61 to 2.6 million tonnes in 1968-69. Over the same period, the value of retail consumer trade undertaken by co-operatives in rural areas rose from Rs. 17 crores to Rs. 226 crores. The corresponding figures for turnover in urban areas in 1960-61 and 1968-69 are Rs. 40 crores and Rs. 280 crores respectively. In these spheres of cooperative activity also, emphasis has been laid on consolidation and strengthening of the existing structure rather than an organisation of new units and societies. Adoption of commercial practices, employment of trained and competent personnel, strengthening of technical know-how and attention to economic viability have been stressed as the basic criteria for building up a sound structure.

The Conference of Chief Ministers and Ministers incharge of Cooperation held in June, 1968, recommended certain measures for curbing the growth of vested interests in cooperatives. The Governments of Maharashtra, Kerala, Punjab, Orissa and U.P. have already incorporated certain amendments in the cooperative laws of the States in pursuance of these recommendations. Certain other States have appointed committees to consider comprehensive amendments to the State Cooperative laws, while in some other States amendments are under consideration.

Introduction of Indian Journalistic Service

4911. SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are planning to introduce the

Indian Journalistic Services (I.J.S.) for objective journalistic work in the country;

(b) if so, when; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Newspapers being in the private sector, it is neither necessary nor advisable for Government to introduce any service for manning posts in newspaper establishments.

Cases pending with Tribunals appointed by Government

4913. SHRI DEVEN SEN: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the number of cases pending with Tribunals, appointed by the Central Government as on the 31st January, 1970; and

(b) the number of cases disposed of by each of them in 1969?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): (a) Adjudication cases 301 and applications 2069.

(b) A statement is placed on the Table of the House.

Statement

S. No.	Name of the Tribunal	No. of cases/applications disposed of	
		cases	applications
1.	Central Government Industrial Tribunal-*cum*-Labour Court No. 1, Bombay.	19	437
2.	Central Government Industrial Tribunal-*cum*-Labour Court No. 2, Bombay.	23	265
3.	Central Government Industrial Tribunal-*cum*-Labour Court No. 1, Dhanbad.	16	58
4.	Central Government Industrial Tribunal-*cum*-Labour Court No. 2, Dhanbad.	50	560
5.	Central Government Industrial Tribunal-*cum*-Labour Court No. 3, Dhanbad.	81	1
6.	Central Government Industrial Tribunal-*cum*-Labour Court, Calcutta.	98	135
7.	Central Government Industrial Tribunal-*cum*-Labour Court, Jabalpur.	47	896
8.	National Industrial Tribunal, Dhanbad.	9	52
9.	National Industrial Tribunal, Calcutta.	2	36
10.	National Industrial Tribunal, New Delhi.		—
	TOTAL	345	2440

Disparity in the Project Allowance etc. paid to P. & T. Staff at Dakpathar in U.P.

4914. SHRI DEORAO PATIL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the P. & T. staff posted at Dakpathar in Uttar Pradesh Circle is paid project allowance at a rate much lower than that paid to the State Government's staff; if so, the reasons for the difference between the two rates;

(b) whether it is also a fact that the P. & T. Staff have to pay rent @10 per cent of their salary p.m. for accommodation; if so, the reasons for this disparity;

(c) whether it is also a fact that the children of P. & T. staff have to pay for transport for going to school @ Rs. 10 p.m. per head while the children of the staff of the State Government get free transport; if so, the reasons therefor; and

(d) the steps which Government propose to take to remove these disparities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the Table of the House shortly.

Reduction in Licence Fee for Domestic Radios

4915. SHRI N. R. DEOGHARE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to reduce the Radio Licence fee for the domestic radios in view of a big increase in the number of radio sets in the country and also lot of income being derived from the Commercial services on Vividh Bharati;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Radio licence fee is the main source of income of A.I.R. It is at present just sufficient to meet the recurring expenditure. A reduction in licence fee for domestic sets will affect its revenues substantially.

Applications pending for Telephone Connection in Gwalior

4916. SHRI RAM AVTAR SHARMA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of telephone connections working at present in Gwalior;

(b) the number of applications pending for fresh telephone connections;

(c) the rate of demand and supply per month of telephone connections; and

(d) the steps Government propose to take to reduce the number of applicants on the waiting list?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) 2,447.

(b) 93.

(c) Average demand per month ...33

Average number of phones installed per month 30

(d) Compared to other stations in the country the position of Gwalior in respect of telephones is much better. There is, however, a programme to expand the existing capacity by 200 lines and later to replace the entire system by 4000 lines crossbar exchange.

अभ्रक उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड

4917. श्री मधु लिमये : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक श्रमिकों की मजदूरी निर्धारित करने के लिए सरकार का विचार

अभ्रक उद्योग के लिए एक मजूरी बोर्ड गठित करने का है, जैसा कि अन्य उद्योगों के बारे में किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) बिहार, आन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों में अभ्रक श्रमिकों की पृथक-पृथक न्यूनतम तथा अधिकतम मजूरी कितनी है ;

(घ) क्या अन्य खनन उद्योगों की तुलना में यह बहुत कम नहीं है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस के वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). जी नहीं। राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर निर्णय होने तक, कोई भी नया मजूरी बोर्ड स्थापित करने का विचार नहीं है।

(ग) उपलब्ध सूचना भारतीय श्रम आंकड़े 1969, प्रकाशन की तालिका संख्या 4.10 (पृष्ठ 88–89) में दीगई है।

(घ) और (ङ). अभ्रक व्यवसायों का रोजगार न्यूनतम मजरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आता है और जहां कहीं आवश्यक हो वहां संबंधित सरकारें मजूरी-दरों का पुनरीक्षण तथा उनमें संशोधन कर सकती हैं।

Hindi Programmes over A.I.R., Madras

4918. SHRI YAJNA DATT SHASTRI:
SHRI JAI SINGH:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no provision for Hindi Programmes at Madras Station of the All India Radio;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) what Government is doing to make such a provision;

(d) if not, how much time is allotted to Hindi programmes; and

(e) which of the Fundamental Rights are considered to be inappropriate by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

(d) Hindi programmes are broadcast from Madras Station twice a month on alternate Mondays for a duration of 15 minutes each in its primary service in addition to daily broadcast of the main Hindi news bulletins. The bulk of the programmes of the Vividh Bharati Service broadcast from Madras is also in Hindi.

(e) Does not arise.

Closure of Fair Price Shop in Andrews Ganj, New Delhi

4919. SHRI VALMIKI CHOUDHURI:
SHRI SHARDA NAND:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that out of two, one Fair Price Shop in Andrews Ganj, New Delhi, where rationed articles were sold to residents, has been closed;

(b) whether it is also a fact that the closure of the Fair Price Shop has caused a great deal of inconvenience to about 1500 card holders who were drawing rations from this shop; and

(c) if so, what steps are being taken to reopen another Fair Price Shop in the Andrews Ganj colony?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes, Sir. One shopkeeper has resigned recently.

(b) and (c). In order to avoid any inconvenience facilities have been given to cardholders to register themselves anew with the other fair price shops in the neighbourhood. Efforts are also being made to find a substitute.

Establishment of ground station for satellite in North India

4920. SHRI D. N. PATODIA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that ground station to link the satellite is going to be stationed in North India; and

(b) if so, whether any decision about the site of the ground station has also been taken and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) A proposal to set up a Ground Station in the Northern region to work with the Indian Ocean Satellite is under consideration.

(b) Not yet.

डॉ० भगवान दास स्मारक श्रद्धांजलि समारोह समिति, नई दिल्ली को राशन की सप्लाई

4921. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह डा० भगवान दास स्मारक श्रद्धांजलि समारोह समिति 2 एफ० लाजपत नगर, नई दिल्ली-24 के उपप्रधान हैं ; और

(ख) राशन परमिट के इस्तेमाल में, जिसे रद्द कर दिया गया है, उक्त न्यास द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण उस के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी नहीं । मन्त्री (खाद्य तथा कृषि) ऐसी किसी समिति के सदस्य नहीं हैं । तथापि, वे डा० भगवान दास जन्म शताब्दी समारोह प्रायोजित समिति की केन्द्रीय कार्यकारी परिषद के 7 उपाध्यक्षों में एक हैं ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट के विरुद्ध आरोपों की जांच की थी । निष्कर्षों का स्वरूप ऐसा नहीं था जिससे ट्रस्ट के विरुद्ध अभियोग का मामला सिद्ध हो सके ।

डाक तथा तार विभाग में टेलीग्राफिस्टों की वरीयता में परिवर्तन

4922. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री 18 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 4486 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार महानिदेशक के पत्र संख्या 253-1/57-एस०टी०बी० दिनांक 19 सितम्बर, 1957 तथा पत्र संख्या 253-9/64 एस०डी०बी० दिनांक 22 अप्रैल, 1965 के जारी होने के बाद आज तक टेलीग्राफिस्टों की वरीयता में पांच बार परिवर्तन किया गया है; और उनकी वरीयता गलत निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक बार निर्धारित की गई वरीयता सूची में बार-बार परिवर्तन करना सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है ;

(ग) यदि हां, तो उन टेलीग्राफिस्टों के नाम तथा पते क्या हैं जो उक्त नियमों द्वारा प्रभावित हुए हैं ; और

(घ) उनकी वरीयता सूची में बार-बार परिवर्तन करने का क्या औचित्य है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :(क) जी नहीं । महानिदेशक डाकतार के तारीख 19 सितम्बर, 1957 के पत्र सं० 253/1/57-एस०टी०बी० के अधीन टेलीग्राफिस्टों की वरीयता के बारे में आदेश जारी किये जाने के पश्चात् उसके बाद जारी किये गए आदेशों में केवल 19-9-57 से पहले की स्थिति स्पष्ट की गई थी । तारीख 28-2-1963 के पत्र सं० 1-28/60-एन०सी०जी० के अधीन जारी किये गए आदेशों में उस तरीके का स्पष्टीकरण किया गया है जिसके अनुसार यह मंत्रालय के कार्यालय

ज्ञापन सं० 9/4/55-आर०पी०एस० तारीख 22-12-1969 (जिसमें सेवाओं में वरीयता निश्चित करने के बारे में सामान्य सिद्धान्त बताए गए हैं) को 22-12-59 से पहले भर्ती किये गए टेलीग्राफिस्टों पर लागू किया जाना चाहिए ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सूचना एकत्रित की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) सरकार द्वारा निर्धारित किये गए वरीयता के सामान्य सिद्धान्त 22-12-59 के बाद भर्ती किये गए सभी संवर्गों पर लागू किये जाने थे ।

Loss due to Storage of Foodgrains

4923. SHRI N. R. DEOGHARE: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the total amount of wheat and rice stored in the different States in the country during the years 1966-67, 1967-68 and 1968-69;

(b) the percentage of loss in wheat and rice as a result of storage during these years; and

(c) the rent paid for the godowns for storing the wheat and rice during these years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) The total quantities of wheat and rice stored in different States in the country by or on behalf of the Central and State Governments was as under:—

(Figures in lakhs of tonnes)

	Wheat	Rice
As on 31-3-1967.	6·74	8·41
As on 31-3-1968.	7·61	14·31
As on 31-3-1969.	18·97	20·66

(b) The losses in the Central Storage Depots with the Food Department before their transfer to the Food Corporation of India were as follows:—

Percentage of loss.

	Wheat	Rice
1966–67	0·12	0·69
1967–68	0·067	0·36
1968–69	0·07	0·204

(c) All the godowns owned by the Food Department have been transferred to the Food Corporation of India from time to time, and the transfer was complete by 1st March, 1969. It is not possible to furnish figures of rent paid for storing wheat and rice only, as the same godowns might have been used for storing other commodities too at various times. The amount of rent paid for all the hired goodowns by the Food Department and the Food Corporation of India during the three years in question were, however, as follows:—

(Rs. in lakhs)

Year	Paid by Food Deptt.	Paid by FCI.	Total
1966–67	92·05	73·11	165·16
1967–68	70·02	170·36	240·38
1968–69	65·60	257·44*	323·04

*Provisional.

Central Assistance for Minor Irrigation Schemes in Maharashtra

4924. SHRI DEORAO PATIL: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the financial assistance asked by the Government of Maharashtra for minor irrigation schemes in 1969-70;

(b) the amount given by the Central Government to Maharashtra towards the minor irrigation schemes during the year; and

(c) whether Government are going to increase the amount in this financial year for the dry and drought affected areas of Maharashtra?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) and (b). According to the pattern in vogue, Central assistance is not related to any individual programme/scheme, but it is provided by the Centre on block loan and grant basis in respect of the Annual Plan as a whole. No separate financial assistance was asked by the Government of Maharashtra for minor irrigation during 1969-70 nor had any particular central assistance been allocated by the Government of India for minor irrigation schemes during the year.

(c) The scheme of development of chronically drought affected areas has come in the State Sector since the financial year 1969-70. However 10% of the Central assistance would be made available during the Fourth Plan period to assist the States in tackling certain special problems including those relating to chronically drought affected areas.

Applications pending for Telephone connections in Maharashtra

4925. SHRI DEORAO PATIL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the present number of persons who are on the waiting list for telephone connections district-wise in the State of Maharashtra; and

(b) the number of applications for telephone connections received, district-wise, during 1969 and the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) and (b). A statement giving the requisite information district-wise is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-3069/70.]. Telephones are being progressively provided to applicants on the waiting lists. The applications received during 1969 are also being accordingly attended to.

Villages provided with Post Offices and Telephone Exchanges in Yeotmal District, Maharashtra

4926. SHRI DEORAO PATIL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the total number of villages in Yeotmal District of Maharashtra and the number of villages where Post Offices and Telephone Exchanges exist on date;

(b) the number of villages which have sought the above facilities; and

(c) the number of towns and villages in the said area that would be given new Post and Branch Post Offices and Telephone Exchanges in 1970-71?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) Total number of villages in Yeotmal District of Maharashtra—1924. Number of villages in Yeotmal District of Maharashtra where Post Offices exist as on 28-3-70—258. Number of villages in Yeotmal district of Maharashtra where Telephone Exchanges exist as on 26-3-70—8.

(b) Number of villages which have sought the facility of Post Office during 1969-70—9. Number of villages which have sought the facility of Telephone Exchange during 1969-70—2.

(c) **Post Offices.**—The number of towns and villages in Yeotmal district of Maharashtra that would be given new Post Offices during 1970-71 has not yet been finalised.

Telephone Exchanges

Towns — Nil

Villages — 2

Expenditure on Nilokheri Colony in Haryana and Assistance to Refugees to Earn Livelihood

4927. SHRI SURAJ BHAN: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the total expenditure incurred so far in connection with the construction and lay-out of Nilokheri Colony

(Haryana) as well as the original allocation for the said colony by Government;

(b) whether this exuberant experiment in the Cooperative Sector has been upto the expectation of Government and whether Government are satisfied with its progress; and

(c) if not, whether Government have any other plan to invest or allocate more funds by setting up new industries at the said colony to help the refugees to earn their livelihood as Government have left them to lurch after the failure of the experiment causing more unemployment; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): (a) The total expenditure incurred in connection with the construction and lay out of Nilokheri Colony is Rs. 126.68 lakhs. The scheme of the township stipulated an expenditure of Rs. 1,000 *per capita* of population of the township subject to a maximum of Rs. 75 lakhs excluding the expenditure incurred on vocational and other training.

(b) The experiment in the Co-operative Sector at Nilokheri has not been encouraging.

(c) There is no plan to invest or allocate more funds for setting up new industries in this colony. The Displaced Persons settled at Nilokheri have merged into the main-stream of life of the country and their economic and other problems are, therefore, no longer being dealt with as special problems as was done initially.

Amount Recovered as Rent and Sale Proceeds of Plots from Settlers in Nilokheri Colony in Haryana

4828. SHRI SURAJ BHAN: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the total amount recovered by Government from the settlers at Nilokheri (Haryana) in the form of rent and sale-proceeds of plots and other lands;

(b) whether the amount thus recovered exceeds the amount invested by Government;

(c) if so, whether Government will take some suitable steps to do away with this injustice being perpetuated in the name of Cooperative Sector; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): (a) The amount of recoveries on account of rent and sale-proceeds of plots, other lands, constructed properties etc. at Nilokheri is Rs. 82,56,835.

(b) No, Sir.

(c) and (d). Do not arise.

Setting up of an Independent Body for Certification of Seeds Sold by National Seeds Corporation

4929. SHRI RAM AVTAR SHARMA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an expert committee appointed by Government to examine the certification and marketing of seeds by the National Seeds Corporation recommended the setting up of an independent body to certify the seeds;

(b) whether such a body has been set up; and

(c) if not, the reasons therefor and when such an agency will be set up?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Participation by U.K. and Canada in Intensive Agriculture Development Programme in M.P.

4930. SHRI RAM AVTAR SHARMA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Britain and Canada propose to participate in India's intensive agriculture development programme at district level;

(b) whether some nutrition and research projects are proposed to be set up with British aid;

(c) whether any such project is proposed to be set up in Madhya Pradesh also; if so, the name of the place where it will be located; and

(d) if not, the reasons therefor and whether Government propose to locate such project there in view of the backwardness of the State of Madhya Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) to (d). The question of undertaking programmes of intensive agricultural development, nutrition and research in collaboration with other countries depends upon offers being made by such countries.

After Canadian experts had visited India, the Canadian Government proposed collaboration programmes in the field of (i) ground water exploration in hard rock areas, (ii) research in Dryland Farming, (iii) developing Bulk Handling of Fertilisers at ports.

In the coordinated research project for Dryland agriculture, which is in the process of being finalised it is proposed to have two research centres in Madhya Pradesh, *viz.*, Indore & Jabalpur.

So far as U.K. is concerned, their expert had visited India recently and since his report is still to come, it is not possible to say in what field cooperation from the British Government would be possible.

Promotion of Engineering Supervisors to Class II Post

4931. SHRI RAM AVTAR SHARMA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in 1968-69, the existing vacancies against class II Gazetted posts of Assistant Engineers which were originally reserved for the promotion of Engineering Supervisors who were selected by D.P.C. and put on panel in 1968 were given to persons of class I cadre;

(b) whether it is also a fact that this move of Government has blocked the chances of promotion of Engineering Supervisors to class II cadre; and

(c) if so, what steps Government are taking to provide more avenues of promotion to this category of employees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) No. No vacancies of Asstt. Engineers were specifically reserved for promotion of Engineering Supervisors brought on the panel in 1968. The duties and responsibilities of the officers belonging to TES Class I (Jr.) and TES Class II being interchangeable, they can be appointed to posts sanctioned in either cadre.

(b) No.

(c) Does not arise.

Abolition of Manually driven Rickshaws

4932. SHRI HIMATSINGKA:
SHRI K. N. PANDEY:

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the policy decision for abolition of manually driven rickshaws in the country still stands;

(b) if so, whether any programme has been drawn out for implementation of this policy under the Fourth Five Year Plan, if so, the details thereof;

(c) the estimated number of rickshaws plying in each State at present and how far they would be eliminated by the end of the Fourth Plan under the said programme; and

(d) whether it is also a fact that in some parts of the country women ply rickshaws for their livelihood, if so, where and the steps being taken to abolish it forthwith?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): (a) Yes.

(b) to (d). The subject matter relates to State Governments; as such, the required information is not available.

Lock-Outs in Coal Mines in Bihar

4933. SHRI HIMATSINGKA: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the number of occasions when lock-out has to be resorted to in the coal mines in Bihar during each of the past three years;

(b) the circumstances leading to these lock-outs; and

(c) the steps taken or being taken to avert such situations?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): (a) to (c). In 1967 there was one case of lockout in the Lodna Colliery, which was declared by the management following a strike resorted to by the workers due to the non-implementation of the recommendations of the Coal Wage Board. The Industrial Relations Machinery could not intervene in this case as the High Court, Calcutta was seized of the matter. However, as a result of mutual understanding, and on permission from the High Court, the lockout was lifted by the management on 22-2-1968.

In 1968, besides the above lockout, which was continuing, there was only one case of a lockout, which was in the Kurhurbaree Colliery of M/s. National Coal Development Corporation Ltd., Giridih (Hazaribagh). This was the result of the workers adopting go-slow tactics. The Assistant Labour Commissioner (Central,) Hazaribagh intervened and brought about a settlement as a result of which the lockout was lifted on 17-1-1968.

In 1969 also there was only one case of a lockout, which was in the Madhuband Colliery, Nudkhurkee, Dhanbad. This lockout was declared following a strike resorted to by the workers without any notice or demand. The Deputy Chief Labour Commissioner (Central) intervened in the matter and as a result of his pursuation, the management lifted the lockout from 26-11-69.

Gheraoes in Coal Mines in Bihar

4934. SHRI HIMATSINGKA: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the number of gheraoes that have so far taken place in coal-mines in Bihar during the past three years;

(b) the loss of production caused thereby; and

(c) the causes of these gheraoes?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): (a) The number of gheraos which took place in coal mines in Bihar are as follows:—

1967	=	10
1968	=	2
1969 (up to August)	=	2

(b) The information is not available.

(c) The causes, in the main, were:

(1) non-payment of wages, bonus and lay off compensation;

(2) non-implementation of the recommendations of the Wage Board;

(3) inter-union rivalry; and

(4) demands for reinstatement of dismissed workers, reopening of closed mines, accommodation for villagers whose lands had been taken and employment of local people.

Nationalisation of Vanaspati Industry

4935. SHRI R. BARUA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal under consideration to nationalise the Vanaspati Industry in the country;

(b) whether any proposal in this regard has been mooted by any State Government; and

(c) what is Government's policy in this regard and what would be their reaction if any State Government wants to nationalise the Vanaspati Industry as the shortage of Vanaspati is increasing in certain parts of the country and there has been steep rise in its prices by the producers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) and (b). No, Sir.

(c) Government of India have no proposal to nationalise the Vanaspati Industry in the country. However, if any State Government wants to take it over, there will be no objection.

Confirmation of Temporary Clerks against Senior Clerks in P & T. Department, Palghat (Kerala).

4936. SHRI E. K. NAYANAR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the orders of confirming temporary clerks as permanent by ignoring senior clerks are being issued by the SSP Palghat in (Kerala State) P. & T. Department; and

(b) if so, whether Government will take suitable steps that officials eligible for confirmation are included in the list?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Reduction in Ration Quota in Kerala

4937. SHRI E. K. NAYANAR: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that he had written a letter either on the 15th January last or the 3rd week of January to Kerala Food Minister giving instruction to reduce the ration from 160 grams to 120 grams of rice; and

(b) if so, the reason therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) and (b). A letter was written on 15-1-1970 to the Food Minister of Kerala, advising him that the rice portion of the cereal ration be restored to the level of 120 grams per adult per day as the lean season for which it had been raised to 160 grams was over. The advice had to be given in view of the fact that with the supplies of rice available with the Centre it was considered inadvisable to keep the rice quantum of the ration at more than 120 grams per adult per day except during the lean months of the year, when it could be raised to 160 grams per adult per day. The overall cereal ration was, however, to be maintained at 320 grams per adult per day.

Occupation of Shrine of Khawaja Baqi Billah R. A. at Qutab Road, Delhi by Refugees.

4938. SHRI GEORGE FERNANDES: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Shrine of Hazarat Khawaja Baqi Billah R. A. situated at Qutab Road, Delhi which is visited by the Muslims of various countries is still occupied by Refugees;

(b) whether Government have received representations from Shri Khawaja S. Hasan Baqi requesting that the Shrine be properly restored; and

(c) if so, what action has been taken by Government in this matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): (a) to (c). The Shrine was never taken over as evacuee property and no representation has been received from Khawaja S. Hasan Baqi for its restoration.

Migration of Refugees from Easgaon Rehabilitation Project, Adilabad District, Andhra Pradesh.

4940. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of refugee families from East Bengal sent to Easgaon Rehabilitation Project, Adilabad in Andhra Pradesh, have now come to Patora Pull, Ambegaon in Chanda District, Maharashtra; and

(b) if so, the steps taken to rehabilitate them in District Chanda?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): (a) According to information received from the Director, Chanda Rehabilitation Project, about 685 new migrant agriculturist families from East

Pakistan reached Chanda Railway Station between 7th to 9th March, 1970, after having deserted from their rehabilitation sites in Isagaon, District Adilabad in Andhra Pradesh. On the 10th March, 1970, all the families shifted to village Padoli Ambora at a distance of about one and a half miles from Chanda.

(b) As these families had been resettled in Isagaon Rehabilitation Project in Andhra Pradesh, the question of rehabilitating them again in District Chanda in Maharashtra does not arise. They are being persuaded to return to Isagaon. In fact, some families have already returned. Necessary arrangements are being made in consultation with the Governments of Andhra Pradesh and Maharashtra to provide all facilities to enable the remaining families to return to Isagaon.

उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ड्रिलिंग मशीनों की सहायता से नल-कूप लगाना

4941. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलाहाबाद, बांदा, मिर्जापुर, झांसी तथा अन्य जिलों को सूखे से बचाने के लिये वहां ड्रिलिंग मशीनों की सहायता से नल-कूप लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो नलकूपों के कब तक लगने की आशा है;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में कोई ड्रिलिंग मशीन उपलब्ध नहीं है; और

(घ) किन-किन राज्यों में ड्रिलिंग मशीनों को प्रयोग में लाया जा रहा है और उन मशीनों की कुल संख्या कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) और (ख). बांदा और झांसी जिलों की उप-सतहों में कड़ी चट्टानों की बहुलता और कणदार जल धारक क्षेत्रों के अभाव के कारण सरकारी नलकूपों का निर्माण संभव नहीं था। इलाहाबाद और मिर्जापुर सहित अन्य 19 सूखाग्रस्त जिलों के जिन क्षेत्रों में संभव है राज्य सरकार राजकीय नलकूपों का निर्माण कर रही है। इस 19 जिलों में मार्च, 1969 के अन्त में 3717 राजकीय नलकूप थे और 1969-70 की अवधि में 330 अतिरिक्त नलकूपों का निर्माण पूर्ण कर लिये जाने की आशा है।

(ग) जी नहीं। नलकूप निदेशालय और राजकीय लघु सिंचाई विभाग के पास लगभग 4,000 हैन्ड बोरिंग सेट और 93 शक्ति चालित रिगें उपलब्ध हैं।

(घ) ड्रिलिंग मशीनों का प्रयोग 14 राज्यों में किया जा रहा है और उनकी कुल संख्या में 5400 हैंड बोरिंग सेट और 684 शक्ति चालित रिगें सम्मिलित हैं।

Telephone Bills outstanding against the former Finance Minister, Shri Morarji Desai

4942. SHRI ESWARA REDDY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Shri Kanti Desai, the Personal Assistant of the former Finance Minister Shri Morarji Desai had left a number of telephone bills unpaid;

(b) if so, the total amount to be paid by him;

(c) whether the arrears have been collected; and

(d) if not, the reasons for the delay in collecting the arrears?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) No telephone was provided to Shri Kanti Desai on Government account. Nor is any telephone traceable to have worked for him at Delhi in his private capacity.

(b) to (d). In view of the reply to part (a) above, the questions do not arise.

Memorandum from Employees of Central Fisheries Corporation

4943. SHRI INDRAJIT GUPTA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have received any memorandum from the Central Fisheries Corporation Employees Association, Howrah, putting forward proposals for the efficient functioning of the Corporation;

(b) if so, the proposals made and the demands put forward by the workers in the memorandum; and

(c) the steps so far taken by Government to redress the grievances?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) The Government have received two memoranda dated 12-9-1969 and 21-1-1970 in which certain proposals and demands have been put forward.

(b) The proposals and demands made are:

(i) Not to close down the Corporation and throw the staff out of employment. If closure is unavoidable, to ensure that alternative employment is provided to employees in the same status and under the same service conditions before such closure is effected.

(ii) To examine more fully the causes of failure to see to what extent it had been due to lapse of the management and not to close down the Corporation without examining the feasibility of diversifying the activities of the Corporation in accordance with the objectives laid down in the Memorandum of Association.

(iii) To broad-base the activities of the Corporation for the welfare of the masses.

(iv) To recast the management pattern to fit in with that of the trade.

(v) To take steps for handing over all the catches of Government of India and State Governments fisheries for marketing all over India by Central Fisheries Corporation Ltd. at regulated prices.

(vi) To accept Report of the Review Committee of the Board of Directors, submitted to Ministry of Food and Agriculture.

(c) The working of the Central Fisheries Corporation was examined in detail by a Committee set up by the Board of Directors in 1969 and the Report of the Committee has been carefully examined in the Ministry of Food and Agriculture.

The main problem of the Corporation, as brought out by detailed studies, is the difficulty of securing fish supplies in sufficient quantity to enable the Corporation to have an impact on the Calcutta market. The Corporation has not been able to supply more than 800 tonnes of fish to Calcutta in any year. It has been assessed that the Corporation will not be able to supply more than 2000 tonnes of fish annually to Calcutta even by 1974-75 even if the various suggestions made by the Committee are implemented.

In this context the course of action to be adopted is under careful examination. The question of diversification of the activities of the Corporation has also been examined in detail and it is not considered feasible for the Corporation to undertake fresh activities.

A proposal was made to the Government of West Bengal to take over the Corporation as it was felt that it could be run at the State level in cooperation with other State developmental organisations with reduced overheads. This question is under consideration.

In case a decision is taken to wind up the Corporation, alternative employment for the staff will be simultaneously considered sympathetically under the regulations.

Recruitment of Scheduled Castes/Tribe Candidates as Female Telephone Operators in Delhi

4944. SHRI SURAJ BHAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 45 posts reserved for Scheduled Castes and 18 for Scheduled Tribes were advertised by

the General Manager, Telephone, New Delhi in the month of November, 1969 for the selection of female telephone operators;

(b) if so, the number of Scheduled Caste/Scheduled Tribes candidates who applied for and called for interview separately;

(c) the number of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates selected for appointment; and

(d) the reasons for short recruitment of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates; and the steps proposed to make up this deficiency?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) Yes.

	Scheduled Caste	Scheduled Tribe
(b)	(i) 84	1
	(ii) 69	1
(c)	24	Nil

(d) The others could not fulfil the conditions of age, and qualifications prescribed in the recruitment rules of T.Os. The unfilled vacancies will be carried forward for next recruitment in accordance with rules on the subject.

Damage to Crops etc. in Maharashtra due to Hailstorm

4945. SHRI DEORAO PATIL: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether a severe hailstorm destroyed human beings, cattles and crops in the State of Maharashtra, especially in Vidarbha and Marathawada regions, in the month of March, 1970.

(b) if so, the extent of the damage; and

(c) the relief so far given to the victims, i.e. peasants and the land owners?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) and (b). According to available information, rains accompanied with hailstorm were received in Hinganghat and Wardha tehsils (Wardha District), Gondia Tehsil (Bhandara district) and parts of Yeotmal and Nagpur district on the 6th and 7th March, 1970. It damaged, to a large extent, bajra, rabi jowar, gram, orange and irrigated wheat in 321 villages of Ramtak, Nagpur, Umred and Saoner tehsils of Nagpur District.

(c) No information about details of relief given to the victims is available.

Production and Consumption of Rosin (Dry)

4946. SHRI N. K. SOMANI: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the annual consumption of Rosin (Dry) which is used for sizing purposes in the Paper Industry and in Soap and other industries; and

(b) the total production of this Chemical in the country and what are the possibilities of increasing the production and in how much time?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) and (b). The required information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

Increase in Commercial Broadcasting time in Madras and Tiruchi Stations of A.I.R.

4947. SHRI C. CHITTYBABU: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the commercial broadcasting time in Madras and Tiruchi Stations of A.I.R. in Tamil Nadu has been increased;

(b) if so, by how much time; and

(c) the extra amount it will fetch to Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) No, Sir.

(b) and (c). Does not arise.

Censor Certificates in Hindi for Tamil films

4948. SHRI C. CHITTYBABU: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Film Council set up by Government had decided to issue Censor Certificates for Tamil films in Hindi;

(b) if so, the reason thereof;

(c) whether it is also a fact that on this ground an important film personality has resigned from the Council; and

(d) whether there is any proposal to review Government stand and give the certificates in English as usual for Tamil films?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS (SHRI SATYA NARAYAN SINHA): (a) and (b). Censor certificates are issued by the Central Board of Film Censors. The certificates for Tamil films are being issued in English.

(b) Does not arise.

(c) A letter of resignation had been submitted by a member to the Central Board of Film Censors which was later withdrawn.

Closure of Vanaspati Manufacturing Units

4949. SHRI HIMATSINGKA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at least seven Vanaspati manufacturing units in the country have closed down recently and some others have curtailed production;

(b) if so, in what circumstances; and

(c) the steps taken by Government to ensure working of the industry upto the capacity?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) and (b). No, Sir. Only 4 factories had suspended production for varying periods of one to two weeks and one factory for 3 weeks; a few others had curtailed their production to some extent because of rise in the prices of raw oils.

(c) The matter has been discussed with the representatives of the industry, and it is expected that the production which has already picked up will be restored to normalcy in the very near future.

Strikes in Textiles, Jute, Tea and Coal Mines Industries and their Settlement

4950. SHRI P. C. ADICHAN:
SHRI D. AMAT:
SHRI VALMIKI CHOUDHARY:

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the number of industry-wise strikes in the textile, jute, tea and coal-mines industries in the country during the last three years which resulted in settlements through (i) collective bargaining, (ii) arbitration, (iii) adjudicaiton, and (iv) Government mediation; and

(b) the number of settlements reached through each of these means in these industries during this period without resort to strike?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): (a) A statement is placed on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-3070/70.]

(b) The information is not available.

A.I.R. Station for Bundelkhand

4951. SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have decided to locate a Broadcasting Station in Bundelkhand area of Madhya Pradesh;

(b) if so, its location and by when; and

(c) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) Yes, Sir.

(b) Chhatarpur, by 1973.

(c) Does not arise.

A.I.R. Station for Jabalpur

4952. SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state when A.I.R. station at Jabalpur will become a full-fledged independent station like others?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): The question of upgrading Jabalpur station into a full-fledged one during the Fourth Five Year Plan is under consideration.

Move to Eliminate Outsiders from Trade Unions by Andhra Pradesh

4953. SHRI YOGENDRA SHARMA: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Centre is aware of the Andhra Pradesh Government move to bring legislation to eliminate outsiders from trade unions; and

(b) if so, the Centre's views thereon?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA): (a) The State Government have reported that they have no such proposal under consideration.

(b) Does not arise.

Chanda Committee Recommendation on A.I.R. Artistes

4954. SHRI ESWARA REDDY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the Chanda Committee on A. I. R. had recommended the treatment of A. I. R. artistes as Government servants; and

(b) if so, the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Rehabilitation of Scheduled Tribes Families of East Pakistan Refugees in Chanda District, Maharashtra

4955. SHRI K. HALDER: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) what is the extent of financial help provided by Government to each East Pakistan Scheduled Tribe family in the Chanda district of Maharashtra for rehabilitating them in trade and business;

(b) whether this help was not given in one instalment, but in small instalments spread over a long period;

(c) whether it is a fact that the Scheduled Tribe families have represented that for the above reason they could not rehabilitate themselves in trade or business and had exhausted the Capital; and

(d) if so, what steps Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): (a) The pattern for rehabilitation of East Pakistan new migrants in trade and business has been laid down generally for all the new migrants, and not with reference to any specific section of new migrants. A statement indicating the rehabilitation assistance given to 'Small Trader' new migrant families from East Pakistan for resettlement in trade and business is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-3071/70.]

(b) The amount of loan was generally given in two instalments—the second instalment being given on proper utilization of the first instalment.

(c) Some representations from 'Small Trader' families have been received; it is not known how many of them are from Scheduled Tribes.

(d) Instructions have already been issued to all concerned that the number of instalments, in which the amount of loan is disbursed, should not ordinarily exceed two.

Constitution of Indian Forest Service Cadre in Union Territories

4956. SHRI C. C. DESAI: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Union Territories Cadre of Indian Forest Service had been constituted on 1st October, 1966 and Selected Officers to that Cadre appointed and posted against encadred posts; if not, why not and the reasons for the delay; and

(b) whether Government are finding ways for immediate replacement of rejected Officers holding charge of territorial and other important Divisions and Circles in the Territories by highly qualified Indian Forest Service Officers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes. The selected officers have been appointed and posted against respective posts.

(b) All the cadre posts in the Union Territories Cadre are manned by cadre officers except for two non-cadre officers in Andamans Forest Department who are working against the cadre posts of Deputy Conservator of Forests, and Government are considering replacing these officers by suitable cadre officers as soon as possible.

Discrimination against Scheduled Caste Employees of Central Tractor Organisation

4957. SHRI SURAJ BHAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the posts of Teleprinter Operator reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes were advertised by the Indian Airlines by the end of 1969 the application of none of the Scheduled Caste candidates from C.T.O. New Delhi was forwarded to the authorities concerned;

(b) whether it is also a fact that for the General Posts of Teleprinter Operator advertised by the same organisation after one month of previous advertisement the applications of the applicants of C.T.O. New Delhi were forwarded to the authorities concerned;

(c) if so, who is responsible for this discrimination against Scheduled Caste employees and what action has been taken or is proposed to be taken against him?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) and (b) No. The Department is not aware of any advertisement for posts of Teleprinter Operators reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes. In December, 1969 there was an advertisement and in response to this 49 applications including 4 of Scheduled Caste officials were received and all these applications were forwarded to the Indian Airlines. Before this, 10 applications, from Scheduled Caste officials, without reference to any advertisement were received. Of these, nine applications could not be forward due to non-compliance of requisite formalities and other administrative grounds.

(c) In view of reply to (a) & (b) above, question does not arise.

Promotion of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees of P and T Department to Class II posts

4958. SHRI SURAJ BHAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of class III postal and RMS officials promoted to class II during the last three years (year-wise separately);

(b) the number of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe Postal and RMS officials who were considered for promotion to class II during this period (year-wise separately); and who had been actually promoted to class II (year-wise separately); and

(c) the reasons for inadequate representation given to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees of postal and RMS in the matter of these promotions and whether Government propose to make up the deficiency of these communities; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the Lok Sabha. As no reservation or preferential treatment for scheduled caste/tribe officials in matters of promotion (other than by competitive examinations) was provided prior to the instructions issued by the Ministry of Home Affairs in their O.M. No. 1/12/67-Ests (c), dated 11-7-68 there was no question of ascertaining the community of an official within the zone of consideration. After July, 1968 one selection each in PSS Class II and P.Ms. Service Class II has been held and necessary benefit wherever admissible was given to scheduled caste candidates who were in the zone of consideration.

(c) Prior to the issue of the general instructions by the Ministry of Home Affairs on 11-7-68 no reservation nor any concessional or preferential treatment was shown to the scheduled caste/tribe officials within the zone of consideration. Therefore, the question of making up any deficiency does not arise.

STATEMENT

	Actually promoted			Scheduled cast officials considered for promotion		
	1967	1968	1969	1967	1968	1969
PSS CL. II	7*	47*	33@	-*	No Selection	3†
P.M'S Service, Cl. II	15*	9*	6**	-*	-*	2‡£
Dy. SRM (Sorting) in GCS Cl. II	No Selection	4*	No selection	No selection	-*	No selection

*As there was no reservation for officials belonging to scheduled caste/tribe officials nor any preferential treatment or concessional grading was provided for members belonging to scheduled caste/tribe communities prior to the issue of the Ministry of Home Affairs O.M. No. 1/12/67-Ests (C) dated 11-7-68, no record was available for such officials.

After the issue of the orders by the Ministry of Home Affairs referred to above, one selection each in PSS Class II and P.M's. Service, Class II was conducted in June, 1969 and the break-up as given above is explained below:—

@Out of 33 officials 1 is a scheduled caste official.

†Out of 3 scheduled caste candidates considered only one was promoted.

**Out of 6 officials one is a scheduled caste official.

‡Two scheduled caste officials were in the zone of consideration and one of them was selected.

Dissolution of Board of Directors of Central Fisheries Corporation

4959. SHRI C. JANARDHANAN: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Board of Directors of the Central Fisheries Corporation had been dissolved since 31st December, 1969 and no appointments for the posts of the directors had been made so far; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) and (b). According to the provision of the Articles of Association of the Central Fisheries Corporation, all the Members of the Board of Directors, except the Managing Director and the Chairman, retire at every annual general meeting of the Company. The Board dissolved at the last annual general meeting held on the 30th December, 1969, was reconstituted on the 17th January, 1970.

Relinquishing of Charge by Managing Director of Central Fisheries Corporation

4960. SHRI K. HALDER: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Managing Director of the Central Fisheries Corporation had relinquished his charge on the 12th August, 1969; and no fresh appointment yet has been made; and

(b) if so, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes, Sir.

(b) On the basis of a review of the working of the Central Fisheries Corporation the question of the future of the Corporation has been receiving serious attention. In this connection a proposal for transfer of the Corporation to the West Bengal Government was also under consideration. In the circumstances the appointment of a Managing Director was deferred. The Board of Directors have authorised one of the Directors to look after the work with the assistance of the Divisional Manager and the Secretary of the Corporation.

Closure of Stalls of Central Fisheries Corporation at Delhi and Calcutta

4961. SHRI K. HALDER: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some of the stalls under the Central Fisheries Corporation in Calcutta and Delhi have been closed and the casual staff in those stalls retrenched; and

(b) if so, the reasons of the closure?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes, Sir.

(b) A review committee appointed by the Board of Directors to examine the functioning of the Corporation had recommended in May, 1969 that departmental stalls should be maintained only in such places where they could be operated without loss. The management, in acceptance of the recommendation, is making adjustments in the pattern of retail sale of fish, and abolishing stalls which have been found to be uneconomical.

Telephone Connection to Haji Mastan Mirza of Bombay under Exempted Category

4962. SHRI GEORGE FERNANDES: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that one Haji Mastan Mirza living at Baitul Sarur, 61/1, Warden Road, Bombay-26 has been given a telephone connection (No. 359358) under 'Exempted Category' as a Social worker;

(b) if so, who are the people who recommended his application under this category;

(c) whether the Bombay Telephones made any inquiries into the nature of Social Work done by Haji Mastan Mirza;

(d) whether it is fact that a telephone under exempted category had been refused to him on an earlier occasion; and

(e) what made the Bombay Telephones change its decision ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTINGS AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH) : (a) Yes.

(b) (1) Shri Adam Adil, MLA.

(2) Shri B. M. Yagnik, Minister of Prohibition, Bombay.

(3) Shri Bhagwan Dass K. Ashar, President, B-Ward, Distt. Congress Committee.

(4) Shri T. P. Kareemsha, Vice President, Maharashtra Mazdoor Sabha, Bombay.

(5) Shri M. A. Khatal, Municipal Councillor, Hony. General Secretary, T. B. Patient Welfare Society, Bombay.

(6) Shri Ismail Khawja, Hussein, J. P., Hony. General Secretary, National Service Society, Bombay.

(7) Shri S. K. Patil.

(8) Shri Baburao H. Shete, J. P., Municipal Councillor, Member TAC, Bombay.

(c) No.

(d) The application dated 6-3-1968 from Shri Mirza for a connection under "Exempted" Category was returned to him for certain clarifications and for filling some omissions. He re-submitted the same on 24-6-1968. His case was subsequently placed before the Telephone Advisory Committee who approved its being sanctioned.

(e) Does not arise.

Accommodation for P. & T. Staff in Kolhapur City.

4963. SHRI GEORGE FERNANDES : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the total number of Post and Telegraph staff of all categories working within the municipal limits of Kolhapur City in Maharashtra;

(b) how many of these employees have been provided with houses;

(c) whether there have been demands from the P. & T. employees for accommodation; and

(d) when it is proposed to meet their demands ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) 701.

(b) 9.

(c) Yes.

(d) It will take about 3 to 4 years to construct more quarters. State Government has been requested to allot land for Staff Quarters.

Increase in Death Rate in Mines

4964. SHRI K. N. PANDEY : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that death rate in the mines has increased during the last six months in spite of the fact that no major accidents occurred during the said period; and

(b) if so, what are the reasons for the same ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA) : (a) The death rate has not increased.

(b) Does not arise.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

STAY ORDERS BY CERTAIN HIGH COURTS ON GOVERNMENT'S DECISION FOR FIXING LOW PRICE OF SUGAR

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor): Sir, I call the attention of the Minister of Food and Agriculture to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:—

> "Reported stay orders issued by certain High Courts on the Government's decision for fixing low price of sugar on Tariff Commission's recommendations."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): Notices have been received from the Mysore High Court in respect of seven sugar factories and from the Andhra Pradesh High Court in respect of three sugar factories, having filed writ petitions against the Sugar (Price Determination) Order, 1970 fixing prices of levy sugar for sugar produced in the sugar year 1969-70. Ex-parte interim orders have been passed by both the High Courts staying the operation of the Sugar (Price Determination) Order, 1970. In four cases (2 in Mysore and 2 in Andhra Pradesh), the High Courts have permitted the sugar factories to continue to charge for the sugar produced during the current season 1969-70 the prices fixed for sugar produced by them in 1968-69. The Andhra Pradesh High Court in another case has directed the respondents to permit the sugar factory to sell sugar at the price fixed for Tamil Nadu sugar factories for the current season. Action is being taken to contest the Writ Petitions and to apply for vacation of the stay orders.

The system of fixation of ex-factory controlled prices of sugar zone-wise on the basis of average recovery of sugar from sugarcane and duration of the crushing season of the factories in the respective zones has been in vogue for the last many years. The Tariff Commission (1959) recommended four cost zones and the Sugar Enquiry Commission (1965) recommended five cost zones. However, in actual practice, till 1966-67, the number of price zones, was much larger, varying between 16 to 23. This was done with a view to reducing the wide variation in the zonal prices of sugar on account of the large dispartiy in the recovery and duration of the factories falling in a bigger zone.

After introduction of partial decontrol of sugar from 1967-68 season, Government decided to fix prices of levy sugar on the basis of the five zones recommended by the Sugar Enquiry Commission in view of the flexibility in prices available to the sugar factories in respect of their production released for free sale. There were, however, representations with regard to the five zones adopted by Government from 1967-68 and for the restoration of larger number of zones as prevalent before 1967-68. The Government of India, therefore, requested the Tariff Commission to examine this matter along with the enquiry into the cost structure of sugar industry. The Tariff Commission in their report submitted recently have recommended 15 cost zones. The main reason given by the Commission for forming a larger number of zones is to reduce, though not eliminate, *inter se* anomalies in the cost structure. The justification for a smaller number of large sized zones is that it tends to introduce competition among the factories and reduce costs. On the other hand, the point in favour of a large number of small sized zones is that it recognizes wide variation in the performance of factories, their recoveries and durations and thus reduces the opportuniy for the larger and more efficient and better performing factories to make large profits at the expense of less fortunate factories in the same zone. In view of the justification given by the Tariff Commission, which is an expert body in this regard Government have accepted their recommendations in respect of price zones and cost schedules and have fixed prices for levy sugar for the year 1969-70 accordingly. In arriving at this decision, Government took into account the fact that the wide margin between the prices of free market sugar and levy sugar has narrowed considerably due to the better supply position in the country.

In respect of the sugar factories in the South, that is the erstwhile zones I and II of the Sugar Enquiry Commission, price for the factories in North Mysore, North Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Pondicherry and Gujarat are

[Shri Annasahib Shinde]

higher than those fixed for the year 1968-69. But those fixed for factories in Maharashtra, South Mysore, the rest of Andhra Pradesh, Kerala and Orissa are lower. It may be mentioned that recoveries and durations of the crushing season vary from year to year. As such, the price fixed in any year is not comparable with that fixed in any other year even if the same zones and cost schedules are adopted in the two years for fixing the prices. Further, in 1968-69, because of the smaller number of large sized zones, there was wide variation in recovery and duration of factories included in the same zone. This gave an advantage to factories situated in low cost areas in the zone as compared to factories in the high cost areas of the same zone. With the adoption of a large number of smaller zones in 1969-70, these anomalies have been reduced. It will thus be seen that the variation between the prices for 1968-69 and 1969-70 are partly due to adoption of different zones and cost schedules, and partly to the yearly variations in the recoveries and durations.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: I have heard the long reply of the Minister. The Minister says that to remove the injustice and disparities the Tariff Commission was appointed and that the Commission went into this matter. But the Tariff Commission, instead of doing justice, has done injustice in some case. In Maharashtra, Andhra Pradesh and other States there is one area which is a delta area and another area which is a dry area. Sugarcane is grown in both delta and dry areas. The cost of production is different in delta areas and dry areas. Since the cost of production has gone up the Tariff Commission was appointed so that it might fix reasonable prices. But the Tariff Commission, instead of doing justice, has done injustice to many areas. I do not know whether they really enquired into the matter or they simply camped there, spent their days having dinners and never cared to collect the correct data. I may tell you that last time, in 1968-69, Madras suffered. When in Chittoor we were getting Rs. 15 more, in Madras they were getting Rs. 15 less and I raised this question on the floor of the House. Now they have increased the amount for Madras but they have reduced the same Rs. 15 to Andhra. Is this justice? The cost of production is going up day by day. In spite of that, instead of increasing the price, the Tariff Commission has reduced the price. Even if the Tariff Commission has made such a recommendation, if the Food Ministry take a decision without properly scrutinising the Tariff Commission's Report, if it happens in any other country, the government will be prosecuted in a criminal court; but in this country they are not only allowed to go scot free but they are rewarded. I can show the Minister the price differs between North Andhra and South Andhra. Instead of five zones, they have increased it to 15 zones; each State has become one zone now. The Food Minister comes from Bihar where there are two zones, North Bihar and South Bihar. Because he knows the conditions and difficulties of Bihar, he has done it in Bihar. I am not objecting to that. It is necessary to have a north zone and a south zone. But why don't you do it in the case of other bigger States? Now an injustice has been done to Andhra Pradesh, Mysore and Maharashtra. Will the government open their eyes, go into the matter and fix proper prices? Otherwise, the High Courts will give different judgments. Why can't you correct yourself? Will the government appoint another Tariff Commission, if necessary, or an expert agricultural committee, not of ICS or IAS officers but of people who have knowledge of agriculture, who grow sugarcane and some Members of Parliament to go into the matter and correct the disparity and remove the injustice by fixing the right price?

SHRI ANNASAHIB SHINDE: As I have explained in the statement, the price structure of sugar mainly depends upon the duration of the season of the factories and the recoveries of the factories. The price structure always being a controversial subject, government do not like to take arbitrary decisions. Therefore, in the past, in the year 1959 this matter was referred to the Tariff Commission for the first time. Subsequently, a high-level Sugar Enquiry Commission was appointed and the government were having prices on the basis of five zones as recommended by the Sugar Enquiry Commission from 1967 onwards. Then there was a demand from the sugar industry that this matter should be referred again to the Tariff Commission. As a result of the

demand, government decided to refer this matter to the Tariff Commission. The Tariff Commission in their wisdom have recommended that the country should be divided into 15 zones and they recommended a particular cost schedule. This being an expert body, government has naturally decided to accept the recommendations of the Tariff Commission. I think it will not be wise or proper for the government to make a departure from the recommendations of the Tariff Commission.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: If a government committee makes a mistake and if the government stand on false prestige and not rectify it, it is not proper because the agriculturists will suffer. I want the government to admit that they have committed a mistake. If the government or the Tariff Commission have made a mistake, they must come forward to appoint an expert committee to rectify the mistake and do justice. I can show you some figures. In Maharashtra the cost of production, according to the Tariff Commission, is Rs. 89.49. They have fixed a price of Rs. 110.3. In Andhra, again, the price differs. In Mysore it is Rs. 88.03. The recovery is the same but the price has been reduced. When the Tariff Commission has done some injustice, is this government not going to come forward to correct them? Then the people will have no other option except to go to the courts. If they have to go to the courts to get justice, what is the use of this government. I am asking a straight question now. If the High Court decides otherwise, will this minority government resign on that account?

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I would not like to refer to the proceedings of the High Court because these matters are sub-judice. Supposing the High Court gives a decision, we will certainly respect the decision of judicial bodies.

DR. SUSHILA NAYAR (Jhansi): Though the writ petitions have been filed in two cases, as has been already stated, injustice has been done in many other cases as well. For instance, in Haryana the price has been reduced by Rs. 18.13; in Western UP it is minus Rs. 16 and so on. Will the hon. Minister tell us that if at all they think in terms of making a change, that will not be only for the cases where the writ petitions have been filed, Maharashtra, Andhra Pradesh or any other place, but they will sit with the representatives of the different States and come to a uniform decision? They may take into account whatever factors have to be considered but they should not make a change for some parts and not in other parts, because many other parts have been hit badly in the same way. I would like to know from the hon. Minister what their intention is.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: As far as price fixation every year is concerned, in the beginning of the season we have to make some assumptions, assumptions with regard to two factors. The first assumption is with regard to the duration of the season, whether the factories are running for 150, 160 or 180 days. Some assumptions have to be made. At the end of the season it is checked up whether the factories have actually run 160 days or 170 days. Then the prices are reviewed on the basis of actual figures. But in the beginning an assumption is made.

The second assumption is made in regard to the recovery. In regard to the recovery, naturally, we take the average of the last year because in the beginning of the season it is humanly not possible to estimate precisely as to what is going to be the recovery during the whole of the season. So, some assumptions are made. At the end of the season the position is reviewed on the basis of actuality. But if any State Government brings to our notice that any assumptions which have been made by us in working out the cost structure are not correct, we shall be prepared to take into consideration the factual position. Government would not like to make this an issue of prestige; Government would be prepared to review the position on the basis of reality.

DR. SUSHILA NAYAR: Does the hon. Minister realise that by their assumptions they do not wipe out injustice to sugar cane growers? The sugarcane is in the fields is not being purchased by the Mills and the agriculturist is suffering.

MR. SPEAKER: Order, order. Shri Krishna .... Absent.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Shri Krishna has instructed me to put a question with your permission.

MR. SPEAKER: I am sorry, the rules do not allow that.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : इस सरकार के समाजवादी बूर्के को फाड़ कर इनका जो असली राक्षसी चेहरा है वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। लैवी वाली चीनी के दाम निश्चित करते समय किस बात को मद्देनजर रखा जाता है। इन्होंने कहा है:

> "In arriving at this decision, Government took into account the fact that the wide margin between the prices of free market sugar and levy sugar has narrowed considerably due to the better supply position in the country."

मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि जो खुली चीनी के दाम हैं इनको जानबूझ कर बढ़ाने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं सबूत दे रहा हूं। सरकार ने यह तय किया था कि 70 प्रतिशत पैदावार सरकार नियंत्रित दामों मे लेगी और 30 प्रतिशत पैदावार खुले बाजार में बेचने के लिए देगी। लेकिन इस सरकार ने क्या किया? आप हर महीने के आंकड़े देखें। मेरे पास तीन महीनें के आंकड़े एक अर्से से मौजूद हैं। उन को अगर आपने देखा तो आपको पता चलेगा कि 70 और 30 प्रतिशत के अनुपात को ये जानबूझ कर नहीं रख रहे हैं। हर महीने में खुली चीनी कितनी छोड़ी जाती है, उसके बारे में तो फर्क हो सकता है लेकिन जो भी चीनी छोड़ दी जाएगी, रीलीज की जाएगी उस में तो अनुपात 70 और 30 का होना चाहिये या नहीं? लेकिन क्या हुआ है? एक आदमी ने मेरे पास यह लिख कर भेजा है। अक्तूबर 1969 में 65.4 नियंत्रित चीनी थी और खुली चीनी थी 34.6 यानी 4.6 प्रतिशत आपने ज्यादा छोड़ी। नवम्बर में 64.4 प्रतिशत नियंत्रित चीनी और 35.6 प्रतिशत खुली चीनी। दिसम्बर में 61.4 प्रतिशत नियंत्रित चीनी और 38.6 प्रतिशत खुली चीनी। इसका मतलब है 4.6 एक महीने में ज्यादा, 5.6 दूसरे महीने में ज्यादा, और 8.6 तीसरे महीने में ज्यादा। मैं किसी व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं आरोप करना चाहता हूं कि चीनी मिल मालिकों से पैसा ले कर जो व्यवस्था यहां पर बताई गई थी उसको तोड़ा जा रहा है। क्या मंत्री महोदय इसका खुलासा करने को तैयार है कि 70 और 30 का अनुपात इन तीन महीनों में आपने क्यों नहीं रखा जहां तक पैदावार का सवाल है 12 लाख टन इनके पास पहला स्टाक था। आपने सदन में कहा था कि इस साल 40 लाख टन का उत्पादन होने वाला है। इसका मतलब है 52 लाख टन की अवेलेबिलिटी इस साल में है। इसके बावजूद खुली चीनी के दाम गिरे नहीं हैं। इसलिए पैसा लेकर आपका मंत्रालय यह गंदा काम कर रहा है और इस मामले की जांच करने की मैं मांग कर रहा हूं।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह 4.6, 5.6 और 8.6 परसेंट ज्यादा अनुपात किन मिलों को दिया गया है। उन मिलों के नाम क्या हैं? वे मिले महाराष्ट्र में हों या यू० पी० या बिहार में हों, उस से मुझे मतलब नहीं है।

जब आन्ध्र प्रदेश और मैसूर की मिलों को अदालत के हुक्म के अनुसार पुराने दामों पर चीनी बेचने का अधिकार मिला है, तो उस से बिहार, यू० पी० और महाराष्ट्र के साथ अन्याय हुआ है। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चीनी के दाम के बारे में समूचे देश के लिये कोई इनटेरिम आर्डर जारी करवायेगी? वह फ़ैसला सभी पर लागू होगा। आज तो सरकार अन्य राज्यों के साथ बड़ा अन्याय कर रही है। इस लिए क्या दरमियानी-अरसे के लिए दामों के बारे में कोई अखिल भारतीय नीति निश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही करेगी? वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करे या स्वयं करे। अगर वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करे, तो ज्यादा अच्छा होगा। उस

को कोई चूनौती नहीं दे पायेगा। क्या सरकार इस बात के लिए तयार है कि सरकार जो हेरा-फेरी कर रही है, मंत्री मंत्रालय में कौन लोग पैसा बना रहे हैं, इन सब बातों के बारे में जांच की जाये ? अगर मंत्री महोदय इन प्रश्नों का ठीक जवाब देंगे, तो उस से इस देश का और उपभोक्ताओं का भी, उपकार होगा।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जांच के बारे में जो कुछ कहा है, म उस का समर्थन करना चाहता हूं। चीनी और वनस्पति की कीमतें मंत्रालय द्वारा जान-बूझ कर बढ़ाई जाती हैं। इस की जांच होनी चाहिए।

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I would like to explain the position in regard to some of the points raised by the hon. Member. But at the outset, I would like to object to the statement made by the hon. Member and I would really challenge him to prove his statement or, otherwise, to withdraw it.

श्री मधु लिमये : मैं कुछ भी विदड्रा नहीं करने वाला हूं। 70 और 30 का अनुपात तय हुआ है। मैं ने तीन महीनों के आंकडे दिये है। मंत्री महोदय जनवरी, फरवरी और मार्च के फिगर्ज दें। मैं जब कोई बयान देता हूं, तो मैं उसको विदड्रा करने वाला नहीं हूं। मैं दबने वाला और डरने वाला आदमी नहीं हूं। मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। अगर एनक्वायरी की जायेगी, तो पता लगेगा कि सरकार क्यों मिल-ओनर्ज का उपकार कर रही है। उस के पीछे जरूर कोई रहस्य है और वह जरूर खुलना चाहिए।

श्री रवि राय (पुरी) : चूंकि सरकार 30 और 70 का अनुपात नहीं रख रही है, इसी लिए यह आरोप लगाने का मौका मिलता है।

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I would like to explain the position in regard to the points raised by the hon. Member. But baseless allegations should not be made on the floor of the House.

श्री मधु लिमये : मैं ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है।

SHRI ANNASAHIB SHINDE: That is all right. But then you have tried to defame the Government for nothing. If you have any proof, I would challenge the hon. Member.. (*Interruptions*)

श्री मधु लिमये : इस चैलेंज का क्या मतलब है ? क्या मैं सरकार के सामने प्रूव करूं ? सरकार ही तो मुजरिम है।

SHRI ANNASAHIB SHINDE: In regard to the prices of free sugar the levy sugar which is freely available in the market, it is not correct to say that the prices have been rising . . .

श्री मधु लिमये : मैं ने ग्रेडिंग के बारे में सवाल पूछा था। बाद में साबित हुआ कि ग्रेडिंग के बारे में मिलों द्वारा घोटाला किया जाता है। मैं यहां गैर-जिम्मेदाराना ढंग से बात नहीं करता हूं। मंत्री महोदय मेरी चुनौती को स्वीकार करें।

SHRI ANNASAHIB SHINDE: . . . or that the Government has been instrumental in artificially raising the prices. The factual position is that, for instance, in 1967, the price-level was as high as between Rs. 400 to Rs. 500 a quintal and, continuously thereafter, the prices had been going down. Even during the current year, the position has been that, in January, 1969, the prices have ruling at the level of Rs. 339 a quintal. Then, the prices came down to Rs. 298 a quintal and now, recently, during the three or four months, the prices have been ruling between Rs. 170 to Rs. 190.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। वह जो कुछ कह रहे हैं, वह बिल्कुल इर्रेलिवेंट है। अगर हर महीने 70 प्रतिशत रिलीज किया जाता, तो दाम और गिरते।

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I am coming to that. (*Interruptions*) I have still not completed my reply. One of the points was about the price. I

[Shri Annasahib Shinde]

was explaining the position about the prices. (*Interruptions*) A year or two earlier the prices per quintal were as high as Rs. 350 to 450. I was explaining the latest price position. For instance, in March and April it was between Rs. 187—176 per quintal. It will indicate that the prices have been gradually falling and particularly after the recent Budget where the excise duty on free sugar has been steeply increased, despite that the prices have not gone up. Though the excise duty on levy sugar is only 25% *ad valorem*, the excise duty on free sugar is almost 37.5%. Despite that, the prices have not gone up.

A point has been raised by the hon. Member that Government makes discrimination in the percentage of releases of the levy quota and the free sugar. When we go on releasing the sugar when the production is on, naturally it is not possible for us to know as to what exactly is going to be the precise production of sugar. We make a rough estimate of what is going to be the production. On that basis, 70% and 30% quantities are fixed. Of course, when the season concludes, then we can make a precise calculation. But even for that the season extends upto October end. Some factories in Madras and other areas are also in production in September and October. I would like to submit that 30% and 70% ratio is being followed. The only difficulty is that in the case of some factories, they are not in a position to sell the stocks. So stocks are accumulating in the factories but that is not due to any fault on the part of the Government. There is no off take because the availability of sugar is so easy in the country that some of the States where the prices of levy sugar are high, they are not in a position to sell sugar in the open market. But the Government is releasing on the basis of 70:30. (*Interruptions*).

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन प्रश्नों में से किसी का भी उत्तर नहीं आया है। मंत्री महोदय ने कहा है कि चीनी ओपन मार्केट में नहीं बिकती है। मैं ओपन मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि लेवी शूगर की सप्लाई 70 परसेंट क्यों नहीं है। वह 4.5,5.6, 8.6 परसेंट के हिसाब से हर महीने बढ़ती जा रही है। मंत्री महोदय जनवरी, फ़रवरी और मार्च के फ़िगर्ज़ दे दें। मैं ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आर्डर जारी करवाने के बारे में पूछा है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार किन मिलों को फ्री शूगर ज्यादा बेचने की इजाजत दे रही है। एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। आप हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिए। मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं और जो मैं ने पूछा नहीं है, उस पर उन्होंने पांच मिनट ले लिये हैं।

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I would like to clarify the position further. . . .

SHRI RANGA (Srikakulam): Clarification, clarification but you don't give a straight answer.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: For instance, take the case of Madhya Pradesh. There the price of levy sugar is almost Rs. 194 per quintal. I am giving the approximate figure. The price of levy sugar in Maharashtra is between Rs. 136-137. Naturally, where sugar is available at a cheaper rate, there the factories are in a position to sell the sugar.

But in some States where the prices are much higher than other States, they are not able to sell the sugar. The main question raised by the hon. Member is that as a result of the price structure recommended by the Tariff Commission it differs from State to State. In some States the prices are higher and the stocks are not being lifted. We have told the State Governments, 'You ask as much sugar as you want from the levy quota, that is controlled sugar. We are prepared to give as much as you want.' Some State Governments wanted additional quota. We have allotted them additional quota also and we have not refused the demand of any State Government. But, despite the release orders, if sugar is not being lifted by the representatives of State Governments, I don't think the Centre can be blamed for that.

श्री मधु लिमये : क्या सरकार इनटेरिम प्राइसिज के बारे में सुप्रीम कोर्ट से एक आर्डर

जारी करवायेगी ? मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देते हैं ?

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, चीनी के मामले में इस सरकार ने हमेशा बहुत बंगलिंग की है, इस सरकार की कोई लोंग-टर्म पालिसी नहीं है। कभी चीनी मिलती नहीं है और कभी बहुत ज्यादा मिलती है, कभी ब्लैक-मार्केट में मिलती है। मधु जी ने जो कहा है, मैं भी वही एलीगेशन लगाता हूं—चीनी के मामले में इस सरकार ने बहुत बंगलिंग किया है, इस में करप्शन होता है और खास तौर से जो बम्बई का सेशन हुआ था, उस के लिये सारे का सारा पैसा, जो महाराष्ट्र की शुगर आपरेटिव सोसायटीज हैं, उन से आया। मैं चाहता हूं कि इस के बारे में एन्क्वायरी होनी चाहिये। यहां महाराष्ट्र के जो कांग्रस नेता हैं इन्होंने उन्हीं चीनी मिलों के कारण एम्पायर बना रखी है और वे ही शोर मचा रहे हैं। मुझे पता है कि इस में चेन्ज होगा, क्योंकि जो पोलिटीकल प्रेशर आ रहा है—उस में चाहे कन्ज्यूमर को नुकसान हो, चाहे फार्मर को नुकसान हो, उस की चिन्ता न करते हुए, सरकार उस प्रेशर के सामने झुकेगी, क्योंकि उन्होंने इन को पैसा दिया है और दे रहे हैं। इस लिये मैं मांग करता हूं कि आप इस की सी० बाई० आई० की इन्क्वायरी कराइये और हम यह साबित करेंगे कि किस तरह से बम्बई सेशन के लिये—जो रानी-कांग्रेस का सेशन वहां हुआ, उस में पैसा कैसे आया।

मेरा दूसरा सवाल वह है—अभी 42 लाख टन की पैदावार है और डिमाण्ड 28 लाख टन की है। करीब 12 लाख टन आपके स्टोर में है। इस लिये देश की डिमाण्ड पूरी होने के बाद जो चीनी बाकी बचेगी, क्या आप उस को एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था करेंगे ताकि सरकार को फौरन एक्सचेन्ज मिल सके ?

क्या आप केन-ग्रोअर्स को यह विश्वास दें कि केन की पिछले सालों में जो प्राइस रही है—10 रु० या 11 रु० उन को मिले हैं, उससे और ज्यादा प्राइस उन को मिलेगी और उन का जितना शुगर-केन होगा, वह सारे का सारा मिल-मालिकों को लेना पड़ेगा—क्या इस प्रकार की व्यवस्था भी आप करेंगे ?

आखरी प्रश्न—हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि प्राइस फिक्सेशन का ईशू और जोन फिक्सेशन का ईशू बड़े कम्पलीकेटेड ईशूज हैं और मोटे तौर से टेरिफ कमीशन ने जो कहा है, वह मुझे साइन्टिफिक चीज लगती है, कोई लम्बी-चौड़ी गड़बड़ भी इस में नहीं है, लेकिन क्या इस के लिये कोई लांग टर्म पालिसी सरकर बनायेगी, जिससे जितनी चीनी की जरुरत हो, उतनी पैदा हो और केन-ग्रोअर्स को ठीक दाम मिले। यह न हो कि आज अगर ज्यादा केन पैदा हो गया है तो उन को कम दाम दे दो और कल जब वह दूसरी चीज पैदा करने लगें तो चीनी की स्केअर सिटी हो जाय ऐसा न हो, इस के लिये सरकार की क्या योजना है ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I don't know why the hon. Member should have brought in the Bombay session. I know, the hon. Member is opposed to cooperative sector and he has grievance against the cooperative sugar factories also.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: We have demanded cooperatives in U. P. We have demanded them. But we don't want bungling in the cooperative sector. We don't want corruption in the cooperative sector. I don't want any corruption sector . . .

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I know that. The cooperatives in Maharashtra are one of the best run and efficiently run in the country and unnecessarily the hon. Member is trying to bring in extraneous factors. If the hon. Member looks into the price structure he will see that Maharashtra sugar factories have been lowest priced, and even the Tariff Commission suggested lowest prices and Government fixed lowest prices in Maharashtra. (*Interruption*).

[Shri Annasahib Shinde]

Then, Sir, as far as the exports are concerned, Government is exploring the possibility as to whether some quantities could be exported outside. Beyond the quantities which we have agreed to export, it may be possible subject to the clearance by Finance and the assistance rendered by the Minister of Foreign Trade. We may succeed in exporting to a certain extent. I must say that as a result of the government policy, production has gone up and sugar availability is also more and there is no complaint of blackmarketing at the moment. I do not know what the hon. Member wants to know when he referred to the C. B. I. case. The pricing structure which is under discussion has been evolved on the basis of the recommendations of the Tariff Commission.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैंने केन-ग्रोअर्स के बारे में पूछा था– उन को ज्यादा प्राइस दी जाय, उन को विश्वास दिलाया जाय कि उन का जो केन बचेगा, वह सब लिया जायगा, लांग टर्म पालिसी के बारे में बतलाइये ।

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I do not know whether the hon. Member wants to discuss the entire sugar policy. I would like to submit that we expect this year more sugarcanes to be made available to the sugar factories. Government have already announced the policy of paying Rs. 8 per quintal in excise duty rebate on excess production over and above that of last year.

MR. SPEAKER: Now papers to be laid on the Table. Shri Fakhruddin Ali Ahmed.

12.39 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

PRESS NOTE RE: INDUSTRIAL LICENSING POLICY

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE & COMPANY AFFAIRS (SHRI BHANU PRAKASH SINGH): On behalf of Shri F. A. Ahmed, I beg to lay on the Table a copy of the Press Note dated the 13th March, 1970 regarding clarifications of the modified Industrial Licensing Policy. [Placed in Library. See No. LT-3055/70.]

A. I. R. CODE FOR BROADCASTS

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS (SHRI SATYA NARAYAN SINHA): I beg to lay a copy of the Code for broadcasts on All India Radio by individuals. [Placed in Library. *See* No. LT-3056/70.]

NOTIFICATIONS UNDER WAREHOUSING CORPORATIONS ACT, AND ESSENTIAL COMMODITIES ACT, ETC.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): I beg to lay on the Table:—

(1) A copy of the Central Warehousing Corporation (Amendment) Rules, 1970 (Hindi and English versions) published in Notification No. G. S. R. 438 in Gazette of India dated the 14th March, 1970, under sub-section (3) of section 41 of the Warehousing Corporations Act, 1962. [Placed in Library. *See* No. LT-3057/70.]

(2) A copy each of the following Notifications under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:—

(i) The Tripura Foodgrains Movement Control (No. 2) Amendment Order, 1970, published in Notification No. G.S.R. 427 in Gazette of India dated the 10th March, 1970.

(ii) The Foodgrains (Prohibition of Use in Manufacture of Starch) Amendment Order, 1970 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 444 in Gazette of India dated the 16th March, 1970. [Placed in Library. *See* No. LT-3058/70.]

PAPERS UNDER INDIAN TELEGRAPH ACT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): I beg to lay on the Table a copy of the

Indian Telegraph (Fourth Amendment) Rules, 1970 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 302 in Gazette of India, dated the 28th February, 1970, under sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885. [Placed in Library. *See* No. LT-3059/70.]

REPORT OF THE EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION, 1968-69

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI S. C. JAMIR): I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the Employees' State Insurance Corporation for the year 1968-69 under section 36 of the Employees' State Insurance Corporation Act, 1948. [Placed in Library. *See* No. LT-3060/70.]

ESTIMATES COMMITTEE

HUNDRED AND TWELFTH, HUNDRED AND SEVENTEENTH, AND HUNDRED AND EIGHTEENTH REPORTS

SHRI THIRUMALA RAO (Kakinada): I beg to present the following Reports of the Estimates Committee:—

(1) Hundred and twelfth Report regarding action taken by Government on the recommendations contained in their Eighty-seventh Report on the Ministry of Foreign Trade and Supply—Import of Wool, Nylon, Woollen Yarn and other Woollen Products for the Woollen Textile Industry and its allocation to various units since October, 1962.

(2) Hundred and Seventeenth Report regarding action taken by Government on the recommendations contained in their Sixty-eighth Report on the Ministry of Irrigation and Power—Kosi Project.

(3) Hundred and eighteenth Report regarding action taken by Government on the recommendations contained in their Seventyfifth Report on the Ministry of Irrigation and Power—Gandak Project.

12.40 hrs.

RE: PAPERS LAID ON THE TABLE

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, आइटम 7 पर मेरा प्वाइन्ट आफ़ आर्डर है। मंत्री महोदय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन रखा है, जिस में दो साल की देरी हुई है। इस देरी की क्या वजह है, यह इन को संसद को बतलाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। सोमवार को जो पत्र सभा-पटल पर रखे गये उन में श्री डी० आर० चव्हाण का भी एक आइटम था जिसके साथ उन्होंने रीजन्ज-फोर-डिले का स्टेटमेन्ट भी दिया था कि इन कारणों से देरी हुई है। क्या आप मंत्री महोदय को कहेंगे कि अगर वह रिपोर्ट रखने में देर करते हैं तो साथ ही साथ स्टेटमेंट भी दें कि क्यों देरी हुई है?

अध्यक्ष महोदय : इस में डिले का सवाल ही नहीं है। 1968-69 की रिपोर्ट आपके पास आ गई है।

श्री शिव कुमार शास्त्री (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एस्टीमेट्स कमेटी के कागजात हमें अभी हिन्दी में नहीं मिलते हैं। हमारी इस शिकायत को दूर करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हम इस का इन्तजाम करवा रहे हैं। श्री राममूर्ति।

12.41 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

A. I. R. VERGE OF C.P.(M) MEMBER'S SPEECHES IN LOK SABHA

SHRI P. RAMAMURTI (Madurai): Mr. Speaker, Sir, the debate on the President's Address to both Houses of Parliament took place in the Lok Sabha on 25-2-70, 26-2-70, 2-3-70 and 5-3-70. The A.I.R. covered this debate everyday in its 9 P.M. English news broadcast and also in its corresponding language news bulletins.

The broadcast covered the speeches of 14 members from the Congress(R), 4 from Congress (O), 1 from the

[Shri P. Ramamurti]

Swatantra Party, 1 from the Jan Sangh, 2 from the CPI, 1 from the D.M.K., 1 from the P.S.P., 1 from the S.S.P., 1 from the Forward Block, 1 from the Muslim League and 3 Independent Members.

It will be seen that while the news bulletins covered every other group—both recognised and otherwise—in the Lok Sabha, the only group which was completely blacked out was the C.P.I. (M) whose spokesman Shri Umanath participated in the debate on the 3rd March, 1970. Any explanation that on that date the speech of no member of the Lok Sabha was covered cannot conceal the fact that on all the other three days, speeches of members belonging to other parties had been covered. In fact, before the 2nd, all the other groups had already been covered and the CPI (M) was the only group which had not yet participated.

In these conditions, it was the responsibility of the AIR to cover the speech of our party also. By not doing so, the impression had been created that our party had not even participated in the discussion and had nothing to say on the President's Address.

This is a glaring instance of how the AIR is practising unfair discrimination against our party in its broadcasts. (*Interruption*)

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापड़) : मैं एक बात बता दूं उससे शायद राममूर्ति जी का दर्द कम हो जायेगा कि हमारी पार्टी के जो सदस्य बोले उनका नाम भी सम्मिलित नहीं किया गया . . (**व्यवधान**) . . .

श्री राम सुभग सिंह (बक्सर) : ए०आई० आर० में विरोधी दलों को जो गालियां दी जाती हैं उस हर्कत को बन्द किया जाना चाहिए और सब के बारे में न्यायपूर्ण ढंग से ब्राडकास्ट किया जाना चाहिए । (**व्यवधान**) . .

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : हमारी यह बहुत बड़ी शिकायत है कि 85 फीसदी रेडियो का टाइम अपोजीशन ले जाता है । यह बहुत गलत बात है । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मेरा सुझाव यह है कि एक पार्लमेन्टरी कमेटी बनाई जाये जोकि इस बात की इन्वायरी करे कि किस तरह से पक्षपात होता है । हमेशा इनकी तरफ से जो बात कही जाती है उसकी अस्लियत सामने आ जायगी ।

श्री रणधीर सिंह : अब आल इंडिया रेडियो नहीं, आल अपोजीशन रेडियो हो गया है ।

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपूर) : हमने इस बात की पहले भी शिकायत की है कि आल इंडिया रेडियो पर कांग्रेस पार्टी के मेम्बर्स के नाम बहुत कम आते हैं । . . . (**व्यवधान**) . .

श्री रणधीर सिंह : इन लोगों की बकार बात रेडियो पर ब्राडकास्ट की जाती है । . . . (**व्यवधान**) . . .

SHRI P. RAMAMURTI: I only want to say that all this hullabaloo does not mean anything because out of the 29 people whose names have been mentioned, 14 people belong to the Congress(R). Therefore, to say that their names have not been mentioned is not correct. Fourteen means almost half. (*Interruption*)

श्री रवि राय (पुरी) : कोई तथ्य आपके पास नहीं है, आप बैठिए ।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : 6 तो इनके आदमी हैं और कहते हैं सारा टाइम इनको मिल जाय, यह कैसे हो सकता है ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND COMMUNICATIONS (SHRI SATYA NARAYAN SINHA): The debate on the President's Address began in the Lok Sabha on February 20, 1970 and continued on February 26, 27, March 2 and 3. In all, 47 Members, excluding the Prime Minister who replied to the Debate, participated in the discussion. The names of as many as 39 Members were mentioned in the news bulletins of All India Radio or in the two commentaries, *'Today in Parliament'* and *'Sansad Samiksha'*. The name of the hon. Member . . . (*Interruption*) Shri R. Umanath, was mentioned in "Today in Parliament" on March 2 . . .

SHRI KANWAR LAL GUPTA: What does it mean? (*Interruption*)

SHRI SATYA NARAYAN SINHA: His name could not, however, be included in the News Bulletin on that day . . .

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli): Why?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA: As a matter of fact, no Member of Parliament who participated in the debate on the President's Address that day was mentioned in the main News Bulletin owing to heavy news . . .

SHRI P. RAMAMURTI: That is bogus: saying that there was heavy international news. I have seen it. There was no international news of importance. (*Interruption*)

MR. SPEAKER: There is a limit to this.

SHRI SHEO NARAIN (Basti): What is more important than a Member of Parliament? (*Interruption*)

MR. SPEAKER: Order, order. There is a limit to this. Let the Minister answer.

SHRI SATYA NARAYAN SINHA: No Member of Parliament who participated in the debate on the President's Address that day was mentioned in the main News Bulletin owing to . . .

SHRI NAMBIAR: Why? (*Interruption*)

SHRI SATYA NARAYAN SINHA: Let me finish; I am explaining.

SHRI RANGA (Srikakulam): It was wrong. Why should the AIR be there?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA: . . .was mentioned in the Main News Bulletin owing to heavy . . . (*Interruption*).

SEVERAL HON. MEMBERS *rose*—

SHRI SHEO NARAIN: Shut up. (*Interruption*)

MR. SPEAKER: Order, order. I would request their leader to kindly see that their Chief Whip uses decent language. (*Interruption*) You must withdraw it, to whosoever you addressed it. You must withdraw it.

श्री शिव नारायण : मैं विदड्रा करता हूं।

MR. SPEAKER: Thank you very much and do not use it again.

SHRI SATYA NARAYAN SINHA: . . .on the President's Address that day was mentioned in the main News Bulletin owing to heavy news fall, both national and international. This has not happened for the first time. Such situations have arisen in the past also. (*Interruption*). I have looked into the matter carefully and find that there was no attempt on the part of All India Radio to suppress or to black out the proceedings of the House or of the CPI(M)'s views as has been alleged by Shri Ramamurti. As a matter of fact, All India Radio had given coverage to Shri Umanath's views in "Today in Parliament". As no Member who participated in the debate on the President's Address on that day was mentioned by name in the main News Bulletin, Shri Umanath's name could not be said to have been singled out for omission. I hope this clarifies the position . . .

SHRI RANGA: You must apologise.

SHRI SATYA NARAYAN SINHA: . . .that there was no *mala fide* intention on the part of the AIR. This was purely accidental. However, I have drawn AIR's attention to this, so that such situations do not arise in future.

SHRI P. RAMAMURTI: I want the protection of the Chair.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Sir, I want to raise a point of order. ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर के स्टेटमेंन्ट के बाद सवाल नहीं पूछे जा सकते।

SHRI P. RAMAMURTI: I want your protection, because it is a question of the House itself. Please listen to me. The Minister stated that Shri Umanath was covered in "Today in Parliament". (*Interruption*)

श्री प्रेम चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये नहीं बोल सकते हैं। अगर ये बोलेंगे तो हमें भी मौका देना पड़ेगा। ... (व्यवधान)... ये क्यों बोल रहे हैं? इनको बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ... (व्यवधान) ...

SHRI P. RAMAMURTI : I am addressing the Speaker. I have got the right to address the Speaker. I am addressing you, Sir. Sir, you have to protect me.

MR. SPEAKER: You may address me but do not ask any questions.

SHRI P. RAMAMURTI : Sir, it is for you to decide. I want you to exercise your judgment in this case and decide whether this matter should not go to the Privileges Committee and whether his explanation can be accepted. Here he says that Shri Umanath was covered by "Today in Parliament". If he goes through these bulletins he will find the same people have been covered both in this as well as in the news coverage several days. Therefore, the news coverage is entirely different from "Today in Parliament". When you cover the entire debate, the fact that on one particular day you did not mention the name of a person does not matter. But this debate lasted for four days and during those four days this was the only party which was not mentioned at all among the participants. For instance, in the second day it is mentioned here that a number of speakers referred to the law and order situation and the Opposition Congress said that if the State Governments undertake the nationalisation of industries the whole economy would be disrupted. Even there you could not mention that a member of the Communist Party (Marxist) participated in the debate, even if you do not wish to give his name. For AIR the mention of the word "Communist Party (Marxist)" is an anathema and the Minister is not prepared to express even a regret for that. He tries to give an explanation that is something else. The news bulletin is different from "Today in Parliament". Many people do not listen to "Today in Parliament". News bulletin is listened to by the entire people. I want to know why it has not been covered there.

SHRI SATYA NARAYAN SINHA: I had accepted that.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मेरा पौइंट आफ़ आर्डर है। आप सब लीडर्स आफ़ अपोजीशन को बुला कर इस की इन्क्वायरी कराइये। मेरे पास एक ऐसी टाक है जिस में एक पार्टी को मलाइन किया गया है। यह बहुत गलत बात है, बड़ा गम्भीर मामला है।

MR. SPEAKER : No point of order.

DR. RAM SUBHAG SINGH: Regarding this matter of Shri P. Tharyan being invited to make a broadcast over the AIR, I want this matter to be gone into. The AIR must be made to stop iniviting such people . . .

MR. SPEAKER: This subject is over.

12.55 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS 1970-71

MINISTRY OF HOME AFFAIRS—*Contd.*

MR. SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs. I would like to bring it to the notice of the House that only 3 hours and 40 minutes now remain. How much time does the Home Minister require to reply?

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): This is a very important debate. The time should be extended and the Home Minister should reply tomorrow.

MR. SPEAKER : Will you kindly resume your seat?

श्री ओंकार लाल बोहरा (चित्तौड़गढ़) : मान्यवर, सदन का समय बढ़ाइये।

अध्यक्ष महोदय : एक आदमी हर वक्त कैसे इतना सर खपा सकता है। आप थोड़ा सा मुझपर रहम कीजिये। मुझे तो सब के साथ निपटना पड़ता है, बड़ी मुश्किल है

The Minister has agreed to reply tomorrow.

SHRI RANDHIR SINGH: That is what I wanted.

MR. SPEAKER: So, you have got a big triumph.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, इस से दूसरी डिमान्ड में गड़बड़ हो जायगी। जो बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में तय हुआ था कि हर डिमान्ड पर विवाद होगा, वह निर्णय लागू होना चाहिये। अगर इस तरह से आप समय बढ़ाते जायेंगे, तो और डिमान्ड्स पर डिस्कशन नहीं हो पायेगा।

अध्यक्ष महोदय : एक तरफ कहते हैं समय बढाओ और दूसरी तरफ़ कहते हैं न बढाओ ।

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peermade): If you are going to extend the time in this way right from the beginning, we will be forced to guillotine the demands of many Ministries. We have to go by the report of BAC.

MR. SPEAKER : It is for the House to decide. If the House wants, the Home Minister can reply even today; I have no objection.

MR. SPEAKER: There are almost four hours left and up to 6 O'clock we will finish this. Later on we have to take up the other discussion. If they do not want to extend the time on this Demand, I would request every Member to consider his own case. I have such a big list from both sides. Then they should not press for any time for any Member from any party.

श्री कंवर लाल गुप्त : जिस पार्टी का जितना समय है उतना ही समय दिया जाय, और सवा पांच बजे मिनिस्टर जवाब दें ।

SHRI RANDHIR SINGH: We want the Minister to reply tomorrow.

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : यह बड़ी महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री है इस पर बहुत समय लगेगा । तो यही मान्यवर, फ़ैसला हुआ कि मिनिस्टर कल जवाब देंगे?

MR. SPEAKER: That is all right. The Home Minister will reply tomorrow. Shri K. K. Chatterjee may continue his speech.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI (Howrah): Mr. Speaker, Sir, yesterday when I started my speech I began by quoting a few lines from the report of the Home Ministry for the year 1969-70 from which it was quite evident that our Home Minister was fully aware of the fast deteriorating law and order position throughout the country. Shri S. K. Patil who, until the other day, was a minister of the Congress Party was fully aware that the law and order question was purely a State subject and that any undue interference by the Centre at this stage of our delicate relationship with the States was fraught with all kinds of dangers. Therefore, the Centre was exercising caution in the matter of dealing with the law and order situation in the States.

It was very hypocritical on the part of Shri S. K. Patil to condemn defections in a sarcastic way. Was it fair for him to condemn defections when he himself had crossed the floor of the House only a few days ago? But I have a different opinion about these defections. These defections, according to me, are a symptom of the confusion prevailing in the political life of the country. They may ultimately lead to fruitful complete polarisation in the political field. This polarisation may, after all, counteract the danger that is facing parliamentary democracy in the country today.

Socio-economic forces are responsible for the tension and violence prevailing in the country. The Home Minister is determined to fight this out by removing the causes that create these social and economic tensions in different parts of the country. I will remind this House of the solemn warning given by the great apostle of non-violence, the Father of our Nation, Mahatma Gandhi. In his memorable words he said:—

> "Economic equality is the master-key to non-violent independence. Working for economic equality means abolishing the eternal conflict between capital and labour. It means the levelling down of the few rich in whose hands is concentrated the bulk of the nation's wealth on the one hand and the levelling up of the semi-starved naked millions on the other. A non-violent system of government is clearly an impossibility so long as the wide gulf between the rich and the hungry millions persists. The contrast between the palaces of New Delhi and the miserable hovels of the poor labouring class nearby cannot last one day in free India in which the poor will enjoy the same power as the richest in the land. A violent and bloody revolution is a certainty one day unless there is voluntary abdication of riches and the power that riches give and sharing them for the common good."

MR. SPEAKER: He may continue after Lunch.

13 Hours.

Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[SHRIMATI SUSHILA ROHATGI *in the Chair*]

DEMANDS FOR GRANTS, 1970-71—*Contd.*

MINISTRY OF HOME AFFAIRS—*Contd.*

MR. CHAIRMAN: Mr. Chatterji.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI: Madam Chairman, I was just placing before the House the solemn utterances of Mahatma Gandhi, the last sentence of which is this:

> "A violent and bloody revolution is a certainty one day unless there is a voluntary abdication of riches and the power that riches give and sharing them for the common good."

Horrifying social and economic injustices, the appalling poverty of the people and the ever-increasing unemployment in the country have generated discontent of an explosive nature. Our Prime Minister and her worthy colleague, our Home Minister are both trying to push on with certain measures to fight out these evils which may one day endanger our national security. It is no wonder that the Naxalites and the Communists are trying to thrive on the woes and miseries of the people and in that process, Madam, all human values that are cherished in India are being slaughtered.

In this context I have to plead for more financial allocation for the Central Reserve Police Force. They are quite inadequate and they will be called upon in the near future to fight out in the various parts of the country anti-social and anti-national forces and to safeguard our national security and to see that the socialist objectives of the country are realised quickly so that the country may go through a peaceful progress. Nobody in this House will deny that no developmental progress is possible in an atmosphere of bitterness and horror.

With regard to corruption that is prevailing in the administrative machinery, I have one word to say. In the 78th Report presented to the House by the Estimates Committee on Central Bureau of Investigation, they point out that many of the complaints of the CBI cases are lying with the Ministries and the Departments of Government for a long time without any justice being done or action being taken. At page 85 the Committee says:

> "The Committee are deeply concerned to note the large number of Central Bureau of Investigation cases pending with the Ministries/Departments for disciplinary action; quite a substantial portion of these have been pending for a long time. Apart from the fact that delays in disciplinary proceedings whittle down the deterrent effect of punishment, the more prolonged the proceedings the greater is the difficulty experienced by the witnesses and greater still is the hardship to the public servant involved."

The CBI investigation in the States cannot get the co-operation from the State Police. On this point the Committee has said on page 11:

> "The Committee feel that the possibility of a divergence of opinion between the CBI and the State Police is inherent in the existing administrative understanding and working arrangement even though some guidelines have been laid down in regard to the type of cases to be handled by the CBI and communicated to State Governments. The fact that no difficulty in this regard has been felt so far does not rule out this contingency in future."

Therefore, I wish to remind the Home Minister about this fact that for better co-ordination between the CBI and the State Police a process has to be evolved so that we can get their co-operation. I would recall that in the Eastern Region of India the agents of Pakistan and China are very active, particularly, in my State of West Bengal. In that connection I have to remind our Home Minister that the Central Intelligence Services have been found wanting and we have to improve its working if we have to meet the challenge.

Then, Madam, with regard to the Border Security Forces, I would point out that the measures so far taken are inadequate to meet the challenge of the times. Unless the border is properly

Protected we will not be able to control the anti-national and anti-social activities prevailing in India. They are in such a volume already that it will probably be difficult for us to control this even if we exercise the greatest of caution. I would therefore plead with the Home Minister that the Border Security Forces have to be very much strengthened and also they should be provided with modern equipments, so that they can properly do their functions.

Then I wish to draw the attention of the Home Minister to the subject of the Bureau of Public Enterprises and their functions. It has been pointed out in the Report of the Estimates Committee that although the Bureau of Public Enterprises holds a panel of top executives, they have no such panel for the middle and junior executives who can be pooled in case of need. This should be attended to.

There is one more thing to which I wish to draw the attention of the Home Minister. That is, in the prevailing circumstances in West Bengal, we should deal with the situation in such a way that President's rule must be stabilised there and there should not be any question of mid-term election before peace is restored there. The people are still in a panic and terror and therefore things have to be stabilised there before we think of mid-term poll.

With these words I conclude.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): Madam Chairman, the Home Ministry's arena of operations is a very vast one, practically covering half of the Government of India's. It is not possible in this limited time at my disposal to make a comprehensive assessment of its multifarious activities, but the thing that depresses me most is one which is quite alarming. In this Report which the Ministry has brought out I find no attempt being made at a Central assessment of the problems which are worrying everybody. Here in this House this has been expressed in the speeches of so many hon. Members. That is to say, over the last year, has the general trend been in the direction of strengthening the forces of national integration or is the trend going the other way? Are the other forces which are working for disintegration of various kinds gaining the upper hand? There is no answer to this in this Report. Everything here is given in a very compartmentalised way. There is no general assessment made whatsoever. I would like to point out, Madam, if we are to think over it ourselves, though it is a depressing admission, we do find that the forces of disintegration seem to be growing and they are gaining the upper hand. This is the most alarming thing about it. Everybody has got his own remedy or diagnosis for this thing. Many people talked about violence and different manifestations of violence which are also on the increase. But, as far as I understand it, this violence is only a symptom. Violence in different forms is a symptom—it is not the basic cause of the trouble at all. The basic cause is something else and that should have been dealt with. These aspects have been referred to earlier by many speakers. For example take the question of Centre-State relations. I don't want to dilate on that. Have those relations become more harmonious or more strained? If they are becoming more strained then it devolves upon the Government of India seriously to apply its mind so as to bring about new changes in the structure of present Centre-State relations so that these tensions can be relieved and the pressures which are coming from the States for a further measure of decentralisation and for much greater share of powers must be attended to more seriously than it is being done so far.

Then, about the border disputes, several speakers have dealt with this point at length and I do not want to go into it, though I want to say one thing. There is no consistent principle or democratic solution being pursued consistently by the Government. A formula was laid down long time back about the basis or unit being taken as the village. Contiguity of territory and the language which prevails, the majority language, should be made the basis.

But we find in the various cases which have come up before us that no consistent principles are being followed by Government. What is being followed is political expediency. And once you replace principles by political expediency, then all sorts of opportunist trends are bound to creep in. That is what is happening now. In the case of regional disparities they are born out of economic imbalances. And all sorts of chauvinistic trends are growing. But

[Shri Indrajit Gupta]

there is some basis. The vast masses of people are feeling frustrated. Youth are feeling frustrated. Unemployment is growing. Causes of student and youth unrest which often manifest themselves in the form of some regional outbursts are not tackled seriously. They are not even discussed in any report that the Home Ministry gives.

Madam, the Shiv Sena has been invested with a halo of respectability now by the Ministry. Last year they created a commotion in Bombay which everybody decried. This year there was another commotion. All the powers that be, from the Home Ministry to the Maharashtra Government and to the Millowners in Bombay, everybody was prepared to conspire and collude with the Shiv Sena so that the whole city could be held to ransom. Shiv Sena has now attained respectability. What is the basis on which it rests except the worst kind of chauvinism and the worst kind of provincial hatred that is being fanned up by them?

In to-day's news-papers I find a report—I am sorry to state it—that the ruling party in Maharashtra is consulting the High Command as to whether they can enter into a Municipal Election pact with the Shiv Sena. How can you fight these tendencies of disintegration if political expediency is allowed to rule the roost like this? In this Gandhi Centenary year I need not remind you of what we have witnessed. Probably we witnessed one of the most barbarous and worst communal disturbances or riots in the city of Ahmedabad. We have witnessed probably a number of most savage and bestial pogroms—I will call it pogroms as it used to be called at one time—carried out against the poor Harijan population in many parts of the rural countryside in our country. What I wish to say is that the Government is drifting about this question. Violence is only an outward symptom of this basic malacy. The Government is drifting and the Government is compromising itself by following an opportunist path and I say it is unfair to put any blame on the National Integration Council or to criticise it. It has been reduced to a sterile nullity by the fact that it is not backed up by a proper administrative and legal action by Government. What can the National Integration Council do except to issue pious appeals and by expressing well-intentioned sentiments? Unless it has the support of government in the form of firm legal and administrative action the National Integration Council can never do anything.

The reason why I am stating this is that once you allow these unpricipled practices and this opportunist and political expediency to gain an upper-hand in all these different fields, even the remaining part of our system which was supposed to be above all these things, namely the judiciary—the administration and legislatures, are already infected—will also be affected. I say we are reaching that stage and I warn the Home Minister that he will not even be able to keep the judiciary fully insulated from this infection. The infection is beginning in a small way now. But it is beginning to penetrate into the socalled sacred realms of the judiciary. Somebody has raised a demand that certain Supreme Court judges for their improper conduct should be impeached. Some very eminent jurists are throwing up their hands in horror and shock. They are horrified and shocked to hear such a suggestion. The Supreme Court judges after all are men. If they are departing from well-established and accepted principles of jurisprudence and are violating certain well-established conventions, then nobody throws up their hands in horror and shock. I am referring of course to the controversy that is raging at the moment over the conduct of certain Supreme Court judges in the recent Bank Nationalisation Act which was struck down by the Supreme Court. This Act was struck down on the ground of the compensation principle being unfair and wrong, and it was found—I am not suggesting that these facts were kept hidden or undisclosed, no it was known—that two of the Honourable Supreme Court Judges were shareholders of some of these nationalised Banks, and therefore had an interest, direct or indirect, in the compensation which was going to be awarded by the Act. But they continued to sit on that Bench. My question is on the ground of impropriety and nothing else. I want to know if the Government defends the conduct of the Judges in this case. Should they not in all propriety have voluntarily withdrawn from the Bench which heard this case when they were themselves shareholders in the banks?

I do not want to take up much time, and I do not want to educate the Home Minister, because he knows much more about this than I do, but there are so many authorities on the subject which have said beyond a shadow of doubt as to what should be the position in such cases. May I quote just one or two?

Lord Campbell, Chief Justice of England has said:

"No one can suppose that Lord Cottenham—Lord Cottenham was the Lord Chancellor who sat in judgement in a case when he was a shareholder in a company which was concerned in that case—

> " . . . could be, in the remotest degree, influenced by the interest that he had in this concern; but it is of the last importance that the maxim that no man is to be a judge in his own cause should be held sacred. And that is not to be confined to a cause in which he is a party, but applies to a cause in which he has an interest."

Lord Cave, another notable Justice said:

> "If there is one principle which forms an integral part of the English law, it is that every member of a body engaged in a judicial proceeding must be held to act judicially; and it has been held over and over again that, if a member of such a body is subject to a bias, whether financial or other, in favour of or against either party to the dispute or is in such a position that a bias must be assumed, he ought not to take part in the decision or even to sit upon the tribunal."

These are all well-established principles laid down. Nearer home, our own Justice Gajendragadkar has said, I am quoting one of his observations :

> "It is an elementary rule of natural justice that a person who tries a cause should be able to deal with the matter before him objectively, fairly and impartially. As has been observed in the Jewitt's Dictionary of English Law, 'anything which tends or may be regarded as tending to cause such a person to decide a case otherwise than on evidence must be held to be biased.' If a person has a pecuniary interest in the case brought before him, that is an obvious case of bias which disqualifies him to try the causes."

Lastly, one more quotation I will give you from Lord Esher. Lord Esher held:

> ". . . The doctrine which is applied to judges, not merely of the Superior Courts, but to all judges, that, not only must they be not biased, but that, even though it be demonstrated that they would not be biased, they ought not to act as Judges in a matter where the circumstances are such that people, not necessarily reasonable people, but many people, would suspect them of being biased."

These are the well-established principles known to everybody and Mr. Chavan, I am sure, but the Government has remained silent. I want to know what their opinion is. In the court it was admitted that these two Judges of the Supreme Court who sat in the Bench which heard the appeals against the Bank Nationalisation Act were shareholders in those Banks. Was it not proper for them voluntarily to have withdrawn themselves? They did not do so. I see that some people are saying, because there is a talk going round of impeaching these two Judges and already over a hundred Members of Parliament have signed a petition to that effect, that politics is being introduced into the Supreme Court. I say that it is exactly the reverse. If the highest traditions, noble traditions, of the Supreme Court are to be upheld, it is by such vigilance of the Members that it can be done. It is the Judges who are allowing themselves to be infected by the general atmosphere of political expediency and opportunism, it is they who have introduced politics by the backdoor. This is the main point that I would like to make.

The other point is regarding the abolition of the privy purses. The report says that a Bill is being prepared and is to be brought before the House, and then, it says—I quote :

> "Details of transitional arrangements to enable the former rulers to adjust themselves to the changed circumtances are being worked out."

That means some sort of scheme is being prepared. I would like to know from the hon. Minister, because rumour hath it that the Cabinet which is discussing this matter at first considered that wealth-tax should be levied in the case of these ex-rulers on at least one

[Shri Indrajit Gupta]

building which is declared to be the official residence of that ruler. They may be owning ten buildings, but if one building is declared to be the official residence, wealth-tax should continue to be levied at least on that building and that on the purse income-tax should be levied. After that, some consolidated amount or something should be given to them by way of relief. But now, the report goes—I would like to know from him whether it is right or wrong—that there is a great deal of pressure being exerted to see that these people are exempted totally from both wealth-tax and income-tax. Also, I have heard that a scheme is being prepared under which an amount of Rs. 100 crores or more, with interest on the bonds, should be paid as compensation to these rulers. I want to know what is the position. In the name of abolishing the privy purse, are the common people of this country going to be saddled with another huge burden? They are not going to pay for this. I would warn the Government. Compensation in the case of the banks came to Rs. 80 crores or Rs. 85 crores. If the Government are preparing to pay again over Rs. 100 crores as compensation to these ex-rulers for the privilege of becoming the ordinary citizens of this country, the ordinary people of this country are not going to be saddled with this burden. I would like to know what is the exact position, and I would like to tell the Government that when they bring the Bill, if the Bill is not accompanied by a scheme, the scheme for transitional arrangements which will allow them "to adjust themselves to the new situation"—very nice language and that means there is a scheme—we will not support it. That scheme should come along with the Bill. If the Bill is presented to us minus any scheme, we will not be in a position to support it.

My last word to the Minister would be in his capacity as the employer versus the employees. 6,000 people are still facing prosecution in the courts, because of the strike of 19th September, 1968. They have condoned the break in service. But I would like to request him to be a little more generous and take steps to see that these cases are dropped. Although their service-break has been condoned, their promotion according to seniority and confirmation have been held up in their case, and the whole order of promotion, etc. has got upset. Therefore, I would plead for the normalisation of their position and would request him to see that these people, the strikers, whose service-break has been condoned now are not in anyway made to suffer on account of due promotion, seniority and so on.

Thank you.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Mr. Chairman, when Mr. S. K. Patil spoke yesterday, he primarily referred to boundary disputes that we are facing in various parts of the country. He started saying that he did not believe in the linguistic reorganisation of the States in the country. But then he again said that he wanted that the recommendations of the States Reorganisation Commission should have been accepted in toto. This has some contradiction which I could not understand, because he probably forgot that the States Reorganisation Commission had recommended the reorganisation of the administrative units in the country on linguistic basis. If the hon. Member was opposed to linguistic States, I do not understand how he wanted that the entire recommendation of the Commission should have been accepted. He pleaded for two in the same speech like that. Again, he started by saying that there should have been more respect shown to the recommendations of the Commissions and the kind of political decisions we took should not have been taken on such matters. He also went on saying that such matters should be referred to the Supreme Court for their decision. As we all know, the Supreme Court is primarily for adjudicating in matters of law, to interpret law and lay down case law by interpreting them. The forum for political decision or for political administration of the country is this hon. House. I do not know how we can refer such political matters to the judicial courts. I think it would be completely against the scheme of our Constitution if such matters were to be referred to the judicial forums. We all know that unless the decision of the government has evoked a measure of acceptability in the parties or in the region it is often necessary for us to come back to this House and change those decisions. I want to remind Shri Patil that even where the unanimous recommendations of the States Reorganisation Commission were accepted by the

government without any change, ultimately Parliament had to change those decisions because those decisions did not evoke that measure of acceptability which is necessary when such matters are decided and implemented.

I will remind him of the case of Punjab. The SRC did not want Punjab to be divided, but ultimately this House had to take a decision to divide that State. In the case of the erstwhile State of Bombay the recommendation of the SRC was that a bilingual State should be formed. Though that bilingual State was formed, ultimately that decision had to be changed by Parliament because the people affected by the decision did not accept that. I am mentioning these things only to prove that the solution does not lie in accepting the recommendations of commissions, however high and mighty they may be, without any concession and without accepting the political responsibility which any government of the day has to accept.

Therefore, the criticism of Shri Patil that the government has created these boundary disputes and that the government is responsible for it is absolutely wrong.

SHRI SHEO NARAIN (Basti): Then who is responsible for it?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: If you listen to me carefully, you will understand it.

We know that when India was conquered by the British, the administrative units in the country were created, not on any rational or logical basis but they were created on the basis of conquests; as they went on annexing various parts of the country, they formed certain administrative units here and there. Even before independence, the Indian National Congress, which then represented the will and the consensus of the country, had adopted a resolution saying that after the attainment of freedom, India shall be divided on a linguistic basis and the administrative units of India will be carved out on a linguistic basis.

What was the rationale behind it? The rationale was very simple. India during slavery was administered in English, which was not the people's language. It is a plain and simple thing to see that after independence in the democratic constitution and framework that we have adopted for ourselves it is absolutely necessary and compulsory that the administration of various administrative units of the country has to be carried on through the people's language. And if the people's language had to be used in the administrative units, only one language could possibly be used in a proper manner. If one language had to be used, this decision about linguistic reorganisation had to be taken.

We know what passions this linguistic question has given rise to in our country. I must give a compliment to those who were in-charge of this matter then, that they took a series of wise decisions and they organised the various administrative units on linguistic basis, and since then we have been trying to conduct the administration of these units in the people's language. We have had success in certain areas; in certain areas we have not succeeded. But to say that this decision was wrong, I do not accept that and I do not see how any political leader of eminence can oppose the linguistic States. As a matter of fact, linguistic States fortify the unity of the country. They do not give rise to any tendencies for division. Those who say English is serving as a link language and it would preserve the unity of the country should remember that English is only understood or spoken by less than 2% of the people of this country and this has happened after 200 years of domination of those people who wanted to impose English on this country. This shows the unfortunate past and this shows the predicament we have in our political life. In the Union we have adopted two official languages—English and Hindi.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi): We have only adopted Hindi and we have tried to bring English from the backdoor.

SHRI ANBAZHAGAN (Tiruchengode): It was actually English which was there for so long.

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash): What is the language of the State which is being inaugurated today?

MR. CHAIRMAN: Order, Order.

SHRI G. VISWANATHAN: It is English.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Because of historical reasons we have to take two official languages in the country. We have also to consider that there is a large chunk of our population which does not know Hindi which is our official language and it is our bounden duty to see that these people whose mother-tongue is not Hindi are given a chance to participate in the national affairs in the language in which they can understand and use. It is our established policy that there shall be no imposition of Hindi either directly or indirectly, and the promise that was given by the late Prime Minister Pandit Jawahar Lal Nehru that there would be a statutory recognition of this right of the non-Hindi speaking people of the country has been given effect to.

We have provided by law of this Parliament that English shall continue to be used in our country for the business of the Union Government as long as the last of the non-Hindi speaking States by a resolution in its Assembly desires the use of English to be discontinued. Till then English has to be used.

Apart from that we have also ensured that every employee of the Central Government is allowed to work either in Hindi or in English. There would be no imposition or compulsion on any Government employee of the Central Government to work either in Hindi or in English. They are completely free to work in the language that they choose. This has also been enshrined in the law of this Parliament.

The various measures that we have taken also show that anybody whose mother-tongue is not Hindi would be able to get into the services of the Union without any difficulty or disadvantage to him. Here I would recall the Resolution that this House passed which enjoined upon the Government to see that all the 14 or 15 official national languages of the country, which are mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution, would henceforth be used for recruiting persons to the highest services of the Union Government through the Union Public Service Commission. I am glad to say that the first such examination has been held by the UPSC in which candidates were given the freedom and the option to use any of the languages for two compulsory papers. According to the interim information that we have received from the UPSC it appears that about 10 per cent of the candidates, who appeared in the examination, utilised this concession in the first year. I am happy about this figure although there are obvious difficulties in appearing in an examination in two media, two papers to be answered in one language and the other papers to be answered in another language. That really causes a great deal of difficulty and disability to the candidate. Still, it shows how people are utilising these facilities which are being given. I want to assure the House that it is Government's established policy that on the basis of language nobody will be discriminated against and promotional prospects, working facilities or anything of the kind in the Central Government shall not be affected just because one belongs to a particular language group.

Before I pass on to other subjects, I would like to revert back to the subject of border disputes. There is one small thing that I omitted to mention and that was the current dispute between Maharashtra and Mysore.

SHRI SHEO NARAIN: Leave it for the Home Minister.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: This is a subject which I have been dealing with since the time I entered the Home Ministry in 1966. In our work allotment order, fortunately or unfortunately, this subject had been assigned to me before Shri Chavan came to the Home Ministry. This is a matter of record.

SHRI ANBAZHAGAN (Tiruchangode): When did the trouble start?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: The trouble started before Shri Chavan came into the Home Ministry.

The dispute is a very complicated dispute. I do not have to show how complicated it is; hon. Members of the House know how complicated this dispute is. To solve this dispute in an amicable and proper manner we will have to take very sound and very rational decisions.

SHRI YOGENDRA SHARMA (Begusarai): What is the basis on which you are trying to solve it?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: When passions are excited it is not very easy to solve these things rationally and on a logical basis.

AN HON. MEMBER: Principled basis.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: The Hon. Member knows that we have utilised principles to solve a dispute between Tamil Nadu and Andhra. The Tamil Nadu-Andhra border dispute has been settled on the basis of certain principles. Those principles could be utilised only if the parties concerned agreed to those principles. When there is no agreement on principles, it is difficult to apply . . .

SHRI YOGENDRA SHARMA: You apply the same principles here.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: The difference between the case of Tamil Nadu and Andhra and that of Maharashtra and Mysore is that, whereas, there, the Chief Ministers had agreed to certain set of principles to be applied, here, in spite of the best efforts, the two Chief Ministers have not been able to agree on any basis or on any set of principles on which this dispute could be solved.

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : दो स्टेट्स का सवाल ही कहां है ? वहां के लोगों से पूछना चाहिए ।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I would request him to ask a question after I have finished.

SHRI SHEO NARAIN: He should give a reply; he should have come prepared.

MR. CHAIRMAN: Mr. Sheo Narain, please stop this running commentary now. You don't have the right.

SHRI SHEO NARAIN: I have the right. We have a right to put questions.

MR. CHAIRMAN: I request you not to interrupt again. You do not have the authority unless it is given by the Chair.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I was saying that, when we try to solve the question on the basis of negotiation, when we want to settle it on the basis of. . . (*Interruption*)

SHRI SHEO NARAIN: You should control them also.

MR. CHAIRMAN: You should not dictate to me.

SHRI SHEO NARAIN: You should control them also.

MR. CHAIRMAN: I would again request you not to interrupt. You should not interrupt again.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I was saying that various attempts at an agreement have so far failed. I am not saying that there is no desire for an agreement between the parties. But the main difficulty is that this is a very very complicated and ticklish problem. When we started to look at it again, we thought that it was impossible to either fully accept the recommendations made in the Mahajan Commission Report or to fully, totally, reject them.

श्री योगेन्द्र शर्मा : लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्ज एप्लाई कीजिए । सब मामला ठीक हो जायेगा ।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: It is not possible either to fully accept what the Mahajan Commission Report says or to fully, totally, reject it. Therefore, we wanted to talk about this matter. The hon. Prime Minister was in touch with the respective Chief Ministers and she talked to them on the basis of certain provisional proposals that she had evolved. This negotiation is going on. I cannot indicate how long it will take before we can reach the end of the problem. But one thing I can make clear before the House, that we shall keep on endeavouring to reach a solution which will have the maximum acceptability with the two parties.

SHRI J. MOHAMED IMAM (Chitradurga): I think, the Minister is not giving a proper version. The Mysore stand has been that the recommendations of the Mahajan Commission's Report should be fully accepted.

MR. CHAIRMAN: You will have a chance to speak later. You can do that later.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I have already mentioned that it is not possible for us to apply those principles. We will be very happy to apply those principles. Those principles are very clear which could be applied. But I can tell the hon. Member, unless the Chief Ministers agree on a set of principles, it is impossible to apply those principles. . .

SHRI YOGENDRA SHARMA: That is the problem. You are concerned with the Chief Ministers. We are concerned with the principles. Here, you are running away from the principles. That is the difficulty.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: We are not running away from the principles. We are concerned with the agreement and the solution of the problem and, by whatever means we can do, we will try to get the solution of the problem.

MR. CHAIRMAN: Let the hon. Minister confine himself to the principles now.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I would mention something about the Union Territories. When Mr. C. C. Desai was speaking yesterday, he mentioned about the oil potential of Andaman and Nicobar islands and the potential of those islands for the development of tourist traffic and the development of a free port there. All these matters have engaged our attention earlier and the Oil & Natural Gas Commission has started surveying the area. That survey has not yet been completed. I suppose it will take about 2 years before the survey is completed. About other matters he mentioned like the development of free port and the development of tourist facilities there, the hon. House knows that these islands have very great strategic importance. If the security angle is not compromised, we can consider all these suggestions. But if the security caution is involved, we cannot compromise the security angle and take steps in the islands to develop them for tourist purposes. We want to develop these islands to the extent it is possible, but the security angle, as I was saying, will have to be kept in the fore.

Certain hon. Members have mentioned about the reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Services. We have answered several questions in this hon. House in the past few months indicating the new steps we have taken to increase the reservation and making the reservation more effective. As a matter of fact there was no difficulty about reservation as such. The difficulty mainly arose in filling these vacancies by competent and appropriate candidates. Various difficulties in this regard have been faced by us. The new decision that we have taken, particularly, about carrying over these vacancies for more period than before would help it.

In the case of All India Services, opening of some training institutes has helped a lot and now for the last few years we have been able to completely fill the vacancies in the All India Services and the Central Services which were reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We have also taken a decision to revise the reservation quota for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services on the basis of the census figures. These new reservations will be announced shortly.

Certain hon. Members had spoken about the All India Services. As the House knows, in the Chief Ministers' Conference a decision was taken in 1961 to create certain All India Services. Mr. Kandappan, when he was speaking yesterday, questioned the propriety of basing our decision on the recommendations made by the Chief Ministers in the 1961 conference. I may remind him that whatever we have done and whatever we are now doing is not based only on the recommendations of the Chief Ministers' Conference of 1961; but on the basis of those recommendations the Parliament considered this matter and the Parliament took certain decisions. An Act was passed and a resolution was adopted by the Rajya Sabha regarding this matter and on the basis of this parliamentary direction and the law passed by Parliament we have taken steps to create these All-India Services. Indian Forest Service has been created. Indian Engineering Service is about to be notified. The draft Rules and Regulations have been sent to the UPSC for approval and vetting. As soon as we receive them, we shall notify the constitution of the All India Service of Engineers. About the Indian Health and Medical Service, it is also in an advanced stage of being constituted. We have had certain communications or letters from State Governments where they have expressed certain reservations. One or two States wanted to opt out of the I. H. and M. Service which they joined before. We are now considering this entire matter and we will take a decision. In view of the representations and letters that we have received from various States we have to see whether we have to proceed with the new All-

Services or not. The decision will be taken shortly.

श्री योगेन्द्र शर्मा : पब्लिक सैक्टर के लिये इण्डियन इकानामिक सर्विस क्यों नहीं बनाते हैं ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: There are various other things that are under consideration regarding the public undertakings.

श्री योगेन्द्र शर्मा : इण्डियन इकानामिक सर्विस भी क्या कन्सीड्रेशन में है ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Madam Chairman, Mr. C. C. Desai while he was speaking yesterday mentioned about the privileges of the ICS officers and he referred to the points made regarding deletion of Article 314 to remove the privileges that have been given to ICS officers. The hon. Member, Shri Madhu Limaye has moved a non-official Bill regarding this matter. Mr. C. C. Desai's point was that Parliament was not competent to make any legislation to do anything about it. The advice that we have received from the Law Ministry is that Parliament is perfectly competent to legislate or take any action on it. This is the limited point of Mr. Desai's speech that I wanted to answer.

Then, the last point that I want to mention here is regarding the strike of the Government employees and here, the honourable House knows certain decisions that have been taken to normalise the situation and I am glad to say that the situation has almost come back to normal. There are some cases pending in the courts of law which we have not withdrawn. But those people who are facing these cases in the courts of law have been reinstated and they have been allowed to go back to work. It is our intention to see that nobody is unnecessarily harassed and nobody is punished without a verdict being given against him.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Is there any re-thinking about Delhi policemen also?

AN HON MEMBER: What about detention?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: We have announced this earlier also. If there are cases in which there is no evidence those cases will be withdrawn. We have withdrawn several cases in which we found that evidence against those people were not sufficient. But where there is evidence and it is seen that there is a sufficient evidence against those people, it will be difficult for the Government to withdraw such cases. It would be best if these cases are gone through quickly and then appropriate action taken. As the hon. Members know, out of 3 lakhs of employees, now there are a few left who are facing the cases in the court of law and who have not been reinstated in the Services. But we are going to review the entire position and we will see what can be done in the matter. (*Interruption*)

Shri Madhok was asking me about the Delhi Police.

15 hrs.

श्री रणधीर सिंह : हम सभी पूछते हैं, सारे ही इस में इन्टरेस्टेड हैं ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : हम लोग पूछते नहीं हैं, हम निवेदन करना चाहते हैं—अपने कर्मचारियों से मुकदमेबाज न बनिये, सुहृदय बनिये ।

श्री रणधीर सिंह : इन्होंने पहले एलान कर दिया वह सफीशिएन्ट है । बाद में होम मिनिस्टर साहब से हम और क्लैरिफिकेशन चाहेंगे । . . . (**व्यवधान**) . . .

SHRI PILOO MODY (Godhra): Whatever happens don't mention my name.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: All the hon. Members of Parliament have been raising this matter in this House and outside this House. A few days back, I had mentioned that we were having a new look at the case. We are examining this matter again. We shall really redress their grievances. I have also stated that we shall take a decision about this matter which will please the hon. Members who have been raising this matter from time to time.

SHRI PILOO MODY: No question of pleasing.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: What is the specific proposal; we want to know?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I would request the hon. Member not to press this matter. Let us solve this problem as amicably as possible.

श्री कंवर लाल गुप्त : बुलाकर बात करिएगा, एकतर्फा मत करियेगा ।

SHRI INDRAJIT GUPTA: Let him say one word about government employees with regard to their seniority, promotions, confirmations etc. When will they be normalised?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: We shall look into that.

श्री एस० एम० जोशी : मैं आपकी इजाजत से एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं । आपने बताया है कि दो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स जो हैं उनको एक्सी करना चाहिए लेकिन मैं तो बुनियादी सवाल उठा रहा हूं कि जब हमने लोकतंत्र को माना है तो दस लाख आदमी जो हैं उनकी राय लेनी है या नहीं लेनी है? जितना डिस्प्यूटेड एरिया है वहां के लोगों की राय लेने के लिए आप तैयार ह या नहीं कि कौन मैसूर में जाना चाहते हैं और कौन इधर रहना चाहते हैं?

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमें इस बात को बहुत ही प्रैक्टिकल दृष्टि से देखना पड़ेगा । जोशी जी जिन सिद्धान्त की बातों का जिक्र कर रहे हैं उनसे काम चलने वाला नहीं है । इस तरह की बातें करेंगे तो पता नहीं कितने सालों तक यह मामला चलेगा ।...(व्यवधान)...दोनों पार्टीज को मिलाकर दोनों से बातचीत करके ज्यादा से ज्यादा जो समझौता हो सकता है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं । सिद्धान्तों को लागू करना मुश्किल है यद्यपि अगर हम सिद्धान्तों को लागू करें तो सबसे अच्छा फैसला हो सकता है लेकिन जब सिद्धान्तों को लागू करने की स्थिति न हो तब हम क्या कर सकते हैं ।

MR. CHAIRMAN: Shri Badrudduja.

SHRI BADRUDDUJA (Murshidabad): Madam Chairman, at the outset, I add my feeble voice to the chorus of condemnation from all sections of the House of the dastardly attempt on the life of Shri Jyoti Basu and brutal murder of Ali Imam. The cult of violence and the hymn of hatred that has been systematically preached with impunity over the years has not only resulted in these attacks on individuals, but has also led to holocausts all over the country, resulting in horrible scenes of carnage and bloodshed which have disgraced the fair name of secular India. If the State administrations and the Central Government had adopted stern measures betimes, combated, resisted, thwarted and crushed the forces of darkness and destruction, the subversive elements in the country, if they had meted out condign punishment to miserants officials and non-officials alike—, these unfortunate happenings would have been things of the past. The administration, however, miserably failed to rise to the occasion with the result that holocaust, after holocausts, genocide after genocide and devastation of properties on a large scale occurred all over the country.

Madam, I congratulate the Central Government in one respect that they took an objective assessment of the recent developments in West Bengal. They arrested the drift and saved the fast-deepening crisis in Bengal. Unfortunately, however, the Governor of West Bengal has come in for scathing condemnation on the floor of this House. I do not hold any brief for the Governor, nor do I know anything about the secret parleys he might have had with the Home Minister or the Prime Minister at Delhi before he recommended President's Rule in the State. It has been insinuated that the voice is the voice of Jacob, but the hand is the hand of Yasu. I do not know if the Governor on his own initiative or on the advice of the Central leaders recommended President's Rule in West Bengal. Whether he did it on his own initiative or on the advice of others, he has done a very great service to much-distracted, much-agitated, much-distressed West Bengal. People of all classes and conditions in West Bengal including the hapless Muslim minority there has heaved a sigh of relief. Bombs have been unearthed these days, culprits have been rounded up and arrests are taking place. And it is so encouraging to see that the Governor of West Bengal rushed to the scene of disturbances after that tragic incident at Burdwan on the 17th March

to soothe the troubled heart of the unfortunate mother before whose presence two of her darlings were butchered and massacred in cold blood.

How I wish he went a step further and ordered a judicial enquiry into the communal killings at Naihati and Bansbania in Hooghly district, and also ordered a judicial probe into the more heinous, more ghastly incidents of deliberate, calculated murder in 24-Paraganas in the village Madhusudan Pore, where at the instigation of a local MLA belonging not to the CPM, but to such a constituent unit of the United Front, a mob was egged on, set upon six Muslim owners of paddy fields on the plea of robbing, looting and plundering the standing crops, and these owners of paddy land and two other youngmen, who had accompanied them were torn to pieces, limb by limb, cruelly butchered and massacred. The police were there, but no action was taken against the miscreants, not even against the MLA even when the Home Ministry was in the saddle, the whole thing was hushed up. It pains me very much to say this:

"खूं रे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले"

I have been all praises for the Communist friends, particularly for the CPM. Even now there are many friends among them with whom my relations have ever been so cordial. They stood by us in the hour of our greatest need. In 1964, 1965 and 1967, on three occasions, both the wings of the Communist party stood by the Muslims in a way which no other party in the whole of India did. That inspired confidence in us. It is not for nothing that I struggled, suffered, and almost risked my life in rallying round the banner of the United Front by far the largest Muslim voters in West Bengal for the first time in 1969 during 22 long years, which tilted the scales heavily against the Congress. But unfortunately we have been disillusioned so soon.

Madam we owe a deep debt of gratitude to the ex-Chief Minister Shri Ajoy Mukherjee for taking a courageous stand in ending the wretched show when he could not mend it. Madam I was at the birth of the United Front, naturally I was very much interested in its growth, expansion and development to the fullest stature. When he (Shri Mukherjee) announced that he was going to resign on the 16th March, I rushed to Calcutta and discussed with him all about the development in West Bengal. I was closeted with him for about an hour I urged him to explore all possible avenues for settlement of the vexed problem, for a *reapproachment* I told him to bide his time and postpone the day of reckoning. He replied, more in sorrow than in anger, that he was no longer to remain a silent spectator of the horrible excesses, wanton loot, plunder, murder of innocents, and even molestation of mothers and sisters. He said he must end this. And for this magnanimous act he has earned the gratitude of the people of West Bengal.

Madam, President's rule has now been imposed. Attempts are being made to restore the United Front and avenues are being explored for forming an alternative Government. I do not know how long it will take for normal conditions to be restored, but the longer the President's rule continues, the better for us. It is much more important for us that we must have a stable government, a cleaner government, a more dependable government, a more efficient government, a government sympathetic to the aspirations and responsive to the demands of the people, a government that can inspire confidence in the public mind.

Madam, I have a conviction, not an impression, that Communism has come to stay as a mighty force all over the world. It has swept across the continents like an elemental force, representing, as it does the urges of millions of have-nots all over the world. I believed that Communism had a future in India also. Madam, I am not a communist myself. I do not believe in the Communistic philosophy of life, in its policy of regimentation, a philosophy of life that denies political freedom, social freedom, cultural freedom, religious freedom, freedoms of all kinds and denominations. It negates all values—spiritual and moral upon which the structure of human civilisation has been reared up. It denies even the existence of God. But, Madam, behind the shimmering sea, the rushing wind, the vast illimitable ocean green verdure underneath, the star-spangled sky overhead and the beautiful sights and sounds of Nature, behind the laws of gravitation, correlation, conservation of energy, and

[Shri Badrudduja]

causation; behind the deepest throbbings of the human heart, the burning aspirations of the human soul, the innermost urges of the human mind, there is a Power that throbs in every constitution, pulsaties every atom, regulates and guides all existence, shapes the destinies of the human race and controls the growth and evolution of the universe and the systems of universes through all eternity.

And yet, we reallied round the banner of the Communists, in the hope that perchance they might come to our rescue, perchance they might come to our relief. I told some of our Communist friends including Shri Jyortimoy Basu, M.P. with whom my relations have been so cordial, "For God's sake, do not go so fast. Do not try to impose your will upon the whole State of West Bengal. There are also other progressive parties in the land, representing considerable volume of opinion. Grab by all means, loot by all means, plunder by all means, benami properties, but do not rob the poor agriculturists owning two bigas, three bigas, four bigas or 10 bigas of land, in the name of unearthing benami properties." I made this observation more in sorrow than in anger.

Madam, Now the Communists (Marxist) have isolated themselves, in West Bengal. Nine constituent units of the United Front were opposed to the formation of an alternative Government by Shri Jyoti Basu, the leader of the Marxist Party; the ruling Congress also ranged against them. 165 members in a House of 280 were opposed to them when formation of an alternative Government by Shri Jyoti Basu was being discussed and mooted by the Governor of West Bengal.

Madam, this is the unfortunate position there. Today I look upon the ruling party of India for guidance. For the first time, during the last 22 years, I have voted with this Government on many occasions. Since December, 1941 I have never joined any party. I broke away from the Muslim League on the issue of partition, lined up with the progressive forces and formed a coalition Ministry, with my leader, Mr. Fazlul Haq as Chief Minister, and Dr. Shyama Prasad Mukherjee, leader and founder of the Jan Sangh, as Finance Minister. We fraternised with the great Hindu Community, forming a government with the leading lights of both the communities. I expected that after Independence our friends, who were at the helm of affairs, would extend to us the same sympathy and consideration.

"व तजिल्लो मन तशांयताजे लो मन तशा व बे यदिल खैर अला कुल्ले शइन क्दीर"

(وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -)

Madam, Providence alone can raise one to the highest position. Mr. Chavan, you are today at the helm of affairs. Minorities look up to you for guidance, for quarter, for shelter, for recognition, for appreciation, for encouragement, for facilities for opportunities, for self-expression in every sphere of life, every domain of thought, every field of activity.

Madam, there are noble souls in the Congress, noble souls in the various sections of the House, some noble souls in the Jan Sangh, as well who are full of sympathy for us. But unfortunately, some of them are out to Indianise us. Madam, we are Indians; we have been born and brought up in India. Our great forebears and leaders, that brilliant galaxy of stars like Ali Brothers, Maulana Abul Kalam Azad, Maulana Hasan Ahmed Madani, Mzhar-Ul-Huq and Hazrat, Mohani shed an ineffable lustre on the political and cultural firmament of modern India, contributed so much in the struggle for independence and with their lofty idealism and burning patriotism, with their services, and sacrifices, with their vision, and imagination, with their sobriety of judgement and serenity of temperament, contributed to the political, the social and the cultural evolution of the mother land. Madam, we are not to be Indianised. Who could think of Indianising us when 80 million Muslims, ancestors with a great past, with a great history, with a great culture and cultural hegemony behind them contributed so magnificently to art, architecture, music, painting, philosophy and polity of India for centuries together?

I am not a believer in the theory of quantitative determination of human destiny. I can never persuade myself to

believe that arithmetical calculations and mathematical computations will determine human culture, human civilisation, human ideas, thoughts and aspirations. How can a sensible man believe that 51 per cent of even undersirable people, not by virtue of their superior wisdom and sagacity, not by virtue of their superior vision and imagination, not by virtue of their services and sacrifices, not by virtue of their significant contributions to the political and social life of the country, but by sheer force of numbers will impose their will upon millions of people who constitute only 49 per cent, may be linguistic, may be political, may be religious minorities? Madam, God declares in the Quran:

"लकव कतवना फिज निमवादिस ज़िक्रे इनल्ला अर्दा मूरोमुहा इवादिस सालेहुन"।

(لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض
يرثها العباد الصالحون)

"I have laid down in the Gospels that it is not by virtue of sheer force of numbers, it is not by totalitarian dictatorship that you are going to rule the roost or boss the show. Only well-meaning men like Mahatma Gandhi, men like Chitta Ranjan Das of revered memory, men like Asoka, men like Sher Shah Suri, men like Nasiruddin who by their unimpeachable integrity of character, mental catholicity, charity of outlook and their noble urge for the welfare of millions, will alone rule the world. Madam, the character of an administration is, to my mind, immaterial, whether it is bureaucratic, theocratic, democratic or even autocratic, provided the men at the helm of affairs are men of vision and imagination, men of lofty idealism, of mental catholicity, men of burning patriotism, men who inspire confidence in the public mind.

Mr. Chavan, I look up to you. Unfortunately, however, you have not played the game. But even now you have a great future because you are the biggest party. It is the great leader of your party, one of the greatest men in the modern world, Mahatma Gandhi, declared in the Nagpur Session of the Congress "I am a man of peace, I believe in peace, but I do not want that brand of peace which is in a piece of stone or in a grave; I want that peace which is imbedded in the human breast, exposed to the arrows of the whole world, protected from all harm by that Almighty God". This peace has got to be established and if need be, Shri Chavan will have to wage war against the forces of reaction, may be against Baddruduja, may be against Indrajit Gupta, will have to wage war against reactionary forces, the anti-social elements, anti-national elements, anti-secular elements, till they are crushed out of existence. For God's sake, do not hesitate there.

Unfortunately, however, the Congress did not play the game during these years. When the riots broke out in 1964 and when in 1965, in the wake of the Indo-Pakistan conflict, hundreds and thousands of innocent Muslims were thrown behind the prison bars, I thought that the game of Congress was up. At no distant date the Congress was thrown out lock, stock and barrel from West Bengal, Madras and Kerala and the Muslims contributed the most to the debacle of the Congress in these States. I would, therefore, appeal to the Congress Opposition and the ruling Congress to pause and consider. The Congress is the only party which had 50 years of leadership in India and 20 years' domination in the country. If you played the game, no other party could step in.

Madam, my hon. friends of the Communist persuasion might disagree with me when I say that I do not believe in a class-less society. We too belong to a class; we constitute a class which has contributed the most towards world civilisation and culture. We have produced the greatest teachers, philosophers, thinkers, statesmen, nation builders and administrators. We have contributed so magnificently to the cultural, political, social, moral and spiritual advancement of the entire human race. We do not want to be eliminated; we refuse to be eliminated. You have to provide all opportunities and facilities to the mazdoor, Kisans and other have not. Raise them by all possible means to the highest position, but we cannot crouch, sneak and skulk about like charity boys before them sacrificing our cultural identity, political integrity and social individuality before any section of the people—mazdoors, kisans, jotedars or zamindars, or even before rulers of the land. Much has been said about the unfortunate communal riots in the country and I would not today take-up the unpleasant past.

[Shri Badrudduja]

Madam, in a democracy the maiority must rule. Badrudduja will not aspire for the highest position; it is Shri Chavan, Shrimati Gandhi or Dr. Ram Subhag Singh who will rule. We will only cooperate, as I said, with those members and sections of the majority community who are sympathetic to us and who soothe our troubled hearts in our deep distress.

Madam, I was saying the other day—Mr. Chavan will not take it amiss—as to what has happened to the Mussalmans of India during the last 22 years. They are not found fit for any position today. Out of 7 million gazetted and non-gazetted officers, there is hardly 1 per cent of Mussalmans in the administration. If your administration could not protect the life, liberty, honour and property of the Indian Muslims, who constitute an integral part of the Indian nation, give us power and weapons to defend ourselves. We could defend ourselves before partition. 14 per cent Mussalmans in UP held their own against 86 per cent; 11 per cent in Bihar against 89 per cent even; 7 per cent in Madras against 93 per cent could protect their life and property from the vandalism of miscreants.

Madam, we are not concerned with one Zakir Hussain or Fakhruddin Ali Ahmed. I would say in all earnestness, the highest positions in the land should go to the members of the majority community. We do not claim them We will be quie satisfied with small mercies.

عطائے تو بلقائے تو بخشیدم
[عطائے تو بلقائے تو بخشیدم]

Your gift, Mr. Chawan, I return to you with all good grace. I only urge upon you to give us representation in the Services, adequate though it may not be when 80 per cent of Hindu youths are knocking about the streets for careers they must be provided; but Mussalmans should also be provided particularly in the police and the executive so that as magistrates and police officers they can give some sort of natural protection to Mussalmans who suffer so much during the riots.

Madam, about language many hon. Members have already discussed; said and I would not stress it further. I would only add that Urdu is the only language in India which fortunately enshrines the culture and cultural heritage of Islam. Why should not the Government come forward to recognise Urdu as a regional language which has been guaranteed in the Constitution? A section of the people in India may perhaps go against this language; but I do not understand why the Government should, in violation of the spirit and letter of the Constitution, deny regional character to Urdu which has been guaranteed unto it in the Constitution.

Madam, there are so many problems before us—problems, big with the fate of the community and the nation problems of a far-reaching significance, problems which are bound to have repercussions upon the growth and evolution of Indian society. Madam, we look towards a greater India, a happier India, a brighter India in which all of us, Mussalmans, Hindus, Christians, Buddhists, must contribute according to our own lights and convictions.

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : सभापति महोदया, मुझसे पहले भगवान पर विश्वास करने वाला और भगवान पर विश्वास न करने वाले दोनों पक्ष के सदस्य बोले हैं। एक पक्ष ने आर्थिक नीति के बारे में और सामाजिक तथा कानून के बारे में कहा है। मेरे कामरेड दोस्त ने होम मिनिस्टर की आलोचना की है और कुछ आशंकाएं भी जाहिर की हैं। दूसरे मेरे दोस्त ने बड़ा प्रभावशाली भाषण दिया है और उन्होंने जिन भावनाओं का और जिन भावनाओं के द्वारा अपने विचारों का उल्लेख किया है, उसकी तारीफ भी की जा सकती है। लेकिन एक ऐसा सवाल वे सामने लाए जो कि मुझे अखरता है। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग से कई चीजों की मांग की है और उनका गला भर आया था और वे इस तरह से बोल रहे थे कि जिससे सुनने वाला हर व्यक्ति उनसे हमदर्दी करता। लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह हकीकत नहीं है। हम जिस समाज में रह रहे हैं वह जम्हूरी समाज है और इस जम्हूरी समाज में हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई का कोई सवाल नहीं है। हमारा जो विधान है, उस विधान में हर व्यक्ति को तरक्की करने के, उन्नति करने के रास्ते खुले हुए हैं और अगर

हम विधान के बारे में शंकाएं रखेंगें, तो मैं समझता हूं कि समाज में कोई कितना भी बड़ा हो और वह कुछ भी विचार रखे, किसी प्रकार से भी रखे, हम उन विचारों का, हम उन भावनाओं का आदर नहीं कर सकते, क्योंकि अपने इस समाज को, हिन्दुस्तान को, इस भारत को, हमें एक बनाना है और इस भारत देश ने, जिसने बड़े कड़ुवे घूंट पिये हैं, 1947 में जो यह बंटा है और पंजाब और बंगाल के लोगों को जिस का पता लगा है, जिनको तजुर्बा है, मैं समझता हूं कि हमें कोई ऐसी नींव नहीं रखनी चाहिए, जिस नींव के द्वारा हम हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई के बारे में ऐसी बातें कहें । मैं माननीय होम मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि वे विचार जो उन्होंने कहे उनको और मेरे विचारों को अपने सामने रखें और कोई विवाद इस प्रकार से नहीं होना चाहिए ।

इस से पहले कि मैं कुछ और बातें कहूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं ने मेरे दोस्त श्री द्विवेदी ने कल जो भाषण दिया था, उस को पढ़ा था । मैं उन का भाषण कल नहीं सुन सका, लेकिन उन्होंने यह कहा था कि होम मिनिस्ट्री बिल्कुल असफल हो चुकी है और इस कारण हमारे होम मिनिस्टर को त्यागपत्र दे देना चाहिए । यह उन्होंने कहा था । श्री द्विवेदी जी मेरे दोस्त हैं और इस हाउस के सीनियर मेम्बर हैं, एक पार्टी के नेता हैं और मैं उनका आदर करता हूं पूरी तरह से, लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे कितना बड़ा हो, यदि हकीकत को नजरान्दाज करता है और एक आंख से देखता है तो हमारा फर्ज हो जाता है कि हम कहें कि वह दूसरी आंख भी खोले और उस आंख के खोलने के लिए मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं ।

एक माननीय सदस्य : अगर वह काना हो ?

श्री प्रेम चन्द वर्मा : काना हो, तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वे काने नहीं हैं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् 1947–48 का टाइम जो था, उस वक्त होम मिनिस्टर का जो काम था, वह बड़ा अहम काम था । 1950, 1951 और 1952 में 600 रियास्तों का मसला हमारे सामने था और हमारे होम मिनिस्टर सरदार पटेल ने उस मसले को बड़ी योग्यता से, बड़ी मजबूती से हल किया । उसके बाद आजादी के दिन आये, जवाहरलाल जी का युग आया और वह इस प्रकार से चलता चला गया कि किसी भी होम मिनिस्ट्री को कोई मुश्किलात सामने नहीं आई । लेकिन 1967 के चुनावों ने एक नई समस्या खड़ी कर दी. . . .

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभाध्यक्षा जी, मैं पूछना चाहता हूं कि सदन में किसी सदस्य को इस बात की आज्ञा है कि वह दूसरों को अपने साथ बिठाकर पान वितरण करे ?

सभापति महोदय : मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने इस ओर ध्यान आकर्षित किया । मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अगर यह हो रहा है तो इसको तुरन्त समाप्त करें और लाबी में जाएं ।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : मैं कह रहा था कि उस वक्त सरदार पटेल ने वह समस्या हल की और जवाहरलाल के युग में किसी होम मिनिस्ट्री को कोई समस्या नहीं आई । 1967 के चुनाव के बाद विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न दलों की सरकारें बनीं और आपको मालूम होगा कि एक-एक प्रांत में 14-14 पार्टियों की सरकार बनी, भानमती के कुनबे की सरकारें बनीं । उनके पिटारे बनते गये और टूटते गये और इस तरह कई सरकारें बनीं । वह सारी की सारी समस्याएं होम मिनिस्ट्री के सामने थीं । एक ओर तेलंगाना का झगड़ा, दूसरी ओर चंडीगढ़ का झगड़ा था । इस प्रकार अगर इस बात को कोई आंख बन्द करके देखता है और कहता है कि कोई समस्या का हल नहीं हुआ, तो यह उचित नहीं कहा जा सकता । जिस देश में खून की नदियां बहीं, लेकिन सारी की सारी समस्याओं को कंट्रोल किया गया । मैं श्री चव्हाण जी

[श्री प्रेमचंद वर्मा]

को मुबारकबाद देता हूं कि उनकी मिनिस्ट्री ने बड़ा कार्य किया । अगर कोई मैम्बर इस बात को नहीं मानता और इस प्रकार की बात करता है तो वह हकीकत को नजरअंदाज करता है । मैं तो हकीकत को हकीकत कहा करता हूं । हकीकत को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। इसलिये मैं श्री चव्हाण साहब को तथा उनके मंत्रालय को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत से काम ऐसे किये हैं जिनसे देश की सुरक्षा हुई थी और सब की सुरक्षा हुई। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी वह ऐसा करते रहेंगे ।

अब मैं आता हूं सबसे पहले डिमांड नं० 45 पर जिसमें पुलिस के बारे में लगभग 70 करोड़ रुपये की डिमांड्स हैं । मैं इस सिलसिले में एक बात कहना चाहूंगा । (घंटी बजती है)...ये मेरे सुझाव हैं, भाषण मैंने नहीं करना है । उस 70 करोड़ रुपये में से मैं चाहता हूं कि जो हमारा पुलिस का सिपाही है, उससे लेकर सब-इंस्पेक्टर तक की तनख्वाहों की देखभाल की जाए और उनको इतनी तनख्वाह दी जाए कि उनका पेट भर सके और उनके बाल-बच्चों का कुछ हो सके । इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस को इस ढंग से टेक्निकल और वैज्ञानिक शिक्षा दी जाए कि वह क्राइम को रोकने के लिए जरूरी कार्यवाही कर सके । उसके पास सब तरह के यंत्र हों ताकि वह मुजरिमों को ठीक ढंग से पकड़ सके और उनको सजा दे सके ।

डिमांड नं० 46 पर मैं कहना चाहता हूं कि उसमें 7 करोड़ रुपये जनगणना के बारे में हैं जो कि 1971 में होने वाली है । मैं कहना चाहता हूं कि जब हम सवाल पूछते हैं कि कितने बेरोजगार हैं तो उसमें यह भी पता लगाया जाए कि सरकारी नौकरी पर कितने हैं, उसके साथ ही खेतीबाड़ी कितने करते हैं । इसके अलावा मैं जो कहना चाहता हूं वह यह कि पीने के पानी जो कुदरत की चीज है, कितने लोगों को दे रखा है और कितने लोगों को ठीक तरह से मुहैया नहीं है । इस प्रकार की जो चीजें हैं वह जनगणना के फार्म में भरनी चाहियें । कितने लोगों को बिजली नहीं मिली, यह बात भी उसके साथ होनी चाहिए ।

अब मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूं, वह है मेरे प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में । मैं माननीय होम मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि उनकी अपील पर और हम सब लोगों की कोशिश पर जो एक लाख कर्मचारी वहां पर नान-गजटेड हैं उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और ऐसी हालत पैदा कर दी है कि शान्ति की हालत में उनके साथ बातचीत की जाए । उनकी मांग है कि पंजाब के स्केल्स उनको दिये जाएं । वह कहते हैं कि पंजाब के स्केल से हमें कुछ कम नहीं चाहिए क्योंकि पहले वे पंजाब में थे । मैं उम्मीद करता हूं कि जब हालत नार्मल हो गई है तो पंजाब के स्केल के बारे में उनके साथ बातचीत किस प्रकार से हो, उस पर वह हमदर्दी से गौर करें। उसके साथ ही विक्टिमाइजेशन के जो वहां केसेज हुए हैं, सस्पेंशन हो गई हैं, वह सारी बातें वापस ले लेनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि उनको कहें कि वह वापस ले लें ।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि बाउंडरी कमीशन...

सभापति महोदय : आपका टाइम खत्म हो गया । उनकी पार्टी का टाइम था ।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : चंडीगढ़ के बारे में हमारे साथ बेइंसाफी हुई है । हिमाचल प्रदेश को उसका हिस्सा नहीं मिला जब कि बाउंडरी कमीशन की टर्म्स आफ रिफरेंस में भी यह था । ऊना तहसील का इलाका हमें मिलना चाहिए था । उसके साथ ही कांगड़ा, नंगल, पठानकोट, मुकेरियां घाट और काल्का भी हिमाचल प्रदेश को दिया जाए तथा वहां के लोगों की जो मांग है उसका फैसला हो । उन लोगों को बुलाया जाए और पूछा जाए कि वह कहां जाना चाहते

हैं, अगर वह हिमाचल प्रदेश में जाना चाहते हैं तो उनको हिमाचल प्रदेश में भेज दिया जाए। स्टट के लिए बहुत दिन से हमारे प्रदेश ने मुकम्मिल सिफारिश की है। मैं भी स्टेट के लिए जैसा कि होम मिनिस्टर साहब कहते हैं, उम्मीद करता हूं कि जल्दी दे देंगे। मुझे उम्मीद है कि 1971–72 का जो बजट आने वाला है उसमें हिमाचल प्रदेश को पूरे स्टेट का दर्जा दे देंगे।

इसके अलावा सेंटर-स्टट रिलेशंस के बारे में रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने इस बारे में रिपोर्ट दी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि वह इस बारे में बतायें कि जो रिपोर्ट मिली है, उस पर सरकार ने विचार किया है ? अगर किया है तो उस बारे में क्या फैसला हुआ ? क्या ऐक्शन ले रहे हैं ? क्योंकि मैं चाहता हूं कि चाहे कोई भी प्रदेश सरकार हो, कुछ भी हो, प्रदेश सरकारों को इस प्रकार से कोई काम नहीं करने देना चाहिए जिससे कि सेंट्रल सरकार कमजोर हो और इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि कुछ भी तरीके अपनाए जाएं, कुछ भी सिफारिशें हों, लेकिन सेंटर को कमजोर करने की कोई बात नहीं मानी जानी चाहिए।

मेरा एक सुझाव यह है कि डिफेंस और कम्यूनिकेशन या रेलवेज के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ ही साथ ऐजुकेशन भी सेंटर के पास होनी चाहिए। एक सी एजुकेशन सारे प्रदेशों में हो, सारे देश में हो। यह जरूरी है कि हम सर्विसेज को राष्ट्रीय भावना दे सकते हैं, एक सी चीजें हम दे सकते हैं, इस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए।

इसके साथ ही मैं एक अर्ज यह करना चाहता हूं कि आइ० सी० एस० आफिसर और आइ० ए० एस० आफिसरों के जो विशेषाधिकार हैं वह समाप्त होने चाहिए। जब हम राजाओं को खत्म करने लगे हैं, उनके प्रिवी पर्स खत्म करने लगे हैं तो कोई वजह नहीं है कि हम आइ० सी० एस० आफिसर्स को विशेषाधिकार दें। उसके साथ ही आइ० ए० एस०, आइ० पी० एस० जितने भी सरकारी आफिसर्स हैं, इनके डाइरेक्ट रेक्रूटमेंट बन्द होने चाहिए और रेगुलर सर्विसेज में ही ज्यादा हिस्सा दिया जाना चाहिए ताकि वह लोग अच्छी तरह से काम करें।

सभापति महोदय : अब मैं आपको एक मिनट भी नहीं देना चाहती हूं। आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : तो मैं कहना चाहता हूं कि आइ० ए० एस० में जो जाते हैं, वह सीधे डी० सी० हो जाते हैं या सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस बन जाते हैं। उनको कोई तजुर्बा नहीं होता। मैं समझता हूं कि जो शिक्षा हमें मिलती है, उसके मुताबिक काम हो जाना चाहिए। मैं, जो समय आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य समाप्त कर चुके हैं अब वे अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री जे० मुहम्मद इमाम को बुला लिया है।

SHRI J. MOHAMED IMAM: Madam Chairman . . .

श्री प्रेम चन्द वर्मा : सभापति महोदय, मैं मिनिस्टर साहब के सामने देश की भावना रखते हुए कहना चाहता हूं . . . (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Order please.

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh): One request. Kindly complete one round of all the parties before you give time to a second representative of those parties, which have already spoken. Major parties have not spoken yet.

MR. CHAIRMAN: If the hon. Members kindly resume their seats I will be able to explain the position. The position as it stands now is SSP 14; CPI 16; BKD 8; Congress (O) 4; Swatantra 14; Jan Sangh 9 and CPI (M) 16 minutes. I would like to go according to the maximum time at the disposal of the party. I am calling them first. I called Swatantra first. After that I will call the CPI (M). (*Interruption*).

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : परम्परा अब तक यहां की यह रही है जैसा कि गोयल जी ने भी बतलाया कि एक बार सब पार्टियां और ग्रुप्स जितने भी है एक, एक व्यक्ति उन का बोल जाता है, एक राऊंड जब पूरा हो जाता है तो जो शेष समय रहता है उस में फिर बाद में उन के वक्ताओं को बुलाया जाता है ।

SHRI RANDHIR SINGH: One this side and one that side.

MR. CHAIRMAN: I was taking the time of the parties rather than the first or second round. It is up to the parties . . .

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peermade) : The usual practice is that major parties are all finished first.

MR. CHAIRMAN: All right. Already one Member has spoken from the Swatantra party. All right, I will give chance to the party which has not had a chance.

SHRI J. MOHAMED IMAM : I am already on my legs. You called my name.

MR. CHAIRMAN: I request you again. We shall follow the healthy conventions of the House. Your name will be taken up a little later. In respect of all those parties which have had one chance, I will call them later. I will call upon the CPI (M) which has 16 minutes at its disposal first. We shall follow the convention.

SHRI J. MOHAMED IMAM : You called my name, and I said 'Madam Chairman'. Now, strictly speaking, I was in possession of the floor. This is not the first time; yesterday also you called the Member of the Congress Opposition and he spoke and you called me. Now I am in possession of the House and if you ask me to sit down, I will have to protest against it.

MR. CHAIRMAN: I quite realise your point. I am telling you that you will be given a chance. There are certain parties who have not had a chance. I request you to give up the floor to them. You will get your chance in a few minutes. I hope you will kindly agree to that. I call upon the hon. Member from CPI (M) to speak.

SHRI P. GOPALAN (Tellicherry) : Madam, Chairman, I cannot proceed with my speech without having a look at the way this Ministry has been conducting itself by practising its favourite pastime of toppling operations. After 1967 elections, two non-Congress Progressive Governments emerged on the political scene of our country and these two governments were a direct challenge to the ruling party as well as the ruling government here. Since then this Ministry and our Home Minister, Shri Chavan sitting on the top of this Ministry are not happy at all. They toppled the two non-Congress Governments twice in Bengal and once in Kerala. We know that the head of the State Governor is appointed by the Union President. These governors are used as a convenient political tools. The Central Government and the Home Ministry used them to further their own political ends. The principles they have adopted in Kerala could not be adopted in West Bengal. In West Bengal, after the resignation of the Chief Minister, Shri Ajoy Kumar Mukherjee, the largest single party which was our Party must have been invited by the Governor to form the Government. But then the West Bengal Governor was given specific instructions by the Home Ministry not to invite Shri Jyoti Basu to form the Government. Shri Jyoti Basu was even prepared to prove his majority in the Assembly within two days of the forming of the Government. But then the Governor turned down this suggestion. He was not given that opportunity to form the government. But what they have done in Kerala is just contrary to what they have done in Bengal. After Shri Namboodripad resigned, Shri Achutha Menon was brought from Delhi to Kerala and he was asked to form the Ministry. On what basis was he asked to form the Ministry we do not know even now. The Chief Minister designate, Shri Achutha Menon categorically declared that he would not rule the State even for a single day with the support of the Congress Party. This was a firm declaration made by him, may be to hoodwink the people. Everybody knew Shri Achutha Menon had no majority among the MLA's without Congress support.

SHRI J. M. BISWAS (Bankura): That has been proved in the Assembly.

SHRI P. GOPALAN: Our party had a strength of 50 in the Kerala Assembly. The strength of S.S.P. members is 6. Both these parties declared that they were not supporting Shri Achutha Menon's Government; and one Member belonging to the K.T.P. and another as the K. S. P. along with two or three other independent members very clearly declared that they would not support Achutha Menon's Government. Thus the minority government was allowed to be formed in Kerala. He was given three long months to manipulate and prove his majority in the Assembly with Congress support. And even for convening the Assembly we had the Sacrifice of many lives. We conducted a bitter struggle and it was only after that that the Chief Minister was prepared to convene the Assembly and even now he is calling himself as a great democrat. This is double dealing. The Central Government have adopted different methods, one in Kerala and another in West Bengal. While in West Bengal Shri Jyoti Basu was prepared to prove his majority in the Assembly within two days he was not allowed to form the Ministry, in Kerala when Shri Achutha Menon was not even prepared to prove his majority in three months, he was allowed to form a minority government. And what was the expectation of Shri Achutha Menon? He said that half a dozen Communist Marxist members would defect to his side, that all the 6 members of the SSP would support him, even after the SSP leaders had firmly declared that they would not support him. It was on the basis of this anticipated election and support that Achutha Menon was invited. The reason for this is very clear. In Kerala they could have a sycophant's government through Shri Achutha Menon while in West Bengal they could not have a sycophant's government through Shri Jyoti Basu. So in Kerala they allowed it.

Here many members talk loudly about democracy. All this is mere bogus talk. They have no faith in and respect for democracy. This has been proved by the Home Minister's actions through the Governors in respective States. In identical circumstances, contradictory standards are adopted.

Here there are certain champions of democracy. We are dubbed wreckers of Constitution. Of course, our party is for a thorough change in the present Constitution. But every party is now championing the cause of democracy while actions prove otherwise. We know who has set a magnificient example for the democratic system in our country. When Shri E. M. S. Namboodiripad found he had no majority in Kerala Assembly within an hour he tendered his resignation and stepped down. But what have we seen in Haryana? When the so-called champions of democracy lost majority in the Assembly, they got the Assembly prorogued and thereby saved democracy! This is the wonderful spectacle we see at present. What happened in Jammu and Kashmir? When the champions of democracy lost the support of majority members, Shri Sadiq got the Assembly prorogued. This is how democracy was saved in these two States, by ruling Congress.

Some other members from the Opposition also shout so much about the sanctity of the Constitution and parliamentary institutions. But we have seen what happened in Gujarat. When they were about to face a snap vote against them, they immediately adjourned the Assembly. The same thing was done in Orissa where the Swatantra Party is in power. There also, when the big Champions found that they will have to face an adverse vote, they immediately adjourned the House. This is what we see.

SHRI PILOO MODY: A slight correction—it did not happen in Orissa.

SHRI P. GOPALAN: A much more strange thing happened in Kerala. The Assembly was adjourned. When was it? When the Central Committee of one of the constituent parties supporting the Government, took a decision, to quit the Government. (*Interruption*)

MR. CHAIRMAN: Kindly address the Chair. No disturbance please.

SHRI YOGENDRA SHARMA: Twice they have been defeated in the Assembly. How many times more they want to be defeated? (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please do not get yourself involved in controversies.

SHRI P. GOPALAN : They were asked to withdraw from the Government, because the other constituent parties also were asked to withdraw from the Government (*Interruption*)—the right Communist party, the Congress party—(*Interruption*).

SHRI VASUDEVAN NAIR: It is a lie. They have not withdrawn their support. (*Interruption*)

SHRI P. GOPALAN: That is their decision. Without allowing the Assembly to have a thorough discussion on the budget, the Assembly was adjourned by the Chief Minister. This is a wonderful thing we have seen. All these people are the champions of democracy. Shri E. M. S. Namboodiripad, when he lost the majority in the Assembly, within an hour, tendered his resignation. (*Interruption*)

SHRI VASUDEVAN NAIR: He was thrown out. They had to go out. What else could he do? (*Interruption*)

SHRI P. GOPALAN: Sir, I want five minutes; my time is taken away by such interruptions.

SHRI VASUDEVAN NAIR: What is there to boast about it ? When one loses the majority, one has to resign. (*Interruption*).

SHRI P. GOPALAN : Sir, this nonsense should be stopped.

SHRI RANDHIR SINGH: Sir, this should be expunged.

MR. CHAIRMAN: I want the hon. Member to address the Chair. He should not get himself involved with the hon. Members there, and that will keep away the controversy. Please continue, if you want to continue.

SHRI P. GOPALAN: Madam, there has been so much loud talk about Marxist violence. So many instances have been quoted here. Sometime back, an hon. lady Member of this House painted a harrowing tale saying that truck-loads of sarees were carried from Rabindra Sarovar Stadium in Calcutta. I do not know what happened to those truck loads of Sarees after the impartial enquiry. After that, I do not know where this truck-loads of sarees has disappeared !

Then came the story that 14 bodies were recently exhumed from a grave. But here is a report published in *Patriot* of March 26th. The Inspector-General of Police, Shri S. M. Ghosh, according to this report, has said that two skeletons of bodies have been dug out, which appeared to have been buried long ago. It was reported in a section of the press that 16 bodies have been recovered. This is the type of propaganda which is being let loose by certain interested parties and the press which is always against the Communist Party (Marxist).

Madam, what is the basic reason for this vilification against our party? You know the basic reason is that our party has strengthened its position in West Bengal. Here, I may just read a few sentences from an article published in the *Indian Express* of the 12th March, 1970, by its Delhi Editor, Mr. Nandan Kagal. He says in this article:

> "Mr. Jyoti Basu's party has not only a wide base in West Bengal both in the cities and in the rural areas; what is even more significant in the context of the long-rope theory, the CPM's popular base has become considerably wider and stronger since the second United Front Government was formed a year ago."

He goes on to say:

> "The CPM has improved its position considerably amongst all organised section in the cities, despite the counter-efforts of other members of the United Front, particularly the CPI."

This is the basic reason why our party is sought to be isolated and our party people are vilified.

16 hrs.

The same author says:

> "In the rural areas also, the CPM today is much stronger than it was when the second United Front was formed after the mid-term poll in February last year. Indeed there is some reason to believe that the CPM now has firmer control over the countryside than the Congress Party ever had in the past."

This is the conclusion of the *Indian Express*, which is not favourable to us,

which has written this article. He goes on to say:

> "The only thing that Mr. Mukherji's fast did was to expose the Chief Minister and his Bangla Congress to public ridicule."

Lastly he says:

> "President's Rule would no doubt have to be followed in due course by a fresh election in West Bengal. It is just possible that in such a poll the CPM might emerge with an absolute majority even if the other parties combine against it."

This is the basic reason why the other parties are trying to vilify our party and isolate us, talk about law and order, exhuming 14 dead bodies from the grave, etc. At this rate they can exhume any number of bodies in Calcutta and say that they are the bones of persons killed by the Marxist workers.

Lastly, I would say something about the Shiv Sena atrocities in Bombay. The other day when I spoke about it, Mr. Shukla intervened and said that whatever the Member has said was most irresponsible and unfounded but here is a speech made by a Member of the ruling Congress, Mr. S. B. Sawant, in the Maharashtra assembly. He says :

> "If the Government failed to put down the menace of the fascist Shiv Sena the organisation might become a Frankenstein."

He goes on to say:

> "A Government which cannot fight such tendencies has no right to remain in power."

And lastly he says:

> "The Shiv Sena had grown largely because of the acts of omission and commission of the State Government."

He himself has admitted it and he has also said that some top leaders of the administration are having close links with the Shiv Sena. I do not know whether the Home Minister also is having some link with the Shiv Sena. Therefore, I conclude by saying that the Home Ministry has all along been specialising in toppling operations, and therefore I oppose these Grants.

श्री नागेश्वर द्विवेदी (मछली शहर) : मैं गृह मंत्रालय की जो बजट मांगें हैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

इस में सन्देह नहीं है कि आज देश में असामाजिक तत्व अपना सिर उठा रहे हैं । उन्होंने साम्प्रदायिकता की भावना भड़काई है और क्षेत्रीय और भाषाई प्रश्नों को ले कर एक चिन्तनीय स्थिति पैदा कर दी है । यह सन्तोष की बात है कि पिछला वर्ष भाषाई विवाद के बिना शान्तिपूर्वक बीता है और उस वर्ष में भाषाई झगड़े नहीं हुए हैं । लेकिन उसी वर्ष में जब हम गांधी शताब्दी मना रहे थे साम्प्रदायिक झगड़ा हुआ और प्रान्तीय झगड़े भी उभड़ कर सामने आए और उस कारण से हमारे देश की काफी बदनामी हुई । इतना ही नहीं हम ने देखा कि उत्तर प्रदेश चोरियों, डकैतियों, तथा कत्ल की घटनाओं से काफी आतंकित भी रहा । इन चीजों की तरफ सरकार का ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिये । अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में निराशा ही हाथ लगेगी और यह समस्या सरकार के लिए बड़ी ही चिन्तनीय बन जाएगी ।

जहां तक क्षेत्रीय झगड़ों का सम्बन्ध है, दो प्रान्तों की सीमायें इधर उधर बदलने का सम्बन्ध है, जैसे चंडीगढ़ का सवाल है या बैलगाम का सवाल है, उनको छोड़ भी दिया जाए तो भी बम्बई जैसे शहर में शिव सेना का जो संगठन रहा है, उसके द्वारा उपद्रव भड़काये गये हैं और दूसरे प्रान्त वालों के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया गया है । आज भी वहां इस तरह की घटनायें हो रही है जिन के कारण दूसरे प्रान्त वाले चिन्तित हैं । मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी प्रान्तीय सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करें और उसको कहें कि इस तरह की होने वाली दुर्घटनाओं को वह रोके ।

आजादी के पहले हमारे देश में साम्प्रदायिक दंगे बहुत हुआ करते थे । आजादी के बाद, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बनने के बाद यह चीज काफी उग्र रूप में सामने आई । बाद

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

में उस में बडी कमी आई । लेकिन पिछले वर्ष जिस को हम गांधी शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे थे, अहमदाबाद की घटनाओं को लेकर सारे देश में और दुनिया में हमारी बदनामी हुई और चिन्तनीय स्थिति पैदा हुई । लेकिन एक बात की तरफ मंत्री महोदय ध्यान दें । ये जो झगड़े होते हैं ये शहरों में ही होते हैं जहां पढ़ लिखे लोग ज्यादा होते हैं, जहां जात और सम्प्रदाय की बात नहीं होती है, वहीं पर ये झगड़े होते हैं । लेकिन गांवों में जहां साम्प्रदायिक कट्टरता भी होती है, जहां विभिन्न जातियों के लोग भी बसे होते हैं, ये झगड़े नहीं उभड़ते । शहरों में ही जहां पढ़े लिखे, सुशिक्षित, सभ्य कहे जाने वाले लोग होते हैं और जो अपने को आगे बढ़ा हुआ समझते हैं, अपने को सक्रिय नागरिक कहते हैं, वहां पर ये झगड़े यदा कदा होते हैं । आखिर इसका कारण क्या है ? कारण को ढूंढ कर उसका पता लगा कर उसको दूर करने का उपाय किया जाना चाहिए ।

राष्ट्रभाषा का प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । पिछले साल भाषा को ले कर काफी काम हुआ है, इस दिशा में काफी प्रगति हुई है । लेकिन एक बात देखने में आती है । सन् 1965 से हिंदी राष्ट्र भाषा हो गई है और अंग्रेजी सहभाषा के रूप में चल रही है । लेकिन व्यवहार में देखने में यह आया है कि जैसे राष्ट्र-भाषा के पद पर अंग्रेजी हो और हिंदी सह-भाषा के रूप में चल रही हो । जिन चीजों का प्रकाशन सरकारी तौर पर होता है उनको पहले अंग्रेजी में दिया जाता है और बाद में उनका अनुवाद हिंदी में किया जाता है । होना यह चाहिये कि जिन को हम आसानी से हिंदी में दे सकते हैं, उनको पहले हिन्दी में दें और बाद में अंग्रेजी में दें अन्यथा दोनों को साथ साथ दिया जाए ।

जहां तक दक्षिण वालों का प्रश्न है, तमिल-नाडु के लोगों या डी० एम० के० वालों का सम्बन्ध है, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा कि पिछले साल उन्होंने भाषा को ले कर कोई आन्दोलन नहीं छेड़ा है और न ही कोई झगड़ा खड़ा किया है और न ही कोई उत्तेजना इधर उधर पदा की है । लेकिन कांग्रेस के नेता श्री कामराज के मद्रास के कुछ भाषणों से कुछ बुरा असर पड़ा है और अगर उन्होंने ये वक्तव्य न दिए होते तो यह झगड़ा खड़ा न होता । हम लोग जानते हैं कि जब मद्रास के मुख्य मंत्री श्री राजा-गोपालाचारी थे तब उन्होंने हिन्दी को बढावा देने का प्रयास शुरू किया था। उन्हीं के नेतृत्व में स्टेशनों पर हिन्दी में लिखें गए साइन बोर्ड को तारकोल से पोता गया था। कांग्रेस के नेता पद पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने उस मनोवृत्ति को नहीं रोका । 1967 के चुनाव से पहले भी उन्होंने इस तरह की बातें कीं और आज भी डी० एम० के० वालों ने जो इस बारे में फिर से बोलना शुरू किया है, उस का भी कारण उन का मद्रास का भाषण है । मैं समझता हूं कि इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के लोगों को सारे देश को ध्यान में रख कर बात करनी चाहिए ।

तामिल भाषा पुरानी है, उस का साहित्य पुराना है । उस में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं । लेकिन अपनी जटिलता के कारण कहिये, या कठिनाई के कारण कहिये, वह तामिलनाडु के अगल-बगल में भी नहीं बढ़ सकी है । तामिलनाडु के पड़ौस में ही तेलुगु, कन्नड़, और मलयालम बोलने वाले लोग हैं । लेकिन तामिल भाषा उन लोगों पर भी अपनी छाप नहीं छोड़ सकी है । प्राचीन काल से लेकर अब तक उस का दायरा बहुत सीमित रहा है ।

इस की तुलना में हिन्दी काफ़ी व्यापक क्षेत्र में प्रचलित है । जिस भाषा को लोग आसानी से समझ सकें, उसी भाषा का विस्तार होगा । भाषा की समस्या का समाधान एक राष्ट्रीय स्तर पर ढूंढा गया था, इस लिए अब उसके विरोध का कोई औचित्य नहीं है । जिस भाषा का राष्ट्र-भाषा के रूप में गांधीजी ने समर्थन किया था, उस के विरोध का कोई कारण नहीं हो सकता है । जब श्री कामराज जैसे नेता इस तरह की बातें करते हैं, तो स्वभावत: कुछ उत्तेजना पैदा होती है । यह मालूम होता

है कि वे क्षेत्रीय दृष्टि से नहीं, बल्कि राजनैतिक दृष्टिकोण से ऐसा करते हैं । दूसरी पार्टियां भी उस का फायदा उठाने की कोशिश करती हैं ।

चूंकि समय नहीं है, इस लिए मैं संक्षेप में अपने क्षेत्र की तरफ माननीय गृह मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं ने इस विषय में बहुत से पत्र भी लिखे हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित मछलीशहर की मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में डकैतियां और कत्ल बहुत बढ़ गये हैं । ऐसी हालत हो गई है कि एक एक थाने में कई कई कत्ल हुए हैं, लेकिन कातिलों का पता नहीं चला है । इस कारण उस क्षेत्र के लोग बहुत आतंकित हो गये हैं । आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकारें बदलती रहती हैं । वहां पर 1967 में एक सरकार बनी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही एक दूसरी सरकार बन गई और फिर राष्ट्रपति-शासन आ गया । मालूम होता है कि इस तरह से सरकारों के बार-बार बदलने का आम लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है और खास तौर से डकैतों और अन्य असामाजिक तत्वों को बड़ा बढ़ावा मिल गया है, उन में निर्भयता सी आ गई है । अगर इस तरह की घटनाओं की तरफ़ ध्यान नहीं दिया जायेगा, तो यह समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है ।

इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस स्थिति की तरफ़ प्रदेश सरकार का ध्यान दिलायें और वह जिन कत्लों और अपराधों का पता लगाने में असमर्थ रही है, गुप्तचर विभाग के द्वारा उन का पता लगाने की कोशिश करें ।

1967 के चुनाव के बाद राजनैतिक क्षेत्र में दल-बदल की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है । पहले लोग जिस पार्टी से चुने जाते थे, उन की निगाह में उस का एक विशेष महत्व होता था । कोई सैद्धान्तिक मतभेद होने के कारण किसी पार्टी को छोड़ना तो आपत्तिजनक बात नहीं है, लेकिन आज यह हालत हो गई है कि शाम को लोग एक सिद्धांत और विचार के समर्थक बनते हैं और सुबह उस का परित्याग कर के दूसरी तरफ़ चले जाते हैं । हम जात-पात ताड़ने और साम्प्रदायिकता से ऊपर उठने की बात करते हैं, लेकिन कुछ राजनैतिक दल और ग्रुप भी इसी आधार पर बनाए जाते हैं । दल-बदल की यह स्थिति शासन चलाने के लिए बड़ी ख़तरनाक है । इस सम्बन्ध में कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए । यदि एक व्यक्ति किसी पार्टी से चुना जाये और उस के बाद उसको छोड़ दे, तो उस का स्थान रिक्त समझा जाना चाहिए और वहां फिर से चुनाव कराया जाना चाहिए, क्योंकि जिस जनता के समर्थन से वह चुना गया था, दल-बदल कर के उस ने उस जनता की भावनाओं और इच्छाओं के विपरीत काम किया है ।

श्री ग़यूर अली खां (कैराना) : मोहतरिमा चेयरमैन, हमारा मुल्क एक अज़ीम मुल्क है और एक बहुत बड़ी जम्हूरियत है । इस मुल्क में होम मिनिस्ट्री सब से अहम मिनिस्ट्री है, क्योंकि जितने भी अन्दरूनी इन्तज़ामात हैं, उनमें ज्यादातर होम मिनिस्ट्री का दख़ल है । जिस मुल्क के अन्दरूनी इन्तज़ामात सही हैं, वही मुल्क मज़बूत और ताकतवर हो सकता है । जिस मुल्क के अन्दरूनी इन्तज़ामात सही नहीं हैं, जिस मुल्क में झगड़े-फ़साद होते हैं, वह कभी ताकतवर नहीं हो सकता है, न वह अपना डिफ़ेंस कर सकता है, न अपने मुल्क की तिजारत और सनअतों-हिरफ़त को तरक्की दे सकता है, न तालीम के मैदान में तरक्की कर सकता है और न ही अपनी हिफ़ाज़त और तरक्की के लिए कुछ सोच-विचार कर सकता है । वह अमन-शान्ति और ला एंड आर्डर को भी कायम नहीं रख सकता है ।

बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बहुत से झगड़े हैं, जिन पर तवज्जुह देना निहायत जरूरी है । अगर ऐसा न किया गया, तो मुल्क और डेमोक्रेसी को नुक्सान पहुंचने का अन्देशा है । हमारे सामने बहुत सी समस्याएं हैं, जिन को हमें हल करना है । हमारे यहां ला एंड आर्डर में कोताही है, अमन-शान्ति में कमी है, इलाकाई और लस्सानी झगड़े हैं, सरकारी मुलाज़िमों में अशान्ति है

[श्री ग़यूर अली खां]

और हमारे स्टुडेंट्स में इनडिसिप्लिन है। अगर हम इन सब मसलों की तरफ़ ध्यान नहीं देंगे और उन की तरफ़ से अपनी आंखे बन्द कर लेंगे, तो नतीजा यह होगा कि हमारे मुल्क को सख्त नुक्सान होगा।

यह एक नाकाबिले-इन्कार हकीकत है कि मुल्क के अन्दरूनी इन्तजामात करने के लिये पुलिस की जरूरत है, लेकिन हमारी पुलिस जनता की हिफ़ाजत करने और अमनो-अमान कायम रखने में बिल्कुल असमर्थ रही है। मुल्क में आये-दिन फ़िर्कावाराना फ़सादात होते हैं, लड़ाई-दंगे होते हैं, लोग लूटे जाते हैं, कत्ल किये जाते ह, मकानात को आग लगा दी जाती है और लोगों की प्रापर्टी बर्बाद की जाती है। लेकिन हमारी सरकार इस तरफ़ कोई तवज्जुह नहीं दे रही है। यह बात बड़ी ग़लत है। इस से मुल्क और डेमोक्रेसी को नुक्सान होगा।

पिछले साल काश्मीर में नैशनल इनटेग्रेशन कौंसिल का इजलास हुआ था। सैंटर में भी पार्टी लीडरस् की एक कांफ़रेंस बुलाई गई थी, जिस में यह तय हुआ था कि जहां भी दगे-फ़सादात होंगे, जहां भी कोई डिसटर्बेन्स होगी, इस कौंसिल के मेम्बर हर ऐसी जगह में भेजे जायेंगे। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि जहां भी कहीं झगड़े-फ़साद हुए हैं, या तकरार हुई है, या ऐसी समस्यायें पैदा हुई हैं, आज तक ऐसी किसी जगह भी इस कौंसिल का कोई दौरा नहीं हुआ है और न ही उन लोगों ने वहां जा कर यह मालूम किया कि किस की ज्यादती है और किस पर ज्यादती की गई है।

उस पर तमाशा यह है कि अगर कोई शख्स अज़खुद वहां जाने की कोशिश करता है, और जाता है, वहां के हालात मालूम करने के लिये, जो लोग सताये गये हैं, जिन के साथ ज्यादती की गई है, जो मज़लूम हैं, उन की मदद करने के लिए, तो उस पर एतराज किया जाता है, उस को फ़िर्कापरस्त, कम्यूनल, बताया जाता है, उस के मुताल्लिक कहा जाता है कि वह लोगों को उभाड़ने और उकसाने के लिए गया है। जब इलाहाबाद में फ़साद हुआ, तो राज्य सभा के मेम्बर, मौलाना असद मदनी, और यू० पी० कौंसिल के मेम्बर, मौलाना अब्दुल रऊफ़, उस फ़साद की खबर सुन कर लोगों को समझाने के लिए, उन की मदद करने के लिए, उन को तसल्ली और दिलासा देने के लिए वहां पहुंचे। लेकिन वहां की अथारिटीज ने, उन को पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया। अगच वे सरकारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी उन के साथ ऐसा बर्ताव किया गया।

अहमदाबाद में फ़सादात हुए। जब हमारे डिपुटी मिनिस्टर, श्री यूनस सलीम, मौलाना असद मदनी और दूसरे साहब वहां गये, तो गुजरात गवर्नमेंट ने उन पर इल्जाम लगाया कि ये लोग मुसलमानों को बहका रहे हैं, गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। अखबारों और मज़ामीनों में सेन्ट्रल गवर्नमेंट से शिकायत की कि ये लोग यहां के लोगों को बहकाने आये हैं, न कि अमन कायम करने के लिये। हकीकत यह नहीं थी, वे लोग देखने गये थे कि उन के हालात क्या हैं, उन को तसल्ली देने गये थे, उन के आंसू पूछने गये थे। मोहतरिमा, अगर यही हालत रबी तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी को खतरा है, इस मुल्क को भी खतरा है। हमें भाइयों की तरह से मिलजुल कर रहना चाहिये, एक दूसरे के जज़बात का अहतराम करना चाहिये, एक दूसरे की मदद करनी चाहिये, मज़लूमों की फरियाद सुननी चाहिये और उन की मदद करनी चाहिये। मेरी राय में अगर ऐसा कर दिया जाय कि जिन लोगों के साथ ज्यादती हो, जिन पर जुल्म हो, जिनकी जायदादों को जलाया जाय, तबाह-व-बरबाद किया जाय, उन की फरियाद सुनी जाय, उस के उपर एक्शन लिया जाय और यह भी किया जाय कि जो लोग उस के लिये मुलज़िम और मुजरिम साबित हों, उन पर सख्त तावानी-जुर्माने किये जांय। जो अफसर इन मामलों में कोताही करते हुए साबित हों, उन पर सख्त कार्यवाही की जाय, सख्त सज़ा दी जाय, तो मैं समझता हूं कि इस तरह से इस चीज को रोकने में, फिरकेवाराना

फिसादों और रोज रोज के दंगों को रोकने में मदद मिलेगी।

मोहतरिमा, तशद्दुद की फिजा इस देश में बढ़ रही है और उस को बढ़ावा देने में हमारा सियासी निजाम बिलकुल खोखला हो गया है। ऐसे मौके पर अगर हम लोग जम्हूरियत और अदमेतशद्दुद के जरिये से देश में बुनियादी परिवर्तन लाना चाहते है तो आज ऐसा वक्त आ गया है कि जब सब लोगों को इकट्ठा हो कर यह तय करना होगा कि हम सब लोग मिल कर इस के लिये कोई तजवीज सोचें, कोई हल तलाश करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस का नतीजा यह होगा कि देश को नुकसान पहुंचेगा।

अभी परसों की बात है—पटना स्टेशन पर श्री ज्योति बसु पर, जो बंगाल के डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर थे, गोली चली। इस से साफ़ जाहिर है कि तशद्दुद उभर रहा है और उसको तकवियत पहुंच रही है। यहां हम सब को मिल कर इस को रोकने की कोशिश करनी है। मुझे उम्मीद है हमारे चव्हाण साहब इस तरफ़ तवज्जह देंगे और इस का इन्तजाम करेंगे ताकि तशद्दुद न उभरने पाये और मुल्क को नुकसान न पहुंचे।

हमारे सामने दूसरी समस्या यह है कि हमारे सूबों की सरहदों पर झगड़े हो रहे है। एक सूबा कहता है यह जमीन मेरी है और दूसरा कहता है कि यह इलाका मेरा है। इस पर अक्सर झगड़े होते हैं। मैसूर-महाराष्ट्र का झगड़ा, बिहार और यू० पी० का झगड़ा, पंजाब और हरियाणा का झगड़ा इस की मिसालें है। ऐसे झगड़ों को तय करने के लिए हमारी सरकार फौरन कोई कार्यवाही नहीं करती। अभी परसों यहां पर एक सवाल था, जिसका जवाब देते हुए मिनिस्टर साहब ने बतलाया था कि वह मामला हाई-कोर्ट पटना के अधीन है—मैं बिहार और उत्तर प्रदेश के सिलसिले में अर्ज कर रहा हूं। लेकिन बाद में मालूम यह हुआ कि बिहार की आर्म्ड-पुलिस ने आकर यू० पी० के काश्तकारों की पूरी फसल कटवा दी और वे देखते रह गये। यह भी मालूम हुआ कि 7 आदमी इस के अन्दर कत्ल हुए—यह बड़े दुख की बात है। महाराष्ट्र और हरियाणा में भी पिछली दफ़ा आपने देखा कि क्या हालात हुए।

मैं आपके जरिये जनाब चव्हाण साहब से अर्ज करूंगा कि वह इन मामलातों में जल्द से जल्द तवज्जह दें और अगर कहीं ऐसा किस्सा खड़ा हो तो उस को कमीशन के जरिये फौरन तय करने की कोशिश करें, ताकि सूबों के ताल्लुकात खराब न हों, सूबों में रहनेवाले वाशिन्दों के ताल्लुकात खराब न हों।

हमारे यहां एक बात यह भी बहुत उड़ रही है कि यहां तीन सूबे ऐसे हैं यानी हिन्दुस्तान के तीन हिस्से ऐसे हैं जिन को आज तक स्टेटहुड नहीं दी गई है। अभी कल ही एक साहब मेरे पास आये और मुझ से कहा कि उन के कागज पर दस्तखत कर दूं। मैंने कहा—क्या चीज है। उन के कागज को पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि वह मणिपुर के लिये स्टेटहुड चाहते हैं। हिमाचल प्रदेशवालों का भी यही मुतालबा है, त्रिपुरावालों का भी यही मुतालबा है कि उन को स्टेटहुड दी जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को इस में क्या हिच है, क्या रुकावट है। वह इन हिस्सों को भी स्टेटहुड दे, ताकि उन को भी अपने अन्दरूनी मसायल को अपने जरायों से हल करने का मौका मिले, अपने इलाकों में वे आजाद हों और तरक्की कर सकें। हमारे सामने ऐसे बहुत से मसायल हैं जिन पर हम को तवज्जह देनी है और उन के कोई न कोई हल तलाश करने हैं।

अब मैं चव्हाण साहब की तवज्जह अकलियतों की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। करीब करीब तमाम अकलियतों के साथ नारवा बर्ताव किया जाता है, इन में हरिजन भी शामिल हैं। अभी पिछली दफ़ा मैंने अखबार में देखा था कि बर्तन की चोरी पर एक हरिजन को जिन्दा जला दिया गया, कई जगह हरिजनों को मार दिया गया। मेरे अपने जिले में पांच हरिजन मारे गये। मैं चाहूंगा कि अकलियतों का तहफ्फुज हो, उन के साथ हमदर्दी का सलूक किया जाय

[श्री गयूर अली खां]

हमारे मुल्क में जुबानों के मुताल्लिक भी झगड़े चल रहे हैं । हमारे मुल्क में आईन के मुताबिक 15 जुबाने ऐसी हैं जिन को रीजनल लैंग्वेज करार दिया गया है । उन में से एक जुबान उर्दू भी है । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उर्दू दिल्ली में पैदा हुई, दिल्ली में पली, दिल्ली में परवरिश पाई, यहां से चली और सारे हिन्दुस्तान में फैली । फिर भी बाज लोग गलतफहमी में उस को दूसरी जगह की जुबान बतलाते हैं, उस को मुसलमानों की जुबान बतलाते हैं, पाकिस्तान की जुबान कहते हैं—यह गलत चीज है । अगर हमारी कोई अच्छी चीज पाकिस्तान अपना ले, तो इस का मतलब यह नहीं है कि हम उस को छोड़ दें । उर्दू हमारी जुबान है, जो हिन्दुस्तान में पली, परवरिश पाई, तो हमें उस जुबान को उस का जायज हक देना चाहिये । कई साल हुए—जब हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद जी थे, उस वक्त 20 लाख आदमियों ने, जिनमें हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी शामिल थे, दस्तखत कर के एक मेमोरेण्डम उन की खिदमत में पेश किया था जिसमें हम ने दरख्वास्त की थी कि उर्दू को चार सूबों में—दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में —दूसरी सरकारी जुबान तसलीम किया जाय । मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वह उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान तसलीम कराने की तकलीफ़ गवारा फरमायें ।

सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एम्पलाइज के मुताल्लिक भी मुझे कुछ कहना है । अगरचे हमारे मुअज्जिज वजीर श्री शुक्ला साहब ने उन के मुताल्लिक बहुत कुछ कह दिया है और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने यह भी कहा कि वे उन 1500 दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के मामले में भी बहुत अच्छी तरह गौर करेंगे और उन के साथ हमदर्दी की निगाह से देखेंगे । मैं खुश हूं कि उन्होंने ऐसा कहा । मुझे उम्मीद है चव्हाण साहब उन सब को बहाल करने की तकलीफ़ गवारा फरमायेंगे और उन को खुश करने की कोशिश करेंगे ।

मोहतरिमा, मैं बड़ा मशकूर हूं आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मेरा जो टाइम बचा है, वह मेरे साथी निहाल सिंह जी इस्तेमाल करेंगे ।

श्री कुशक बाकुला (लद्दाख) : सभापति जी, गृह मंत्री महोदय ने जो मांगें पेश की हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । सन 1967 के बाद इस देश के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न दलों की सरकारें बनी और समाप्त हुई, उनके बीच में काफी झगड़े हुए । इसके अलावा हमारा देश इस समय काफी कठिनाइयों से गुजर रहा है लेकिन हमारे गृह मंत्री ने दूरदर्शिता से काम लेकर लोकतंत्र को सुरक्षित रखा, और इस देश में शान्ति बनाये रखी, इसके लिए मैं उनको मुबारिकबाद देता हूं ।

अब मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान लद्दाख की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । एक साल पहले हमारे लद्दाख में जो हालत थी वह सूरत अब इस समय नहीं है । जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर, श्री सादिक साहब ने लद्दाख के संबंध में काफी दिलचस्पी इस बीच में ली है । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पूरे तौर पर उसका समर्थन करता हूं । वहां पर जो गजेन्द्रगडकर आयोग नियुक्त हुआ था उसने अपनी कुछ सिफारिशें दी थीं । उनकी मूल सिफारिशें 11 थीं जिनमें से केवल 6 सिफारिशों को ही अभी तक लागू किया गया है और उनपर भी पूरी तरह से अमल नहीं किया गया है । उन्होंने सबसे आवश्यक सिफारिश यह की थी कि लद्दाख का एक कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए जो कि लद्दाख का मेम्बर हो तथा लद्दाख सम्बन्धी सभी शक्तियां उसी के सुपुर्द होनी चाहिए । लेकिन बड़े दुख की बात है कि अभी तक उस सिफारिश को अमल में नहीं लाया गया है । अभी तक केवल एक स्टेट मिनिस्टर लद्दाख का बनाया गया है और उसको भी लद्दाख अफेयर्स नहीं दिये गये हैं । पहले 14—15 साल तक वहां का डिप्टी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर रहा है फिर अब क्यों नहीं दे रहे हैं ? आज कल

लद्दाख एफयर्स एक ऐसे आदमी के पास है जो लद्दाख का रहने वाला नहीं है । लद्दाख अफेयर्स को कोई भी मिनिस्टर, जोकि लद्दाख का न हो, डील करें, इसपर हमें कोई भी आपत्ति नहीं है । लेकिन हमारे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वे रेल, मोटर और हवाई जहाज से चलना पसन्द करते हैं, लेकिन लद्दाख जाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है और घोड़ों की सवारी करनी पड़ती है और वहां पर खाने-पीने की सुविधा भी नहीं रहती है । इसके अलावा वे लद्दाख की जबान भी नहीं समझ सकते हैं । लद्दाख कितना बैकवर्ड है, कई सदस्य वहां पर गए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने देखा है कि उन लोगों के रहन सहन, खाने पीने और पहनने की क्या हालत है । इसलिए उसको यहां पर बयान करने की जरूरत नहीं है । जम्मूकश्मीर के मुख्य मंत्री यहां पर आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब उनसे कहेंगे कि लद्दाख को एक कैबिनेट मिनिस्टर दिया जाये । लद्दाख आज शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सभी दृष्टियों से पिछडा हुआ है । लद्दाख में पहले पहल स्वर्गीय पं० नेहरू जी की कृपा से तथा सेन्ट्रल गवर्नमेंट की दिलचस्पी से काफी कुछ हुआ है तथा अब उसी कार्य को श्री सादिक साहब काफ़ी दिलचस्पी लेकर आगे बढ़ा रहे हैं । मैं इसलिए उनका बहुत शुक्रगुजार हूं । उन्होंने एक कमेटी भी बनाई और कहा है कि पूरे लद्दाख जिले को बैकवर्ड क्लास में शामिल कर देंगे लेकिन वह कब तक होगा ? मैं ने यहां पर सवाल किया था कि लद्दाख को शेड्यूल्ड ट्राइब्ज या बैकवर्ड क्लास में रखना चाहिए लेकिन उस वक्त जवाब दिया कि संविधान का वह अंश जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है । लेकिन अब कहते हैं कि बैकवर्ड क्लास में शामिल कर देंगे परन्तु खाली एलान करने से ही तो नहीं हो जायेगा जबतक कि उसको किया न जाये । इस पर हमको सन्देह होता है। अगर जम्मू कश्मीर में संविधान का वह अंश लागू नहीं है तो उसको वहां पर लागू करना पड़ेगा । जब वहां पर एजिटेशन हुआ तो कह दिया कि कर देंगे लेकिन बाद में फिर कुछ नहीं होता है । इसलिए उसको वहां पर करना चाहिए । शेड्यूल्ड ट्राइब्ज में शामिल होना चाहिए । शेड्यूल्ड कास्ट का सवाल वहां पर इसलिए नहीं उठता है क्योंकि वहां पर ज्यादातर बुद्धिस्ट और मुसलमान हैं ।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, वहां पर काफी बच्चे शिक्षा में दिलचस्पी लेते हैं । डाक्टरी, इंजीनियरिंग और दूसरी टेक्निकल एजूकेशन वह लेना चाहते हैं लेकिन उनको सीट नहीं मिल पाती है । बहुत से बच्चे आई० ए० एस० बनना चाहते हैं लेकिन उसके लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्ज होना जरूरी है जिस से उनको कुछ कन्सैशन मिल सके । क्यूंकि लद्दाख के बच्चों की बुनियादी शिक्षा ही ठीक नहीं है इसलिए वहां के बच्चे दिल्ली और दूसरे प्रान्तों के बच्चों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं । इसलिए इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है ।

गजेन्द्रगडकर कमीशन ने एक सिफारिश यह की है कि जम्मू कश्मीर राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहिए ताकि उसमें लद्दाख का नाम भी आये जिससे लद्दाखियों का विश्वास प्रबल हो सके । वैसे लद्दाख की तरफ किसी की निगाह नहीं जाती है । अगर चीन का हमला हो जाये या पाकिस्तान की तरफ से गड़बड़ हो जाय तभी लद्दाख की याद आती है । इस वक्त तो लद्दाख का नाम तक नहीं है, जम्मू कश्मीर का ही नाम है । गजेन्द्रगडकर कमीशन की उस सिफारिश पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि किसी न किसी दिन झगड़ा जरूर होगा, वहां के लोगों को एजिटेशन करना पड़ेगा और वहां के लोग एजिटेशन करेंगे ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि लद्दाख के लिए एक डेवलपमेन्ट कौंसिल बनाई गई है, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि उससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि उस के पास कोई पावर नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पहले

[श्री कुशक बाकुला]

लाहौल स्पीति में टगर कौंसिल बनी हुई थी जिसको कि पूरी पावर्स थी उसी प्रकार से पूरी पावर्स देकर के लद्दाख की डेवलपमेन्ट कौंसिल को भी बनाया जाना चाहिए ।

इसके साथ साथ एक बात मुझे यह कहनी है कि प्रीवी पर्स को यहां खत्म कर दिया गया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उसके बारे में निर्णय लेना चाहिए । मैं इसी सिलसिले में लद्दाख के राजा के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं । वहां पर राजा महाराजा तो कोई होता नहीं था लेकिन राजा का नाम है । लद्दाख पहले तक स्वतंत्र राज्य था तथा वहां पर लद्दाख के राजा जिसका वंश, अभी तक कायम है, राज्य करता था । मैं इस बेसिस पर यह क्लेम कर सकता हूं कि लद्दाख को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिये । परंतु मेरी इस बात पर अब लोग हसेंगे क्योंकि मैं स्वयं समझता हूं कि यह सम्भव नहीं है । पर मैं तथा लद्दाख की जनता यह जरूर चाहेगी कि लद्दाख के राजा जिसके पूर्वजों ने स्वतंत्र लद्दाख पर राज किया था, को कुछ इमदाद दी जाय क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इस समय अत्यन्त दयनीय है । उनकी प्रीवी पर्स का भी कोई सवाल नहीं है । उनका साधारण लोगों की तरह से भी गुजारा नहीं हो पाता है । जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से उनको साल में 6 हजार रुपए मिलते हैं लेकिन उससे कोई काम नहीं चलता है । उनके पास बहुत से मंदिर हैं, उनको कुछ न कुछ पूजा करनी होती है और नया साल आने के मौके पर बहुत खर्चा करना पड़ता है । जो रुपया मिलता है वह उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी पूरा नहीं हो पाता है । उनका सालाना खर्चा करीब 53,225 रुपए होता है । लेकिन उस को पूरा करने के लिये, इस वक्त जो नये डेवलपमेंट कमिश्नर भजे हैं, उन्हों ने इंसाफ़ कर के 10,000 रु० के लिये सिफारिश की है । जो मेरी राय में काफ़ी नहीं होगा, इस रकम को और बढ़ाना चाहिये । जो इस वक्त के डेवलपमेंट कमिश्नर हैं वह नौजवान और सोच समझ कर काम करने वाले व्यक्ति हैं, और मुझे आशा है कि उन के द्वारा अच्छा काम होगा ।

आप ने सुपरिन्टेंडेंट पुलिस को भी यहां से ही भेजा है, वह भी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन इस बारे में मुझे यही कहना है कि जब लद्दाख के पढ़े लिखे नौजवान लड़के वहां मौजूद ह तो उन को पदोन्नति का अवसर क्यों नहीं दिया जाता ? कारगिल के वहां दो मुसलमान आदमी हैं, एक का नाम श्री हसन खां है और दूसरे का नाम श्री मुहम्मद अब्बास है । एक और हमारे बुद्धिस्ट भाई हैं जिन का नाम श्री कोनचोक हैं जो बहुत काफ़ी बात से वहां डी० एस० पी० हैं । आप उन को एस० पी० क्यों नहीं बनाते हैं ? जब लद्दाख के पढ़े हुए लोग हैं तो उन को मौका मिलना चाहिये ।

लेह में पन-बिजली के स्तकना प्रोजेक्ट को आप ने हाथ में ले लिया अच्छा किया । लेकिन लद्दाख में तीन तहसीलें हैं—लेह, कारगिल और एक छोटी तहसील ज़ान्सकर । इस छोटी तहसील में भी एक डीज़ल जैनरेटर लगाना चाहिये और पानी के द्वारा भी बिजली पैदा करने की कोशिश होनी चाहिये । कारगिल इलाके में एक मुरू नाला है, वहां से पनबिजली तैयार करने की एक स्कीम है लेकिन जो बिजली वहां पैदा की जायगी वह सिर्फ मिलिटरी की जरूरतों को ही पूरा करेगी लेकिन वहां के सिविल लोगों को इस स्कीम से कोई लाभ नहीं होगा । मेरी प्रार्थना है कि सिविल पौपुलेशन को भी बिजली देनी चाहिये । लेह में बुद्धिस्ट ज्यादा हैं, तथा कारगिल में मुसलमानों की संख्या अधिक है । अगर कारगिल में बिजली नहीं मोहिया की गई तो वहां चूंकि मुसलमानों की संख्या अधिक है इसलिए हो सकता है कि वहां के मुसलमान भाई यह सोचें कि उन के साथ भेदभाव किया जा रहा है और इस के लिये केन्द्रीय सरकार को दोषी ठहराया जा सकता है । इसलिये वहां भी बिजली का प्रबन्ध होना चाहिये । मैं ने इस बारे में होम सेक्रेटरी से बात की थी और उन को लिख रहा

हूं, होम मिनिस्टर से कहूंगा कि इस साल वह कारगिल में पनबिजली प्रोजेक्ट शुरू करें।

हिंदुस्तान में बौद्धों की संख्या कम है पर उन थोड़े लोगों पर भी जुल्म हो रहे हैं । अगर लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता है तो लोग उस का विरोध करते हैं, जब कि यदि यही काम और धर्मविलम्बियों द्वारा किया जाता है तो कोई उस की चिन्ता नहीं करता । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उस का विरोध नहीं होना चाहिए । डा० अम्बेडकर ने लोगों को बौद्ध बल प्रयोग कर के नहीं बनाया था बल्कि भगवान बुद्ध का शान्ति, अहिंसा और मित्रता का संदेश दे कर लाखों लोगों को बौद्ध बनाया था, और यह लोग ज्यादातर अनुसूचित और आदिम जन जातियों से आये थे । बौद्ध धर्म में आने से पहले जो अनुसूचित जाति में होने के कारण उन को कुछ सुविधायें मिलती हैं वे सुविधायें उनके धर्म परिवर्तन के बाद बन्द कर दी जाती हैं । यह सरासर अन्याय है । पिछड़ी जातियों को कन्सेशन देने का पर्पज यह है कि उनको और जातियों की बराबरी में आने का चान्स हो । पर बौद्ध धर्म कबूल कर लेने से ही उनका यह पर्पज पूरा नहीं होता । उनकी स्थिति वैसी ही रहती है । अतः मेरे विचार में यह कन्सेशन उनको मिलना चाहिये । माननीय चव्हाण साहब जब महाराष्ट्र में मुख्य मंत्री थे तो उन्हों ने कुछ लोगों को सुविधायें दी थी । अब वह केन्द्रीय सरकार में गृह मंत्री हैं इसलिये उन से मेरी प्रार्थना है कि वह बौद्ध लोगों की मदद करें, और देखें कि उन को किसी प्रकार की धमकियां लोगों द्वारा न दी जायें ।

अब मैं एक बात नेफ़ा में स्थित तावांग मोनास्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं । यह स्थान चाइनीज़ सीमा पर है । उस मौनास्ट्री के हैड लामा वहां के करीब 200 बच्चों के लिये एक एजूकेशनल इन्स्टीटयूशन खोलना चाहते हैं । उसके लिये उनकी आर्थिक सहायता की आवश्यकता है । मैं गवर्नमेंट से यह प्रार्थना करूंगा कि इस शुभ कार्य के लिये उनकी सहायता करें । इसके अतिरिक्त तवांग के सेला पास के जरिये एक सड़क द्वारा देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा जाय ताकि वहां की तरक्कीयाती कामों के करने में आसानी हो । इसके अतिरिक्त वहां पर पीने के पानी तथा सिंचाई के साधनों की उचित व्यवस्था बहुत जरूरी है ।

मैं इन शब्दों के साथ गृह मंत्री द्वारा पेश की गई मांगों का समर्थन करते हुए अपना विचार समाप्त करता हूं तथा आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर दिया ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभाध्यक्षा जी, हमारे देश में गृह मंत्रालय का और गृह मंत्री का कितना महत्व है इस का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में गृह मंत्रालय का दायित्व सरदार पटेल ने स्वयं अपने कंधों पर लिया । सरदार पटेल का साहस, उन की निर्भीकता और उन की प्रतिभा तीनों ही गृह मंत्री के लिये आदर्श का काम कर सकती हैं । परन्तु दुर्भाग्य से सरदार के पश्चात् इन तीनों बातों में कुछ न्यूनता आती हुई दिखाई देती है । उदाहरण के लिये एक ही बात मैं कहना चाहता हूं । 1962 में जब हमारे देश पर चीन का हमला हुआ तो 14 नवम्बर, 1962 को हम ने इसी सदन में खड़े हो कर के सब ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिस के शब्द थे कि "भारत की धरती जब तक हम स्वतंत्र नहीं करा लेते शत्रु से तब तक हमारा यह संघर्ष बराबर जारी रहेगा भले ही वह कितना ही लम्बा क्यों न हो ।" लेकिन कुछ दिन बाद आग चल कर जब राष्ट्रीय एकता का एक सप्ताह या दिवस मनाना हम ने प्रारम्भ किया तो हम ने उस प्रतिज्ञा को कुछ दूसरे शब्दों में बदल दिया । और उस प्रतिज्ञा के शब्द यह थे : "मैं अपने देशवासियों के संकल्प को दोहराता हूं कि मैं अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता तथा एकता की रक्षा करूंगा चाहे इस के लिये संघर्ष कितना ही कड़ा और लम्बा क्यों न करना पड़े । मैं राष्ट्रीय एकता तथा सबलता के लिये तन मन से काम करने की शपथ लेता हूं ।" लेकिन इस बार राष्ट्रीय

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

एकता सप्ताह के सिलसिले में एक छोटा सा प्रकाशन भारत सरकार की ओर से प्रकाशित हुआ है । इस प्रकाशन में स्वयं इन्हों ने लिखा कि 1962 में चीन द्वारा आक्रमण के बाद शपथ की भाषा में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है, और जो शब्द परिवर्तित किये गये हैं उन को भी मैं सुनाना चाहता हूं । "मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा और मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा, प्रान्त संबंधी तथा अन्य सभी राजनीतिक और आर्थिक विवादों का शान्तिपूर्वक और संवैधानिक उपायों द्वारा हल किया जाना चाहिये ।"

अब मैं आप के माध्यम से जानना चाहता हूं कि 1962 में जो संसद ने यह निर्णय किया था क्या भारत सरकार अपने उस निर्णय से हट रही है ? और अगर अपने निर्णय से हट नहीं रही है तो यह जो एक सरकारी प्रकाशन है कि जिस में 1962 की शपथ में परिवर्तन किये गये हैं उस के आधार क्या हैं ? क्या इसे हम यह समझें कि चीन का किसी तरह का दबाव इस प्रकार का पड़ रहा है कि जिस ने सरकार के सोचने के ढंग में परिवर्तन कर दिया है ? मैं गृह मंत्री महोदय से विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल जिस आसन पर बैठ थे आज आप उस आसन पर बैठे हैं और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व आप के कंधों पर है । इस प्रकार के ये प्रकाशन जो सरकार की दुर्बलता के परिचायक हैं इन के सम्बन्ध में आप को गम्भीरता से कुछ निर्णय लेना चाहिये और सोचना चाहिये कि कौन तत्व हैं इस प्रकार के जो संसद के निर्णय के खिलाफ़ इस प्रकार के प्रकाशन कराते हैं ।

दूसरी बात मैं साम्प्रदायिक तनावों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । इस साम्प्रदायिक तनाव से निश्चय ही हमारे देश की जो आंतरिक स्थिति है उस में चिन्ता व्याप्त है और दुनिया के दूसरे देशों में हमारा देश बदनाम होता है । पहले मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अब तक जितने भी साम्प्रदायिक उपद्रव हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद हुए हैं, गृह मंत्रालय इस बात की जानकारी ले कि इन का प्रारम्भ कहां से होता है और कौन उन का प्रारम्भ करता है ? अगर इस देश का बहुमत उन का प्रारम्भ करता है अपने संख्या बल के दुरभिमान में, तब तो मेरा कहना यह है कि बड़ी कड़ाई के साथ उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिये । और अगर अल्पसंख्यकों की तरफ़ से प्रारम्भ होता है तो मैं समझता हूं कि उन के अन्दर इतनी अज्ञता नहीं होगी । जब वह जानते हैं कि इस का परिणाम यह होगा कि हम को और हमारे दूसरे सहयोगियों को चोट लग सकती है । फिर भी वह इस का प्रारम्भ करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तीसरी शक्ति जरूर है जो आज भी 22 वर्ष के बाद हमारे सामाजिक जीवन को विषम बनाना चाहती है । उदाहरण के लिये मैं एक ही बात कहना चाहता हूं । पहले गृह-मंत्रालय जब अपनी यह वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता था तो इस के अन्दर यह आंकड़े दिया करता था कि हमारे देश में दुनिया के किस किस देश के कितने नागरिक रह रहे हैं । लेकिन अब शायद जानबूझ कर गृह मंत्रालय ने अपनी दुर्बलताओं को छिपाने के लिये कई आंकड़े देना बन्द कर दिया है । लेकिन फिर भी प्रश्नों के उत्तर में यदा कदा कुछ इस प्रकार के आंकड़े सामने आ जाते हैं । अभी यहां जब पूछा गया कि हमारे देश में पाकिस्तान के नागरिक कितने ऐसे हैं कि जो पासपोर्ट ले कर के रह रहे हैं ? तो इन्हों ने 27-2-70 को उत्तर दिया कि इस समय पासपोर्ट के आधार पर जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं उन की संख्या 27,615 है । जब यह पूछा गया कि ऐसे कितने हैं कि जिन के पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गयी और जो यहां रह रहे हैं । तो इन का कहना यह है कि 11,7171 दोनों को मिला कर यह संख्या लगभग साढ़े 39 हजार होती है । फिर यह पूछा गया कि ऐसे कितने हैं जो इस देश के अन्दर अवैध ढंग से रह रहे हैं या बिना पासपार्ट के रह रहे हैं ? तो 25-2-70 को

राज्य सभा में यह उत्तर दिया कि उन की संख्या 12,823 है, और जिन में 3,773 वह पाकिस्तानी नागरिक हैं कि जिनका कुछ पता ही नहीं है कि भारत के किस कोने में और किस प्रांत में हैं। इन आंकड़ों को अगर मैं जोड़ूं तो ये सब मिलकर 52 हजार के करीब बैठते ह। पहले गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा के आधार पर आसाम के अन्दर भी कुछ पाकिस्तानी अवैध रूप से प्रवेश कर गये थे। साढ़े तीन लाख से अधिक उनकी संख्या थी। उस में से शायद 50 हजार पाकिस्तानी वापस नहीं भेजे जा सके हैं। तो आज जो चार, पांच लाख पाकिस्तानी भारत के अन्दर रह रहे हैं, मैं गृह मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्रालय ने इस बात की जानकारी ली है कि हमारे देश में जो साम्प्रदायिकता की आग जगह जगह पर भड़कती रहती है इनमें क्या इन पड़ोसी देशों और उनके एजेन्टों का हाथ तो नहीं है जो लोग हमारे देश के आन्तरिक जीवन को विषाक्त कर रहे ह।

दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के अन्दर बहुसंख्यक हिन्दू हैं, हमारे देश में यहूदी भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं उनके साथ साम्प्रदायिक विवाद की स्थिति कभी नहीं आई। इससे मुझे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पड़ौसी देश हमारी स्वतन्त्रता के बाद इस प्रकार की गतिविधियां हमारे देश में जारी रखे हुए हैं जोकि हमारे सामाजिक जीवन को विषाक्त और हमारे देश को बदनाम करे।

अगली बात मैं जो कहना चाहता हूं वह प्रान्तों के विवादों के सम्बन्ध में है। प्रान्तों के विवादों की स्थिति हमारे देश में इस प्रकार की होती जा रही है जैसे कि दो शत्रु देशों की आपस में। बेलगांव को लेकर मैसूर और महाराष्ट्र में जो तनाव आजकल बढ़ रहा है, वह बिल्कुल इसी प्रकार का है। कुछ दिन पहले चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा में एक तनाव चला। तेलेंगाना को लेकर आन्ध्र प्रदेश में इसी प्रकार की स्थिति चल रही है। उसमें 300 के लगभग लोग मर गये और एक हजार से अधिक घायल हुए और कहा जाता है कि 25 हजार के लगभग जेल में गये, जिसमें 30 वहां के विधान सभा के सदस्य भी थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के निर्णय लेने की स्थिति क्या है? सरकार में कुछ दिन पहले चंडीगढ़ के सम्बन्ध में निर्णय लिया। न्याय कहता है कि चंडीगढ़ हरियाणा को जाना चाहिए, शाह कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि चंडीगढ़ हरियाणा को जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हरियाणा की जनता सीधी-साधी थी, इनके पास जल मरने की धमकी देने की और इसी प्रकार की दूसरी बातें नहीं थी। इसका परिणाम यह हुआ कि चंड़ीगढ़ पंजाब को दिया गया। पर चंडीगढ़ पंजाब को दिये जाने के बाद आज क्या पंजाब में चंड़ीगढ़ के प्रश्न पर शान्ति हो गई? पहले जो वहां के चीफ़ मिनिस्टर गुरनाम सिंह थे, उन्होंने निर्णय होते ही फिर धमकी देना शुरु कर दिया। अब जो नई सरकार बनी, वह भी इस प्रकार की धमकी दे रही है और मुख्य मंत्री धमकी दें तो दें, यह बात समझ में आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति की बात यह है कि गृह मंत्रालय जिन लोगों को राज्य के राज्यपाल के पद पर बैठाता है, इस प्रकार के जिम्मेदार आदमी अगर किन्हीं प्रान्तों में जा कर आग भड़काने की कोशिश करें और गृह मंत्री चुपचाप बैठ कर देखते रहें तो क्या यह गृह मंत्री का काम है? राजस्थान के राज्यपाल श्री हुकम सिंह ने अभी चंडीगढ़ के एक कालेज के दीक्षान्त भाषण में फाजिलका और अबहोर के प्रश्न को लेकर यह कहा कि पंजाब को बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ी है। केन्द्रीय सरकार के इस निर्णय के और भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय को इस के ऊपर मजबूती के साथ कोई कदम उठाना चाहिए। अगर इस प्रकार से एक प्रान्त का राज्यपाल दूसरे प्रान्त में जाकर इस प्रकार की आग भड़काए, तो इस प्रकार के लोगों को राज्यपाल के जिम्मेदार पद पर बैठने का

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

कोई अधिकार नहीं है। मेरा कहना यह है कि आप इस पर गम्भीरता से सोचें।

तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वह है सीमा विवाद। मेरा तो निश्चित रूप से यह सुझाव है कि जितने भी राज्य के इस प्रकार के विवाद हैं सीमा सम्बन्धी या किसी और प्रकार के इस के लिए कोई एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण बनाया जाए लेकिन वह वास्तव निष्पक्ष न्यायाधिकरण हो। उस की राय का या उसकी जो रिपोर्ट हो, उस का सम्मान होना चाहिए। ऐसा न हो कि शाह कमीशन की तरह से उसकी रिपोर्ट आए और फिर वह इस प्रकार विवाद का विषय बन जाए। इस पर आप को गम्भीरता से सोचना चाहिए।

दूसरी बात, मैं अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते हुए, राज भाषा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। राजभाषा के सम्बन्ध में मेरा कहना है, चव्हाण साहब को यह पता है, कि आज देश में अधिकांश राज्यों के विश्वविद्यालयों ने अपने राज्यों की भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बना दिया है, पर दुख है कि जो संघीय लोक सेवा आयोग है, उस पर अंग्रेजी छाई हुई है। 1967 के राज्य भाषा संशोधन विधेयक के अनुसार इस देश की राज्य भाषा हिन्दी है, अंग्रेजी केवल सह-भाषा है, लेकिन कानून के हिसाब से तो हिन्दी ही राज भाषा है, पर धक्केशाही के हिसाब से अंग्रेजी राज भाषा है, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि 1967 के कानून में आपने इजाजत दी है कि आपके कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्ति चाहें तो छोटी छोटी टिप्पणियां हिन्दी में लिखें। लेकिन मुझे पता है कि आज आप के इन कार्यालयों में इस प्रकार के अधिकारी बैठे हुए हैं जो कि मौखिक रूप से उनकी धमकियां देते हैं कि अगर वे हिन्दी में टिप्पीणयां लिखेंगे तो उनकी पदोन्नति पर असर पड़ेगा। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आप कम से कम इतना काम करें कि जो हिन्दी जानने वाले मंत्री हैं अगर वे कुछ थोड़ा बहुत हिन्दी में काम करना प्रारम्भ कर दें, सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर पर काम हिन्दी में करना प्रारम्भ करें तो नीचे के व्यक्तियों को उससे प्रोत्साहन मिलेगा और इससे एक वातावरण बनेगा। आप इस दृष्टि से इस पर विचार करें।

अगली बात, सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं इस लोक सभा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि राज्य सभा ने अपने यहां अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी अधिकांश काम प्रारम्भ कर दिया है। आज ही का समाचारपत्र आपने देखा होगा। जरा सी घटना राज्य-सभा में घटी कि वहां की जो सिनोपसिस है, सारांश है, एक दिन देर से आया और राज्य सभा के अन्दर शोर हो गया। यहां पर तो पन्द्रह पन्द्रह दिन में सारांश मिलता है। मैं आप से केवल इतना कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से गृह मंत्रालय को कि वह लोक सभा सचिवालय को इतना कह दे कि लगभग 150 सदस्य यहां इस प्रकार के हैं जिनको अंग्रेजी के आप के प्रशासनों से कोई लाभ नहीं हो पाता और वे अभी तक धैर्य से काम ले रहे हैं। क्या आप यह चाहेंगे कि लोक सभा में खड़े हो कर किसी प्रकार का प्रदर्शन उन्हें करना पड़े? ऐसी स्थिति न आने पाये तो कम से कम यह अवश्य होना चाहिए कि जितने भी विधेयक या जितनी भी सरकारी विज्ञप्ति आएं, उनको दोनों भाषाओं में आना चाहिए। संविधान में आने के बाद और राज-भाषा संशोधन विधेयक के पश्चात हिन्दी का अपमान नहीं होना चाहिए।

दो बातें और हैं जिनको मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं। एक बात तो कहना चाहता हूं लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु की जांच के सम्बन्ध में। श्री यशवन्तराव चव्हाण, हमारे देश के उस समय रक्षा मंत्री थे जिस समय कि लाल बहादुर शास्त्री का देहावसान ताश्कन्द में हुआ। सरदार स्वर्ण सिंह भी वहां पर थे। अब जो तथ्य धीरे धीरे प्रकाश में आ रहे हैं जैसे डाक्टरों की रिपोर्ट परस्पर विरोधी है इन तमाम तथ्यों ने देश के मस्तिष्क

में बड़ा भारी सन्देह उत्पन्न किया हुआ है। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लिए अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनकी मृत्यु की दुबारा जांच करने के लिए मंत्री-परिषद एक व्यक्ति के आयोग की नियुक्ति कर सकती है, तो लाल बहादुर शास्त्री तो इस देश के प्रधान मंत्री थे और ऐसे प्रधान मंत्री थे कि जिन्होंने कुछ महीनों में ही इस देश के दिल को जीत लिया था। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से कहना चाहता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु किन परिस्थितियों में किन कारणों से और कैसे हुई, इस की एक उच्च-स्तरीय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिये, जिससे कि इस देश के दिमाग में बैठा हुआ जो सन्देह है, वह मिटे। मेरे पास कुछ तथ्य हैं और मैं चाहता हूं कि अगर उच्च-स्तरीय जांच होगी, तब उनको उसके सामने रखूंगा और अगर उच्चस्तरीय जांच का कोई फैसला नहीं किया गया तो विवश हो कर सदन के अन्दर उन तथ्यों को रखना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए।

अन्त में एक बात, जिसको कह कर मैं बैठ जाना चाहता हूं, प्रशासनिक सुधार आयोग के सम्बन्ध में है। प्रशासनिक सुधार आयोग की 27 रिपोर्टें आप को मिल चुकी हैं और 27 रिपोर्ट मिलने के बाद भी आपने कोई अमल उन पर नहीं किया। जब प्रशासनिक सुधार आयोग बैठा था तो आप ने यह कहा था कि इस को इसी तरह का महत्व दिया जाएगा जिस तरह से अमरीका में हूवर कमीशन को महत्व दिया गया था। 27 रिपोर्टों के मिल जाने के पश्चात भी आपने कितने प्रतिशत रिपोर्टों पर अमल किया है? इतना उच्च-स्तरीय आयोग आपने बैठाया और होना तो यह चाहिए था कि आज उस की रिपोर्ट आती और कल सरकार उस पर निर्णय लेती। लेकिन वह तो आई० सी० एस० और आई० ए० एस० आफिसर्स के चक्कर में पड़ी है। उन पर टिप्पणी चल रही है, उन पर नोटिंग चल रही है और प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टों को रद्दी की टोकरी में फेंकने की तैय्यारी की जा रही है। अगर इतने महत्वपूर्ण आयोग की रिपोर्ट पर सरकार अमल नहीं कर सकती, तो इस देश में कोई आयोग बैठाने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसपर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और उनके सुझावों को तत्काल लागू करना चाहिए

MR. CHAIRMAN: Shri Randhir Singh.

SHRI RANGA (Srikakulam): When is Shri Imam going to be called?

MR. CHAIRMAN: That question has already been resolved. Probably you were not in the House at that time.

SHRI RANGA: We cannot go on waiting for three rounds.

MR. CHAIRMAN: It has already been decided that every party must have a round first. The first round is completed with Shri Prakash Vir Shastri's speech. After this the second round will start and Shri Imam will have the first chance.

SHRI SHRI CHAND GOYAL: The time allotted for the party in power and the Opposition is fixed. The ruling party was allotted 3 hours and 5 minutes. You should call them only after taking into consideration the 40 minutes that the Home Minister is likely take. If some time remains after that, you can accommodate them. But if their time is exhausted . . .

MR. CHAIRMAN: It is not exhausted.

SHRI BAKAR ALI MIRZA (Secunderabad): Those who are on your list should be given some time because they have been waiting here in the queue.

SHRI SHRI CHAND GOYAL: Kindly find out how much time has been taken by the party in power.

MR. CHAIRMAN: Mr. Bakar Ali Mirza, your name happens to be in a group which has not time allotted to it.

SHRI BAKAR ALI MIRZA: I should have been told that I will not get a chance. I have been waiting for three days. I have no time to waste. I have not come here only to listen to you or to these people. I have also something to say.

MR. CHAIRMAN: Shri Randhir Singh.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मैडम, हमारा देश एक अमली दौर से गुजर रहा है। कई ताकतें ऐसी है जो देश में तब्दीलियां चाहती है। जब तब्दीलिया होती है किसी देश में तो उसमें कुदरती तौर पर कुछ जगह ऐसी बातें भी है जिनके लिए तजबीज होती है, लेकिन फिर भी, होम मिनिस्ट्री की तरफ़ इसकी जो कारकीर्दगी है, पिछले कई सालों से उन बातों में हम महसूस करते है कि खमियां भी हो लेकिन कई चीजें ऐसी है जिनसे हम दिली तसल्ली है। जैसे नागालैंड का मसला है, जैसे वहां पहले हालात थे, अब वहां हालात खराब नही है और इसके लिए हम कुछ न कुछ मुबारकबाद देते हैं होम मिनिस्ट्री को कि वहां इलेक्शन के बाद ऐसी ताकतों के हाथ में हुकूमत है जो कि देश की साथ ज्यादा से ज्यादा रिस्ता-नाता जोड़ती जा रही है और जो ताकतें देश के खिलाफ पहले काम करती थी वह नहीं है।

काश्मीर में भी शेख अब्दुल्ला को बड़े गर्ममिजाज होते थे, उनके दिल मे तब्लीदी आती मालूम देती है और वह हिन्दीके हिन्दुस्तान के हक की बातें करने लगे है। असम में भी जहां झगड़े होते थे, वहां भी हम देखते है कि मेघालय में जो रिफाइनरी का झगड़ा था वहां अब हालत नार्मल हो गई। जहां तक लैंग्वेज का सव्वाल है, तमिलनाडु में जो कंट्रोवर्सी चलती थी, वह भी पूरी की पूरी तो नहीं, कमोवेश 80 प्रतिशत तय हो चुकी है। बंगाल में की एक दो दफे मिनिस्ट्री को हटाने की कोशिश की गई, उनको काबू कर लिय गया। हिमाचल में आप देखिए, वहां कई हजार मास्टरों ने हड़-ताल की, वह भी डालात अब ठीक हो गए। अहमदाबाद में आपने देखा कि देश बड़ी गलत डाइरेक्शन में चल रला था, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने महसूस किया कि इसका हल होना चाहिए और इस रिपोर्ट भी हमने सोंपी तो नज आया कि उधर भी कोई न कोई देश के हित की बात कही जा रही है। डिफे-क्शन के लिए कमेटी बनाई हुई है।

मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे 4-5 मिनट डिस्टर्ब न कीजिए। जो बात मैं कहना चाहता था, वह यह है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक वार्निंग आई है कि इस देश में वह हालात नहीं है, जो गरीब जनता चाहती है वह जल्दी से जल्दी किया जाय वरना इस देश के लिए खराबी हो सकती है। यहां के हालात खराब हो जाएंगे। जितनी भी बातें मैंने कही है उनके लिए होम मिनिस्ट्री की छाप है, जितमें वजीर है उनकी छाप है, उसको हमें दरगुजर नहीं करना चाहिए, वरना हमारी कोताही होगी।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वह मेरे सूबे के सिलसिले में है, फाजिल्का के मिलसिले में। हमें मंजूर नहीं था, फिर भी चंडीगढ हमसे लिया गया क्योंकि मैं महीं मानता हूं कि चंडीगढ़ और खरड का 75 परसेंट पंजाबी स्पीकिंग है। मैं पाटिल साहब की बात यहां मानता हूं कि एक ओर तो जुडिशरी को वह चीज दी जाए और मैं उनकी बात को दुहराता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 5-7 जजों का परमेनेंट पैनल क्रियेट किया जाय और वह ऐसे झगड़ों को जिनमें करोड़ों लोगों का खून होता है इस किस्म के तथा चंडीगढ़ और खरड हिंदी स्पीकिंग हैं या पंजाबी स्पीकिंग हैं, हरियाणा का है या पंजाब का है। वह काम उनको सोंप दिया जाय। फ़ाजिल्का का बाउन्ड्री कमीशन से क्या ताल्लुक है। उसका कबजा हमें दे दिया जाए। अगर वह नहीं करेंगे तो वहां तो कौवे बोलने लग जाएंगे। पानी नहीं मिलेगा, कोई रोड्स नहीं बनेगी। उन लोगों को क्यों फांसी के तख्ते पर लटका रहे हो। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि फाजिल्का तुरंत हमको दे दिया जाए। बाउंडरी कमी न की जो बात कही गई है यह उस को आग लगा रही है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अगर कोई झगड़े हों तो उनके चीफ़ मिनि स्टर आपस में बैठकर तय करें, वरना वह

काम पैनल को दिया जाए। अगर एक कमीशन आपने बना दिया, शाह कमीशन की क्या दुर्गति हुई महाजन कमीशन की क्या दुर्गति होगी, इन कमीशनों से भगवान हमें बचाये, हम इन कमीशनों की बात नहीं मानते। हाई कोर्ट के जज और आप क्या फैसला करते है यह सभी को मालूम है। आप उनको क्यों इन कमीशनों में डालकर उनकी बेइज्जती करते हो।

जब जो बात मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा खतरा इंडियनाइजेशन से है। आप इंडियनाइज किसको करते हैं। यह देश सिखों का है, हिन्दुओं का है, बौद्धों का है, चीनियों का है। तुम ठेकेदार इस देश के कहां से बन गए। यहां दस करोड़ आसमी हैं, कितनी पार्टियों का यह देश है, विरादरी का है, उसके लिए रेक्रूटिंग आफिसर जनसंघ को बना दिया कि यह मुसलमान हिन्दुस्तानी है या नहीं, सब सबसे ज्यादा छुरा घोंपने वाली बात है देश के लिए। देश के इंटिग्रेशन के लिए ये दुश्मन हैं।

दूसरी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। बंगाल के भाई कहते हैं कि हमें जगहें दो वरन हम इस देश में एक इंकलाब ला देंगे, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में विलीन नहीं करते। केरल के भाई कहते है हमें गेहू हो, चावल दो, नहीं दोगे तो हम अलग हो जाएंगे। अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात न रोकी गई तो यह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं समझता हूं कि देश में सेंट्रलाइजेशन करो। अगर चार-पांच जोन बना दें तो अच्छा है। पांच-सात सूबों के अन्दर एक जोन बना दिया जाए।

17.08 hrs.

[**Shri Shri Chand Goyal** in the chair]

पांच-सात सूबों का एक जोन बना दिया जाए और उनके लिए एक सर्विस कमीशन बना दिया जाए, एक हाई कोर्ट बना दी जाए। वरना इस देश का क्या बनेगा। हिन्दुस्तान में 148 सूबे भी बन जाएंगे तो भी कसर रहेगी। तो डिसेन्ट्रलाइजेशन का जो नारा है, इसके नाम पर जो झण्डे जलाये जाते हैं, जो रेलें फूकी जाती हैं, जो आईन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, वह खत्म कर दो।

ओवर सेंट्रलाइजेशन की जो बात करते हैं वह ठीक नहीं। क्या आप भैंस का भी नेशनलाइजेशन करेंगे, बकरी का नेशनलाइजेशन करेंगे? किसान कहता है कि सीलिंग तो कर दी फिर भी सीलिंग की ज़मीन हमारे पास रहेगी या नहीं। कुम्हार कहता है कि मेरा गधा मेरे पास रहेगा या नहीं। चरवाह कहता है मेरे पशु मेरे पास रहेंगे कि नहीं। दुकानदार कहता है कि सीलिंग मुकर्रर करने के बाद भी मेरी दुकान रहेगी या नहीं। या गरीब हरिजन मकान भी उसके पास रहेगा या नहीं। यह ओवर सेंट्रलाइजशन का जो बिल है, नाथपाई का जो बिल है, यह आम देश में चला गया है इस बात को आप देखें।

यह ओवर नेशनलाइजेशन की बात खत्म होनी चाहिये जिसमे कि एक काश्तकार की 20-20 एकड़ तक के लैंड पर यह सीलिंग आदि न लगाई जाय और इस लिमिट तक न छेड़ा जाय बाकी के ऊपर जो करना हो वह भले ही करा जाय....

सभापति महोदय: माननीय सदस्य अब बैठ जायं। मैं दो मर्तबा घंटी बजा चुका हूं।

श्री रणधीर सिंह: बस मैं बैठा ही जाता हूं तीन में ने दुश्मन बताये। एक तो बताया वह इंडियेनाइजेशन जिसका कि मेरे भाई गुप्ता जी नारा लगाते हैं। दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन है और तीसरा ओवर नेशनलाइजेशन है।

सभापति महोदय: आर्डर आर्डर। मैं श्री इमाम को बुला रहा हूं:

श्री रणधीर सिंह: खत्म हुआ जाता है। मैं वहां पार्लियामेंटरी डेलिगेशन में अहमदाबाद गया था और मैं ने प्रधान मंत्री जी को एक

[श्री रणधीर सिंह]

रिपोर्ट पेश की थी कि वहां के जैसे हालात हैं उस में पुलिस विभाग में मुसलमानों का हिस्सा होना चाहिए। इस के अलावा मैं इस बात का भी कायल हूं कि उर्दू को जोकि इस देश की एक नेशनल जबान है उसको उसकी वाजिब जगहा और दर्जा सरकार की तरफ़ से मिलना चाहिए।

मैं सभापति महोदय, आप का बड़ा मशकूर हूं कि आप ने मुझे मौका दिया।

SHRI J. MOHAMED IMAM (Chitradurga): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this chance. The Home Ministry is an important Ministry in the Government. It plays a vital role in the national integration of the country. The responsibility is all the greater in a country where there are a number of political parties, where there are a number of States, with different political complexions. It is the duty of the Home Ministry to see that it forges the unity of the nation and that the nation is strengthened and consolidated. It is also the function of the Home Ministry to see that there is stability, safety and well being and also there is peace in the country. But the recent events have shown that the Home Ministry has not been contributing to the safety and well being of the country. We see in the horizon various disintegrating tendencies. We have seen on the horizon various disruptive tendencies. There is more of disruption rather than construction. Sir, it is more marked after the recent split in the Ruling Congress party, a split into Cong(R) and Cong(O). They consider that the party is above the country and the nation is forgotten and they have forgotten their own duties.

Sir, yesterday, Shri S. K. Patil said that the Centre does not regard it as its duty to maintain law and order. And, whatever happens in the States, whatever turmoil happens in the States, is shoved on the States. Sir, the Naxalites have been doing havoc throughout the country. They have been killing people. Is it not the responsibility of the Centre to put them down?

Sir, students are in a rampage throughout the country and they even go to the extent of getting into the room of he Vice-Chancellor' manhandle and burn the offices. Is it not the responsibility of the Centre? In Bengal, it has been mentioned, thousands of persons have been killed. Still the Centre does not care for it. The Shiva-Senas and other militant bodies have come into prominance and the Centre is not doing anything to put them down. The Home Ministry is complascent. Then, whose responsibility is this? If it is not the responsibility of the Home Ministry, then, whose responsibility is this? What justification is there for the existence of the Home Ministry? They are interested in only satisfying their party appetities. They cannot rise above the party; they place the country below their party interests and act accordingly. I may mention briefly how they have bungled to resolve the dispute between Mysore and Maharashtra and also other similar questions.

All the greatest things are simple. Any complicated matter can be resolved, provided its solution is based on justice? Truth, and Honour. But when you deviate from the path of justice complications will arise. I state—the Home Minister, the Home Ministry and the Central Government have bungled from the very beginning in this matter; and completely mismanaged it. They have shown lack of foresight and failed to realise the serious situation and the serious tension and this serious position now is entirely due to the Home Minister and the Home Ministry. Sir, just now the Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri Vidya Charan Shukla has stated that he was not responsible, the Government of India is not responsible for the complicated state of affairs. But I say emphatically that it is they,—and they alone—that are responsible. Why has this become so serious? Who is responsible? I can state the factors which made with serious.

In the first place it is no wisdom to disturb and unsettle a matter which has already been settled by competent authorities. Secondly, our agreements, pledges entered into must be honoured and must be implemented. Thirdly, when a Commission has been appointed by the agreements of both the parties, it is the duty of the government as well as the duty of the Home Minister to treat the recommendation as binding on them especially when the Commission was appointed at the instance of these States themselves. Fourthly, sabotaging the existing principles laid

down by the S.R.C.,—principles according to which the entire country was reorganised, and accepted by Parliament,—and substituting them by new principles according to one's own convenience. And, fifthly, this is the most important point, the Home Minister has placed himself in an embarrassing position and his failure to rise above regionalism and parochialism. Lastly, the failure of the government to take the Parliament into confidence, by refusing to place the Mahajan Commission's Report before this House, for its consideration.

The appointment of this Commission was intiated by the State of Maharashtra —Maharashtra Government—and its people resorted to satyagraha and hunger strike and forced the Prime Minister and the Government to appoint this Commission. Then the Commission was appointed. Mysore State on the other hand resisted its appointment. A number of lives were lost as a result of firing. Mysore did not want to re-open the boundary question as they knew that complications would arise. They also observed satyagraha and as a result there was a shooting and half a dozen people were killed. It was at the instance of the Maharashtra Government alone that this Commission was appointed and wanted a single man Commission. When the Commission was appointed both the Chief Ministers of Maharashtra and Mysore, the Home Minister and the Working Committee, entered into a solemn agreement that the findings of the Mahajan Commission would be binding and they must be treated as an award. It is on record. The Working Committee composed of members from both the parties, resolved that the border disputes shall be resolved on the basis of the principals laid down by the S.R.C. Report and that its findings shall be final. There are a number of statements made by Shri V. P. Naik and others stating that the Commission's Report would be honoured. Till the report was published they were hailing Mahajan that he was a Daniel. But when the report came out Mysore had cause for depression because many valuable tracts including Nippani and Khamapur which fetch an income of more than Rs. 4 to 5 crores were given to Maharashtra. Maharashtra wanted Belgaum. They forgot about their previous assurances and previous obligations and pledges. They began to blaspheme and command tirade against Shri Mahajan. He was a retired Supreme Court Chief Justice. He was appointed to demarcate the border with Pakistan, whose services were hailed and recognised. But he was treated with contempt and his effigy was burnt. He was very much hurt and this hastened his death. Is this the attitude to be adopted ? Is there no sanctity for his report? On the other hand, what pained me most was that when a Mysore delegation consisting of MPs approached the Prime Minister—and I myself put forward the case of Mysore and pointed out that the sanctity of the report must be respected, the Prime Minister—these are her very words—"Where is the sanctity for any report of any commission?"

SHRI PILOO MODY: It is a direct quotation from Lenin and Stalin.

SHRI J. MOHAMED IMAM: Later on, it was said that what she said had been distorted, but these are her very words which I repeat, 'Where is the sanctity for any report of any commission?". It gave me a shock.

SHRI KAMALNAYAN BAJAJ (Wardha): Her farther unfortunately did the same thing with SRC.

SHRI J. MOHAMED IMAM: I said, 'We stand by the Commission report in spite of the fact that we lose very valuable tracts of Nippani and Khanapur.'

I know Shri Chavan is a nice gentleman and stalwart. But all those who know him best will be the first to sympathise with him. I know he is in a fix, because this movement was started when he was Chief Minister of Maharashtra. Then he came over to the Centre. The best thing for him would have been to divest himself of the Home portfolio, but I admire his strategy.

SHRI PILOO MODY: He should have taken up tourism.

SHRI J. MOHAMED IMAM: What were his moves? In the first place when the report was published in Aug. 1967, instead of doing his duty to place it before Parliament, he threw it into the gutter. Was that the reason for which the Commission was appointed? I will cite three or four instances showing his attitude to scuttle the report. I am sorry he is not here; let me not be misunderstood that I am saying this behind his back. When the question was raised

[Shri J. Mohmed Imam]

in this House he said 'I am going to ascertain the national consensus'. He invited MPs and opposition leaders. There was no understanding reached. Then he took it up in the National Integration Council at Srinagar. He moved that all border disputes should be solved through an agency to be appointed which the Mysore Chief Minister opposed. He wanted to scuttle it by appointing some other agency. His next move was evident when the Prime Minister sent her emissaries to Bangalore with a proposal to bifurcate Belgaum and other places. I am sure this was not the proposal of the Prime Minister because she knows very little about that area, about those villages and towns. She must evidently have been briefed by the Home Minister or someone of his view. The Mysore Chief Minister refused to agree. The Home Minister cannot escape his responsibility for this preposterous propositions but before the Mysore Chief Minister which he wisely rejected.

SHRI KAMALNAYAN BAJAJ: There would be two Berlins then. in India.

SHRI J. MOHAMED IMAM: It is said that Shri Mahajan made his recommendations without any principles or a yardstick. But what was the mandate given to him by the Working Committee on the basis of the fundamental principles laid down by the SRC and accepted by Parliament! He followed exactly those principles. They were four: historical background, administrative convenience, economic viability and linguistic homogeneity . . Filar it was on a district-level; still they said we can go down to taluk level. When the population of a linguistic group was 70 per cent, when it will go to that area. These were the principles according to which the entire country was reorganised and these have been approved by Parliament. What is the village Until principle? The Chief Ministers of Andhra and Tamil Nadu came to an agreement regarding the allocation of the villages on the border between Tamilnadu and Andhra. Whoever had a greater majority would take that village. After they entered into the agreement, they asked Mr. Pataskar to implement it. In fact, Mr. Pataskar is not the originator of this formula. The formula was laid down by the Chief Ministers themselves, and this was confined only to those villages. Now, our Maharashtra friends want this to be applied to the entire country and to disturb the re-organisation of the entire country. Logically I ask: why not on the mohalla basis?

SHRI S. M. JOSHI: Administrative unit.

SHRI J. MOHAMED IMAM: In Hubli there is a Maharashtra division. Bangalore is contiguous to Hosur, in Tamil Nadu area. In fact, the Tamilians are in a majority there and they will claim it on this basis. So also Kolar. So, if you accept this village unit formula, the entire country will be in a turmoil, you will have to reopen the whole thing, and put a Berlin wall in every village and town.

SHRI S. M. JOSHI (Poona) : Why did you ask for Bellary ?

SHRI J. MOHAMED IMAM: Administrative convenience.

SHRI S. M. JOSHI: It was there, not here?

SHRI J. MOHAMED IAMA: Our friends are so particular about Belgaum.

SHRI S. M. JOSHI: Of course, because it is a question of ten lakhs of people, they are not chattel.

SHRI J. MOHAMED IMAM: Whenever there is conflicting opinion, whenever there is a dispute, it is the opinion of an impartial tribunal that must prevail. This Belgaum city has been subjected to the judicial scrutiny of two impartial bodies consisting of eminent judges and jurists, whose sincerity and *bona fides* you cannot question. The Fazl Ali Commission went into the whole matter and assigned Belgaum to Mysore.

SHRI S. M. JOSHI: They had also given Bellary to Andhra.

SHRI J. MOHMED IMAM: The Mahajan Commission went there, studied the entire thing and assigned it to Mysore. Are you going to be guided by the impartial opinion of these two judicial bodies or are you going to be guided by the interested opinion and the agitation of my Maharashtra friends?

SHRI S. M. JOSHI: There are ten lakhs of people. Ask them what they want.

SHRI J. MOHMED IMAM: If people do not have regard for their own words or attach solemnity or sanctity to the verdict of an impartial body, it will become an endless quarrel.

Boundary dispute means only dispute relating to the boundary along Maharashtra, it cannot be converted into a regional dispute, but they want to claim Karwar and beyond. They say that Konkani is Marathi. Mahajan has studied it and he says that Konkani is not Marathi.

SHRI S. M. JOSHI: Why do you not ask the people?

SHRI J. MOHMED IMAM: We have asked the people of Goa. If Konkani was Marathi, Goa would have gone to Maharashtra.

SHRI SONAVANE (Pandharpur): Does he know Konkani to sit in judgment?

SHRI J. MOHMED IMAM: I know that it is allied to Kannada.

SHRI S. M. JOSHI: That is what you think. So, I said, if this boundary dispute has become so serious, it is because of the attitude taken by our Maharashtrian friends. It is because of their failure to honour the commitment. Also, it is due to our Home Minister, for whom I have great regard, because from the beginning he has failed to take a definite decision. He is trying to scuttle it. (*Interruption*)

SHRI SONAVANE : What about the atrocities committed by the Mysore Government on the Maharashtrian people? (*Interruption*)

SHRI J. MOHAMED IMAM: As soon as the report came, why did they not accept it? (*Interruption*) Sir, this agitation has been backed up by Shiv Sena and other forces. I have a cutting here which says some Members of Parliament want to revive the agitation. Let them see justice. By justice, any dispute can be solved. But if they still continue like this, what could be done? So, taking the present political situation into consideration, taking all these aspects into consideration, I think the Maharashtrians are emboldened with the help of the Chief Minister, with the help of the Home Minister and also the Shiv Sena, and they want to create trouble, and dominate and threaten the people of Mysore. Sir, on behalf of the people of the State of Mysore, let me say that we can withstand any onslaught; we are not cowards. I would appeal to the Home Minister that he should be frank and straight forward. Did not the Home Minister say that the Commission's report would be accepted? Why go back on that assurance? That is not the way. Politics is religion. You must have discipline. Yesterday Shri S. K. Patil said that democracy cannot be a success unless it is based on discipline and character. Here, where is the discipline? Is there discipline in the Government itself? When they refused to accept the report, what does it show? Is it discipline? Is it character?

So, with these words, I request them to accept the Mahajan report. You are bound to accept it; in honour, accept it. Accept the report of the Mahajan Commission, who took a lot of trouble and went round and examined a number of witnesses. Many lawyers appeared before the Commission. Please accept it. Because the Belgaum question is there though two Commissions have given a verdict that Belgaum should go to Mysore please do not make the matter more complicated and bitter.

I would respectfully advise my friends here not to resort to violence or to do anything, because threats of doing something are already there. In the interests of the country, let them accept the report. I am sure hey are more Indians than Maharashtrians.

श्री एस० एम० जोशी : यह इन्होंने क्या कहा—वे लोग ज्यादा इण्डियन्ज हैं—देन महाराष्ट्रियन्ज । इस का क्या मतलब है ?

SHRI J. MOHAMED IMAM: I want them to be first Indians, and then Maharashtrians. (*Interruption*)

SHRI PILOO MODY: He is taking objection to a compliment!

MR. CHAIRMAN: Order, order. No objection can be taken. Please maintain order in the House. Now, Shrimati Sangam Laxmi Bai. I have to make it clear that your party has al-

[Mr. Chairman]

ready taken more time than was allotted to its share. Therefore, kindly take a few minutes only.

श्रीमती लक्ष्मी बाई (मेडक) : सभापति जी, मैं होम मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देती हूं। और उन की डिमाण्ड पर बोलना चाहती हूं। उन की डिमाण्ड को सपोर्ट करते हुए, हमारी कुछ दिक्कतें हैं, कुछ दुख हैं, उन को बतलाना चाहती हूं। कल से हम अपने दुख को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं तेलंगाना के बारे में बोलना चाहती हूं। तेलंगाना के बारे में आप सब सहमत हैं, लेकिन हमारे होम मिनिस्टर सहमत नहीं हैं। सब सुनते हैं, लेकिन आपने काम करना बन्द कर दिया। इन पर मुझे बहुत श्रद्धा है। जब ये बम्बई से सेन्टर में आये तो हम ने समझा कि संजीव आ रहा है। लेकिन आज इस संजीव को क्या हो गया है, मालूम नहीं। तेलंगाना के बारे में वहां के बच्चे और बड़े बहुत नाराज हैं। आज के बच्चे कल मिनिस्टर बनेंगे, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आप तेलंगाना के एक करोड़ 30 लाख लोगों को नाराज करके क्या करने वाले हैं, यह समझ में नहीं आता है। 14 महीने बीत गए हैं, वहां पर 50 हजार टीचर्स हड़ताल पर हैं। लेकिन आप कुछ भी खयाल नहीं करते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि आपका इन्टेलिजेन्स ब्यूरो क्या कर रहा है जिसके लिये आप इस सदन से इतना पैसा मांग रहे हैं। पहाड़ों में जाली करेन्सी नोट्स चल रहे हैं, गोल्ड स्मगलिंग हो रही है, अभी दो दिन पहले श्री ज्योति बसु की हत्या करने का प्रयास किया गया, आज उनको गोली मारी गई तो कल दूसरों को मारी जायेगी फिर पता नहीं, आपका इन्टेलिजेन्स ब्यूरो क्या काम करता है ? क्या इसी तरह से आप कन्ट्रोल करेंगे ? क्या आपको नहीं मालूम कि तेलंगाना में इसी प्रकार से 14 महीने गुजर गए हैं लेकिन फिर भी आपके दिल में तेलंगाना के लिए कोई रहम नहीं पैदा होता है। आप यह क़बूल किये हैं कि यह मास मूवमेन्ट है और फिर कहते हैं कि रास्ता नहीं निकलता है। जो भार्गव कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट सितम्बर, अक्तूबर में आई लेकिन फिर भी आप ने इसकी चर्चा सदन में नहीं की। महाराष्ट्र मैसूर वाले इतना हल्ला गुल्ला मचाते हैं तो उनकी बात को आप सुनते हैं लेकिन तेलंगाना के 1 करोड़ तीस लाख लोगों के लिए आप कुछ भी नहीं करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रजाकारों और कम्युनिस्टों के अत्याचार से पुलिस ऐक्शन के द्वारा हम लोगों को बचाया था लेकिन 14 महीने से सेप्रेट तेलंगाना का एजिटेशन चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई भी वहां आने का कष्ट नहीं करता—प्राइम मिनिस्टर नहीं आतीं और कोई दूसरे मिनिस्टर नहीं आते। तेलंगाना के लोगों की बात कोई भी नहीं सुनता। कोई आकर के पूछता भी नहीं। पैसे भी नहीं मिलते। 2864 मुलाजिम और 880 गजटेड आफिसर्स को नुक्सान पहुंचा है लेकिन आप कोई भी जांच नहीं करते। आप समझते हैं कि उनको इसी तरह से जलने मरने दिया जाये। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि होम मिनिस्ट्री किस बात के लिए है ? मरने वालों को कोई भी नहीं पूछता। चीफ मिनिस्टर का वहां से टेलीफोन आ जाये तो आप वहां पर हजारों पुलिस भेज देंगे, क्या यही आपका काम है ? वहां पर बच्चे स्कूल नहीं जाते, टीचर्स बाहर हैं, उनके पीछे पुलिस लगी हुई है लेकिन फिर भी आपको कोई रहम नहीं आता। आपको देखना चाहिए कि वहां पर हैदराबाद में क्या हो रहा है।

आपने जो फोर्थ फाइव ईयर प्लान 6 हजार करोड़ रुपये का बनाया है वह किस लिए बनाया है ? क्या सिर्फ सेन्ट्रल पुलिस के लिए बनाया है ? किसी भी स्टेट में डेवलपमेन्ट का काम नहीं हो रहा है, सिर्फ पुलिस बढ़ाने का काम ही हो रहा है। जिस प्रकार से एक बच्चा जब रोता है तो उसको गुलगुल दिखाकर बहलाया जाता है तो उस तरह से काम चलने वाला नहीं है। बच्चे को दूध देना चाहिए। आखिर इस तरह से कबतक काम चलेगा ? वहां की वास्तविक स्थिति को समझना जरूरी है। आप पुलिस

से कबतक कन्ट्रोल करेंगे ? आप वहां पर कुछ देते नहीं, किसी की बात सुनते नहीं और कुछ करते नहीं । यहां पर हरयाणा नजदीक है, चन्डीगढ़ नजदीक है, पंजाब नजदीक है, वह हल्ला मचाते हैं तो उनकी बात को आप सुन लेते हैं। महाराष्ट्र और मैसूर वाले शोर मचाते हैं तो उनकी बात भी सुनी जाती है लेकिन तेलंगाना की बात को कोई भी सुनने वाला नहीं है । तेलंगाना का कहीं नाम भी नहीं आता है । तेलंगाना के बारे में मोशन लाया जाये तो वह डिसएलाऊ कर दिया जाता है । कोई सवाल पूछा जाये तो उसको भी एलाऊ नहीं किया जाता है । तो इस तरह से कबतक काम चलेगा, यह मैं जानना चाहती हूं । तेलंगाना के बारे में कोई परवाह ही नहीं करता है । भार्गव कमेटी की रिपोर्ट आई है, जिसमें कुछ रखा नहीं है । रीजनल कमेटी के चैयरमैन का दावा है कि तेलंगना के बारे में 107 करोड़ की मांग है । 107 करोड़ रुपये का हमारे साथ अन्याय हुआ है । अगर यह रुपया हमारे ऊपर खर्च किया जाता तो हम बहुत मजबूत होते और हम किसी के मोहताज नहीं होते । लेकिन हमारे साथ सेकेन्ड क्लास सिटिजन का सा व्यवहार किया जा रहा है । यह कहना है कि रीजनल कमेटी में तेलंगाना के विकास के बारे में अगर कोई बात तय की जाती है तो उस पर अमल होना चाहिये, लेकिन वह चीज मुख्य मंत्री पर बाईंडिंग नहीं है । और उस के खिलाफ़ हम गवर्नर को अपील कर सकते हैं । पर वस्तु स्थिति यह है कि होता वही है जो चीफ़ मिनिस्टर चाहता है ।

स्थिति यह है कि आन्ध्रा और तेलंगाना दोनों ही एक दूसरे से नाराज हैं । आज ही अखबार में मैं ने श्री लाचन्ना का एक वक्तव्य देखा जिस में उन्हों ने कहा है कि हम इस बात का स्वागत करेंगे यदि तेलंगाना आन्ध्र से अलग कर दिया जाय । उन का कहना है कि हम इस एडमिनिस्ट्रेशन से फ़ैड अप हैं । कहा जाता है कि तेलंगाना का विकास हुआ है । लेकिन मैं पूछती हूं कि हमारा क्या डेवलपमेंट हुआ है ? हम तो पहले से ही हैदराबाद स्टेट के अंग थे, हमारा हाई कोर्ट था, हमारी यूनिवर्सिटी थी और 1200 मील की रेलवे थीं । हम तो किसी के मोहताज नहीं थे । फिर आप कैसे कहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो गया । जब कि वस्तु स्थिति यह है कि जब से अलग होने की मांग हो रही है, और जिस को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, हमारा विकास होने के बजाय नुकसान ही हो रहा है । हमारे बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है । हमारे बच्चों की पढ़ाई दो साल पीछे हो गयी है । साथ ही लोगों की सीनियारिटी और नियुक्ति में भी नुकसान हुआ है । इस नुकसान को रुपये में नहीं आंका जा सकता ।

हम कहते हैं 107 करोड़ और गवर्नर बोलता है कि 40 करोड़, भार्गव साहब बोलते हैं 28 करोड़ और आप बोलते हैं 26 करोड़ । यह क्या तमाशा है ? कब तक हम ये बातें सुनते रहेंगे । आप लोगों ने कहा है कि हर साल 10 करोड़ रु० खर्च करेंगे । इस से हमारा काम नहीं चलेगा । आप को मालूम होना चाहिये कि भार्गव कमेटी ने आठ पौइंट प्रोग्राम रखा है । प्रेसीडेंट के इंस्ट्रक्शन हैं कि हर 6 महीने चीफ़ मिनिस्टर तेलंगाना के बारे में इन्कम और ऐक्सपेंडिचर की रिपोर्ट असेम्बली की मेज पर रखेंगे, और अगर वह न रखी जाय तो रीजनल कमेटी वाले गवर्नर को अपील कर सकते हैं । अब आप बतायें कि क्या कोई गवर्नर चीफ़ मिनिस्टर के खिलाफ़ कुछ बोल सकता है, या कर सकता है । आज कल गवर्नर की क्या ताकत है ? हमारे यहां के गवर्नर बिल्कुल बूढ़े हैं जो चल नहीं सकते हैं, और वह सर्वोदय वाले आदमी हैं जो स्वभावत: किसी को डरा धमका भी नहीं सकते । इन सब बातों और कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मेरी गृह मंत्री जी से प्रार्थना है कि तेलंगाना की समस्या के बारे में वह कुछ न कुछ करें । तेलंगाना सेपरेट होना चाहिये । हजारों साल से हम सेपरेट हैं । हमारी एक काबिल स्टेट थी । अगर इतिहास पर नजर डाली जाय तो आप पायेंगे कि आन्ध्र और तेलंगाना कंडीशनली जोड़े गये हैं और यदि तेलंगाना वाले

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

उन के साथ नहीं रहना चाहते, दस साल तक हमारी कोई उन्नति नहीं होती तो यह प्रोवीजन है कि तेलंगाना के जितने एम० एल० एज० हैं यदि उन में से दो तिहाई इस पक्ष में हों कि तेलंगाना को अलग होना चाहिये तो हम अलग हो सकते हैं । लेकिन वर्तमान आन्ध्र के जो मुख्य मंत्री हैं उन्हों ने अधिकतर एम० एल० एज० को अपने साथ कर लिया है जिसका परिणाम यह हुआ कि अब हमारा उतना बहुमत नहीं है ।

बच्चा जब किसी नाटक में श्री राम का वेष धारण करता है तो उस को वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है । और अगर वह ऐसा न करे तो दर्शकों के बीच उस की हंसी होगी । लेकिन आजकल के केन्द्रीय नेता ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं जो सभा की दृष्टि से देखें और वैसा ही आचरण करें । परिणाम यह है कि समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और लोगों की भावनाओं को दबाया जा रहा है, उस की उपेक्षा की जा रही है । यही कारण है कि तेलंगाना वाले आप से नाराज़ हैं । सम्भवतः सेन्ट्रल लीडरशिप यह सोचती है कि अगर तेलंगाना की पृथक मांग को मानते हैं तो उन्हें डर लगता है कि कल को झारखंड की, विदर्भ की समस्या भी खड़ी हो सकती है । इसलिये हमारे साथ केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं करना चाहती । मगर मैं आप को चेतावनी देना चाहती हूं कि यदि आज आप हमारी मांग नहीं मानेंगे तो कभी न कभी आप को तेलंगाना को अलग करना ही पड़ेगा । आन्ध्र गवर्नमेंट की रिपोर्ट यहां पर आई है कि वहां पर इतनी बसें जलाई गई और इतनी तोड़ दी गई लेकिन ये लफ्ज़ नहीं हैं कि इतने लोग मरे और इनकी इतनी गिनती है । जो ये कमियां हैं उनको पूरा करने की कोई परवाह नहीं करते हैं और रिपोर्ट में लिखते नहीं हैं । यही सब बातें मुझे कहनी थी ।

सभापति जी, आप का बहुत बहुत धन्यवाद । आप की वजह से मैं बोल सकी, नहीं तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलता ।

श्री राम गोपाल शालवाले (चान्दनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में अनेक सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । मैं अनुभव करता हूं कि इस मंत्रालय का कर्तव्य है कि देश की यथार्थ स्थिति का अध्ययन करके सामयिक समस्याओं को तुरन्त हल करे । इस समस्या का हल राजनीतिक दलबन्दी, वैयक्तिगत दबाव अथवा प्रभाव पर नहीं किन्तु यथार्थता पर आधारित होना चाहिए । इसी सम्बन्ध में मैं कुछ विचार यहां व्यक्त करना चाहता हूं ।

सबसे पहले मैं हिन्दू कोड बिल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । हमारी सरकार ने हिन्दू कोड बिल पास किया और इस का प्रभाव केवल हिन्दू जाति तक ही सीमित है । ऐसा क्यों है जबकि भारत एक धर्म-निर्पेक्ष राज्य है और इसमें किसी विशेष धर्म या किसी विशेष मज़हब का सवाल नहीं है । चाहिए तो यह था कि सरकार समान रूप से एक आचार-संहिता का निर्माण करती और हिन्दू कोड बिल के बजाय इन्डियन कोड बिल बनाती । आज इस का दुष्प्रभाव यह हो रहा है कि बिगड़े हुए हिन्दू और सिक्ख दूसरी शादी करने के लिये अपना धर्म-परिवर्तन करते हैं और धर्म-परिवर्तन कर तब दूसरी शादी करते हैं । मैं बहु-विवाह का समर्थक नहीं हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं आपकी सेवा में कि अगर आप ने हिन्दुओं पर प्रतिबन्ध लगाया है तो इससे मुसलमानों को क्यों मुक्त रखा । मेरा कहना यह है कि हिन्दू कोड बिल के स्थान पर इन्डियन कोड बिल बनना अत्यन्त आवश्यक है ।

गुड़गांव जिले की नूह तहसील में मुसलमान देवियों ने, जिनकी संख्या 100 थी, एक बहुत बड़ा जलूस निकाला और मतालबा किया कि मुसलमानों पर भी प्रचलित बहु-विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगा दिया जाए । आप ने इस बिल को मुसलमानों पर लागू नहीं किया, मैं उस का विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि हिन्दू कोड बिल को इन्डियन कोड बिल का रूप देकर एक समान आचार-संहिता का निर्माण किया

जाए और मुसलमानों में बहु-विवाह की कुप्रवृत्ति को समाप्त किया जाए ।

दिल्ली मैट्रोपोलिटन कौंसिल में एक कांग्रेस सदस्य ने, जनसंघ के सदस्य ने नहीं, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि एक समान आचार-संहिता बननी चाहिए और इस प्रकार का एक कानून बनना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बहु-विवाह नहीं कर सकता चाहे वह हिन्दू हो, चाहे वह मुसलमान हो और चाहे वह सिक्ख हो और वह प्रस्ताव सर्व-सम्मत से पारित किया गया । इसलिए मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस पर गहराई से विचार करें और जो संरक्षण हिन्दू देवियों को दिया हुआ है उससे मुस्लिम देवियों को वंचित न करें। वह संरक्षण मुस्लिम देवियों को क्यों नहीं दिया गया है और जब वे उस का मतालबा करती हैं, तो उस को स्वीकार क्यों नहीं किया जाता है ।

इसके साथ ही साथ मैं दुख के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश को स्वतंत्र हुए 23 साल बीत गये हैं और भारत सरकार हरिजनों की समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ रही है और पिछड़े हुए वर्गों पर अनेक प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं देश में घटित हो रही है । अभी गुड़गांव जिले के अन्दर एक विवाहित लड़की का अपहरण किया गया और अपहरण करनेवाले एक मुस्लिम सज्जन थे । लड़की को उड़ा लिया गया । लड़की के पिता ने पुलिस में इत्तला की और गृह मंत्रालय को पत्र लिखे और अपहरण करनेवाले का नाम तक बता दिया, लेकिन वह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है ।

श्री रणधीर सिंह : यह तो कोई बात नहीं है, हिन्दू भी भगा ले जाते हैं ।

श्री राम गोपाल शालवाले : हां, हिन्दू भी भगा ले जाते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस के बारे में गृह मंत्रालय विचार करे। दूसरी एक और घटना मैं बताऊंगा जो कि दानापुर (बिहार) में हुई । समाचारपत्रों में उस हरिजन लड़की, जिसका नाम दुईजी है, की तस्वीर निकली है । वह एक करोड़पति के घर में उपले थापने गई थी और वहां पर उस करोड़पति के लड़के ने उस का अपहरण किया और उस के साथ बलात्कार किया । पुलिस में रिपोर्ट कराई गई पर पुलिस ने उस को गिरफ्तार नहीं किया और उस को और उस की मां को वहां से भाग जाने पर मजबूर किया गया । उस के बाद उस लड़की को उड़ा दिया गया और पुलिस ने उस को बरामद किया । लेकिन वह जो करोड़पति व्यक्ति जो एक मुसलमान भी हैं, उनके लड़के ने यह सब किया था, अभी तक उन लोगों में से—न बाप न बेटे—किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है । कल के समाचारपत्रों में यह सारी कहानी प्रकाशित हुई है । मैं गृह मंत्रालय से और श्री चह्वाण साहब से कहना चाहता हूं कि वह इस प्रकार की घटनाओं को देश के अन्दर रोकने की कोशिश करें ।

एक और घटना घटी है पटियाला जिले के अन्दर । वह है शहीदगढ़ गांव के अन्दर ग्राम पंचायत ने हरिजनों के मकानों के आगे दीवारें खड़ी कर दी ताकि हरिजन अपने घर से निकल न सकें और अपने घरों में घुस न सकें । इस प्रकार का अत्याचार वहां हरिजनों के साथ किया जा रहा है । इसके साथ साथ यहां पर हरिजनों की बेकारी, हरिजनों की बीमारी और उनकी गरीबी का पूरा लाभ उठाकर विदेशी मिशनरियां जिनकी संख्या गृह मंत्रालय के अनुसार साढ़े 6 हजार है, वह उनका धर्म परिवर्तन करते है और वह उनको भारत विरोधी बनाकर खड़ा कर देते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और अपने कर्तव्य का पालन करे ।

1963 में गृह मंत्रालय को 170 सेक्शन आफिसरों की नियुक्ति करनी थी, लेकिन उन 170 में से एक भी हरिजन नहीं था और जब गृह मंत्रालय से एक संसद् सदस्य ने पूछा तो उनको बताया गया कि कुछ प्रभावशाली पार्लियामेंट

[श्री राम गोपाल शालवाले]

के मैम्बरों ने जाकर गृह मंत्रालय को प्रभावित किया और उनके प्रभाव में आकर उन्होंने 170 आदमी नियुक्त किए । मैं आज जानना चाहता हूं, गृह मंत्री जी से कि उन 170 लोगों को नियुक्त करने के लिए जिन सदस्यों ने प्रभाव डाला और हरिजनों का विरोध किया, उनके नाम बताये जाएं ।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी राज्य में सुप्रीम कोर्ट के जजों और हाईकोर्ट के जजों को जो वेतन मिलता था, हमारा संविधान जिस समय निर्माण किया गया तो वह वेतन कम कर दिया गया और इन 23 वर्षों में महंगाई कितनी हो गई है, यह गृह मंत्री जी जानें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के और हाईकोर्ट के जजों के वेतन में वृद्धि नहीं हुई । उनको जो सुविधाएं हमारे मंत्रियों को मिलती है वह नहीं मिली हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि योग्यतम व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में और हाईकोर्ट में जज बनें, उनके लिये आप उनकी योग्यता के अनुसार उनके वेतन में वृद्धि करें।

जम्मू काश्मीर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि लद्दाख, जम्मू और काश्मीर राज्य के अन्दर है, लेकिन जम्मू और लद्दाख के साथ जो व्यवहार किया जाता है उस पर बार-बार इस सदन में आवाज उठाई गई । जम्मू में आपको चावल दो रुपये सेर मिलता है, जब कि काश्मीर में छह आने सेर है । नौकरियों में लद्दाख और जम्मू के लोगों को नजरअंदाज किया जाता है । इसलिए मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि श्री कुशोक बकुला ने जो निवेदन किया है वह उनके हृदय की आवाज है । इसके साथ साथ मैं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह है गोहत्या-बन्दी का मसला । आपने बार बार यहां पर आश्वासन दिया कि कई राज्य गोहत्या बन्द कर चुके हैं, और केवल बंगाल और नागालैंड बाकी हैं, उन पर भी हम दबाव डाल रहे हैं कि वह बन्द करें। ऐसा हमको श्री जगजीवनराम जी ने बताया लेकिन मैं ने कल प्रश्न पूछा था कि कितने टन गाय का चमड़ा भारत सरकार द्वारा निर्यात किया जाता है तो जवाब दिया गया कि 1967 में 1033 टन का निर्यात हुआ जिसकी कीमत 157 लाख थी । इसके अतिरिक्त 1968–69 में 4243 टन, जिसकी कीमत 580 लाख थी, और 1970-71 के जो आंकड़े दिये गये हैं उसमें बताया गया है कि 1970-71 में 592 1/2 टन बछड़े के चमड़े का निर्यात किया जाएगा । मैं जानना चाहता हूं गृह मंत्री महोदय से कि जब बार बार आप सदन में आश्वासन देते हैं कि हम गोहत्या बन्द कर रहे हैं, वहां आपने 1970-71 में जो निर्यात करना है वह 592 लाख टन है, जब कि 1967 में आपने 157 लाख टन का निर्यात किया । तो क्या आप गोहत्या बंद कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं । इतना निर्यात तो आपने केवल बछड़े के चमड़े का करना है । और गायों के चमड़े के बारे में प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि गायों के चमड़े के बारे में हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं।

मैं समझता हूं कि जिस अबाध गति से आज गायों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और गाय की नसल को यहां पर समाप्त किया जा रहा है उस का उदाहरण संसार में अन्यत्र नहीं मिल सकता है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि देश के अन्दर सुख समृद्धि हो तो उस का कर्तव्य है कि इस देश के 45 करोड़ लोगों के हृदय की भावनाओं का आदर करते हुए गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दे । अगर सरकार ने गोहत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि एक प्रचंड आन्दोलन गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिये छेड़ा जायगा और दुनिया की कोई ताक़त उस आन्दोलन को रोक नहीं सकेगी । यह 45 करोड़ लोगों की भावनाओं का आदर व सम्मान करने का सवाल है । यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है । यह खेद का विषय है कि सरकार मामूली मामूली सवालों पर जोकि केवल थोड़े लोगों द्वारा उठाये जाते

हैं उन पर ध्यान देती है लेकिन इस देश के प्रबल बहुमत की मांग पर सरकार विचार नहीं करती है और उनकी भावना का आदर नहीं करती है । मेरा निवेदन है कि सरकार इस सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्य का पालन करे ।

इस के अतिरिक्त मैं बतलाना चाहता हूं कि अंग्रेजी राज्य में केवल कुछ राय बहादुर, राय साहब, सरदार बहादुर और ख़ान बहादुर ही अंग्रेजी सरकार के समर्थक थे लेकिन हमारे देश की बदक़िस्मती है कि आज इस देश के अन्दर लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग बड़ी बड़ी संस्थाएं लिये बैठे हैं, कोई चीन का समर्थक है, कोई पाकिस्तान का समर्थक है, कोई रूस का समर्थक है तो कोई अमरीका का समर्थक है । मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि उस ने क्या तरक्की की है ? आप कहते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारत पीछे जा रहा है । पूरी तरह से यहां राष्ट्रीयता का सत्यानाश किया जा रहा है और हमारा गृह मंत्रालय है कि टुकर टुकर इन सब बातों को देखता है और अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता है ।

इस के अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी यहां पर फिल्मों का एक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म फैस्टिवल हुआ था और उस के दौरान प्रदर्शित चित्रों में नग्नता के दृश्यों को दिखाया गया था . . . (**व्यवधान**) . . . मैं ऐसी गंदी जगह नहीं जाता हूं । आप ही सोचिये कि आज नौजवान अगर मुझे सिनेमा के अन्दर जाते देखेंगे तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे ? इसलिए मैं सिनेमा आदि ऐसी जगहों पर नहीं जाता हूं । मैं अन्य नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि वह भी ऐसे गंदे स्थानों पर न जाया करें जहां कि इस तरह नग्नता और अश्लीलता का प्रदर्शन होता हो । दूसरों को ऐसे स्थानों पर जाने से मना करने के पहले हमें स्वयं अपने आचरण और व्यवहार द्वारा वैसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये । ऐसा हम न करें कि खुद तो जायें और बाहर आकर दूसरों को हम उपदेश दें कि वह ऐसे गंदे स्थानों पर न जायें । मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं कि कहूं कुछ और करूं कुछ । मैं जो कुछ कहता हूं वही करता भी हूं ।

मैं कहना चाहता हूं कि आप ने खोसला कमीशन की स्थापना की और वह इसलिए नियुक्त किया कि भारतीय फिल्मों में सुधार किया जा सके लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन खोसला साहब ने नग्नता के प्रदर्शन का समर्थन किया है जिसके खिलाफ़ देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आवाज उठी है । सरकार ने इस कमिशन का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जिसका चरित्र नहीं है, जिसका खानपान पवित्र नहीं है, जिसके बारे में लोगों को शक है, ऐसे खोसला साहब को इस प्रकार के जांच कमिशन का आप ने अध्यक्ष बना दिया और उस ने ऐसी सिफारिश कर दी जोकि हमारी परम्पराओं के सर्वथा विपरीत है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस पर विचार करें और देश में व्याप्त नग्नता और अश्लीलता को दूर करने के लिये आवश्यक क़दम उठायें । ऐसी फिल्में जिनमें अश्लीलता और नग्नता का प्रदर्शन होता हो वह बंद होनी चाहिएं क्योंकि इस से हमारे देश के नवयुवकों के चरित्र को नष्ट करने की बात होती है । मैं आशा करता हूं कि मैं ने जो चंद एक बातें आप के सामने रक्खी हैं उन पर आप विचार करेंगे और अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे । मैं आप का धन्यवाद करता हूं ।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : सभापति महोदय, मैं बड़ा अनुगृहीत हूं कि आप ने मुझे आखिरी वक्त में बोलने का समय दिया ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिल जले जब फरियाद करते हैं तो आस्मान हिल उठता है । यहां मैं बर्दवान को लेना चाहता हूं । बर्दवान में 17-3-70 को सेक्रेटरी युवक कांग्रेस मलय साई और प्रणव साई की पुलिस और एस० डी० ओ० के सामने हत्या की गई । उस खून से उन की मां का मुंह पोता गया । इस से बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है ? दिन दहाड़े उन के अफसर मौजूद हैं । आज उन अफसरों को सस्पैंड तक नहीं किया गया । मैं

[श्री शिव नारायण]

आप से कहना चाहता हूं कि इस राज्य में कितना अन्धेर है । हम को डिसिप्लिन की बात बतलाई जाती है । लेकिन सब से पहले डिसिप्लिन को ब्रेक किया होम मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने ।

18 hrs.

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रक्खें ।

I have to bring it to the notice of the House that since the debate has been extended by some time and there are some Members here whose party is still left, we shall have to devote another forty minutes or, so before the Home Minister is in a position to reply. Some of the unattached members like Shri Bakar Ali Mirza want to speak. Shri Bakar Ali Mirza has been requesting for the last two days. There are other Members also whose party is left. Tomorrow, before the Home Minister replies, about half an hour or about forty minutes will be devoted for these members so that they can all be accommodated.

Now we shall take up Discussion under Rule 193.

18.1 hrs.

DISCUSSION *RE*: NON-IMPLEMENTATION OF GAJENDRAGADKAR COMMISSION'S RECOMMENDATIONS IN REGARD TO JAMMU AND LADAKH

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : सभापति महोदय, कुछ दिन पहले जम्मू में एक विराट आन्दोलन हुआ था जिस में ढाई हजार के करीब लोग जेलों में गये । आन्दोलनकारियों में महिलायें भी शामिल थीं जिन की गोद में छोटे छोटे बच्चे थे । आन्दोलन का नेतृत्व जम्मू और काश्मीर के वयोवृद्ध नेता पं० प्रेमनाथ डोगरा ने किया । जिन के प्रति समान रूप से आदर की भावना सारे देश में व्याप्त है । जीवन के अन्तिम चरण में, 89 वर्ष की अवस्था में, शांतिपूर्ण तरीके से कानून का उल्लंघन कर के डोगरा जी को जेल क्यों जाना पड़ा, यह एक सार्वजनिक महत्व का विषय है ।

यह आन्दोलन राजनीतिक नहीं था, आर्थिक मांगों को ले कर था । इतना बड़ा आन्दोलन जम्मू में पहले कभी नहीं हुआ । इस सदन को विचार करना होगा कि कौन से कारण हैं जिन से जम्मू की जनता इतनी असन्तुष्ट हो गई ? कौन सी परिस्थितियां हैं जिन्होंने जम्मू के नागरिकों को कारागार में जाने के लिये विवश किया ?

जम्मू और काश्मीर भारत का अटूट अंग है । हमारा प्रयत्न होना चाहिये कि हम शेष भारत के साथ जम्मू और काश्मीर के सम्बन्धों को और भी मजबूत करें । लेकिन साथ ही यह भी प्रयत्न होना चाहिये कि जम्मू और काश्मीर के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उन के बीच में विकास में, शिक्षा में, नौकरियों में जो असन्तुलन है उस का निराकरण करें । यह दुख का विषय है कि जम्मू और काश्मीर की सरकार गत अनेक वर्षों से जम्मू और लद्दाख के प्रति भेदभाव की नीति अपनाती रही है । इस नीति के विरुद्ध जनता में असन्तोष जागा है जिस के फलस्वरूप राज्य सरकार को केन्द्र के साथ परामर्श कर के श्री गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त करना पड़ा था । उस आयोग की रिपोर्ट आये हुए एक वर्ष से अधिक हो गया, लेकिन अभी तक आयोग की सारी सिफारिशें लागू नहीं की गई । जो असन्तोष है वह मुख्यतया आर्थिक विकास, नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व, शिक्षा सुविधाओं और राशन देने में जो भेद भाव होता है उस को ले कर है ।

तीसरी योजना में केन्द्र की ओर से जम्मू-काश्मीर की सहायता के लिए 235 करोड़ रुपया ग्रांट्स इन एड और 190 करोड़ रुपया ऋण के रूप में दिया गया था । इस तरह से कुल मिला कर 425 करोड़ रुपया दिया गया था । इस में जम्मू-काश्मीर की स्वयं की आमदनी शामिल नहीं है । लेकिन इस 425 करोड़ में से जो जम्मू पर रुपया खर्च किया गया वह मुश्किल से पच्चीस प्रतिशत था और लद्दाख पर खर्च किया जाने वाला रुपया पांच फी सैकड़ा से अधिक नहीं था ।

सब इस बात को जानते हैं कि जम्मू क्षेत्र और काश्मीर की घाटी की आबादी लगभग बराबर है । काश्मीर की घाटी की आबादी चौड़ी अधिक है । लेकिन जम्मू का क्षेत्र काश्मीर की घाटी से दुगना है । जहां तक लद्दाख का प्रश्न है, अकेला लद्दाख बाकी सारे राज्य के क्षेत्र के बराबर है । ऐसी स्थिति में विकास के लिए जो रुपया खर्च किया जाता है उस में इतना भेदभाव करने की क्या आवश्यकता है ?

लद्दाख या जम्मू में स्वाधीनता के बाद कोई भी बड़ा उद्योग स्थापित नहीं किया गया । कहा जाता है कि उद्योग के लिए बिजली की आवश्यकता है । काश्मीर की घाटी की तुलना में जम्मू में बिजली का उत्पादन अधिक सरलता से किया जा सकता है । जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार काश्मीर में पन बिजली की क्षमता बारह सौ मैगावाट की है जबकि जम्मू में यह क्षमता 3100 मैगावाट की है । लेकिन गत 18 वर्षों में काश्मीर में खाली 25 मैगावाट बिजली तैयार करने का प्रबन्ध हुआ है और जम्मू में यह आंकड़ा केवल तीन मैगावाट का है ।

कई वर्षों से सलाल पनबिजली योजना की चर्चा हो रही है । अगर यह शुरू की जाती तो न केवल जम्मू काश्मीर लेकिन हरियाणा और हिमाचल के लिए भी यह योजना बिजली दे सकती थी । अनुमान लगाया गया है कि दो पैसा फी यूनिट के हिसाब से सलाल योजना बिजली तैयार कर सकती है । डा० कर्ण सिंह इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं । गत नवम्बर में उन्होंने जम्मू में घोषणा की थी कि अब सलाल प्राजैक्ट को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले रही है और प्रधान मंत्री महोदया जनवरी में अपने शुभागमन से जम्मू को, अलंकृत करेंगी और अपने कर कमलों से इस योजना का शिलान्यास करेंगी । जनवरी बीत गई लेकिन प्रधान मंत्री के चरण चिन्ह जम्मू की पवित्र भूमि पर नहीं पड़े । शायद उन्हें दिल्ली से फुर्सत नहीं है । सरकारें पलटना, तोड़ना, डगमगाती हुई सरकारों को टिकाना, इस चिन्ता में निर्माण की सारी समस्याएं पीछे पड़ गई हैं । मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि सलाल प्राजैक्ट की स्थिति क्या है, क्या केन्द्र ने उसे चौथी योजना में शामिल कर लिया है ? उसके लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ? कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ? एक बार यह कार्य प्रारम्भ हो जाए तो फिर उद्योग धंधों के लिये हमें इतनी बिजली मिल सकती है जिस के द्वारा हम सारे क्षेत्र का औद्योगीकरण कर सकते हैं ।

किस तरह का भेदभाव किया जाता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं । जम्मू में सिमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए मशीन लाई गई । वह बाहर से मंगाई गई थी । लेकिन वह फैक्ट्री जम्मू में नहीं लगी । वह मशीन श्रीनगर में चली गई । श्रीनगर भी भारत का भाग है । हम श्रीनगर का भी विकास होता देखना चाहते हैं । काश्मीर की घाटी के साथ भेदभाव हो, यह हमें बरदाश्त नहीं है । लेकिन काश्मीर की घाटी, जम्मू और लद्दाख इस में विकास का संतुलन तो हमें रखना पड़ेगा । यदि हमने नहीं किया तो ऐसा असन्तोष पैदा होगा जो राज्य की एकता को भी खतरे में डाल देगा ।

विकास के बाद सेवाओं का प्रश्न आता है । गजेन्द्रगडकर कमिशन ने सेवाओं के सम्बन्ध में बड़ी ठोस सिफारिशें की थीं । लेकिन सारी सिफारिशों को राज्य सरकार ने स्वीकार नहीं किया, उन्हें कार्यान्वित करना तो अलग रहा । जिले के स्तर पर, रिजन यानी क्षेत्र के स्तर पर बोर्ड बनाना मान लिया गया है । लेकिन राज्य के स्तर पर और गजेटिड अफसरों के पदों को ले कर किसी तरह के बोर्ड की व्यवस्था नहीं की गई ।

अनुमान लगाया गया है कि राज्य के सचिवालय तथा राज्यस्तर की अन्य सेवाओं में जम्मू का प्रतिनिधित्व अठारह साल में प्रायः 20 फ़ीसदी घटा है । जम्मू तथा लद्दाख की स्थानीय सेवाओं में 40 फ़ीसदी से अधिक पद काश्मीर

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

घाटी के लोगों को दिये गये हैं । स्थानीय सेवाओं में अगर स्थानीय लोगों को स्थान नहीं मिलेगा तो फिर असंतोष होना स्वाभाविक है । हम यह स्वीकार करते हैं कि सेवाओं में भर्ती गुण के आधार पर होनी चाहिए, क्षेत्र या मजहब के आधार पर नहीं । लेकिन जम्मू-काश्मीर का हाल ही अलग है । वहां सेवाओं में साम्प्रदायिकता का परिचय दिया जाता है और फिर जम्मू तथा लद्दाख के लोगों की उपेक्षा कर के केवल एक ही क्षेत्र के लोगों को भरने की कोशिश होती है ।

मुझे याद है कि जब वर्तमान मुख्य मंत्री श्री सादिक, सत्तारूढ़ नहीं हुए थे, तो उन्होंने पार्लियामेंट के भूतपूर्व सदस्य, मौलाना मसूदी, को 1953 में एक पत्र लिखा था, जिस में स्वयं उन्होंने यह शिकायत की थी कि जम्मू और लद्दाख के लोगों के साथ न्याय नहीं होता है, यहां तक कि जम्मू में अगर चपरासी की जगह ख़ाली होती है, तो उस के लिए भी काश्मीर से आदमी लाना पड़ता है । आज भी परिस्थिति कोई बहुत अधिक बदली नहीं है । शेख़ साहिब चले गये, बख्शी साहब अपदस्थ हो गये और सादिक साहिब का सिंहासन डांवाडोल है । लेकिन सत्तारूढ़ होने से पहले सादिक साहब ने जो आश्वासन दिये थे, वे अमल में नहीं लाये जा रहे हैं ।

गजेन्द्रगडकर कमीशन के अनुसार, 1 अप्रैल 1967 के हिसाब से काश्मीर घाटी की जन संख्या 53.3 फीसदी है, लेकिन सेवाओं में उस को 60.9 फीसदी प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, जब कि जम्मू की जनसंख्या 44.2 परसेंट है, लेकिन सेवाओं में उस का प्रतिनिधित्व केवल 36.1 फ़ीसदी है । लद्दाख का हाल तो और भी बुरा है । 1961-62 के हिसाब से उस की जनसंख्या 2.5 परसेंट थी, जब कि सेवाओं में उस का प्रतिनिधित्व 1.4 परसेंट था ।

एक और भी बड़े खेद की बात यह है कि जम्मू-काश्मीर में सेवाओं के परिगणित जातियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई स्थान सुरक्षित नहीं है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है । शायद सदन को यह बात मालूम नहीं है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 335, जिस में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए रिज़र्वेशन की बात कही गई है, अभी तक जम्मू-काश्मीर में लागू नहीं किया गया है । जब कभी वहां पर सरकारी आदेश के द्वारा परिगणित जातियों के साथ न्याय करने का प्रयत्न किया जाता है, तो कोई सांविधानिक आधार न होने के कारण उस को ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है ।

सम्पूर्ण जम्मू-काश्मीर राज्य में शिड्यूल्ड कास्ट्स की जनसंख्या 7.98 परसेंट है । गजेन्द्रगडकर कमीशन ने सिफारिश की है कि उन को नौकरियों में उन की जनसंख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए । यह आवश्यक है कि हम परिगणित जातियों में भी देखें कि योग्य कौन है और अयोग्य कौन है । लेकिन मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जम्मू काश्मीर में परिगणित जातियों में योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं । लेकिन अगर उन के लिए संरक्षण नहीं है, तो आगे बढ़े हुए वर्गों के साथ दौड़ में उन के लिए टिकना मुश्किल होगा । हमारी मांग है कि संविधान का अनुच्छेद 335 जम्मू-काश्मीर में लागू किया जाये, जिस से वहां की परिगणित जातियों और ट्राइब्ज को नौकरियों में संरक्षण मिल सके ।

भेदभाव किस सीमा तक जा सकता है, यह वहां के खाद्यान्न के वितरण को देख कर समझ में आ सकता है । क्या आप किसी ऐसे राज्य की कल्पना कर सकते हैं, जिस के दो भागों में राशन की मात्रा अलग अलग हो ? क्या किसी ऐसे प्रदेश की कल्पना कर सकते हैं, जिस के दो भागों में सरकारी राशन अलग अलग कीमतों पर दिया जाता हो ?—एक भाग में राशन अधिक हो और दूसरे में कम हो, एक भाग में राशन की कीमत अधिक हो और दूसरे में कम हो ? जब गजेन्द्रगडकर कमीशन के सामने यह बात लाई गई, तो उन्हें यह सारी स्थिति बड़ी

हास्यास्पद लगी । उन्होंने सिफारिश की—मैं उद्धृत करता हूं :

"We recommend that the State Government should review their whole price policy both for the procurement and for the issue of foodgrains and introduce uniform prices for grains throughout the two regions."

आज स्थिति यह है कि श्रीनगर में एक महीने में एक व्यक्ति को 11 किलो चावल और 2 किलो गेहूं का आटा मिलता है, कुल राशन 13 किलो है । लेकिन जम्मू में 3.45 किलो चावल, 6.90 किलो आटा अर्थात 10.35 किलो राशन दिया जाता है । गजेन्द्रगडकर कमीशन के सामने राज्य सरकार ने एक तर्क रखा था—चूंकि काश्मीर की घाटी में ठण्ड ज्यादा पड़ती है, इस लिये लोगों को भूख ज्यादा लगती है और क्या जम्मू में गर्मी ज्यादा है, इस लिये लोग पानी पीकर गुजारा कर सकते हैं, उन के लिये अन्न की आवश्यकता नहीं है । इस पर गजेन्द्रगडकर कमीशन ने लिखा है—

"The State Government explained this difference on the ground that rice is less nutritious than wheat/atta and that on account of the colder climate of Srinagar city the consumption of food is higher in Srinagar city than in Jammu city."

क्या देश में चावल खानेवाला केवल जम्मू-काश्मीर प्रदेश ही है ? और प्रदेशों का भोजन भी चावल है, चावल को अन्नम् कहा जाता है, लेकिन चावल के वितरण में भेदभाव करना, अधिक मूल्य लेना—यह केवल जम्मू-काश्मीर में हो रहा है ।

सभापति जी, केवल राशन की मात्रा में ही अन्तर नहीं है, दामों में भी अन्तर है । वैसे तो जो भी अनाज जाता है, बाहर से जाता है, अधिकांश अनाज पहले जम्मू में जाता है और फिर वहां से श्रीनगर पहुंचता है, इस लिये अनाज जम्मू में सस्ता पड़ना चाहिये और श्रीनगर में महंगा पड़ना चाहिये, क्योंकि श्रीनगर तक अनाज ले जाने में यातायात का भी खर्चा होता है, मगर जम्मू-काश्मीर में गंगा ही उल्टी है । वहां श्रीनगर तक अनाज ले जाने में ज्यादा खर्च करना पड़ता है, मगर वहां अनाज सस्ता है और जम्मू में जहां से अनाज जाता है, वहां अनाज महंगा है । जम्मू में चावल 40 रु० प्रति क्विंटल और गेहूं का आटा 44 रु० प्रति क्विंटल है । मुफस्सिल में गेहूं का आटा 55 रु० और चावल 50 रु० है । देश में हम चावल महंगा देखते हैं और गेहूं सस्ता देखते हैं, इसी लिये देश में यह अभियान चल रहा है कि लोग चावल न खायें, गेहूं खायें, क्योंकि गेहूं अधिक उपलब्ध है, चावल की उपज कम है । चावल के लिय हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है । लेकिन जम्मू-काश्मीर में स्थिति यह है कि चावल खायेगा तो कम दाम देना पड़ेगा और गेहूं खायेगा तो ज्यादा सजा भुगतनी पड़ेगी । क्या जम्मू-काश्मीर अखिल भारतीय नीति की चौखट में नहीं आता है ? क्या क्षेत्र के अनुसार राशन के दाम अलग अलग रहेंगे ? क्या इस से राज्य की एकता बनाये रखने में मदद मिलेगी ?

अभी हाल में जनसंघ की ओर से जम्मू में जो आन्दोलन चला, उसके परिणामस्वरूप स्थिति कुछ सुधरी है, लेकिन अभी तक राशन की मात्रा में भेद-भाव कम नहीं हुआ है । इस के बाद भी काश्मीर की घाटी में अधिक राशन रहेगा और जम्मू में कम तथा दामों में भी अन्तर रहेगा । अभी जम्मू काश्मीर की सरकार ने जम्मू के गांवों में अनाज की कीमत को बढ़ा दिया था, लेकिन जम्मू की जनता के तीव्र आंदोलन के परिणाम-स्वरूप यह कीमत उन्हें वापस लेनी पड़ी, अभी तक भेदभाव समाप्त नहीं हो रहा है, यह भेद-भव समाप्त होना चाहिये ।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है—गजेन्द्रगडकर कमीशन ने साफ़ कहा था कि जम्मू तथा काश्मीर में अलग अलग विश्वविद्यालय होने चाहियें । विश्वविद्यालय बने हैं लेकिन जम्मू के विश्वविद्यालय के लिये व्यक्ति सब श्रीनगर से लाये जा रहे हैं । उस विश्वविद्यालय के लिये भारत के किसी भी भाग से योग्य व्यक्ति लाने के मैं विरुद्ध नहीं हूं । लेकिन यदि स्थानीय योग्य व्यक्ति उपलब्ध हैं, तो पहले उन्हें अवसर दिया जाना चाहिये । मेडिकल

[श्री अटल विहारी वाजपेयी]

कालिज की बात भी गजेन्द्रगडकर कमीशन ने कही थी, लेकिन सरकार कह रही है जम्मू में मेडिकल कालिज 1972 में शुरू होगा। क्या मैडिकल कालिज 1970 में शुरू नहीं हो सकता ? अभी भी जम्मू के व्यक्ति श्रीनगर में जाते हैं, जम्मू के अध्यापक भी मैडिकल कालिज में काम कर रहे हैं। सरकार अगर संकल्प कर ले तो मैडिकल कालिज जल्द प्रारम्भ करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

कुछ और भी भेदभाव हैं। उदाहरण के लिए गजेन्द्रगडकर कमीशन ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि जो रोड टाल हैं, जो सड़क पर चुंगी के नाके हैं, सभी जम्मू में हैं, कश्मीर की घाटी में चुंगी का नाका कोई नहीं है। कमीशन ने सिफारिश की थी कि इस पर विचार किया जाये। केवल एक ही क्षेत्र को चुंगी के नाकों के लिये जुटाया जाये और उनसे होने वाली आमदनी को उस क्षेत्र में न लगाया जाये, यह बात ठीक नहीं है। इसका परिणाम वहां की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इसलिए चुंगी के नाकों के बारे में पुनर्विचार होना चाहिए और सही नीति अपनाई जानी चाहिए।

भेदभाव किस सीमा तक है वह इससे भी प्रकट होता है कि सीज फायर लाइन के पांच मील तक जो बसे हुए हैं उन्हें बैकवर्ड होने की सुविधायें दी गई हैं, पांच मील के भीतर जो कर्मचारी हैं उनको विशेष एलाउन्स दिया जाता है लेकिन पाकिस्तान के साथ जो इन्टरनेशनल बार्डर है उस पर बसे हुए लोगों को और राज्य कर्मचारियों को कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। क्या सीज फायर लाईन ही विभाजक रेखा है, इन्टरनेशनल बार्डर पर रहने वाले लोगों को दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ता ? लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जम्मू से जाती है और सीज फायर लाईन कश्मीर की घाटी में। पिछले बीस सालों से सीज फायर लाइन पर रहने वाले तो फायदे में और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर रहने वाले घाटे में—यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है।

सभापति महोदय, आपको स्मरण होगा कि 50 हजार विस्थापित परिवार, पाकिस्तान के निर्माण के पश्चात् विभिन्न क्षेत्रों से और कश्मीर का जो भाग पाकिस्तान में चला गया वहां से आये लेकिन उन्हें कश्मीर की घाटी में नहीं बसने दिया गया, उन्हें जम्मू में ढ़केल दिया गया। केन्द्रीय सरकार ने उनके लिए 35 सौ रुपया प्रति परिवार दिया लेकिन राज्य सरकार ने उसमें से 25 सौ रुपया जमीन और क्वार्टर के लिए ले लिया परन्तु उन विस्थापितों को उस जमीन और क्वार्टर के लिए अभी तक प्रोप्राइटरी राइट्स नहीं दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में विधान सभा की पिछली बैठक में एक बिल आया तो श्रीनगर में हंगामा हो गया। सरकार झुक गई और वह बिल वापिस ले लिया गया। क्या विस्थापितों के साथ न्याय नहीं होगा ? जिस जमीन को वे जोतते हैं, बोते हैं, जिस मकान में वे रहते हैं, जिसकी कीमत वे अदा कर चुके हैं क्या उसके मालिकाना हक उन्हें नहीं मिलेंगे ? क्या केवल इस आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जायेगा कि वे जम्मू में विस्थापित हैं, कश्मीर की घाटी में नहीं हैं ?

भेदभाव का एक उदाहरण यह भी है कि दस साल हो गए लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर में नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हुए। गजेन्द्रगडकर कमिशन ने सिफारिश की है कि चुनाव न कराने के कारण भी लोकतन्त्र कुंठित हो जाता है, जनता को अपना शासन चलाने में हिस्सेदार बनने का अवसर नहीं मिलता। ये चुनाव तुरन्त कराये जायं। गत वर्ष में पांच बार चुनाव की तारीख निश्चित हुई लेकिन पांचों बार चुनाव टाल दिये गये। सन 1964 में मुख्य मन्त्री, सादिक साहब ने कहा था कि सत्ता में आने के बाद एक वर्ष में हम चुनावक रायेंगे लेकिन पता नही उनका एक वर्ष कितना लम्बा होता है ?

सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर हमारे पर्यटन का क्षेत्र है, हजारों पर्यटक यात्री देश विदेश से जम्मू कश्मीर की यात्रा करते हैं। कश्मीर की घाटी बड़ी मनोरम है। प्रकृति ने अपना

सौंदर्य मुक्त हस्त से वहां पर लुटाया है । लेकिन जम्मू में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जिनका विकास किया जा सकता है । राज्य सरकार ने पर्यटन पर पिछले 18 वर्षों में 6 करोड़ रुपए खर्च किए हैं किन्तु उसमें से कुछ भी रुपया जम्मू में खर्च नहीं किया गया । ऐसा लगता है कि जम्मू पर्यटन के मानचित्र पर नहीं है । विभाजन के पूर्व हजारों पर्यटक कुद, भटोई, भद्रवाह और सनासर में प्रकृति के आनन्द का उपभोग करते थे लेकिन विभाजन के बाद यह स्थिति बदल गई है । पर्यटन केन्द्रों का विकास करने के मामले में भी जम्मू की उपेक्षा की जा रही है । डा० कर्णसिंह यहां पर नहीं हैं, मैं उनसे पूछता कि सारे देश में पर्यटन के विकास के लिए 9 या 10 करोड़ रुपया रखा गया है जिसमें से 3 करोड़ जम्मू कश्मीर के लिए है । उस तीन करोड़ में से जम्मू पर कितना रुपया खर्च होगा ? अभी जम्मू में खाली एक होटेल बनाया है और एक यूथ हास्टेल प्रारम्भ करने की बात है । लेकिन भद्रवाह, सनासर में ऐसे स्थान है जिनका यदि विकास किया जाये तो वहां पर पर्यटक निवास कर सकते ह । आज तो स्थिति यह है कि जम्मू में कोई रुकता नहीं, लोग सीधे श्रीनगर चले जाते हैं । जो उड़कर जाना चाहें वह जा सकते हैं लेकिन जम्मू होकर जाने वालों के लिये पर्यटन क्षेत्रों का विकास भी करना चाहिए ।

अन्त में एक बात कहकर समाप्त कर दूंगा । मैंने निवेदन किय कि हमें जम्मू कश्मीर और शेष भारत के सम्बन्धों को सुदृढ़ करना है और इसके लिये आवश्यक है कि जम्मू कश्मीर की जनता संतुष्ट रहे । इसके लिये यह भी आवश्यक है कि जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनके साथ न्याय किया जाय । और यह भी जरूरी है कि जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाले जितने भी मार्ग हैं वह खोले जायें । अभी रेल गाड़ी जम्मू तक नहीं पहुंची है । कब तक पंहुचेगी ? किस मन्थर गति से चल रही है ? क्या परिस्थिति जितनी तेजी से बदल रही है उसी गति से निर्माण हो रहा है ? फिर भद्रवाह और चम्बा को जोड़ने के लिये जो सड़क बनायी जा रही है वह कब पूरी होगी ? हिमाचल सरकार ने सड़क बना दी, जम्मू की सीमा तक सड़क आ गई, मगर 8, 10 मील का इलाका जम्मू-कश्मीर की सरकार बनाने के लिये तैयार नहीं है । क्या यह भारत से जोड़ने के लिये दूसरे रास्ते नहीं खोलना चाहती ? क्या वह साम्प्रदायिकता की भावना से प्रेरित है ?

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू और लद्दाख के साथ न्याय होना चाहिये । लोगों के धैर्य का बांध टूट रहा है । देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे वहां की जनता भी प्रभावित हो रही है । अलग मेघालय बन गया जनता के मन में नयी आशाएं जाग रही हैं । तेलंगाना में बगावत हो रही है । जम्मू की जनता संयम से कब तक काम लेती रहेगी ? मैं जम्मू के नेताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाया, शान्तिपूर्ण आन्दोलन किया और जब समय आया तो उस आन्दोलन को खत्म भी कर दिया । लेकिन जब तक भेदभाव समाप्त नहीं होगा तो जम्मू की जनता को और लद्दाख के निवासियों को काबू में रखना मुश्किल होगा । मैं गृहमंत्री से कहना चाहता हूं कि परिस्थिति काबू से बाहर हो जाय, क्षेत्रीय असंतुलन को ले कर विघटन की मांगे खड़ी हों, उससे पहले जम्मू कश्मीर की सरकार को तैयार करके भेदभाव को दूर कराने का प्रयत्न करना चाहिये ।

SHRI INDER J. MALHOTRA (Jammu): Mr. Chairman, Sir, I am glad that Shri Vajpayee raised this discussion which has provided an opportunity to this House to take note of certain economic and political problems which are now being faced by the people of Jammu and Kashmir State. At the same time and at the very outset I would like to appeal to this august House that in our enthusiasm to see that all the recommendations of this Commission are implemented. We should not try to create an atmosphere which could help those forces who want the disintegration of Jammu and Kashmir State.

When this Commission was appointed the main purpose not only before

[Shri Inder J. Malhotra]

the Government but before the people also was that we must know and try to remove whatever factors and causes were existing which were hampering the economic development of the three distinct regions of the State. After this report had come most of the recommendations were accepted by the State Government and some of the recommendations have already been implemented.

I quite agree that there are still two or three basic recommendations about which no steps have been taken. When I blame the State Government for delaying the implementation of the major recommendations of this report I would also put some blame or responsibility on the Central Government as to why the Central Government did not take note why the State Government was taking so long and was delaying the implementation of those recommendations.

Shri Vajpayee referred to the agitation of the Jana Sangh.

As far as the people of Jammu region are concerned, he should not have misapprehensions about the political leadership which the Jana Sangh claims there. I would like to remind him that in the 1967 elections the majority of the seats in the State Assembly were won by the Congress Party which is ruling in that State. Both the parliamentary constituencies of the Jammu region were also won by the Congress Party. So, to make this tall claim that the Jana Sangh is the only political party which has always been advocating the aspirations of the common people of Jammu is an attempt to create a wrong impression in the House.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I do not make such a claim. I challenge the Congress Party to start an agitation and to send 2500 volunteers in jail.

SHRI INDER J. MALHOTRA : I accept your challenge. But the only difficulty is that we have to implement the things in the right way. You have only to agitate. We will not be cowed down by you.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: All right; you get them implemented.

SHRI INDER J. MALHOTRA : He said that 2500 people courted arrest. It is not difficult for any political party to get 2500 people to court arrest. As they claim, there was an agitation going on for the last one month. Where was the common man's enthusiasm for that agitation? The common man was never concerned with it. There was only a political motive behind this. By linking every problem with the political capital to be made out of it, they spoil the whole case. As far as the problems of foodgrains and ration are concerned, we in the Congress Party are also as much concerned as they are.

I would like to say only one thing that as far as the rights of the Jammu people are concerned, we are more concerned to see that their rights are protected. As far as the economic problems are concerned, we are more concerned to see that these problems are solved. But since we have the responsibility to give them administration, since we are running the Government there, we have to see from a different aspect and different concept as to how these problems can be solved.

Mr. Vajpayee referred to most of the recommendations which were made in this Report. Be he left out one of the basic major recommendation made about the land reforms. How can the lot of the common man be lifted? Who are the common people ? Who are the majority of the people? They are the farmers. The land reforms were introduced first in the Jammu and Kashmir State. Unfortunately, those land reforms ran into trouble. Now, the Jammu and Kashmir Government appointed the Land Reforms Commission and that Commission has also submitted their report. It is very unfortunate that the State Government has taken no action to see that whatever the recommendations are to be accepted to remove the anomalies and other causes which are causing difficulties for the proper implementation of the land reforms are accepted and the anomalies removed.

Then, I would like to say, when the situation has come to this, the responsibility will now fall upon the Central Government. The Central Government should also get this Report examined in the Home Ministry and see that whatever recommendations are necessary to be implemented for the better economic uplift of the people, not only of the

Jammu region, not only of the Ladakh region, but of the Kashmir region also, are implemented. They must take the responsibility to provide the necessary funds, the necessary technical assistance, and see that those recommendations are implemented.

Mr. Vajpayee also made a reference to the refugee problem. I share his feelings as far as this problem is concerned. There are two categories of refugees in Jammu and Kashmir. One is the category of refugees who migrated from West Pakistan in 1947 after Partition. They have settled in different parts of the Jammu region. They have got no right to hold any property. They have been living there for the last 20-22 years. Their children are born there, their children are educated there. But they have no rights. The first time when direct elections took place, as far as the Lok Sabha is concerned, in 1967, it was the first time in their life when they voted and they saw the ballot paper. They voted for the Parliamentary elections. Now, time and again, we have been impressing upon the Central Government that, as far as this problem is concerned, this is a very grave problem. 22 years is a long period for any Government to solve the problem. The Central Government should take note of this problem and they must see that, before 1972 elections are held and these people are given the right to vote for the State Assembly also.

Then, Sir, the second category is the people who migrated from Pakistan-occupied area. Now, land has been allotted to them. Houses have been allotted to them but, as has been pointed out, they have got no proprietary rights either over the land or the house. The State Government from time to time considered certain proposals. They came out with a legislation also. But again that legislation ran into troubled waters. These are the basic problems on which the State Government alone cannot take decision, implement and solve them. I would urge upon the hon. Home Minister that the problems have come to a point where they can turn into a grave situation. Now, they must take the responsibility on their shoulders, sit down with the State Government, try to thrash them out and come to a solution as soon as possible.

It is true that most of the educational institutions in the past were located in the Kashmir valley. We have no grudge against that. We wish more educational institutions should be opened in the Kashmir valley. But, unfortunately, none of the technical colleges was located in the Jammu region. As the Commission has very rightly pointed out, the location of existing educational institutions need not be disturbed, but in whatever expansions are to be made, whatever new institutions are to be opened, Jammu should get its due share. Likewise, as far as Ladakh area is concerned, there is no degree college and other institutions. Government should also pay attention to that area also.

In the end, I would like to urge, as I said in the beginning, let us not try to make political capital out of the non-implementation of these recommendations. Unfortunately, it is a fact that the State Government has slackened, has delayed taking a decision. The State Government has delayed the implementation of the recommendations. Now, I would urge upon the Central Government to take more interest and feel its responsibility and see that all these recommendations are implemented.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North East): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to you for having given me this opportunity. But I must say that even though I am ready for anything in this House these days, I am a little surprised that we are discussing this subject in an almost cavalier fashion. My friend, Shri Vajpayee, knows very well how delicate and sensitive is the problem of Jammu & Kashmir and its relationship with the rest of India and I hope he would tread on that ground a little more carefully. Anyhow, the subject is being discussed and this House ought to express itself.

Since I have very little time, I can only point out that the Gajendragadkar Commission itself has remarked in paragraph 4 of its report:

> "We do not think that on the basis of the material available to us we would be justified in concluding that the State Government have deliberately discriminated against either Jammu or Ladakh."

In view of this clear statement, I don't think we should, from this forum, castigate a State Government when India is a Union of States and whatever State Government is concerned, they have certain rights which should not be infringed upon. I also repeat what my friend, Mr. Malhotra, said a little while

[Shri H. N. Mukerjee]

earlier that almost all the recommendations of the Gajendragadkar Commission have been accepted. In the matter of implementation, we know very well how slowly the wheels of Government move and if in regard to implementation some delay has taken place, we should not haul the Jammu & Kashmir Government over the coals.

My friend, Mr. Vajpayee, has referred to the idea of the Scheduled Castes getting a better deal. I find from the information at my disposal that the recommendation which was relevant has been accepted and is in the process of implementation and that from 1970-71 the Scheduled Castes would get some special privileges.

Sir, in regard to the difference in the allocation of rations as between Jammu and Kashmir and the difference in prices, we know very well that there are many factors which make for the difference in prices. I am not here to justify what was done in Jammu and Kashmir. I don't know the ins and outs of it; but it is not unlikely that for some special reasons, topographical or otherwise, there were some differences. And, even though Mr. Vajpayee did score a debating-point,—by saying how the people of Jammu were supposed to quench their hunger by drinking some more water because the place was comparatively warm,—it is only a debating point. It may be that in the Kashmir valley which in certain months of the year is liable to be cut off from the rest of the country and supplies might be held up, it is better to ensure for certain reserves so that in the difficult winter months it may not be in a very great difficulty.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi): Jammu is as cold as Kashmir. It is all snow-covered; a large part of Jammu too.

SHRI H. N. MUKERJEE: It may be, Sir. That is why I said, I do not know the details of it. I would leave it to the Government to go into the details of this kind of matter.

Here is a Commission which reported, made recommendations; most of the recommendations are accepted—almost all—and they are in the process of implementation. Both in regard to Jammu and Ladakh the Commission says very clearly that "deliberately discrimination has not been practised." And, the Gajendragadkar Commission also has gone out of its way to remark upon the special character of the Jammu and Kashmir Government, its secular policies and the fact of the freedom of expression which has been allowed to people who might ostensibly be looked upon as having said something which goes against the verbal wording of the Constitution of India. But the Gajendragadkar Commission says "Freedom of expression is allowed to be exercised uninterruptedly in such a sensitive area as Jammu and Kashmir" which speaks volumes for the spirit and strength of Indian democracy. Here is a State, a difficult State, a delicately poised State, which is trying its hardest to integrate itself even better with the rest of the Indian community, and it is not right for the Indian Parliament to put a spoke in the wheel. Let us try to help the Jammu and Kashmir Government if we can. And if I certainly have anything to do with the Kashmir Government I would resent this kind of a discussion. If the Bihar Government is hauled over the coals because Champaran area is comparatively neglected, if the Andhra Government is hauled over the coals with a special discussion because Ravalseema area is not properly looked after, if the West Bengal Government is hauled over the coals because in Purulia and some other areas something that is necessary is not done, then, where do we stand and how do we function in this Union of States? And, that is why, I think that Shri Vajpayee's Motion was uncalled for. But, even so, he has brought up certain matters. And, I do hope that the Home Minister would explain the position and see to it that no fissures take place as between Jammu and Kashmir and the rest of India.

SHRI AHMAD AGA (Baramulla): Mr. Chairman, Sir, it is unfortunate that a motion like this has come from Shri Vajpayee. I wish such motion should not have come up as it will only encourage separatist tendencies and sow the seeds of discord. We have been living together and we want to continue to live together in harmony both in Kashmir as well as in Jammu. The correct facts are not known to Mr. Vajpayee.

Sir, if we look to the Central projects which are now being undertaken, we see that in Kashmir they are proposing

to set up one small unit of the Indian Telephone Industries and one unit of Hindustan Machine-tools for manufacture of watches. But in Jammu region we are having Railway line upto Jammu which will give economic benefits to Jammu region. We are going to have a hydro-electric project at Salal. A Motel is already under construction in Jammu. The Oil and Natural Gas Commission are taking up Saruinsur area for driling of oil. If Kashmir says, we must also have oil, how can that be done? If it is not there, it cannot be done.

So, we can not always say that if anything happens at one place the same thing might happen elsewhere also. We are proposing to have a cement factory in Jammu near Basohli as also a Chemical Pulp Project in Jammu region. That being the case, it is unfortunate that such motions are brought forward here. I am only reminded of the following:

कैसे गुज़रोगे मराहिल मे सफ़र के तावां,
तुम कि मंज़िल से शिनासा हो न रस्ता जानो।

کیسے گزروگے مراحل سے سفر کے تاواں –
تم کہ منزل سے شناسا ھو نہ رستہ جانو –

We have to understand Kashmir in certain background. But before I come to that background I would like to refer to Gajendragadkar Commission with regard to one or two points. On page 28 you will find that the per capita expenditure during the Third Plan was Rs. 186.87 in Jammu but it was Rs. 158.91 in Kashmir. In Ladakh it was Rs. 1,154. Where is the discrimination? This is the expenditure. Now if we go to the development of industry, on page 35 you will find in the same report a list of industries under two heads J & K Minerals and J & K Industry. There is no use reading it out. But I shall only request Shri Vajpayee to look into that. I have no time to read it out. A Medical College has been recommended by Gajendragadkar Commission in Jammu. That cannot be had overnight. The recommendation have come here perhaps a year ago. Equipment has to be bought; Professors have to be found out and even allocation from the Centre has to come. The allocation has not yet come. It is only after we have this allocation that we can have a medical college. The Chief Minister has promised or rather announced that boys will be admitted in Srinagar College in the name of Jammu College. After a certain period, say six or seven months or even a year, when the College comes up there, we shall shift them back to Jammu College. Already the demand for a university has been met. There is a university in Jammu. The recommendation with regard to a Law College in Jammu has also been met. So there is nothing in which the State Government is lacking. In regard to implementation of other recommendations, I can say that development boards are comming up. Of course the State Government admits that with regard to Recommendation No. 38, that is about anomalies in landreforms, they have not yet been able to implement. That is perhaps the only recommendation which has not yet been implemented. About this I want to give you some background. Kashmir, in 1857, was sold to Maharaja Gulab Singh and when it was sold to him that included the land and everything. No cultivator or no landholder owned the land. The feeling was that they were likely to be thrown out. There was no security of tenure. Now the fact is that an agitation was started in 1931 with regard to security of tenure. That agitation finally culminated in this way that in 1938 the National Conference—a Political Party adopted an economic programme known as Naya Kashmir. Muslim League at that time was dominated by landlords. They did not approve of this Plan because they were themselves the landlords. It was the Indian National Congress which gave its blessings to that prgoramme of Naya Kashmir. And that was one reason and perhaps the main reason why Kashmir wanted and tried its best to accede to India. That is the background. Our Indian leaders like Shri Jawaharlal Nehru approved of our economic programme. After Kashmir had acceded to India what the popular Government did as a first step was to have the Act for abolition of big estates. That was introduced in 1948-49.

I can understand that there could be anomalies because it was rushed through and done at once because there was no time to waste on this. The people were agitating for over a century for security of tenure and they had acceded to India because they wanted a socialist programme. So they could not wait and it had to be done at once.

The Wazir Committee was appointed. It gave its report. But the State Government could not for certain reasons

[Shri Ahmed Aga]

implement it. A Land Commission was appointed. We have to understand the background in which these land reforms were effected. It is not the same thing as here; it is entirely a different background there. If in that background there has been any delay in removing this lacuna, it should be understood in the background I have stated.

With regard to food, Shri Vajpayee said that there is discrimination and differentiation. I have figures here. Kashmir meets its own needs by 39.9 per cent, and Jammu by 27.9 per cent. Procurement in Jammu is 4.8 per cent and in Kashmir 9.5 per cent. The sale rates of foodgrains are the same.

It is said that in Kashmir they get a little more in quantity per head than in Jammu. The figures are 156 kg for Srinagar and 126 in Jammu. This also has to be understood. Even since the time of King Lalitaditya, Srinagar had a little more. It has been so during and after the first world war. They have a little more in quantum because they have nothing else to eat. So this is not very surprising.

Then he asked why the price in Srinagar be not the same as in Jammu. I have not been able to understand it. He grudges if the price in Srinagar is a little less. If we take the subsidy, it is the same in Jammu and Kashmir.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Not the same.

SHRI AHMED AGA: This is what the Gajendragadkar Commission has said. It is almost equal.

There is certainly one problem which is there in Jammu, about the DPs of 1947. As Shri Malhotra has said, it cannot be solved by the State Government because it requires more money. It has certain legal implications also. We are claiming that the area from which they have come is ours and there will be a day when our people will go back to those places. These people have become old, and children born on this side of the line after they came will certainly not know where their land was. Legal difficulties do exist. I would suggest that the Central Government appoint a high power board or committee to go into this and ease the difficulties of the 1947 DPs.

With regard to the 1965 DPs, 3 lakhs of them have already been rehabilitated by the State Government with the help of the Ministry of Rehabilitation—no small thing.

The real problem in Kashmir is economic. It is unfortunate that we should go on talking about flimsy things like food ration and other things. In both Jammu and Kashmir, we have forest areas but no forest-based industries. Only 20 per cent of the forest area is exploited; 80 per cent is not. Therefore unless this is understood and forest-based industries are established and those forests which are inaccessible are exploited, we cannot do much. Then we have minerals. Even Mr. Gajendragadkar has given these facts. Our statistical data is also there. We have got gypsum, limestone, copper, lead and zinc, but they are not being exploited, no work has been done. It is said that power is not there. Lower Jhelum is not coming up. The Chinani Project has come up. Salal should be taken up. Upper Sirhind must be completed and the mineral wealth must be exploited. Unless this is done, it is not possible for Kashmir to progress, and these flimsy things will always come up here. It will not lead us anywhere and will only create disaffection between the two regions which we very much resent. It is unfortunate that such motions should be brought up on such flimsy grounds, because an agitation was going on by the Jana Sangh there which was born out of the land reform itself, because they belong to the class of landlords.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभापति जी, मैं बहुत विस्तार से न कहकर केवल दो तीन बातें कहना चाहता हूं । सबसे पहली बात तो यह है कि अभी हमारे मित्र श्री आगा कह रहे थे कि इस प्रकार की चर्चा सदन में उपस्थित करके पृथकतावादी मनोवृत्ति को बढ़ावा दिया गया है । अब मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि कश्मीर घाटी के अन्दर जो अन्न की मात्रा लोगों को खाने के लिए दी जाती है वह पृथक है और जम्मू के अन्दर जो अन्न की मात्रा दी जाती है वह पृथक है । इसको उन्होंने भी स्वीकार किया है कि कश्मीर घाटी में जो खाने

के लिए अन्न दिया जाता है वह पृथक है और लद्दाख के प्रतिनिधि श्री कुशाक बाकुला जी यहां पर बैठे हैं, उन के यहां भी जो खाने के लिए अन्न की मात्रा दी जाती है वह पृथक है। इसके आधार पर अब नहीं, दो महीने बाद, तीन महीने बाद जम्मू और लद्दाख में अगर कश्मीर की सरकार के खिलाफ़ एक पृथकता की भावना बढ़ती है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार के उस निर्णय पर है या उसकी जिम्मेवारी इस प्रस्ताव पर होगी ? पृथकतावादी मनोवृत्ति को सादिक सरकार बढ़ावा दे रही है या पृथकतावादी मनोवृत्ति को यह चर्चा बढ़ावा दे रही है ? मेरा अपना निवेदन यह है कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर में इस प्रकार के हैं जो जान बूझ करके जम्मू और लद्दाख के सम्बन्ध में इस प्रकार का भेदभाव करके एक वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं जिससे जम्मू और लद्दाख के लोग मजबूर हो करके कश्मीर घाटी से अलग रहने का खयाल करें। इसमें उनका हित छिपा हुआ है। उनके मन के अन्दर चोर है। मैं जान बूझ कर चोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन हमारे राष्ट्र के हित में यह है कि इन दोनों ही क्षेत्रों में, भले ही उनकी संख्या थोड़ी हो, किसी प्रकार से भी इस भावना को नहीं पनपने देना चाहिये। जिससे वे कश्मीर घाटी से अपने को अलग होने की बात कहनी तो दूर, सोचें भी।

सभापति जी, आपको याद होगा कि जब सन 1965 में भारत पाकिस्तान का संघर्ष समाप्त हो गया तो शरणार्थी बेघर हो गए थे उनके लिए भारत सरकार ने यहां से कुछ सहायता भेजी। यहां से कुछ रजाइयां और दवाइयां भेजी गई। खाने के लिए अन्न भेजा गया। वह जम्मू क्षेत्र के लिए भेजा गया था लेकिन उसका उपयोग कश्मीर घाटी के अन्दर हुआ। इस प्रकार की शिकायतें सदन में एक बार नहीं, कई बार सुनने को मिली हैं। वहां पर इस प्रकार की घटनायें यह बताती हैं कि केन्द्र सरकार का ऊपर कोई खास नियन्त्रण नहीं है। इस तरह पृथकतावादी मनोवृत्ति को बढ़ाने की जिम्मेवारी कश्मीर सरकार पर होगी। इस प्रकार की चर्चाओं के ऊपर नहीं हो सकती है।

हमारे मित्र कहने लगे कि रेलवे लाइन जम्मू तक ले जाई गई है। मैं उनसे एक मोटी मनोविज्ञान की बात पूछना चाहता हूं कि रेलवे लाइन जमीन पर जाती है या आसमान में जाती है ? जम्मू की भूमि समतल है इसलिए वहां पर रेलवे लाइन पहुंच गई लेकिन श्रीनगर में रेलवे लाइन कैसे पहुंचेगी ? इसमें रेल विभाग ने जम्मू पर अहसान क्या किया है ? वहां की धरती इस योग्य थी, वहां तक रेलवे लाइन गई, आगे भी यदि भूमि समतल हो जायेगी तो आगे को भी चली जायेगी। इस प्रकार की जो छोटी, छोटी बातें हमारे सामने आती हैं उनसे हमको बचना चाहिये।

19 HRS.

एक बात लद्दाख के सम्बन्ध में खास तौर पर कहना चाहता हूं। हमारे गृह मंत्री जी को याद होगा कि कई महीने पहले लद्दाख के अन्दर एक आन्दोलन उठा था और वह इसलिए था कि लद्दाख के 84 हजार निवासियों की योजनाबद्ध ढंग से बौद्ध धर्म से श्रद्धा हटाने के लिये प्रयास किया गया था। वहां के प्रतिनिधि श्री बाकुला जी ने उस बात को यहां सदन में उपस्थित किया था और सदन ने एकमत से उस समय कहा था कि सदन का एक शिष्ट मंडल लद्दाख की स्थिति देखने के लिये जाये और यहां आकर के सदन को रिपोर्ट दे कि लद्दाख की जनता के साथ में क्या हो रहा है। गजेन्द्रगडकर कमीशन ने भी जो अपनी रिपोर्ट दी है उस में भी लद्दाख के सम्बन्ध में कुछ उन्हों ने सुझाव दिया है। जहां उन्हों ने कहा है कि लेह और कारगिल के अन्दर डिग्री कालेज खोले जायें, उस क्षेत्र में यातायात के साधन बढ़ाये जायें, बिजली का विस्तार किया जाय और राशन की मात्रा उतनी हो जितनी कश्मीर घाटी को दी जा रही है। गजेन्द्रगडकर कमिशन ने जो सुझाव दिये उन में एक सब से महत्वपूर्ण सुझाव उन्हों ने यह दिया कि लद्दाख क्षेत्र का एक कैबिनेट स्तर का मिनिस्टर जम्मू-कश्मीर सरकार के अन्दर होना चाहिये कि

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

जिस को यह विभाग सौंपा जाय ताकि वह लद्दाख के हितों की रक्षा करे । तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार के निष्पक्ष आयोग वहां जाते हैं, सारी परिस्थिति को देखने के बाद अपना निर्णय देते हैं क्या भारत सरकार उस रिपोर्ट को फिर जम्मू-कश्मीर सरकार के रहम पर छोड़ देती है । आखिर यह स्थिति कब तक चलती रहेगी ? सरकार को जम्मू-कश्मीर की एकता को बनाये रखना है तो जो चर्चा आज प्रारम्भ हुई है इस की पृष्ठभूमि में इस सरकार को कुछ मज़बूत निर्णय लेना चाहिये ताकि लद्दाख और जम्मू क्षेत्र के निवासियों के मन में पृथकता की भावना पैदा न हो ।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : सभापति जी, बाबू जगजीवन राम जी यहां बैठे हुए थे, वह चले गये इस का मुझे अफ़सोस है । 22 वर्ष तक कांग्रेस में मंत्री रहने के बाद भी आज यह दुखद समाचार सुनने को मिला है कि कश्मीर में संविधान की धारा 335 लागू नहीं है, और धारा 370 को संविधान से निकाल दिया जाय । मैं चव्हाण साहब को धन्यवाद दूंगा अगर वह कश्मीर में धारा 335 लागू करें और 370 धारा को हटा दें जिस से वहां के हरिजनों के साथ न्याय किया जा सके । अगर कश्मीर को अपने साथ रखना है तो धारा 335 को लागू कीजिये और हरिजनों के साथ न्याय कीजिये । आज जो यह ढोल पीटा जा रहा है कि हरिजनों के लिये रिजर्वेशन है तो यह केवल कागज पर ही है, जब कि वास्तव में लोगों को इस का लाभ नहीं मिलता है । मेरे मित्र सादिक़ साहब, बख्शी साहब और शेख़ अब्दुल्ला वहां मुख्य मंत्री रहे हैं, और शेख़ साहब को जवाहर लाल जी के दायें हाथ माने जाते थे उन्होंने इस को लागू नहीं कराया । आपने अभी जवाहर लाल जी की बात की, मैं कहना चाहता हूं कि हिस्ट्री वज़ नाट क्लीयर पंडित जी जो गेम वह देश के अन्दर खेल गये हैं । हरिजनों और मुसलमानों के साथ आप कहते हैं कि बड़ी हमदर्दी है, लेकिन यह नमूना है आप का कश्मीर में । वहां आप ने गरीबों को हेल्प नहीं दी । कश्मीर में दाम की जो बात इन्हों ने कही वह तो अयां हैं : जस करनी तस भोगो ताता, नरक जात क्यों पछताता । जैसा आपने अभी तक किया है उस का फल भोगोगे । जनसंघ के नाम का आप ने जिक्र किया । आप ही उन को बढ़ावा दे रहे हैं । माननीय इन्द्रजीत मल्होत्रा जी अपने मे आग बो रहे हो । हम आग नहीं बोना चाहते । आप और आग़ा साहब कितने पानी में हैं वह मैं जानता हूं ।

मैं माननीय गजेन्द्रगडकर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्हों ने रिकमेन्ड किया है कि साढ़े सात परसेंट वहां हरिजनों की आबादी है इसलिये उन को वहां रिजर्वेशन दो । खूब इंसाफ़ हैं तेरे अंजुमने नाज में । मैं कहता हूं कि आप रिजर्वेशन हटा दें और लड़कों को कम्पटीशन में बैठाओ, जो लड़का आये उस को ले लो । लेकिन आप इंसाफ़ नहीं करना चाहते हो केवल गाल बजाना चाहते हो । बात कहते हो कुछ और करते हो कुछ । इस से स्पष्ट है कि आप के दिल में इंसाफ़ नहीं है ।

मान्यवर, इस देश में हमारी तादाद भी 10 करोड़ है । मुझे याद है कि श्री अब्दुल हकीम को माननीय पंत जी ने कहा था कि हम बाउन्ड हैं माइनारिटी से बात करने के लिये । उस वक्त मुस्लिम लीग, मुसलमानों की आबादी 10 करोड़ के करीब इस देश में थी । 60 मेम्बर जब मुस्लिम लीग के इलेक्ट हो गये तो उन्हों ने कहा कि हम उन से बात करेंगे । इसलिये जब हमारी भी तादाद इतनी है तो हम लोगों को भी आप इग्नोर न करें । माननीय जगजीवन राम जी को कांग्रेस प्रेसीडेंट बना कर यह न समझिये कि आप ने बहुत बड़ा काम किया है । You are digging your own grave. आप सोच लीजिये जो राइट और लैफ्ट कांग्रेस में हो गई, और वह भी दिल्ली में नवम्बर में आप ने माननीय जगजीवन राम जी को प्रेसीडेंट बना दिया, हम ज्यादा रीयली कांग्रेस में हैं, न कि आप । हम एक डिसिप्लिन्ड सिपाही हैं और डिसिप्लिन को मेन्टेन किया है, आप

ने नहीं । इसलिये हमारी मांग है कि ईमानदारी से अगर हम को आप भारतीय समझते हो तो हमारे साथ भी उचित व्यवहार हो ।

भारतीयकरण की बात कही गयी । उसे के क्या माने है ? मेरी राय में भारतीयकरण का मतलब है जो भारतीय हो, जो यहां का अन्न, जल खाये, यहां की धरती माता को अपनी माता समझे वही भारतीय है । यह है भारतीयकरण की परिभाषा । इस का अर्थ किसी पंडित से पूछो, गवार से नहीं । ब्लफ़िंग से काम नहीं चलता ।

Who has corrupted the whole legislature today? Who is responsible for all this corruption? It is this Government. You are responsible.

तो मैं गृह मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इतिहास में एक अमर कीर्ति कर जाइये । आप जब आये थे तो मैं ने आप की बड़ी तारीफ़ की थी :

चार बांस चौबीस गज, अंगुल अष्ट प्रमाण,
तो ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान ।

लेकिन आप चूक रहे हो । इसलिये मैं पुनः कहना चाहता हूं कि धारा 335 को कश्मीर पर लागू कर के हरिजनों का उद्धार कीजिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस का समर्थन करता हूं ।

श्री कुशोक बाकुला (लद्दाख) : सभापति महोदय, मुझे कुछ विशेष कहना नहीं है और बहुत जल्द मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा । हमारे लद्दाख का इलाका जम्मू कश्मीर के क्षेत्रफल को मिलाकर भी अधिक है । लद्दाख का एरिया करीब करीब 29,000 वर्गमील है और उस बड़े एरिया के विकास आदि के लिये सरकार को विशेष प्रयत्न करने चाहिएं । पहले ही मैं श्री गजेन्द्रगडकर कमिशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कह चुका हूं और फिर मैं वहां पर दुहराने की जरूरत नहीं समझता । जैसा मैं ने बतलाया था पहले तो लद्दाख के लोगों को राशन तक नहीं मिलता था लेकिन अब करीब एक साल से लद्दाख में भी लोगों को राशन मिलने लगा है लेकिन वह लेह और कारगिल के शहरों में मिलता है, गांवों में राशन नहीं मिलता है । हक़ीकत यह है कि हमारे यहां गरीब लोग ज्यादातर गांवों में रहते हैं और उन को भी यह राशन मिलना चाहिए जैसे कि जम्मू, काश्मीर और श्रीनगर में हर एक जगह वह मिलता है । फिर यह राशन भी सब को एक बराबर मिलना चाहिये । लेकिन हमारे वहां यह लोकल और नौनलोकल को राशन सप्लाई करन में फर्क किया जाता है । लेह में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको राशन मिलता है । जैसा मैं ने निवेदन किया लोकल को चावल नहीं देते हैं केवल आटा देते हैं जबकि नौन लोकल को आटा व चावल दोनों ही मिलता है । मेरा कहना है कि लोकल को भी यह आटा और चावल मिलना चाहिए । इसके लिए एक साल हुआ उस समय लोगों ने एजिटेशन भी किया है कि राशन में यह भेदभाव बर्ता जाना बंद हो और लोकल और नौनलोकल को एक सा राशन मिले लेकिन अभी यह मांग पूरी नहीं हुई है । मैं चाहता हूं कि यह नाबराबरी राशन के मामले में खत्म की जाय ।

इस के अलावा मैं चाहता हूं कि वहां पर जो कर्मचारी लोग हैं उनकी सीनियारिटी जुनियारिटी सिर्फ लद्दाख के हिसाब से ही होनी चाहिये, जम्मू, कश्मीर को मिला नहीं देना चाहिए । उन की सीनियारिटी जो फिक्स की जाय उस में सिर्फ लद्दाख के लोगों की ही सीनियारिटी जुनियारिटी देखनी चाहिए ।

गजेन्द्रगडकर कमिशन ने वहां की सड़कों और यातायात व्यवस्था के सुधार की भी सिफ़ारिश की है । श्रीनगर से लेह तक जो सड़क बनाई गई है वह पक्की सड़क है और वह मिलैटरी की है लेकिन अपने सिविल इंजीनियरों ने एक भी सड़क पक्की कहीं नहीं बनाई है । लेह से खरजो सड़क बनाई जा रही है लेकिन वह अधूरी है । उस को पूरा करना चाहिये । अभी हमारे यहां यातायात का बड़ा अभाव है । इस के अलावा लेह से खरजे होते हुए न्योमा तक सड़क के

[श्री कुशोक बाकुला]

जरिए मिलाया जाना चाहिये । इसी तरीके से कड़गिल को मुरकट से सड़क से मिलायें । उस सड़क को पक्की बनाना चाहिए । अभी तक वह सिविल इंजीनियरों द्वारा बनाई हुई कच्ची सड़क है । जम्मू, कश्मीर में जितनी सड़कें हैं वह सब पक्की हैं लेकिन लद्दाख में एक भी पक्की सड़क नहीं है । यह लद्दाख और जम्मू, कश्मीर में फर्क है ।

दूसरा मेरा निवेदन है कि लद्दाख को धारा 335 के अन्तर्गत शैडयूल ट्राइब्स तथा शैडयूल ट्राइब्स ऐरिया में शामिल कर दिया जाय । बैकवर्ड क्लास में तो शामिल कर लिया है लेकिन मेरा निवेदन है कि उसे भी अमल में लाना चाहिये । लद्दाख को शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स ऐरिया में शामिल कराने की मांग करने का कारण यह है कि हमारे लद्दाख के 10, 10, 15-15 और 20, 20 विद्यार्थी टैकनिकल एजुकेशन लेकर निकलते हैं लेकिन उन को इंजीनियरिंग कालिजेज में आगे ट्रेनिंग लेने के लिए सीट्स नहीं मिलती है और नौकरी भी मिलना मुश्किल होता है इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि उसे शैडयूल्ड ट्राइब्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स ऐरिया में शामिल कर दिया जाय ताकि उनकी सीट्स इंजीनियरिंग कालिजेज तथा टैकनिकल ट्रेनिंग में रिजर्व हो जायं और नौकरी में भी स्थान सुरक्षित हो जायें ।

श्री मोल्हू प्रसाद (बासगांव) : सभापति महोदय, आप ने जो इस एक घंटे की चर्चा में अपनी पार्टी की ओर से अपने विचार व्यक्त करने के लिये मुझे अवसर दिया उस के लिये धन्यवाद । इस अपने भाषण को प्रारम्भ करते हुए माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि भारत सरकार ने पहली सब से बड़ी गलती यह की कि जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जातियों का रिजर्वेशन तो नहीं रक्खा लेकिन उस ने अन्तर्राष्ट्रीय रिजर्वेशन बना रक्खा है । जब कश्मीर का मामला भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय पंचायत में ले गई तब से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक हस्तक्षेप संरक्षण के रूप में बना हुआ है । मैं उन से कहना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय पता नहीं इस देश के मामलों का किस तरह से मूल्यांकन करती है । दिन रात इस हाउस में चर्चा होती है, अखबारों में छपता रहता है काश्मीर का मामला । अभी कुछ दिन पहले बंगाल की शांति व्यवस्थापक का मामला छपा था । इस सरकार ने पिछडे हुए इलाकों और पिछड़े हुए लोगों की इतनी उपेक्षा की है कि जगह जगह असन्तोष की भावना प्रकट हो रही है । आज पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है, इस के बारे में अखबार वाले सही बात तो छापते नहीं । वहां स्थिति यह है कि शांति और व्यवस्था के मामले में कानून की धारायें अंग्रेजी राज्य की बनाई हुई हैं जो कि भेदभाव पर आधारित हैं । एक किसी आदमी को मार कर इस तरह हालत खराब कर दे कि हड्डी भर न टूटे तो 323 की रिपोर्ट दर्ज होने पर उस में पुलिस को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है । हमारे पार्लियामेंट के मेम्बर दिन रात मगर मच्छ के आंसू बहाया करते हैं । अगर उन धाराओं का प्रयोग पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे प्रांतों में बड़े लोग छोटे लोगों पर करते हैं तो कोई चिल्लाता नहीं है पर उस धारा का प्रयोग बंगाल वाले बड़े लोगों पर करते हैं तो इस हाउस में चिल्ल पौं मचती है । इस लिये मैं गृह मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर सही मानों में धरा 323 गलत है तो उस का फौरन संशोधन होना चाहिये वर्ना इस धारा का बड़े लोग छोटे लोगों पर प्रयोग करेंगे और छोटे लोग बड़े लोगों पर करते रहेंगे तथा बदले की भावना बढ़ती रहेगी और सारे देश में शांति व्यवस्था भंग हो जायेगी ।

दूसरी तरफ विभिन्न राज्यों में जो पिछड़ापन है, चाहे सामाजिक पिछड़ापन ही चाहे आर्थिक पिछड़ापन हो या क्षेत्रीय पिछड़ापन हो, उसको ले कर यह बातें बड़ी तेजी से उठ रही हैं । मैं सारे देश के पिछड़े हुए तबकों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान ले जाना चाहता हूं । साथ ही विभिन्न राज्यों में जो कांग्रेसी या गैर-कांग्रेसी सरकारें बन गई हैं उन के गलत परिणाम नजर आ रहे हैं । फर्ज कीजिये कि

केन्द्र में एक पार्टी की सरकार हैं और राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार है । भारतीय संविधान के अन्दर प्रधान मंत्री को अधिकार है कि वह किसी बस्ती में, किसी क्षेत्र में, किसी गांव जिले में जा सकती हैं । शांति और व्यवस्था राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । फर्ज कीजिये राज्य सरकार ने प्रधान मंत्री के आने के ऊपर रोक लगा दी इस लिये कि प्रधान मंत्री के आने से शांति और व्यवस्था बिगड़ सकती है । अगर उसने अपने अधिकार का प्रयोग किया और प्रधान मंत्री ने अपनी स्पेशल फोर्स का प्रयोग किया तो परिस्थिति क्या हो जायेगी ? इस के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय ने कोई विकल्प नही ढूंढा है । इस लिये मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं गृह मंत्री का ध्यान देश के पिछड़े हुए इलाकों की ओर, चाहे वह इलाका लद्दाख का हो, चाहे जम्मू का हो चाहे काश्मीर हो या हिन्दुस्तान का कोई इलाका हो, दिलाना चाहता हूं । राष्ट्रीय व्यावहारिक और आर्थिक परिषद् ने पिछड़े हुए इलाकों के विकास के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट 1955-56 में दे दी थी । पर वह गृह मंत्रालय में पड़ी हुई है । आज अपने राज्यों और क्षेत्रों के असन्तुलन को समाप्त करने के लिये भारत सरकार का योजना आयोग बना हुआ है लेकिन उस में बैठे हुए मगर मच्छ इस देश के असन्तुलन को समाप्त करने के लिये कोई कारगर उपाय नहीं ढूंढ पा रहे हैं । मैं निवेदन करूंगा, कि आप समझ जायें कि इस देश की पुलिस और इस देश की व्यवस्था को देखना पड़ेगा कि किस जिले में कितनी आबादी है और उस आबादी को नियन्त्रित करने के लिये आप के जेलों में कितनी जगह है, नहीं तो क्या जेलों के अलावा होम मिनिस्टर के बंगले में उन को कैद रक्खा जायेगा ? अगर यह असन्तोष बढ़ गया तो गोली और पुलिस के बल पर उस को रोका नहीं जा सकता है । इस के लिये विश्वास प्राप्त करने की आवश्यकता है ।

मैं इन बातों की ओर ध्यान दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि असन्तुलन को समाप्त करने के लिये आप कोई ठोस कार्रवाई करें और योजना आयोग में जो मगर मच्छ बैठे हैं पहले उन को निकाल बाहर किया जाय । उन में अक्ल जरा भी नहीं है लेकिन सारी अक्ल के ठेकेदार बने हुए हैं । साथ ही इस देश की पंच-वर्षीय योजनाओं में आमूल चूल परिवर्तन किया जाय तभी इस देश में शांति और व्यवस्था बनी रह सकती है नहीं तो यह मामला बिगड़ जायेगा ।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): Mr. Chairman, Sir, about this discussion, whether it was necessary or not, there can be two views about it. But now that the discussion has taken place, it is better that I put in in a proper perspective because some Members did express a view that the discussion about one particular State, about one particular area, might create a feeling that we are discriminating in having discussions about regional balances or imbalances as such. I do not want to go into other arguments because it is much better to come to the facts themselves.

It is true that the Gajendragadkar Commission was appointed and, I must say—I know something about the genesis of the appointment of this Commission, that it goes to the credit of the Chief Minister of Jammu and Kashmir that, when this matter about imbalances or about regional developments was raised and the charges about discrimination were made, he had the courage to agree to appoint the Gajendragadkar Commission. The Gajendragadkar Commission has also come out with certain specific recommendations. But one thing must be said that there are certain regional imbalances, as there are regional imbalances in many other States in the country. And one thing that the Gajendragadkar Commission has categorically said, and that was quoted by the Hon. Member, Shri H. N. Mukerjee, is that there was no deliberate attempt or any planned attempt to discriminate against one area or another.

There are some historical reasons; there are certain climatic reasons. As far as Ladakh is concerned, till '60s began, the area as such was not, really speaking, open and there were no communciations. Only after the Border

[Shri Y. B. Chavan]

Roads Organisation was established certain strategic roads were undertaken and, at present, thanks to the work of the Border Roads Organisation, the area is somewhat open. The hon. Member, Shri Kushok Bakula, did mention about certain difficulties of internal communications in certain areas. Certainly, that requires looking into. But, as I said, there are certain historical reasons and there are certain climatic reasons also because, as we see, this State consists of three main regional areas, Jammu, the Kashmir valley and the Ladakh area, and in these three regions, geographically and climatically, there are certain imbalances. There are certain reasons for that. So, certain imbalances are there.

I entirely agree that these imbalances have to be removed. But they can be removed in certain stages. There have been certain phased programmes about it. The recommendations which the Gajendragadkar Commission has made are in details and they are about the educational facilities, they are about the services and they are about the economic development. There are certain recommendations about the rations also. That was also one of the most complicated controversial aspect.

Now, the information that I have indicates that, in all, about 42 recommendations were made by the Gajendragadkar Commission. The report that we have received from the State Government shows that nearly 35 recommendations, out of 42 recommendations, have been accepted. Maybe, there are some important recommendations about which the hon. Member, Shri Inder J. Malhotra did make a mention, which are not accepted. But I know the reasons for it because there are certain recommendations which have got some specific political overtones, say, for instance, the percentages of posts in the Cabinet, etc. These are matters in respect of which it is very difficult for any Government to bind themselves to any certain formula. But as far as the recommendations about economic development are concerned, certainly, some recommendations have been accepted in principle, not only have been accepted but some of them have been implmented as well .

As far as the Arts college in Ladakh is concerned, it is accepted and, not only accepted, the Education Minister was just telling me that they have made a certain provision about it in this year's budget and about Rs. 90,000 have been provided. The same thing is about the Medical College in Jammu.

Then, the hon. Member, Shri Inder J. Malhotra, said that the Central Government has some responsibility. Whatever responsibility the Central Government have, we do not want to disown it. But that is specifically about the economic development. I know that it is the responsibility of the Central Government to give all cooperation. But the implementation of it will have to be the responsibility of the State Government. If there are any difficulties in their way, it will be our duty to help them. For that purpose, as far as financial aspects are concerned, and so far as the implementation process are concerned, the Government of India have appointed a 4-Ministers committee, which periodically meets either in Delhi or in some part of Kashmir, goes into the implementation progress, finds out whether there are any bottlenecks, finds out any financial difficulties there may be and they make recommendations to the Government of India. I would like to emphasize that Government has made it its own concern to see that the developmental programmes in Kashmir are expedited and are not allowed to slacken.

Now, coming back to the question of ration, it was true that there were hard feelings and there were certain differences in the quantum of rations and in prices, etc. I find that immediately after the recommendations were received, the Kashmir Government started taking certain steps about them. Further, there were some differences between the locals and non locals in Ladakh. There were certainly some differences in the ration quantum and prices, particularly. Then, I think, they took a principled decision about the prices and they fixed certain prices for those people who have got an income of over Rs. 600 per month. For them a certain rate was fixed and a little reduced rate of price was fixed for the low income group people. But, naturally, there was one question that certain quantum of ration was given in Srinagar and a certain other quantum of ration was given in Jammu. That difference is there. Very recently, may be, perhaps as a result of the agitation, certain discussions were

held with local leaders there and at the present moment I am told that certain increases have been made in the quantum of ration to be given in Jammu. Formerly it was 10 plus some points. Now it is said per capita 11 kg. is given per month in Jammu. I know it is somewhat less than in Srinagar itself. But it has certainly increased and the increased quota is to be given in the form of wheat ration. I think the other people also have accepted it as a fair and reasonable solution.

Hon. Member, Shri Vajpayee, made a mention about the Salal Hydro-electric project. He asked, what is going to be its estimated cost? My information is that its cost is likely to Rs. 55 crores and the Central Government has accepted it as a central project. Steps to set up the requisite machinery to execute the work are now under consideration of the Central Government. So, as far as the economic development projects are concerned, things have been undertaken very fast.

The Hon. Member has made certain mention about the problem of refugees, land problem and the question of backward areas. For example, there was a question about treating the local people in Ladakh as backward people. Hon. Member, Shri Kushok Bakula, not on this motion, but earlier when he spoke about the Ladakh problem, mentioned that they should be treated as tribals. That is perhaps an easy suggestion to make but is difficult to accept. But there is some point that these people are backward. A recommendation has been accepted to treat them as backward people and certain percentages have been fixed for them in the general quota of services. I do not want to go into the details. The basic point is that it is conceded that there are certainly some imbalances in certain aspects. It has been accepted in principle, but there was no deliberate intention of continuing them or perpetuating them. The question is of taking steps from time to time to bring about that balance which is necessary in these matters. I am sure the attitude which the Jammu & Kashmir Government showed in appointing a Commission will be appreciated. They said they are prepared for some independent person to go into the matter; let him come and look into it; if there was found anything, they said, they were prepared to accept his recommendations and implement them. This attitude has been shown by the Kashmir Government which is really very creditable, and I have no doubt that when a Government has accepted a commission, its recommendations will be implemented. For that matter, they will need co-operation and support from the Central Government which, I am sure, will not be wanting.

श्री शिव नारायण : हरिजनों की रिज़र्वेशन के लिये कुछ नहीं कहा ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इस के लिये भी कहना चाहिये था । आर्टिकल 335 के अन्तर्गत रिज़र्वेशन की बात है, उस को जम्मू काश्मीर में लागू नहीं किया है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उस के बारे में मैं देख लूंगा ।

MR. CHAIRMAN: The House now stands adjourned to meet at 11 A.M. tomorrow.

19.26 HRS.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 3, 1970/*Chaitra* 13, 1892 (*Saka*).